

भारतीय रिज़र्व बैंक  
**बुलेटिन**



मार्च 2025

खंड 79 अंक 3

संपादक समिति  
मनीष कपूर  
अजीत आर जोशी  
रेखा मिश्र  
प्रज्ञा दास  
सुनिल कुमार  
स्नेहल हेरवाडकर  
पंकज कुमार  
वी. धन्या  
धेता कुमारी  
अनिर्बन सान्याल  
सुजाता कुंडू

संपादक  
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।  
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,  
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को  
<https://bulletin.rbi.org.in> पर देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## भाषण

शिकायत निवारण तंत्र में बदलाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ श्री संजय मल्होत्रा	01
जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में मुख्य भाषण श्री संजय मल्होत्रा	07
डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर संबोधन श्री संजय मल्होत्रा	11
भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड (आईआईएमके)-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के संयुक्त द्वितीय वार्षिक समष्टि अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त सम्मेलन में उद्घाटन भाषण श्री एम. राजेश्वर राव	15

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	23
मानसून और कृषि उत्पादन का स्थानिक वितरण	73
भारत के धन विप्रेषण की बदलती गतिकी - भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि	85
आर्थिक संवृद्धि को उत्सर्जन से अलग करना: एक एलएमडीआई अपघटन विश्लेषण	99
बाज़ार पहुँच और आईएमएफ व्यवस्थाएँ: दुनिया भर से साक्ष्य	111

वर्तमान सांख्यिकी	127
-------------------	-----

हाल के प्रकाशन	181
----------------	-----



## भाषण

शिकायत निवारण तंत्र में बदलाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ  
श्री संजय मल्होत्रा

जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में मुख्य भाषण  
श्री संजय मल्होत्रा

डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर संबोधन  
श्री संजय मल्होत्रा

भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड (आईआईएमके)-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  
(एनएसई) के संयुक्त द्वितीय वार्षिक समष्टि अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त  
सम्मेलन में उद्घाटन भाषण  
श्री एम. राजेश्वर राव



## शिकायत निवारण तंत्र में बदलाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ\*

श्री संजय मल्होत्रा

इस वर्ष के रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिज़र्व बैंक इस सम्मेलन का आयोजन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अर्थात् 15 मार्च के आसपास करता रहा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हम इस सम्मेलन का आयोजन उपभोक्ता सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों पर विचार-विमर्श करने और सेवाओं को बेहतर बनाने तथा शिकायतों को कम करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए करते हैं। हमें उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। यह केवल इसलिए नहीं कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, बल्कि इसलिए भी कि ऐसा करने में हमारा स्वार्थ भी है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में, यदि हम अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो हम लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे।

हमने पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने में काफी प्रगति की है। हमने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को सक्षम बनाया है। अधिकांश बैंकिंग सेवाएँ, चाहे वह जमा खाता खोलना हो या छोटा ऋण लेना हो, डिजिटल हो गई हैं, जिससे सुविधा और गति बढ़ गई है। हम यूपीआई और डिजिटल भुगतान के अन्य साधनों के माध्यम से पहले से कहीं अधिक संख्या में डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के कई लोग शायद कभी बैंक शाखा में नहीं गए होंगे। हमने वीडियो केवाईसी का उपयोग करके खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान की है।

हालाँकि हमने पिछले कुछ वर्षों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया है, लेकिन ग्राहकों की शिकायतों की संख्या बढ़ी है जो गंभीर चिंता का विषय है। मुझे बताया गया है कि पिछले साल

\* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा आरबीआई ओम्बड्समैन के वार्षिक सम्मेलन में दिया गया उद्घाटन भाषण, 17 मार्च 2025, मुंबई।

(2023-24) अकेले 95 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों से 10 मिलियन से अधिक शिकायतें मिलीं। यदि हम अन्य रिज़र्व बैंक-विनियमित संस्थाओं (विसं) में प्राप्त शिकायतों को जोड़ते हैं, तो यह संख्या और भी अधिक होगी। कोई यह तर्क दे सकता है कि यह प्रति वर्ष प्रति हजार खातों पर केवल चार शिकायतें हैं क्योंकि बैंक खातों की संख्या लगभग 2.5 बिलियन है। लेकिन हमारे लिए, एक शिकायत होना भी चिंता का विषय है। हमारे पास 10 मिलियन शिकायतें हैं और तेजी से बढ़ती ग्राहक संख्या और उत्पादों के बढ़ते प्रकारों के चलते यह संख्या बढ़ सकती है, अगर हम मिलकर काम को ठीक से नहीं करते।

### ग्राहक संतुष्टि - बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए आधारशिला

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, वास्तव में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव, किसी भी सेवा उद्योग में एक अनिवार्य शर्त है। हमारा प्रयास समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना होना चाहिए। ग्राहक अनुभव ऐसा होना चाहिए कि शिकायत का कोई कारण ही न हो जिसके लिए निवारण की आवश्यकता हो। मैं एक बुनियादी सच्चाई बताना चाहता हूँ: हर शिकायत भरोसे की परीक्षा होती है। जब कोई उपभोक्ता शिकायत दर्ज करता है - चाहे वह विवादित लेनदेन के लिए हो, सेवा में चूक के लिए हो, अनुचित मूल्य निर्धारण या शुल्क या अनुचित व्यवहार के लिए हो - तो संकेत यह होता है कि हमारी प्रणाली में कमी है। अगर ऐसे मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे उपभोक्ता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदनाम कर सकते हैं।

मुझे ग्राहक सेवा के बारे में एक वास्तविक किस्सा याद आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने, खासकर मैनेजमेंट छात्रों ने इसे सुना होगा। आज के विषय के लिए यह इतना सटीक है कि इसे फिर से सुनाना उचित है। 1975 की सर्दियों में, अलास्का के एक शहर में एक व्यक्ति एक स्टोर में गया और वहां मौजूद सेल्समैन से उसने शिकायत की कि उसने कुछ समय पहले जो बर्फ के टायर खरीदे थे वे टिक नहीं रहे हैं। सेल्समैन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि वह उन्हें बदल नहीं सकता, लेकिन वह देखेगा कि वह क्या कर सकता है और स्टोर के पीछे चला गया। आप में से जो लोग यूएस में डिपार्टमेंटल स्टोर गए हैं, उन्हें पता होगा

कि स्टोर के पीछे रिफंड की प्रक्रिया की जाती है। सेल्समैन कुछ समय बाद वापस आया और रिफंड के रूप में कुछ नकद राशि दी और ग्राहक संतुष्ट होकर चला गया। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि यह अनोखा क्यों था, क्योंकि यूएसए में रिफंड के लिए कोई सवाल नहीं पूछे जाने की नीति काफी आम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित कंपनी नॉर्डस्ट्रॉम है जो टायर बेचती भी नहीं। वह परिधान और जूते बेचती है। लेकिन, नॉर्डस्ट्रॉम के लिए ग्राहक प्रथम है। उस पर भरोसा करना और उसका भरोसा जीतना किसी भी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है।

कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई सच्ची कहानी नहीं है। यह कैसे संभव है? कोई कंपनी ऐसे उत्पाद के लिए रिफंड कैसे दे सकती है जिसे उसने कभी बेचा ही नहीं? हालांकि, नॉर्डस्ट्रॉम का कहना है कि यह घटना हुई थी। नॉर्डस्ट्रॉम ने टायर सहित विविध सामान बेचने वाली एक अन्य कंपनी से तीन स्टोर खरीदे थे। ग्राहक को यह एहसास नहीं हुआ कि स्टोर बदल गया है और वह अपनी शिकायत लेकर चला आया। मुख्य संदेश यह है कि नॉर्डस्ट्रॉम खुद को ग्राहक सेवा के व्यवसाय में देखता है, न कि केवल सामान बेचने में। हमें भी यह समझने की जरूरत है कि हम केवल बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं बेचने के बजाय सच्ची ग्राहक सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में हैं।

### शीर्ष प्रबंधन ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दे

मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हम वास्तव में ग्राहक सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं। लेकिन शायद हम ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण पर पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बैंकों और एनबीएफसी को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, बल्कि संतोषजनक समाधान के अभाव में, उनमें से बड़ी संख्या में शिकायतें आरबीआई ओम्बड्समैन के पास पहुंच रही हैं।

इस बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। रिज़र्व बैंक की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 50 प्रतिशत की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में 9.34 लाख हो गई है। रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय में संसाधित शिकायतों की संख्या 2022-23 की लगभग 2,35,000 से 25 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में लगभग

2,94,000 हो गई। न केवल बड़ी संख्या में शिकायतें अगले स्तर तक पहुंच रही हैं, बल्कि उनमें से एक बड़े हिस्से, जिनमें पिछले साल लगभग 57 प्रतिशत सुनवाई योग्य शिकायतें थीं - के लिए रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन की मध्यस्थता या औपचारिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक अत्यधिक असंतोषजनक स्थिति है और इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसलिए मैं सभी एमडी और सीईओ, जोनल और क्षेत्रीय प्रबंधकों और शाखा प्रबंधकों से आग्रह करता हूँ कि वे, अगर हर दिन नहीं तो हर सप्ताह, कुछ समय शिकायत निवारण पर खर्च करें। यह जरूरी है। सभी मान्यवर सीईओ इसके लिए समय निकालते हैं। हमें भी ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण में सुधार के लिए अपनी डायरी में कुछ समय अवश्य रखना चाहिए।

### ग्राहक सेवा प्रणालियों में सुधार

ग्राहक शिकायतें कोई परेशानी नहीं हैं - वास्तव में वे सुधार, नवाचार और विश्वास बनाने के अवसर हैं। उन्हें उचित ढंग से हल करना आपकी सफलता को परिभाषित कर सकता है। प्रत्येक अनसुलझी शिकायत विनियमित संस्थाओं के लिए ग्राहक विश्वास और ईमानदारी स्थापित करने का एक खोया हुआ अवसर है। यह एक चेतावनी संकेत भी है क्योंकि बार-बार शिकायतें आना अक्सर प्रणालीगत खामियों का संकेत होता है। आजकल शिकायतें अक्सर आधिकारिक माध्यमों तक पहुँचने से पहले ही सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, जो सक्रिय उपायों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

इसलिए प्रयास केवल शिकायतों का समाधान करने का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसी प्रकार की शिकायत दोबारा न आए। डिजिटल लेनदेन विवाद, अनधिकृत शुल्क या गलत संचार जैसी कई शिकायतें बार-बार दोहराई जाती हैं। ये विनियमित संस्थाओं के समग्र ग्राहक सेवा ढांचे में अंतर्निहित मुद्दों के स्पष्ट लक्षण हैं। प्रत्येक शिकायत के मूल कारण का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि उपचारात्मक कार्रवाई को सक्षम किया जा सके और एक ही प्रकार की शिकायत की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

वास्तव में मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। सर्वोत्तम सेवा वह नहीं है जिसमें शिकायत निवारण की आवश्यकता ही न हो, बल्कि वह है जिसमें ग्राहक सेवा विभाग को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही न हो। प्रणाली को निर्बाध और सुविधाजनक तरीके से काम करना चाहिए ताकि ग्राहकों को शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र पर कॉल करने या बैंक या एनबीएफसी में किसी से बात करने की आवश्यकता न पड़े। प्रणाली को इतना उपयोगकर्ता-अनुकूल होना चाहिए कि ग्राहक किसी और पर निर्भर होने के बजाय स्वयं-सेवा पर भरोसा कर सकें।

### आंतरिक शिकायत निवारण प्रणालियों में सुधार

शिकायतों को कम करने के लिए प्रणालियों में सुधार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी विनियमित संस्थाओं को चाहिए कि वे एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करें। मैं आप सभी से इसकी समीक्षा करने का आग्रह करूंगा। हालांकि विनियमन के तहत शिकायत निवारण के लिए किसी निर्धारित ढांचे का कोई निर्देश नहीं है, मेरा अनुभव बताता है कि बड़ी विनियमित संस्थाओं में शिकायत निवारण के लिए कम से कम दो स्तर होने चाहिए, जिसमें अनसुलझे शिकायतों को निचले स्तर से उच्च स्तर पर भेजा जाना चाहिए। उच्चतम स्तर काफी ऊंचे पद का होना चाहिए ताकि कोई अनुरोध वरिष्ठ अधिकारी, जिसके पास ग्राहक हित में निर्णय लेने का अधिकार हो, द्वारा जांचे बिना खारिज न हो। इससे ओम्बड्समैन के पास जाने वाली शिकायतों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आंतरिक ओम्बड्समैन कार्यालय सहित सभी स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी पर्याप्त संख्या में हों।

मैं आपका ध्यान विनियमित संस्थाओं द्वारा शिकायतों को अनुरोध, प्रश्नों और विवादों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता। इसके अलावा, यह एक गंभीर विनियामक उल्लंघन भी है।

### सेवा सुधार के प्रमुख क्षेत्र

अब मैं ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा जहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं केवाईसी, डिजिटल धोखाधड़ी, अप-बिक्री और आक्रामक वसूली प्रथाएँ।

केवाईसी के संबंध में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक बार जब कोई ग्राहक किसी वित्तीय संस्था में दस्तावेज जमा कर देता है, तो हम उसी दस्तावेज को फिर से जमा कराने पर जोर न दें। एक बार जब ग्राहक किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक की किसी विनियमित इकाई के पास अपने विवरण, उदाहरण के लिए, अपने आवासीय पते को अपडेट कर देता है, तो यह सीकेवाईसीआर में अपडेट हो जाता है और अन्य आरई को अपडेट करने की सूचना दी जाती है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए पीएमएल नियम और केवाईसी संबंधी आरबीआई के मास्टर निर्देश में कहा गया है कि विनियमित संस्थाएं खाता खोलने के लिए केवाईसी दस्तावेज मांगने से पहले सीकेवाईसीआर प्रणाली की जांच कर लें। लेकिन अधिकांश बैंकों और एनबीएफसी ने अपनी शाखाओं/व्यवसाय इकाइयों में इसे क्रियान्वित नहीं किया है, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है। इसे शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाए, जो सभी के हित में होगा।

ग्राहक सुरक्षा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा डिजिटल धोखाधड़ी में हो रही वृद्धि है। यह बहुत चिंता की बात है कि मासूम ग्राहक लगातार घोटालेबाजों के शिकार बन रहे हैं। हालांकि इसका कारण डिजिटल लेन-देन में वृद्धि और धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए नए-नए तरीके हो सकते हैं, लेकिन ग्राहकों में जागरूकता की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। इस खतरे को कम करने के लिए, विनियमित संस्थाओं को न केवल मजबूत आंतरिक नियंत्रण लागू करने की जरूरत है, बल्कि डिजिटल वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाने की जरूरत है।

अप-बिक्री और आक्रामक वसूली प्रथाओं के मुद्दे पहले भी उजागर हुए हैं। इस संदर्भ में भी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उपभोक्ता हित को सर्वोच्च रखें।

### प्रौद्योगिकी को अपनाना – कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग

अब मैं इस वर्ष के सम्मेलन के विषय पर आता हूँ: शिकायत निवारण सुधार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता। हम एक उत्साहजनक युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), शिकायत निवारण की गति, सटीकता और निष्पक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है।

एआई प्राप्त होने वाली शिकायतों को तात्कालिकता, जटिलता या विषय क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत करने में मदद कर सकती है, जिससे सही लोगों या सही टीम तक पहुंचने में न्यूनतम देरी हो। एआई शिकायत को सही जगह पहुंचाने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा, वह निर्णय लेने और प्रसंस्करण समय को कम करने में सहायता कर सकती है।

दूसरे, एआई का उपयोग संरचित और असंरचित डेटा, जैसे ईमेल, चैट लॉग और कॉल ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करके प्रणालीगत कमियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। इससे प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और आवश्यक प्रक्रिया सुधार करने में सहायता मिलेगी। लाखों उपभोक्ताओं के शाखाओं में जाने, कॉल सेंटर लॉग, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के डेटा का उपयोग करके, इन सभी गतिविधियों का एक एकीकृत, एआई-संचालित पटल आम समस्या बिंदुओं को अधिक कुशलता से पहचानने में मदद कर सकता है। डेटा एनालिटिक्स, सेंटिमेंट एनालिसिस और प्रेडिक्टिव मॉडल का लाभ उठाते हुए एआई का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है ताकि समस्याओं में कारणों का पता लगाया जा सके - जैसे कि एटीएम विफलता या गलत शुल्क - और विनियमित संस्था को पहले से सचेत किया जा सके।

अंत में, भारत जैसे भाषाई रूप से विविधतापूर्ण देश में, एआई-संचालित चैटबॉट और वॉयस रिकग्निशन टूल स्थानीय भाषाओं में काम करके भाषा संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा, चैटबॉट, वॉयसबॉट और उन्नत आईवीआर प्रणाली में संवादी एआई के कार्यान्वयन से चौबीसों घंटे नियमित प्रश्नों को हल किया जा सकता है, जिससे लोगों को उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा जिनमें सहानुभूति और जटिल समस्या-समाधान की आवश्यकता होती है।

संक्षेप में, शिकायत दर्ज करने से लेकर निपटान तक हर चरण में एआई को एकीकृत करने से एक निर्बाध, कुशल और डेटा-संचालित शिकायत निवारण प्रणाली तैयार हो सकती है। ऐसा ढांचा न केवल प्रसंस्करण समय को कम करता है और बार-बार आने वाली शिकायतों को हल करता है, बल्कि मानवीय पूर्वाग्रहों को कम करके न्यायसंगत परिणामों को भी बढ़ावा देता है। अब समय आ गया है कि बैंकिंग उद्योग शिकायत समाधान तंत्र को मजबूत करने और इसे दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एआई सहित प्रौद्योगिकी के एकीकरण का प्रयास करे और इसमें अग्रणी बने।

## एआई संचालित शिकायत निवारण प्रणाली में चुनौतियाँ और अवरोध

हालांकि एआई अभूतपूर्व अवसर प्रस्तुत करती है, हमें इसके अपनाने से उत्पन्न चुनौतियों और जोखिमों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। एआई-संचालित मॉडलों में डेटा गोपनीयता, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और जटिलता संबंधी चिंताएं हैं। जब हम शिकायत निवारण या किसी अन्य प्रक्रिया में एआई को अपनाते हैं, तो हमें नैतिक विचारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। पारदर्शी और सुसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मानवीय निगरानी, पूर्वाग्रह शमन और डेटा गोपनीयता को एआई प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए।

## मानव संसाधन में निवेश

यह सही है कि प्रौद्योगिकी अपने सभी रूपों में एक शक्तिशाली माध्यम है, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह ईमानदारी, सहानुभूति और मानवीय निर्णय का विकल्प नहीं हो सकती। डेटा, एल्गोरिदम और स्वचालन द्वारा तेजी से संचालित इस दुनिया में, मानवीय तत्व नज़रअंदाज़ हो जाने की बहुत संभवना है। हर लेन-देन सिर्फ़ खाता बही में एक संख्या नहीं दर्शाता है, बल्कि वह किसी परिवार की मेहनत से कमाई गई बचत, किसी छोटे उद्यमी के सपने या किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन भर की बचत होती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि विनियमित संस्थाएं ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण के लिए समर्पित मानव संसाधनों में निवेश करना जारी रखें। कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश करना आवश्यक है, विशेष रूप से ग्राहक सेवा व्यवहार संबंधी पहलुओं में। इसके अलावा, कर्मचारियों को उपभोक्ता शिकायतों के निवारण, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने और उपभोक्ता का विश्वास जीतने के लिए अपने निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

## आरबीआई एक मददकर्ता के रूप में

अंत में, मैं आपको आश्चस्त करना चाहूंगा कि जहां हम आपसे ग्राहकों को कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने का आग्रह करते हैं, वहीं हम रिजर्व बैंक के रूप में विनियमित संस्थाओं को समय पर विभिन्न सेवाएं, अनुमोदन, स्पष्टीकरण आदि भी प्रदान करेंगे। हमारे पास पहले से ही एक नागरिक चार्टर है। हम चार्टर की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं। हम चार्टर को व्यापक बनाएंगे

और उन सभी सेवाओं को शामिल करेंगे जो हम विनियमित संस्थाओं को या सीधे नागरिकों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा, हम प्रत्येक सेवा के संबंध में समयसीमा की समीक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि समयसीमा के भीतर सभी अनुमोदन आदि प्रदान किए जाएं। हम 'प्रवाह' (PRAVAAH) पोर्टल का उपयोग भी अनिवार्य कर रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए रिजर्व बैंक से अपेक्षित प्राधिकृतीकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन समय पर प्राप्त करने के लिए आरबीआई का सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है।

## निष्कर्ष

हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत एक अधिक लचीले और समावेशी 'विकसित भारत' के अपने सपने को साकार करना चाहता है। वित्तीय क्षेत्र लगभग पूरी आबादी के जीवन को प्रभावित करता है इसलिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। इस भूमिका में सफल होने के लिए हमें ग्राहक सेवा और ग्राहक सुरक्षा को बेहतर बनाना जारी रखना चाहिए।

धन्यवाद !



# जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में मुख्य भाषण\*

श्री संजय मल्होत्रा

मुझे यहां उपस्थित होकर और जलवायु परिवर्तन पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर खुशी हो रही है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ध्यान आकर्षित करता रहता है। मैं जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप श्रोतागण न केवल वास्तविक अर्थव्यवस्था पर, बल्कि वित्तीय प्रणाली और साथ ही हमारे दैनिक जीवन पर भी इसके प्रभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जलवायु संबंधी परिवर्तन प्रत्यक्ष, स्पष्ट और दृश्यमान हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से और अधिक खतरे में डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों में प्रभावी ढंग से मिलकर काम करना और योगदान देना हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी रहे।

## जलवायु परिवर्तन जोखिम के आयाम

जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के दो आयाम हैं जिनके बारे में हमें नियामकों, नीति निर्माताओं और अनुपालनकर्ताओं के रूप में जागरूक होना होगा – इसमें पहला- क्षमता निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और हरित एवं स्थायी परिवर्तन के लिए वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है; और दूसरा - जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवेकपूर्ण पहलू है।

हालांकि, जलवायु परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले जोखिमों के प्रबंधन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका को तेजी से पहचाना जा रहा है, हरित और स्थायी संक्रमण के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका बहस का विषय रही है और इसके अलग-अलग आयाम हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने पारंपरिक रूप से आर्स्टि तटस्थ दृष्टिकोण का पालन किया है। दूसरी ओर, उभरते बाजारों और विकासशील

\* भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन जोखिम और वित्त पर नीति संगोष्ठी में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का मुख्य भाषण, 13 मार्च, 2025, नई दिल्ली।

अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में केंद्रीय बैंकों ने अपने-अपने देश की परिस्थितियों और विकासात्मक उद्देश्यों को देखते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों को ऋण देने के लिए निर्देशित ऋण नीतियों को अपनाया है। भारतीय संदर्भ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देश अक्षय ऊर्जा सहित विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करते हैं।

विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से ऐसे कई चैनल हैं जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन जोखिम वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सभी प्रमुख प्रकार के वित्तीय जोखिम - चाहे वह क्रेडिट, बाजार या परिचालन जोखिम हो - जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। इन जोखिमों में चरम जलवायु घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं (भौतिक जोखिम) के कारण क्रेडिट पोर्टफोलियो से होने वाले नुकसान और फंसे हुए आस्तियों (संक्रमण जोखिम) के कारण संपार्श्विक के मूल्य में कमी; निवेश से होने वाले नुकसान; और परिचालन संबंधी नुकसान शामिल हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करता है, लेकिन इन जोखिमों की सीमा और प्रकृति क्षेत्र, उद्योग, भूगोल और संस्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। इसलिए, जलवायु परिवर्तन जोखिमों का शमन - सबसे पहले, जलवायु जोखिमों की आवृत्ति और गंभीरता के यथार्थवादी और व्यापक आकलन पर निर्भर करता है और दूसरा, उनके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना, जो कोई आसान काम नहीं है।

केंद्रीय बैंक के रूप में, रिज़र्व बैंक जलवायु परिवर्तन से वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिमों का समाधान करने और शमन करने में अपनी भूमिका के प्रति सजग है। इस दिशा में, हमारा प्रयास एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाने का रहा है - जिसमें क्षमता निर्माण का समर्थन करना और हरित और संधारणीय वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल विनियामकीय ढांचे को बढ़ावा देना शामिल है। संधारणीय वित्त के लिए हरित वित्तपोषण/ उधार का एक महत्वपूर्ण पहलू उधारकर्ताओं द्वारा नई और उभरती हुई हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण उच्च ऋण जोखिम है, जिनकी विश्वसनीयता, दक्षता और प्रभावशीलता के मामले में अपेक्षाकृत सीमित ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए, विनियमित संस्थाओं को ऐसी हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण में जोखिमों का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त क्षमता और तकनीकी जानकारी विकसित करने की आवश्यकता है।

## भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु परिवर्तन जोखिम और शमन का विकास

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संबंध में रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण न केवल अल्पावधि के लिए बल्कि मध्यम अवधि के लिए भी उन्मुख है, जो विकसित हो रही राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अल्पावधि में, हमारा लक्ष्य जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रभाव का न केवल व्यक्तिगत संस्थानों पर बल्कि समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली पर भी यथार्थवादी अनुमान लगाने में सक्षम होना है। इसमें बॉटम-अप और टॉप-डाउन दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण अभ्यास शामिल होंगे।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए विनियमित संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है। जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करने, जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के व्यापक आकलन और शमन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और दक्षताओं का निर्माण करने तथा ऐसे जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की सीमा के बारे में भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। अब मैं इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा की गई कुछ पहलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम मॉडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें डेटा गहनता की आवश्यकता होती है। जलवायु परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव को मापने के लिए सीमित डेटा उपलब्ध है। इसके अलावा, बेंचमार्क क्षेत्रवार संक्रमण मार्गों और देश-विशिष्ट कार्बन उत्सर्जन डेटाबेस की कमी है। ये बाधाएँ जलवायु परिवर्तन जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करने की हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। ये सीमाएँ वित्तीय प्रभाव की तुलना को भी बाधित करती हैं, क्योंकि प्रत्येक विनियमित संस्था जलवायु संबंधी डेटा को संसाधित करने के लिए अपनी स्वयं की धारणाओं और मॉडलों का उपयोग कर सकती है। ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए, हमने पिछले साल अक्टूबर में रिजर्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) नामक एक रिपोर्टिगरी के निर्माण की घोषणा की थी। रिपोर्टिगरी का उद्देश्य मानकीकृत डेटासेट प्रदान करके डेटा अंतराल को पाटना है। इन डेटासेट में जोखिम डेटा, सुभेद्यता डेटा और भौतिक जोखिम मूल्यांकन से संबंधित जोखिम डेटा, क्षेत्रवार संक्रमण मार्ग और

संक्रमण जोखिम मूल्यांकन से संबंधित कार्बन उत्सर्जन तीव्रता डेटाबेस शामिल हैं। इस रिपोर्टिगरी पर काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा।

कई अधिकार क्षेत्रों ने जलवायु संबंधी जोखिमों के आकलन और प्रकटीकरण पर काम शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)<sup>1</sup> फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जलवायु संबंधी प्रकटीकरण पर मानक जारी किए हैं। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने भी बेसल ढांचे के पिलर III प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत जलवायु जोखिम संबंधी प्रकटीकरणों को एकीकृत करने के उद्देश्य से जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों<sup>2</sup> के प्रकटीकरण पर एक परामर्शदात्री दस्तावेज़ जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ने पहले ही फरवरी 2024 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचे पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे। हमें बहुमूल्य प्रतिक्रिया मिली है और हम दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। विनियमित संस्थाओं के लिए जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर एक मार्गदर्शन नोट भी तैयार किया जा रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में प्रौद्योगिकी और वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन क्षेत्रों में अभिनव समाधान और क्षमताएँ बनाने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक फिनटेक क्षेत्र में अपने विनियामक सैंडबॉक्स और हैकाथॉन पहलों के माध्यम से नवोन्मेषों को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बना रहा है। हम आरबीआई की विनियामक सैंडबॉक्स पहल के तहत जलवायु परिवर्तन जोखिमों और सतत वित्त पर एक समर्पित "ऑन टैप" समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन और संबंधित पहलुओं पर एक विशेष "ग्रीनथॉन" आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं।

हमने अप्रैल 2023 में, हरित जमाओं की स्वीकृति पर रूपरेखा<sup>3</sup> जारी की थी, जिसका उद्देश्य बैंकों को हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने में सक्षम बनाना था।

<sup>1</sup> <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/>

<sup>2</sup> <https://www.bis.org/bcbs/publ/d560.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12487&Mode=0>

यह एक बार फिर हरित/सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। हरित जमाओं के पीछे का विचार सॉवरन ग्रीन बॉण्ड के समान है। हम सभी को ऐसे उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डालना चाहूंगा। हमने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के हिस्से के रूप में छोटी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं - सौर, बायोमास आधारित, पवन चक्कियाँ, माइक्रो-हाइड्रल संयंत्र और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना शामिल किया है।

जलवायु संबंधी वित्त के पर्याप्त प्रवाह में अक्सर बताई जाने वाली बाधाओं में से एक है बैंक योग्य परियोजनाओं की कमी। क्षमता और विशेषज्ञता की कमी जलवायु परिवर्तन शमन का मूल्यांकन करने और इस प्रकार वित्त पोषण करने की क्षमता को सीमित करती है। यह ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के जोखिम को भी बढ़ाता है। इस प्रकार, ऐसी बैंक योग्य परियोजनाओं का एक साझा पूल बनाने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कई गुना लाभ होगा। ऐसी परियोजनाओं के अनुभव वाली विनियमित संस्थाएँ दूसरों के लाभ के लिए इस पूल में योगदान कर सकती हैं, साथ ही अन्य विनियमित संस्थाओं द्वारा साझा की गई ऐसी जानकारी से भी लाभान्वित हो सकती हैं। इससे सभी के लाभ के लिए ज्ञान साझा करने में मदद मिलेगी। इस उभरते और विकसित होते क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है। मैं विनियमित संस्थाओं से उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के पूल की स्थापना पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करता हूँ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं वह कहना चाहता हूँ जो शायद स्पष्ट है। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों का प्रभाव केवल वित्तीय प्रणाली तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। चाहे वह कॉरपोरेट हो या एमएसएमई या कृषि क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन के जोखिम सर्वव्यापी हैं। इसके लिए न केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और विनियमित संस्थाओं बल्कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच भी दृष्टिकोण में एक सुसंगत समन्वय और सामंजस्य की आवश्यकता है। देश की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित

करने के लिए सरकार और अन्य नियामकों के साथ सहयोग और समन्वय करेंगे कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नियमों, विनियमों और हमारे दृष्टिकोण में सामंजस्य और स्थिरता हो।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) की वार्षिक संचालन समिति की बैठक भी आज इसी स्थान पर हो रही है। एनजीएफएस जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ अग्रणी कार्य कर रहा है। चाहे वह एनजीएफएस परिदृश्य हो, अनुकूलन पर हालिया कार्य हो, या डेटा निर्देशिका पर कार्य हो, वे दुनिया भर में तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण का स्रोत रहे हैं। हम एनजीएफएस के साथ निरंतर जुड़ाव और समन्वय की आशा करते हैं।

## निष्कर्ष

अंत में, मैं दोहराना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन के जोखिम वास्तविक हैं और सभी हितधारकों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले जोखिमों और चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि हमने एक अच्छी शुरुआत की है, फिर भी ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन और शमन की दिशा में की जा रही विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए रचनात्मक और परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ता से काम करना जारी रखेंगे जो न केवल भविष्य के जलवायु आघातों का सामना कर सके, बल्कि एक स्थायी और उज्ज्वल भविष्य की ओर भारत की यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान दे सके। मैं आप सभी से इस उद्देश्य के लिए योगदान देने का आग्रह करता हूँ। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था "दुनिया उन लोगों द्वारा नष्ट नहीं होगी जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा नष्ट होगी जो बिना कुछ किए उन्हें देखते रहते हैं।"

मैं इस अवसर पर आपको और आपके परिवारों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।

धन्यवाद।



# डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर संबोधन \*

श्री संजय मल्होत्रा

## डिजिटल भुगतान – पृष्ठभूमि और लाभ

भुगतान वाणिज्य की जीवनरेखा हैं, जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। ये लोगों को जोड़ते हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त बनाते हैं और आर्थिक विकास को गति देते हैं। किफायती कीमतों पर त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय भुगतान एक जीवंत अर्थव्यवस्था का आधार हैं। डिजिटल माध्यमों से भुगतान आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ये उच्च लेनदेन लागत और भौगोलिक सीमाओं<sup>1</sup> जैसी बाधाओं को दूर करके वित्तीय समावेशन को भी गहरा करते हैं। वास्तव में, डिजिटल भुगतान न केवल सुविधाजनक हैं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और विकास का एक शक्तिशाली साधन भी हैं।

## डिजिटल भुगतान - सुविधा: उत्पादों का गुलदस्ता

पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैंक विभिन्न डिजिटल भुगतान उत्पादों को समर्थन प्रदान करता रहा है। इससे ग्राहकों के लिए विकल्प और सुविधा बढ़ी है। हमने ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा) से शुरुआत की। फिर हमने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनएसीएच (यह ई-मैन्डेट के लिए है, इसने ईसीएस की जगह ले ली है), एईपीएस, यूपीआई, एनईसीटी आदि की शुरुआत की। हमने यूपीआई पर कई नई सुविधाएँ शुरू की हैं और ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया है। इनमें यूपीआई123पे, यूपीआई लाइट, रुपये क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करना, सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट के साथ भुगतान मैन्डेट को प्रोसेस करना, यूपीआई के लिए क्रेडिट लाइन सक्षम करना, पीपीआई को यूपीआई से लिंक करना आदि शामिल हैं। अपनी विविध विशेषताओं के साथ, यूपीआई हमें एक साधारण क्लिक,

\* डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 के उद्घाटन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन, 10 मार्च, 2025, आरबीआई, मुंबई।

<sup>1</sup> विश्व बैंक, डिजिटल वित्तीय सेवाएँ, अप्रैल 2020।

टैप या स्कैन से पैसे ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने और खरीदारी करने की सुविधा देता है। हम भुगतान ईकोसिस्टम के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे।

## डिजिटल भुगतान – सुरक्षा और संरक्षा

डिजिटल भुगतान प्रणालियों और उनसे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देते हुए, हम भुगतान में सुरक्षा की जरूरतों को भी ध्यान में रखते रहे हैं। इसलिए, हमने इस उद्देश्य के लिए कई उपाय किए हैं:

- बहु-कारक प्रमाणीकरण; इंटरनेट और मोबाइल भुगतान ऐप्स और कार्ड भुगतान के लिए सुरक्षा नियंत्रण; कार्ड टोकनाइजेशन (व्यापारियों की प्रणालियों में कार्ड विवरणों के भंडारण को रोकने के लिए), आदि का उद्देश्य हमारे भुगतान ईकोसिस्टम को मजबूत बनाना है।
- हमने ग्राहकों को आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैन्डेट बनाने और समाप्त करने पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाया है।

भुगतान ईकोसिस्टम की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। हाल ही में जारी "डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्रों पर रूपरेखा" और "सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (एएफए)" पर मसौदे इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

## भुगतान प्रणालियाँ - आगे का रास्ता

आरबीआई के अलावा, सरकार और बैंकों व भुगतान प्रणाली संचालकों जैसे अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों ने भी डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। हालाँकि इन प्रयासों के परिणाम सामने आए हैं, जैसा कि डिजिटल भुगतान में भारी वृद्धि से स्पष्ट है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आगे बढ़ते हुए, हम तीन व्यापक क्षेत्रों पर काम करेंगे।

## भुगतान प्रणालियाँ - नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट टच विनियम

सबसे पहले, हम भुगतान में नवाचार को प्रोत्साहित करते रहेंगे, जैसा कि सामान्यतः होता है, साथ ही जोखिमों के प्रति

सचेत रहेंगे और उन्हें कम करने के लिए उचित उपाय भी करेंगे। हम भुगतान प्रणालियों को तेज, सुरक्षित, सुलभ और लचीली बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देंगे। हमने भुगतान ईकोसिस्टम और वित्तीय प्रौद्योगिकी को विनियमित करने के लिए एक नरम दृष्टिकोण अपनाया है। इन नियमों के माध्यम से, रिज़र्व बैंक इन विविध अपेक्षाओं को संतुलित करने का प्रयास करता है। हमारा दृष्टिकोण नियामक सुरक्षा नियमन स्थापित करना रहा है जिसके अंतर्गत सभी हितधारक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। हम नरम नियमों के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देते हुए नवाचार को प्रोत्साहित करते रहेंगे।

### जागरूकता सृजन को बढ़ावा देना

दूसरा, हालाँकि डिजिटल भुगतान के विकास, प्रसार और अपनाने में काफ़ी प्रगति हुई है, फिर भी देश में डिजिटल भुगतान को और गहरा और व्यापक बनाने की अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। जनवरी 2025 तक, भारत में लगभग 250 ट्रिलियन रुपये मूल्य के 20 अरब से ज्यादा भुगतान डिजिटल माध्यमों से किए जा चुके थे। हममें से कई लोगों के लिए डिजिटल भुगतान, भुगतान का पसंदीदा तरीका बन गया है। हालाँकि, सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमारी लगभग 40% वयस्क आबादी अभी भी डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं करती है। इसका एक मुख्य कारण डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता या जानकारी का अभाव है।

डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, हर साल मार्च में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसी प्रयास के तहत, 2023 में "हर भुगतान डिजिटल" मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य सभी नागरिकों में डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाकर और लोगों को डिजिटल भुगतान हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा और समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। मिशन हर भुगतान डिजिटल के उद्देश्यों को सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान के उपयोग और जागरूकता में पिछड़ रहे भौगोलिक और जनसंख्या वर्गों की पहचान की जानी चाहिए और जागरूकता बढ़ाने तथा उपयोग में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए।

हम इस मिशन के तीसरे वर्ष में हैं। इस वर्ष का विषय है "भारत डिजिटल भुगतान करता है"। इस वर्ष भी, हम अपनी जागरूकता

गतिविधियाँ जारी रखेंगे। यह दर्शाकर कि कैसे डिजिटल भुगतान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, हम उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अभी तक डिजिटल भुगतान नहीं अपनाया है।

पिछले वर्षों की तरह, रिज़र्व बैंक इस वर्ष भी इस विषय पर मल्टीमीडिया अभियान चलाएगा। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, हम सोशल मीडिया पर आकर्षक पुरस्कारों वाली विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी देश भर में समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए ई बात नामक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम 2012 से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में, ऐसे 1800 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस वर्ष, ई बात की विषयवस्तु और वितरण पद्धति की समीक्षा की जाएगी, और एक पायलट प्रोजेक्ट (एक बड़े राज्य में) चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सबसे प्रभावी तरीके से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचना है।

मैं बैंकों, भुगतान प्रणाली संचालकों और अन्य हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे हर भुगतान डिजिटल के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अभिनव तरीकों से योगदान दें।

### अधिक कुशल सीमा पार भुगतान

तीसरा, घरेलू भुगतान में यूपीआई की सफलता ने भारत को वैश्विक वास्तविक समय भुगतान में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व की स्थिति में पहुँचा दिया है<sup>2</sup>, हम सीमा पार से भुगतान को और अधिक कुशल बनाने का प्रयास करेंगे। यह प्राथमिकता का विषय हो गया है क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। विश्व बैंक<sup>3</sup> की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 2024 में, भारत को लगभग 130 बिलियन अमरीकी डालर का प्रेषण प्राप्त हुआ। हमें सीमा पार से भुगतान में उच्च लागत, धीमी गति और अपर्याप्त पहुँच और पारदर्शिता की चुनौतियों का समाधान करने

<sup>2</sup> एसीआई वर्ल्डवाइड, 2024.

<sup>3</sup> <https://blogs.worldbank.org/en/peoplemove/in-2024--remittance-flows-to-low-and-middle-income-countries-ar>

की आवश्यकता है। हम यूपीआई को अन्य देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़कर द्विपक्षीय रूप से यूपीआई की पहुंच का विस्तार करना जारी रखेंगे। हम कुशल सीमा-पार भुगतान की सुविधा के लिए यूपीआई के अलावा अन्य भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की संभावना भी तलाशेंगे।<sup>4</sup>

पाँचवाँ डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मनाते हुए, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) की स्थापना के 20 वर्ष पूरे हो रहे

हैं। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग को बधाई देता हूँ। सभी हितधारकों के सहयोग से इस विभाग द्वारा किए गए कार्यों ने भारत को डिजिटल भुगतान में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। हालाँकि, भारत की भुगतान प्रणालियों में क्रांति अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हम अभी डिजिटल भुगतान की वास्तविक क्षमता को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नए जोश के साथ काम करते रहेंगे कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना रहे।

धन्यवाद।

<sup>4</sup> नेक्सस, जिसकी संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के इन्वैशेन हब द्वारा की गई है, का उद्देश्य चार आसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) की तीव्र भुगतान प्रणालियों को जोड़ना है; और भारत, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे।



# भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड (आईआईएमके)-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के संयुक्त द्वितीय वार्षिक समष्टि अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त सम्मेलन में उद्घाटन भाषण \*

श्री एम. राजेश्वर राव

## परिचय

सभी को सुप्रभात!

मैं आईआईएम, कोझिकोड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मेलन का विषय— "रचनात्मक व्यवधानों के बीच विकास के लिए वित्त"— वित्तीय क्षेत्र में हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, उसका सार प्रस्तुत करता है—न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर भी। वित्तीय क्षेत्र में व्यवधान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस युग को जो अलग बनाता है, वह है डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रेरित अभूतपूर्व गति और मात्रा में परिवर्तन, और इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नए व्यावसायिक मॉडल का उदय। ये परिवर्तन हमारे लिए यह समझना आवश्यक बनाते हैं कि सतत आर्थिक विकास के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाए।

भारत के लिए, यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हम विकसित भारत 2047 की दिशा में प्रयास कर रहे हैं - एक विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के हमारे लक्ष्य के लिए हमें बाजारों को गहरा करने, वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वित्त के साथ प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना होगा।

\* 21 फरवरी, 2025 को मुंबई में आईआईएमके - एनएसई के मैक्रोइकोनॉमिक्स, बैंकिंग और वित्त पर दूसरे वार्षिक सम्मेलन में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण। प्रमांशु राजपूत द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार।

## रचनात्मक व्यवधान की तुलना में रचनात्मक विनाश

वित्त में नवाचार हमेशा से दोधारी तलवार रहा है—एक ओर, यह दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी ओर, अगर इसे ठीक से प्रबंधित न किया जाए, तो यह पारंपरिक ढाँचों को अस्थिर कर सकता है। यहीं पर रचनात्मक व्यवधान और रचनात्मक विनाश के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके निहितार्थ बहुत अलग हैं। अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रचलित **रचनात्मक विनाश**, नई प्रणालियों के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी प्रणालियों को पूरी तरह से ध्वस्त करने को संदर्भित करता है। इसके विपरीत, **रचनात्मक व्यवधान** एक अधिक सूक्ष्म प्रक्रिया है—यह मौजूदा प्रणालियों को विकसित करने, उन्हें परिष्कृत करने और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाने के बारे में है। हम केवल मौजूदा प्रणालियों को बदलने की नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह मेरे आज के भाषण का संदर्भ निर्धारित करता है। मैं इस विषय पर अपने विचार साझा करूँगा कि कैसे डिजिटल परिवर्तन वित्त को नया रूप दे रहा है, एआई की भूमिका, अधिक सार्थक वित्तीयकरण और वित्तीय समावेशन के लिए आगे का रास्ता और उत्तरदाई विकास को बढ़ावा देने के लिए नियामक परिदृश्य को कैसे विकसित किया जाना चाहिए।

## वित्त में डिजिटल परिवर्तन

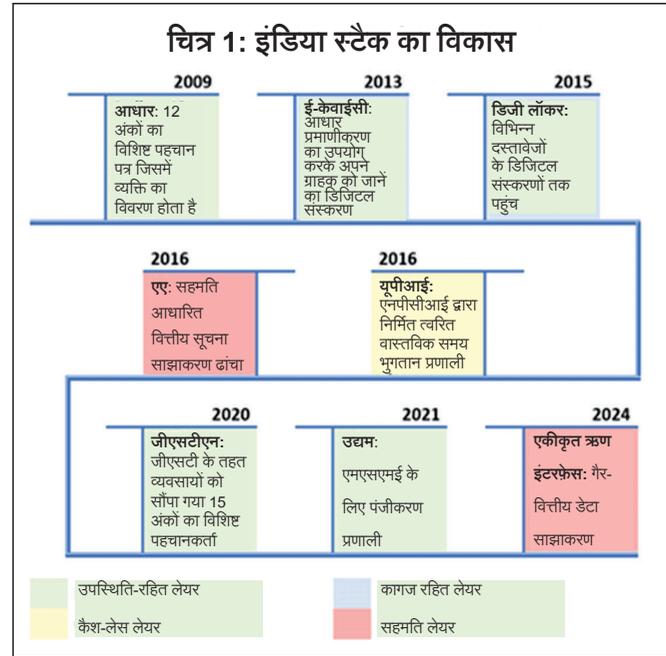
डिजिटल युग में वित्तीय क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है, जिसने व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने और उनके उपयोग के तरीके को नया रूप दिया है। नकदी-आधारित, कागज़-आधारित लेन-देन से एक सहज, तकनीक-संचालित ईकोसिस्टम की ओर बदलाव आधुनिक वित्त में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक रहा है। भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क और हाल ही में लॉन्च किए गए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जैसे नवाचारों के माध्यम से वित्त में रचनात्मक बदलाव का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसने "इंडिया स्टैक" के रूप में पहचाने जाने वाले अन्य घटकों का पूरक बनाया है। पहले उल्लिखित रचनात्मक बदलाव के संदर्भ में, इन पहलों ने न केवल पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली का पूरक बनाया है, बल्कि लेन-देन को और अधिक सहज

बनाकर, वित्तीय पहुँच का विस्तार करके और दक्षता में सुधार करके इसे और मज़बूत भी किया है। इसी प्रकार, डिजिटल ऋण के उदय ने पारंपरिक ऋण माध्यमों को अप्रचलित नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें पूरक बनाया है और वंचित वर्गों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाया है।

मेरी राय में, जो चीज़ भारत को वैश्विक समकक्षों से अलग करती है, वह है इसका खुला दृष्टिकोण। कई अन्य देशों के विपरीत, जहाँ ये प्रगति "चारदीवारी से घिरे" के रूप में आई है, भारत का वित्तीय बुनियादी ढाँचा खुलेपन और सुगम्यता के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे प्लेटफॉर्म प्लग-एंड-प्ले सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं, जो किसी भी संस्था को उन पर निर्माण करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा, नवाचार और समावेशन को बढ़ावा मिलता है। चाहे वह यूपीआई हो, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क हो, या यूएलआई हो, हमारा मार्गदर्शक दर्शन एक ही है—एक खुला ईकोसिस्टम बनाना। यूपीआई खुले डिजिटल बुनियादी ढाँचे का एक प्रमुख उदाहरण है जो नवाचार और समावेशन दोनों को बढ़ावा देता है। यह त्वरित भुगतान के लिए एक अंतःपरिचालनीय ढाँचा प्रदान करता है, जिससे कई निजी खिलाड़ी इसके आधार पर निर्बाध वित्तीय समाधान तैयार कर सकते हैं। आज की तिथि<sup>1</sup> तक, यूपीआई ईकोसिस्टम में बैंकों के ऐप्स के अलावा यूपीआई भुगतान को सक्षम करने वाले 39 तृतीय पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता (टीपीएपी) हैं। 16 अरब से अधिक मासिक<sup>2</sup> लेनदेन के साथ, यूपीआई दर्शाता है कि कैसे सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचा, विशिष्टता के जोखिम के बिना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के नवाचार को सशक्त बना सकता है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के एक शोध लेख<sup>3</sup> में अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल 2016 में अपनी स्थापना के बाद से यूपीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 67 बिलियन डॉलर की बचत कराई है।

## वित्त में एआई / एमएल

जबकि इंडिया स्टैक ने सफलतापूर्वक डिजिटल पाइपलाइनों का निर्माण किया है जो एक निर्बाध और समावेशी वित्तीय प्रणाली को शक्ति प्रदान करती हैं, मेरा मानना है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग



(एमएल) वित्तीय परिवर्तन के अगले चरण को गति देने वाले इंजन बनेंगे। ये हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी प्रगतियों में से हैं। यह बढ़ता महत्व इस बात में परिलक्षित होता है कि कैसे वित्तीय संस्थान और नियामक दोनों ही एआई से संबंधित विषयों में तेजी से शामिल हो रहे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक रिपोर्टों के विश्लेषण (चार्ट 1) से पता चला है कि हाल के वर्षों में एआई और इसके एप्लीकेशनों के संदर्भों में तेज वृद्धि हुई है<sup>4</sup>।

इसके अलावा यह केवल विनियमित संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है—केंद्रीय बैंक भी अपनी सार्वजनिक बातचीत में एआई पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक अधिकारियों के भाषणों<sup>5</sup> की समीक्षा (चार्ट 2) एक समान पैटर्न दर्शाती है, जहाँ एआई से संबंधित विषयों पर चर्चाएँ विशेष रूप से 2022 के बाद की जेनरेटिव एआई लहर के बाद काफी बढ़ गई हैं। यह वित्तीय ईकोसिस्टम के भीतर एआई के प्रति बढ़ती जागरूकता और रणनीतिक फोकस को रेखांकित करता है।

यद्यपि वित्तीय सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ रहा है, यह तीन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है - जोखिम मूल्यांकन और क्रेडिट स्कोरिंग, ग्राहक अनुभव में सुधार, और धोखाधड़ी का पता लगाना।

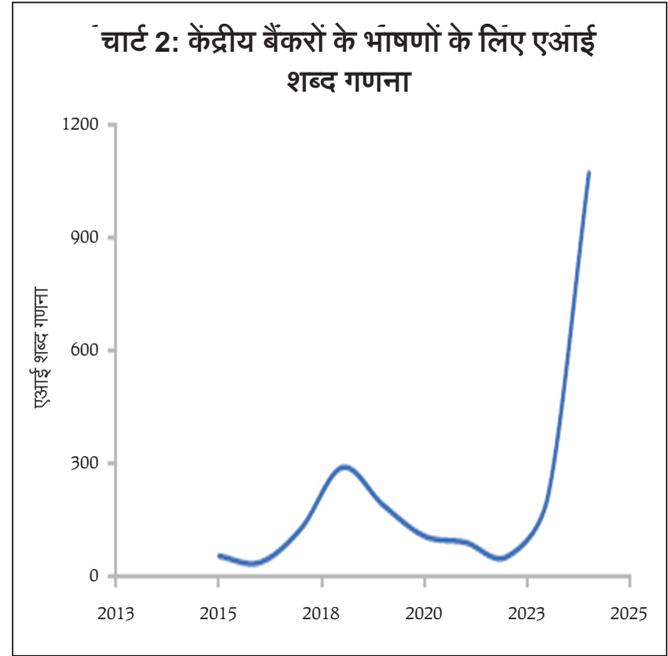
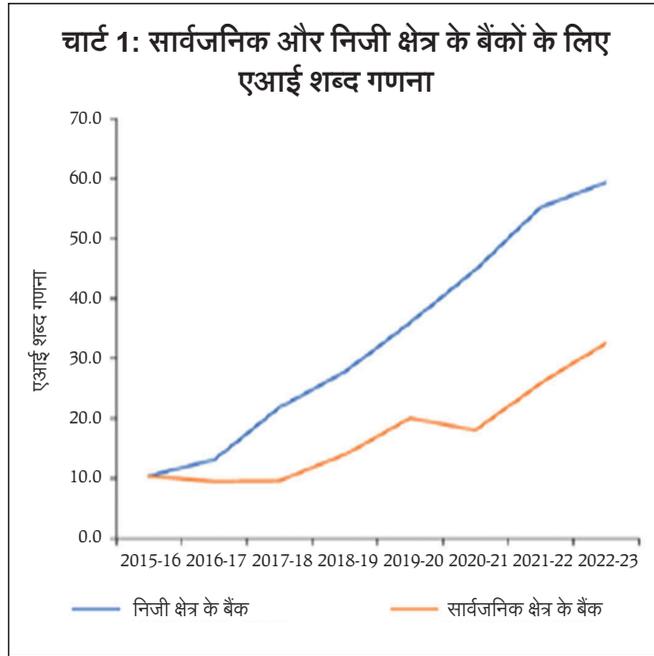
<sup>1</sup> 20 फरवरी, 2025 तक।

<sup>2</sup> आरबीआई भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, 2024।

<sup>3</sup> भारत की डिजिटल छलांग: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस का वित्तीय परिदृश्य पर अभूतपूर्व प्रभाव, दिनांक 26 जून, 2023, <https://www.weforum.org/stories/2023/06/india-unified-payment-interface-impact/> पर उपलब्ध है।

<sup>4</sup> भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपना रहे हैं? आरबीआई बुलेटिन अक्टूबर 2024।

<sup>5</sup> बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2024) में उपलब्ध केंद्रीय बैंक अधिकारियों के भाषणों के टेक्स्ट माइनिंग विश्लेषण पर आधारित। केंद्रीय बैंक के भाषण, 2015-2024, <https://www.bis.org/cbspeeches/download.htm>



पारंपरिक ऋण मूल्यांकन, क्रेडिट हिस्ट्री और आय विवरण जैसे संरचित वित्तीय आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। हालाँकि, एआई-संचालित मॉडल, लेन-देन के पैटर्न, उपयोगिता बिल भुगतान, ई-कॉमर्स व्यवहार आदि सहित, वैकल्पिक आंकड़ों की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं ताकि उधारकर्ता की ऋण-योग्यता का अधिक समग्र रूप से आकलन किया जा सके। यह न केवल प्रारंभिक अंडरराइटिंग में, बल्कि मौजूदा उधारकर्ताओं की सक्रिय निगरानी में भी उपयोगी है ताकि प्रारंभिक चरण में ही तनाव का पता लगाया जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। यह अति-वैयक्तिकृत वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता को भी सक्षम बनाता है जिससे ग्राहक अनुभव में वृद्धि होती है। धोखाधड़ी का पता लगाना एक अन्य प्रमुख उपयोग-मामला है। पारंपरिक नियम-आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणालियों के विपरीत, जो पूर्वनिर्धारित मापदंडों पर निर्भर करती हैं, एआई-आधारित तकनीकें लगातार सीखती और विकसित होती रहती हैं, नई धोखाधड़ी तकनीकों के अनुकूल होती हैं और लेनदेन और भुगतान व्यवहार में सूक्ष्म विसंगतियों की पहचान करती हैं। यह वास्तविक समय के भुगतान और डिजिटल लेनदेन के युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ साइबर खतरे, धोखाधड़ी और म्यूल खातों का उपयोग अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं।

## चुनौतियाँ और नैतिक विचार

पहले एक अवसर<sup>6</sup> पर -मैंने एआई/एमएल मॉडल से जुड़े जोखिमों और वित्त में उनके ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में बात की थी। हालाँकि, आज मैं एक बुनियादी बात पर जोर देना चाहता हूँ: हालाँकि एआई एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह, निष्पक्षता, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, लेकिन इन चुनौतियों और कई अन्य चुनौतियों की जड़ में **स्पष्टीकरण की कमी है।**

## व्याख्यात्मकता और मानवीय निगरानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता

कई उन्नत एआई मॉडल, विशेष रूप से डीप लर्निंग-आधारित प्रणालियाँ, "ब्लैक बॉक्स" की तरह काम करती हैं और ऐसे आउटपुट उत्पन्न करती हैं जिनकी व्याख्या करना उनके डेवलपर्स के लिए भी मुश्किल होता है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ विश्वास, जवाबदेही और नियामक अनुपालन सर्वोपरि हैं, व्याख्यात्मकता का अभाव एआई-संचालित निर्णयों में विश्वास को कमजोर करता है। व्याख्यात्मकता के अभाव में, मानवीय हस्तक्षेप ज़िम्मेदार निगरानी के बजाय, केवल रबर-स्टाम्प बनकर रह सकता है, जिससे प्रणालीगत त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है।

<sup>6</sup> नवाचार - प्रौद्योगिकी और एआई की उभरती भूमिका, 22 दिसंबर, 2023 - दिल्ली में भारतीय आर्थिक संघ के 106वें वार्षिक सम्मेलन में, [https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_SpeechesView.aspx?Id=1400](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1400) पर उपलब्ध

## द्वितीय-क्रम प्रभाव: अस्पष्टीकृत एआई के छिपे हुए जोखिम

एआई मॉडल नए डेटा के आधार पर लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। हालाँकि 'गतिशील अनुकूलन' लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह मॉडलों को डेटा विचलन<sup>7</sup> और अवधारणा विचलन<sup>8</sup> के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। ये परिवर्तन मॉडलों को वास्तविक दुनिया के रुझानों से अलग कर सकते हैं, जिससे गलत वित्तीय निर्णय और अस्थिरता का जोखिम हो सकता है। ऐसे जोखिमों को रोकने के लिए नियमित मानवीय निगरानी और व्याख्यात्मकता महत्वपूर्ण है।

## एआई पर अत्यधिक निर्भरता का खतरा

एआई-आधारित निर्णय मॉडलों का एक कम जाना-पहचाना जोखिम "स्वचालन आत्मसंतुष्टि" है, जहाँ लोग तकनीक पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तब भी जब परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जैसा कि कहावत है, "सभी मॉडल गलत होते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी होते हैं"<sup>9</sup>। हालाँकि एल्गोरिदम मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दक्षता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मानवीय निर्णय का समर्थन करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि उनका स्थान लेने वाले।

## कौशल अंतर: व्याख्यात्मकता चुनौती में एक जटिल कारक

वित्त में जिम्मेदारी से एआई को अपनाने में एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नज़रअंदाज़ की जाने वाली बाधा ऐसे पेशेवरों की कमी है जो एआई मॉडल की व्याख्या और निगरानी कर सकें। अगर वित्तीय संस्थानों में एआई, डेटा विज्ञान और नियामक निगरानी में आवश्यक कौशल वाले कर्मचारियों की कमी है, तो

<sup>7</sup> डेटा ड्रिफ्ट, या सहचर बदलाव, उस घटना को संदर्भित करता है जहाँ डेटा इनपुट का वितरण, जिस पर एक मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित किया गया था, उन डेटा इनपुट के वितरण से भिन्न होता है जिन पर मॉडल लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप मॉडल कम सटीक हो सकता है या पूर्वानुमान या निर्णय लेने में कम प्रभावी हो सकता है (मौसमी परिवर्तन, उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन, नए उत्पादों के जुड़ने के कारण डेटा में परिवर्तन)।

<sup>8</sup> अवधारणा विचलन या ड्रिफ्ट, डेटा का एक ऐसा विकास है जो डेटा मॉडल को अमान्य कर देता है। ऐसा तब होता है जब लक्ष्य चर के सांख्यिकीय गुण, जिनका मॉडल पूर्वानुमान लगाने का प्रयास कर रहा है, समय के साथ अप्रत्याशित रूप से बदल जाते हैं। इससे समस्याएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि समय बीतने के साथ पूर्वानुमान कम सटीक होते जाते हैं।

<sup>9</sup> सामान्यतः इसका श्रेय ब्रिटिश सांख्यिकीविद् जॉर्ज बॉक्स को दिया जाता है।

व्याख्या की समस्या और भी बढ़ जाती है और एआई मॉडल द्वारा लिए गए निर्णय अस्पष्ट रह सकते हैं।

## अंतराल को पाटना: वित्तीय समावेशन के लिए आगे की राह

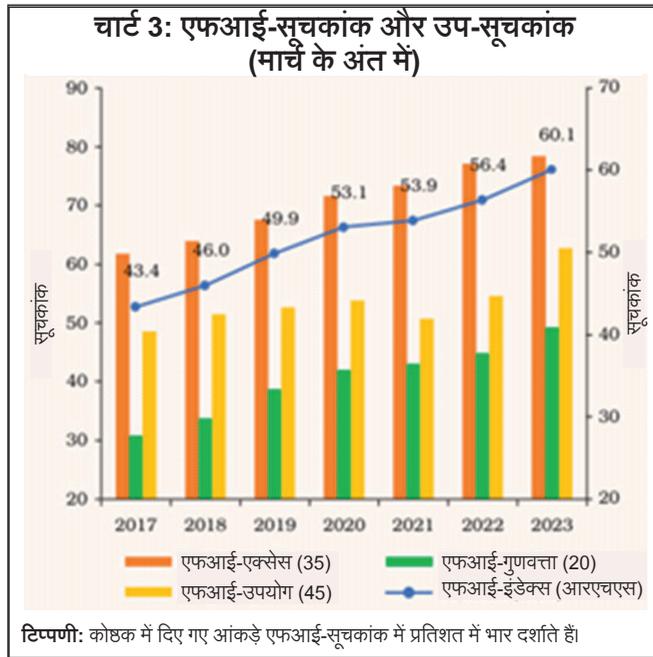
वित्तीय समावेशन की आगे की राह पर गहराई से विचार करने से पहले, एक और महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करना ज़रूरी है। वित्तीयकरण और वित्तीय समावेशन अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास के अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्तीयकरण का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय बाजारों, संस्थानों और साधनों की बढ़ती भूमिका से है। दूसरी ओर, वित्तीय समावेशन यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों की, बचत खाते, ऋण, बीमा और डिजिटल भुगतान जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो। ये दोनों स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं—समावेश के बिना, वित्तीयकरण का जोखिम कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित रह जाता है, जिससे व्यापक आर्थिक भागीदारी सीमित हो जाती है। इसके विपरीत, वित्तीयकरण के बिना, समावेशन सतही ही रहता है, क्योंकि केवल बैंकिंग तक पहुँच व्यक्तियों को तब तक सशक्त नहीं बनाती जब तक कि वे बचत, निवेश और अपनी संपत्ति में वृद्धि भी न कर सकें।

## वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), एक बहुआयामी समग्र सूचकांक जो पूरे देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाता है, मार्च 2024 में 64.2 पर था, जो मार्च 2023 में 60.1 और 2017 में 43.4 था। सूचकांक तीन उप-सूचकांकों - पहुँच, गुणवत्ता और उपयोग पर आधारित है। भारत ने वित्तीय पहुँच का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें पीएम जन धन योजना जैसी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित हुई है कि अब 80% वयस्कों के पास बैंक खाता है<sup>10</sup>। आज तक, पीएम जन धन योजना के तहत 54.84 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल शेष राशि 2.45 लाख करोड़ रुपये है<sup>11</sup>। हालाँकि, सच्चा वित्तीय समावेशन केवल खाते खोलने से

<sup>10</sup> विश्व बैंक, ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट, 2021।

<sup>11</sup> 20 फरवरी, 2025 तक, <https://pmjdy.gov.in/>



कहीं आगे जाता है - इसके लिए वित्तीय सेवाओं के साथ सार्थक जुड़ाव की आवश्यकता होती है<sup>12</sup>

बैंक खाता व्यक्तियों के लिए ऋण, बीमा, पेंशन और निवेश के अवसरों सहित वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँचने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करना चाहिए। इस गहन जुड़ाव के बिना, वित्तीय समावेशन सतही ही रहेगा, और एक औपचारिक वित्तीय प्रणाली के वास्तविक लाभ प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसाय तक नहीं पहुँच पाएँगे। यह जानना उत्साहवर्धक है कि 2023-24 में एफआई-सूचकांक में सुधार मुख्यतः उपयोग के आयाम के कारण हुआ, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को दर्शाता है।<sup>13</sup> यह दर्शाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे कमजोर आबादी और निम्न-आय वर्ग को सुरक्षित और किफायती वित्त तक पहुँच प्रदान करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

महत्वपूर्ण अंतरालों में से एक ऋण तक पहुँच है, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र के लिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। पारंपरिक क्रेडिट मॉडल, जो संपार्श्विक-आधारित

उधार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, पहली बार उधारकर्ताओं और सीमित क्रेडिट हिस्ट्री वाले छोटे व्यवसायों को समायोजित करने में विफल रहते हैं। नतीजतन, ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति या तो कम वित्तपोषित रह जाते हैं या ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की ओर रुख करते हैं, अक्सर अत्यधिक ब्याज दरों पर। एक और महत्वपूर्ण अंतर बीमा उपलब्धता में है, जो वित्त वर्ष 24 में सिर्फ 3.7% है, जो वैश्विक औसत 7% से काफी कम है। इसी तरह, भारत में पेंशन परिसंपत्तियां सकल घरेलू उत्पाद का केवल 21.5% (ईपीएफओ के तहत 17% और एनपीएस के तहत 4.5%) हैं, जो ओईसीडी देशों में सकल घरेलू उत्पाद के 80% की तुलना में बहुत कम है<sup>14</sup>।

### बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना

इन कमियों को पाटने के लिए, हमें वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन की शक्ति का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान पारंपरिक बाधाओं को तोड़कर और आबादी के वंचित वर्गों तक वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लाकर वित्त का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंक खाता होना तब तक बहुत उपयोगी नहीं है जब तक कि इससे वित्तीयकरण में वृद्धि न हो, यानी गुणवत्ता और उपयोग सुनिश्चित न हो। भुगतान के मामले में, यूपीआई पहुँच, गुणवत्ता और उपयोग के तीनों आयामों को पूरा करता है। खुदरा भुगतानों के लिए यूपीआई की सर्वव्यापी प्रकृति और इसके उपयोग में आसानी को देखते हुए, यह कई अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों के लिए आवश्यक हो गया है। इसने एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय छाप छोड़ी है, जो पहले ज़्यादातर नकदी में लेन-देन करती थी। एए ढाँचे के माध्यम से वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए इन वित्तीय छापों तक पहुँच संभव हो गई है और ऋणदाता इसका उपयोग नए ज़माने के मॉडलों का उपयोग करके और अन्य वैकल्पिक आंकड़ों के साथ संयोजन करके अति-व्यक्तिगत उत्पाद प्रदान

<sup>12</sup> आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, पृष्ठ 99.

<sup>13</sup> बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी आरबीआई रिपोर्ट, 2023-24।

<sup>14</sup> आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25.

करने के लिए कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से नए-नए ऋण लेने वाले व्यक्तियों, गिग कर्मचारियों और छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करने में उपयोगी है, जिनका औपचारिक ऋण हिस्ट्री भले ही न हो, लेकिन वैकल्पिक संकेतकों के माध्यम से मजबूत वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार, एए ढाँचा एक सेतु का काम करता है, जिससे बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ग्राहक की वित्तीय प्रोफाइल की अधिक समग्र और सटीक तस्वीर प्राप्त करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, जीएसटी, ई-कॉमर्स बिक्री डेटा आदि के माध्यम से एमएसएमई का औपचारिकीकरण बढ़ने से उधारदाताओं को ऋण पात्रता का अधिक सटीक आकलन करने में मदद मिल सकती है। डेटा-संचालित वित्तीय समावेशन को और बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने उधार देने के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के रूप में यूएलआई की स्थापना की सुविधा भी दी है, जो उधारदाताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय, गैर-वित्तीय और वैकल्पिक डेटा को अनलॉक करेगा ताकि सूचित क्रेडिट निर्णय लिए जा सकें। 6 दिसंबर, 2024 तक, ₹27,000 करोड़ की राशि के 6 लाख से अधिक ऋण, जिनमें एमएसएमई को ₹14,500 करोड़ की राशि के 1.6 लाख ऋण शामिल हैं, यूएलआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वितरित किए गए हैं। विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी सहित 36 उधारदाताओं को इसमें शामिल किया गया है।

### वित्तीय समावेशन, वित्तीय अतिरेक नहीं

जहाँ तकनीक और डिजिटल नवाचार वित्तीय समावेशन और पहुँच को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं ये अपने साथ अत्यधिक जोखिम और अति-लीवरेजिंग का जोखिम भी लेकर आ रहे हैं, जो व्यक्तियों और व्यापक वित्तीय प्रणाली, दोनों के लिए गंभीर कमजोरियाँ पैदा कर सकता है। हालाँकि, जैसा कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी भी अंधेपन का कारण बन सकती है, हमें बेतहाशा वित्तीयकरण के जोखिम के प्रति सचेत रहना चाहिए। हाल ही में हमने असुरक्षित क्षेत्र में अत्यधिक उधारी और पूँजी बाजारों में डेरिवेटिव उत्साह को लेकर कुछ चिंताएँ देखी हैं। अल्पकालिक लाभ का प्रलोभन व्यक्तियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को आसानी से प्रभावित कर सकता है। वित्तीय संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक लीवरेज्ड उत्पादों और सट्टा निवेश से जुड़े जोखिमों को पूरी तरह समझें।

जहाँ आरबीआई अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों के साथ मिलकर ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए प्रगतिशील कदम उठा रहा है, वहीं वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को भी अपनी ज़िम्मेदारी का हिस्सा उठाना होगा। वित्तीय साक्षरता के अभाव में लोग बेईमान खिलाड़ियों के जाल में फँस जाते हैं, जिससे व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होता है। वित्तीय साक्षरता बढ़ने से इस क्षेत्र और इसके प्रतिभागियों में विश्वास बढ़ेगा, जिसका लाभ संस्थाओं को ही मिलेगा।

### तीव्र गति वाले नवाचार के युग में वित्तीय विनियमन

उपभोक्ताओं को शिक्षित करने से उन्हें धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलती है, वहीं विनियमन स्थिरता बनाए रखने और प्रणालीगत विफलता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय सेवाओं का विनियमन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी स्थिरता व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है— वित्तीय क्षेत्र में विफलताओं के वास्तविक दुनिया में गंभीर परिणाम होते हैं, जिसके लिए अक्सर करदाताओं द्वारा वित्त पोषित महँगे बेलआउट की आवश्यकता होती है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट इस बात की याद दिलाता है कि कैसे ढीला विनियमन और अत्यधिक जोखिम उठाने से व्यापक आर्थिक संकट, नौकरी छूटने और लंबी मंदी हो सकती है। ऐसे परिदृश्यों में वित्तीय स्थिरता बहाल करने की लागत अक्सर निवारक विनियमन की लागत से कहीं अधिक होती है। हालांकि ऐसे संकटों को रोकने के लिए मजबूत विनियमन आवश्यक है, लेकिन विनियमन के इष्टतम स्तर का निर्धारण एक नाज़ुक संतुलन बना हुआ है—बहुत कम विनियमन प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा सकता है, जबकि अत्यधिक विनियमन नवाचार को बाधित कर सकता है, ऋण उपलब्धता को सीमित कर सकता है और लागत बढ़ा सकता है। इस प्रकार, तेज़ गति वाले तकनीकी नवाचार के युग में वित्त का विनियमन एक नाज़ुक संतुलनकारी कार्य है।

साथ ही, विनियमित संस्थाओं को उभरते नियमों को लागू करने और उनका पालन करने के लिए आवश्यक क्षमताएँ विकसित करनी होंगी। जैसे-जैसे वित्तीय संस्थान अपने संचालन में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और एपीआई-संचालित वित्त को एकीकृत करते हैं, उन्हें अनुपालन और ग्राहक उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन ढाँचों और जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल में

निवेश करना होगा। वित्तीय कंपनियाँ नियमों को नवाचार में बाधा के रूप में नहीं देख सकतीं—बल्कि, अनुपालन को ही उनकी डिजिटल रणनीति का एक मुख्य घटक बनना होगा। जोखिम जागरूकता, एआई के नैतिक उपयोग और ग्राहक-केंद्रित नवाचार की एक मज़बूत आंतरिक संस्कृति, उभरते वित्तीय परिदृश्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण होगी।

### निष्कर्ष

“परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है,” एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने लिखा था<sup>15</sup> और फिर भी परिवर्तन कठिन, अस्थिर करने वाला, यहाँ तक कि खतरनाक भी लग सकता है। तो क्या तकनीकी परिवर्तन “रचनात्मक विनाश” की ओर ले जाएँगे और क्या वे वास्तव में बैंकों जैसे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की जगह ले लेंगे? बैंकों के ‘मृत’ होने का डर पहले भी उठता रहा है। एक चौथाई सदी पहले, इस मुद्दे की जाँच उस समय के विघटनकारी वित्तीय नवाचार जैसे कि प्रतिभूतिकरण के आलोक में की गई थी, जिसे वित्तीय मध्यस्थों के रूप में बैंकों की आवश्यकता को मिटाने के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में प्रचारित किया गया था<sup>16</sup>। समय के साथ, ये भविष्यवाणियाँ झूठी साबित हुईं और बैंकिंग क्षेत्र

इन व्यवधानों से और भी अधिक लचीला होकर उभरा। हालाँकि, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, और व्यवधान की वर्तमान लहर की क्षमता यकीनन बढ़ी है, फिर भी बैंकिंग के भविष्य के बारे में भविष्यवाणियाँ करते समय सावधानी बरतना समझदारी हो सकती है।

हालाँकि, बैंकों और एनबीएफसी के लिए संदेश स्पष्ट है: अनुकूलन करें या अप्रचलित हो जाने का जोखिम उठाएँ। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, वित्तीय संस्थानों को डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश करना होगा और इस नए परिदृश्य में ग्राहक-केंद्रित, डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाना होगा। साथ ही, संस्थानों को तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों से निपटना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि नियामक अनुपालन और साइबर सुरक्षा, साथ ही ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहे। चुनौती भविष्य के लिए एक संतुलित और लचीला वित्तीय ईकोसिस्टम सुनिश्चित करने की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिमों का प्रबंधन करते हुए लाभों का दोहन किया जाए।

धन्यवाद!

<sup>15</sup> इफिसस के हेराक्लीटस.

<sup>16</sup> बॉयड और गर्टलर की आर बैंक्स डेड? ऑर दि रिपोर्ट्स ग्रेटली इंग्रैजरेटिड? फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ मिनियापोलिस त्रैमासिक समीक्षा खंड 18 अंक 3.



# आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

मानसून और कृषि उत्पादन का स्थानिक वितरण

भारत के धन विप्रेषण की बदलती गतिकी - भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि

आर्थिक संवृद्धि को उत्सर्जन से अलग करना: एक एलएमडीआई अपघटन विश्लेषण

बाज़ार पहुँच और आईएमएफ व्यवस्थाएँ: दुनिया भर से साक्ष्य



## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की परीक्षा व्यापार तनाव में वृद्धि और टैरिफ के दायरे, समय और तीव्रता के बारे में अनिश्चितता की बढ़ती लहर द्वारा की जा रही है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न करने के साथ-साथ, इसने वैश्विक विकास में मंदी के बारे में आशंकाएँ भी पैदा की हैं। इन चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और बेहतर खपत में स्पष्ट रूप से सुदृढ़ता प्रदर्शित करना जारी रखती है। हालाँकि, अशांत बाहरी वातावरण की प्रतिध्वनि निरंतर विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह में परिलक्षित हो रही है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की वृहद आर्थिक ताकत खाद्य कीमतों में और सुधार के कारण फरवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत तक की गिरावट से मजबूत हुई है।

### परिचय

2025 में सुदृढ़ता के एक मजबूत नोट पर प्रवेश कर चुकी वैश्विक अर्थव्यवस्था, बढ़ते व्यापार तनाव और टैरिफ के दायरे, समय और तीव्रता के आसपास अनिश्चितता की एक बढ़ी हुई लहर के तूफान में फंस गई है। हालाँकि, जो अधिक निश्चित है, वह यह है कि व्यापार युद्ध और बढ़ते टैरिफ का विकास और ईंधन मुद्रास्फीति पर न केवल सीधे तौर पर शामिल देशों में बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक प्रभाव हो सकता है। अनुमान बताते हैं कि पूर्ण टैरिफ युद्ध से अमेरिका में मूल्य स्तर 1.0-1.2 प्रतिशत बढ़ सकता है, 2025 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 0.6 प्रतिशत अंकों की कमी आ सकती है, तथा दीर्घवधि में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगातार 0.3-0.4

प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।<sup>1</sup> कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अनुमानों से संकेत मिलता है कि अगले दशक में विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मंदी आने की संभावना है।<sup>2</sup> ये आकलन प्राप्त आंकड़ों से सही साबित हुए हैं जो अमेरिका की विकास गति में कमजोरी की ओर इशारा करते हैं।

वित्तीय बाजार वैश्विक विकास में अपेक्षित मंदी का अनुमान लगा रहे हैं, अमेरिका और अधिकांश गैर-यूरोपीय भौगोलिक क्षेत्रों में बेंचमार्क सूचकांकों में गिरावट देखी जा रही है। 17 मार्च, 2025 तक, अमेरिकी डॉलर ने नवंबर 2024 के मध्य से अपने सभी लाभ खो दिए हैं, जिसका कारण अमेरिकी व्यापार नीति और विकास अनिश्चितताएँ हैं। भू-राजनीतिक तनाव और बदलते वैश्विक शक्ति संबंध जटिलता के स्तर को और बढ़ा रहे हैं। यूरोप में, सुरक्षा प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण सैन्य खर्च में उछाल आ रहा है, विशेष रूप से जर्मनी और उसके पड़ोसी देशों में, जिससे बॉण्ड प्रतिफल में लगभग तीन दशकों में एक सप्ताह में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि राजकोषीय प्रोत्साहन से यूरो क्षेत्र में विकास में बदलाव आएगा, जिससे यूरोपीय इक्विटी में लाभ हुआ, जिससे वे 2025 में अपने अमेरिकी समकक्षों से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक तनाव बढ़ने के साथ, आने वाले महीने अनिश्चितता में डूबे हुए हैं।

इन चुनौतियों के बीच, वैश्विक वस्तुओं के लिए दृष्टिकोण एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। खाद्य और ऊर्जा की आपूर्ति संभावनाओं में सुधार हो रहा है। 2025 के दौरान वैश्विक अनाज उत्पादन 2024 को पार करने का अनुमान है।<sup>4</sup> इस चिंता के कारण कि व्यापार युद्ध आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और ऊर्जा की मांग कमजोर कर सकता है, तेल की कीमतें (यूके ब्रेंट) जनवरी 2025 के मध्य से (11 मार्च तक) लगभग 15 प्रतिशत

\* यह लेख रेखा मिश्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज खान, विश्वजीत मोहंती, श्रेया कंसल, बजरंगी लाल गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता, रजनी दहिया, हरेंद्र बेहेरा, गौतम, अमित कुमार, अमृता बसु, आयुषी खंडेलवाल, ऋषभ कुमार, राधिका सिंह, रशिका अरोड़ा, अमन तिवारी, दिव्या कादियान, सिन्धा योगिन्द्रन, शैलजा भाटिया, शिवम, खुशी सिन्हा, मोनिका, युवराज कश्यप, निखिल प्रकाश कोसे, आशीष खोबरागड़े, सत्यम कुमार और श्रेया गुप्ता ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

<sup>1</sup> येल यूनिवर्सिटी बजट लैब, <https://budgetlab.yale.edu/research/fiscal-economic-and-distributional-effects-20-tariffs-china-and-25-tariffs-canada-and-mexico>. पर उपलब्ध है।

<sup>2</sup> विश्व जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में 3.0 प्रतिशत से घटकर 2027-31 के दौरान औसतन 2.5 प्रतिशत और 2032-37 के दौरान 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड, वैश्विक पूर्वानुमान अपडेट, फरवरी 2025।

<sup>3</sup> व्यापक रूप से ट्रैक किए जाने वाले अटलांटा फेड जीडीपीनाउ मॉडल का अनुमान है कि 2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी वास्तविक जीडीपी वृद्धि (मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दर) -2.1 प्रतिशत रहेगी (17 मार्च, 2025 अपडेट)।

<sup>4</sup> एफएओ अनाज आपूर्ति और मांग ब्रीफ, 7 मार्च, 2025।

घटकर 70 अमेरिकी डॉलर से नीचे आ गईं। मामूली मांग वृद्धि के माहौल में उत्पादन विस्तार के कारण इन्वेंट्री बढ़ने से 2025-26 तक कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है।<sup>5</sup> हालांकि, स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने की खबर के बाद फरवरी में धातु की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। टैरिफ संबंधी चिंताओं और सुरक्षित-पनाहगाह की मांग ने 14 मार्च, 2025 को सोने की कीमतों को 3000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया।

नीति निर्माता अब एक कठिन स्थिति में हैं, उन्हें टैरिफ और मुद्रा अवमूल्यन के कारण बढ़ती कीमतों के ऊपर की ओर दबाव के साथ-साथ आर्थिक मंदी से मुद्रास्फीति पर नीचे की ओर दबाव को संतुलित करना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति की अपरिवर्तनशीलता, साथ ही स्थिर कोर और सेवा मुद्रास्फीति, टैरिफ युद्ध द्वारा उत्पन्न संभावित मंदी का मुकाबला करने के लिए एक उपाय के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली मौद्रिक नीति पर एक बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। उभरती अर्थव्यवस्थाएँ व्यापार, पूंजी प्रवाह और मुद्रा अवमूल्यन चैनलों के माध्यम से इन विकासों के संक्रामक प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। घरेलू वृद्धि आर्थिक स्थितियों में विचलन केंद्रीय बैंकों के बीच नीतिगत कार्यों में मतभेद में भी परिलक्षित होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस अशांत वैश्विक माहौल में सुदृढ़ता प्रदर्शित करना जारी रखती है, क्योंकि विकास की गति को मजबूत क्षेत्रीय प्रदर्शन और उपभोग प्रवृत्तियों में सुधार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में 2024-25 के लिए स्थिर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नवीनतम तिमाही डेटा इस मजबूती को और अधिक रेखांकित करता है, जिसमें वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछली तिमाही की नरमी को दूर करती है। निजी उपभोग व्यय ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो मजबूत उपभोक्ता विश्वास और निरंतर मांग का संकेत देता है। हाल के महीनों में सरकारी खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे

<sup>5</sup> अल्पकालिक आर्थिक दृष्टिकोण, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन, 7 मार्च, 2025।

विकास को और बढ़ावा मिला है। निर्माण, वित्तीय सेवाओं और व्यापार सहित प्रमुख क्षेत्र आर्थिक सुदृढ़ता के स्तंभ के रूप में फलते-फूलते रहे हैं। आर्थिक गतिविधि के विभिन्न उच्च-आवृत्ति संकेतक चौथी तिमाही के दौरान भी विकास में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पहले संशोधित अनुमान (एफआरई) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.2 प्रतिशत बताई गई है - जो कि एक दशक से अधिक समय में सबसे अधिक है, अगर हम कोविड के बाद की रिकवरी को छोड़ दें - यह दर्शाता है कि अनिश्चित दुनिया में, भारत की विकास कहानी स्थिरता और प्रगति का एक प्रतीक बनी हुई है।

विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से विकास की गति में क्रमिक वृद्धि के आकलन की पुष्टि होती है। खरीफ सीजन 2024-25 में खाद्यान्न और तिलहन के उत्पादन अनुमानों में वृद्धि देखी गई है और रबी खाद्यान्न में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से जलाशयों के संतोषजनक स्तरों द्वारा समर्थित सामान्य से अधिक वर्षा के कारण है।<sup>6</sup> गति में मामूली गिरावट के बावजूद, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ने फरवरी 2025 में क्रय गतिविधि और रोजगार में वृद्धि देखी।<sup>7</sup> सेवा क्षेत्र ने नए व्यवसायों और रोजगार में मजबूत विस्तार दर्ज किया।<sup>8</sup>

मजबूत सूक्ष्म-वित्त स्थिति और विवेकपूर्ण नीति पर निर्मित सहज शक्ति के बावजूद, उथल-पुथल भरे बाहरी माहौल का प्रभाव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो के निरंतर बहिर्वाह ने घरेलू इक्विटी बाजारों पर काफी दबाव डाला और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म दिया। जैसा कि खंड IV में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है, हालांकि, घरेलू निवेशकों ने अपनी धारिता में वृद्धि की है, जो एक प्रतिसंतुलनकारी बल के रूप में कार्य करता है, जिससे स्वामित्व पैटर्न में बदलाव होता है।

भारत का वित्तीय परिदृश्य भी घरेलू वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न चैनलों के माध्यम

<sup>6</sup> कृषि फसल उत्पादन (खरीफ और रबी): 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमान।

<sup>7</sup> एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फरवरी 2025।

<sup>8</sup> एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई, फरवरी 2025।

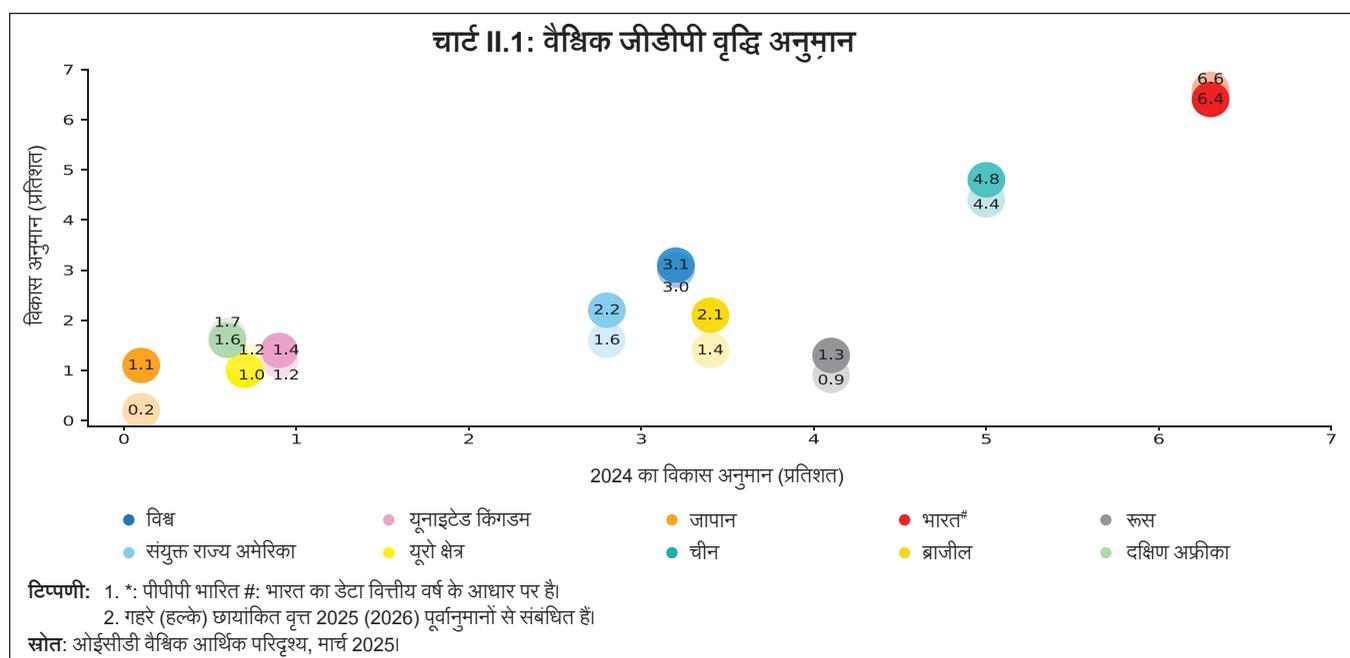
से प्रकट होने वाले इन बाहरी जोखिमों से निपट रहा है। रिज़र्व बैंक सावधान बना हुआ है, सरकारी कर प्रवाह गतिशीलता, मुद्रा रिसाव और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के बहिर्वाह से उत्पन्न चलनिधि की कमी से तेजी से निपट रहा है। रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी और डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी सहित हस्तक्षेपों का एक रणनीतिक मिश्रण संचालित किया है। इन सक्रिय उपायों ने बाजार की चलनिधि की स्थिति को स्थिर करने में मदद की है, जिससे अप्रत्याशित वैश्विक वातावरण में वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई है।

फरवरी 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर आ गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जो बाजार में सर्दियों की फसलों के आने से प्रेरित थी। हालांकि, कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई। समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट से खपत में सुधार को और बढ़ावा मिलने और व्यापक आर्थिक मजबूती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत कवच के रूप में काम करेगी।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

## II. वैश्विक परिदृश्य

लगातार व्यापार और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की परीक्षा ले रही हैं। मार्च 2025 की अपनी वैश्विक आर्थिक आउटलुक अंतरिम रिपोर्ट में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर 2025 के लिए 3.1 प्रतिशत और 2026 के लिए 3.0 बीपीएस से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया (उनके दिसंबर 2024 के अनुमानों से)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, अमेरिका को निकट भविष्य में अन्य एई से बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के वैश्विक विकास के प्रमुख चालक बने रहने की उम्मीद है (चार्ट II.1)। यह पाया गया है कि नीति अनिश्चितता वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के लिए एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरी है (बॉक्स II.1)

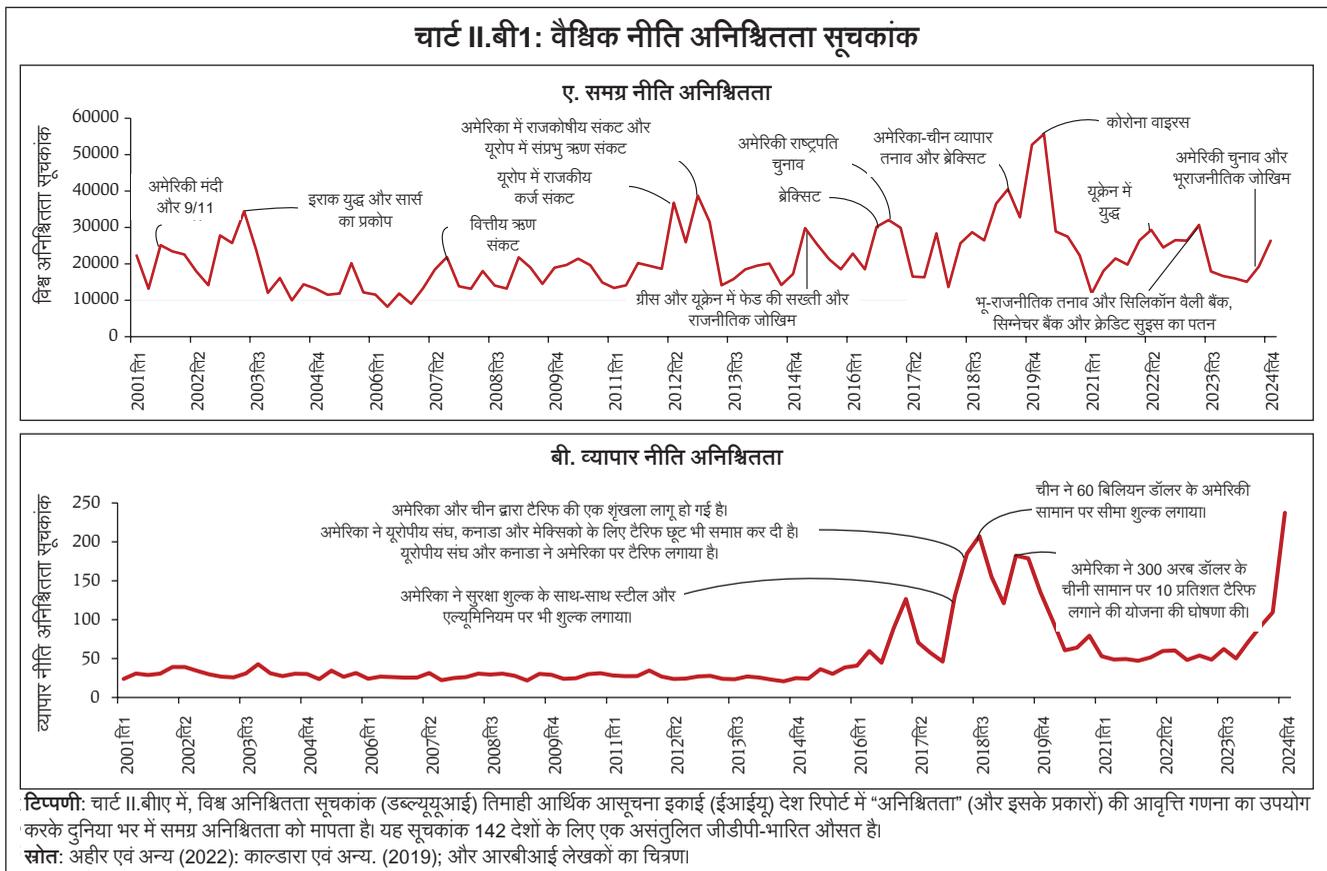


**बॉक्स II.1: वैश्विक आर्थिक गतिविधि पर व्यापार नीति अनिश्चितता का प्रभाव**

हाल ही में नीति अनिश्चितता, विशेष रूप से भूराजनीति और व्यापार से संबंधित (चार्ट II.बी1ए), का पुनरुत्थान हुआ है। विश्व व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक (टीपीयू)<sup>9</sup>, जो 2016 तक अपेक्षाकृत कम और स्थिर था, ने 2018 में एक महत्वपूर्ण उछाल का अनुभव किया, जो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ संघर्षों के साथ-साथ अमेरिका द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के लिए टैरिफ छूट समाप्त करने से प्रेरित था, जिसने प्रतिशोधात्मक उपायों को प्रेरित किया। यह बढ़ी हुई अनिश्चितता 2020 के बाद कम हो गई लेकिन 2024 के अंत में फिर से उभरी, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद नए व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ वृद्धि और सख्त आब्रजन नीतियों के बारे में चिंताओं से प्रेरित थी (चार्ट II.बी1बी)।

व्यापार नीति में अनिश्चितता बढ़ने का असर प्रमुख आर्थिक चरों पर पड़ता है, जैसा कि वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर) ढांचे में टीपीयू में वृद्धि के प्रति उनकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है। टीपीयू में वृद्धि के प्रतिउत्तर में विश्व निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक व्यापार प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभावों को उजागर करता है (चार्ट II.बी2ए)। ईएमई के लिए, टीपीयू में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आती है (चार्ट II.बी 2बी)। यह विशेष रूप से ईएमई के लिए चिंताजनक है जो आर्थिक विकास के इंजन के रूप में निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

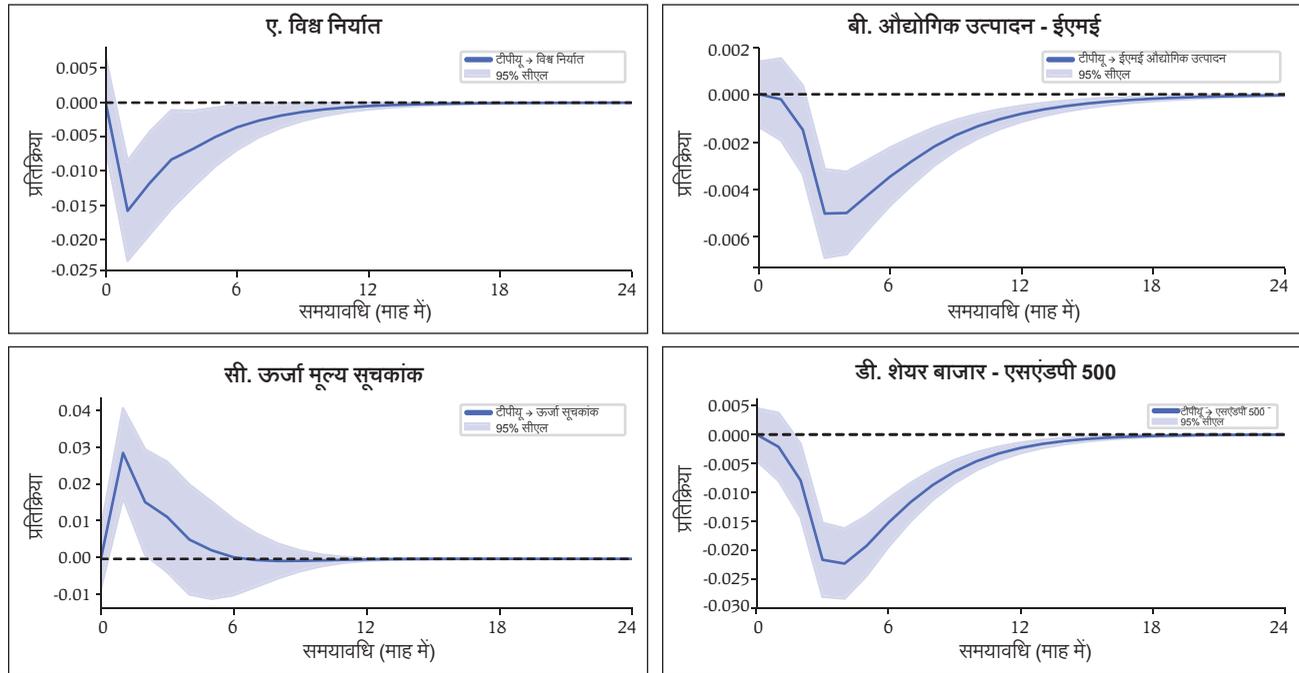
पण्य बाजारों में, ऊर्जा मूल्य सूचकांक में टीपीयू में उछाल के प्रतिक्रिया में अस्थायी वृद्धि देखी गई है, जो जोखिम की बढ़ती



(जारी)

<sup>9</sup> व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक (टीपीयू) फेडरल रिज़र्व बोर्ड के अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है और यह व्यापार नीति अनिश्चितता से संबंधित समाचारों पर मीडिया के ध्यान को मापता है। यह सूचकांक व्यापार नीति अनिश्चितता पर चर्चा करने वाले 7 प्रमुख समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार के स्वचालित पाठ-खोज परिणामों को दर्शाता है: बोस्टन ग्लोब, शिकागो ट्रिब्यून, गार्जियन, लॉस एंजिल्स टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट (प्रोक्वेस्ट हिस्टोरिकल न्यूजपेपर्स और प्रोक्वेस्ट न्यूजस्ट्रीम के माध्यम से एक्सेस किया गया)। सूचकांक को इस प्रकार स्केल किया गया है कि 100 दर्शाता है कि 1 प्रतिशत समाचार लेखों में टीपीयू का संदर्भ है।

**चार्ट II.बी2: टीपीयू में एक मानक विचलन आघात के लिए वीएआर आवेग प्रतिक्रियाएं**



**टिप्पणियाँ:** 1. विश्लेषण के लिए जनवरी 2000 से दिसंबर 2024 तक के मासिक डेटा का उपयोग किया गया।  
 2. डेटा को लॉग ट्रांसफॉर्म किया गया और एचपी फ़िल्टर का उपयोग करके डीटेंड किया गया। टीपीयू में एक मानक विचलन वृद्धि के साथ एक सामान्यीकृत वीएआर मॉडल का उपयोग किया गया, जिसका उपयोग अकाइक सूचना मानदंड (एआईसी) द्वारा निर्धारित इष्टतम अंतराल के साथ किया गया।  
 3. छायांकित क्षेत्र 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल (सीआई) का प्रतिनिधित्व करते हैं।  
**स्रोत:** कैलडारा एवं अन्य. (2019); विश्व बैंक; सीआईसी; एस&डपी ग्लोबल; विश्व बैंक पिक शीट; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

धारणाओं और संभावित आपूर्ति व्यवधानों को दर्शाता है (चार्ट II.बी2सी)। इसी तरह, इक्विटी बाजार, जैसा कि अमेरिका के लिए एस&डपी 500 सूचकांक द्वारा मापा जाता है, बढ़ते टीपीयू पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है, जो निवेशकों के विश्वास में गिरावट का संकेत देता है (चार्ट II.बी2डी)। ये प्रतिक्रियाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर टीपीयू के व्यापक और परस्पर प्रभाव को रेखांकित करती हैं।

**संदर्भ**

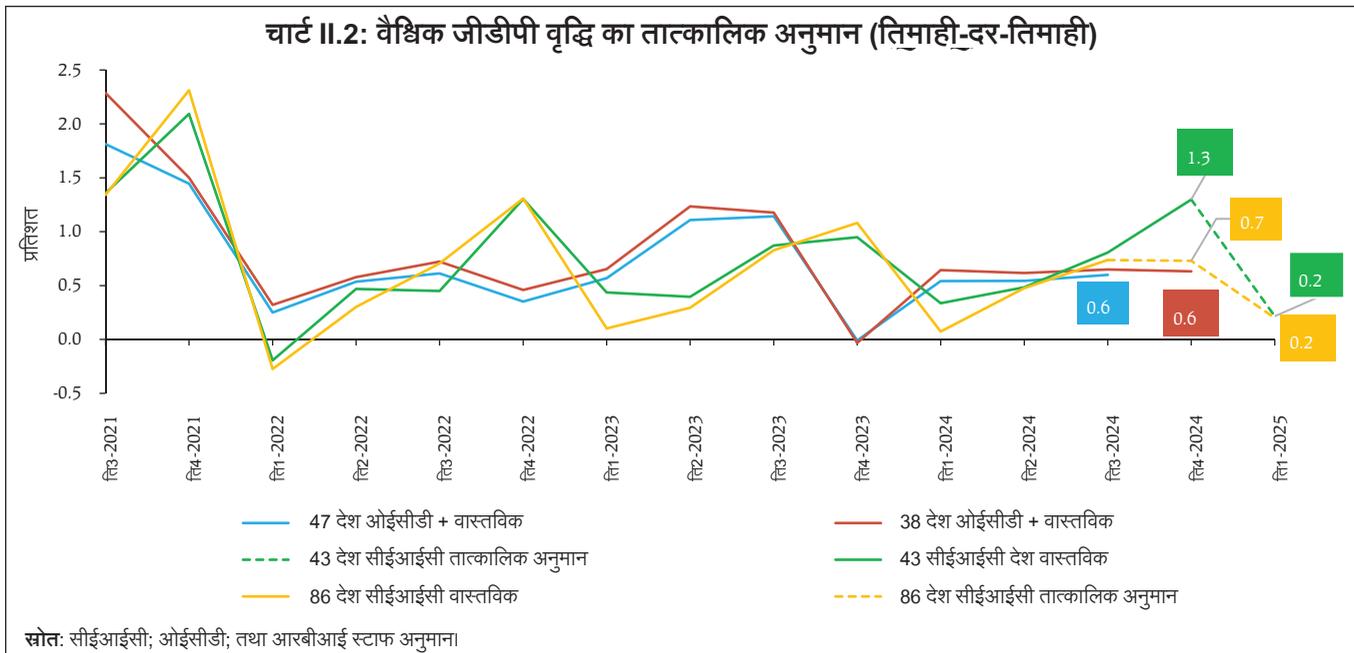
Ahir, H., Bloom, N., and Furceri, D. (2022). World Uncertainty Index. *NBER Working Paper*.  
 Caldara, D., Iacoviello, M., Molligo, P., Prestipino, A., and Raffo, A. (2019). Does Trade Policy Uncertainty affect Global Economic Activity? *FEDS Notes*. Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System. <https://doi.org/10.17016/2380-7172.2445>.

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के हमारे मॉडल-आधारित पूर्वानुमान से पता चलता है कि 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास की गति में महत्वपूर्ण गिरावट आएगी (चार्ट II.2)।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबावों में फरवरी में वृद्धि दर्ज की गई, जो ऐतिहासिक औसत स्तरों की ओर बढ़ रहा है (चार्ट II.3ए)। मध्य पूर्व में नाजुक युद्धविराम के बावजूद बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और उबलते राजनीतिक तनाव के कारण फरवरी 2025 में भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक बढ़ गया (चार्ट II.3बी)। वैश्विक शिपिंग लागत के संकेतकों ने मिश्रित संकेत दिखाए क्योंकि

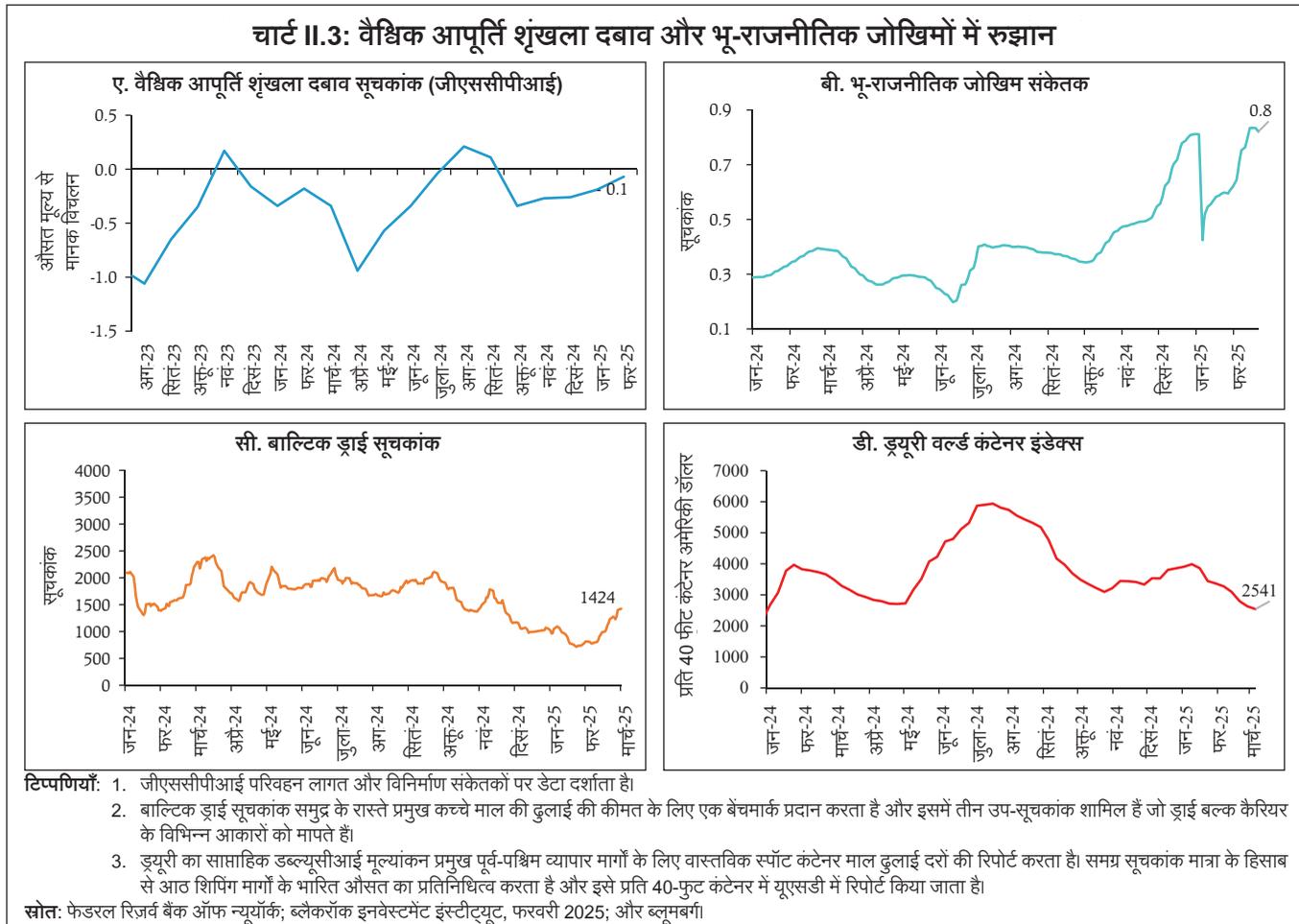
बाल्टिक ड्राई इंडेक्स फरवरी में तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने एशिया में चंद्र नववर्ष अवधि के दौरान देखी गई गिरावट को पलट दिया (चार्ट II.3सी)। इस बीच, ड्यूरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स में शिपिंग क्षमता में वृद्धि के कारण गिरावट जारी रही (चार्ट II.3डी)।

फरवरी 2025 में, यू.एस., जापान और ब्राजील में उपभोक्ता भावनाएँ प्रतिकूल हो गईं, जबकि यूरो क्षेत्र और यू.के. में मामूली सुधार हुआ (चार्ट II.4ए और II.4बी)। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थितियाँ आसान हुईं, लेकिन उभरती

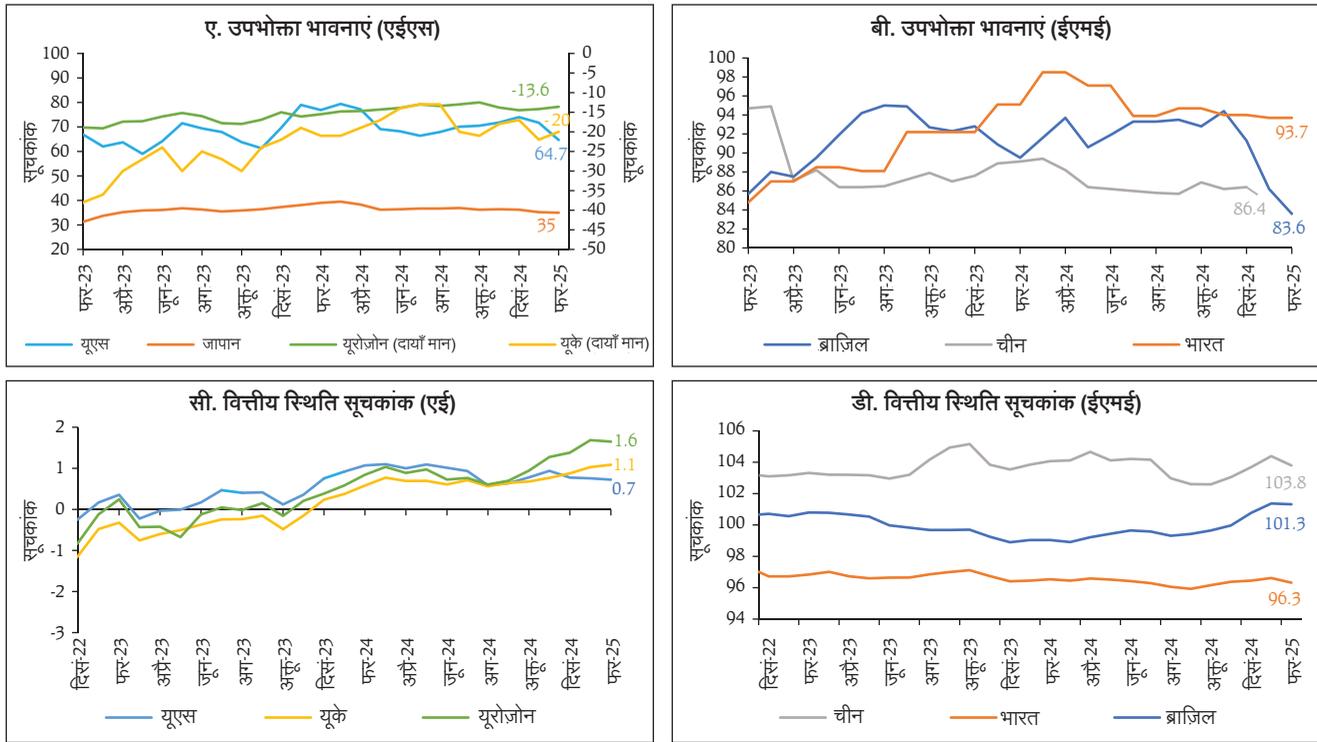


अर्थव्यवस्थाओं में, चीन और ब्राजील में वे सख्त हो गईं (चार्ट II.4सी और 4डी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) फरवरी 2025 में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि विनिर्माण



**चार्ट II.4: उपभोक्ता भावना और वित्तीय स्थितियाँ**



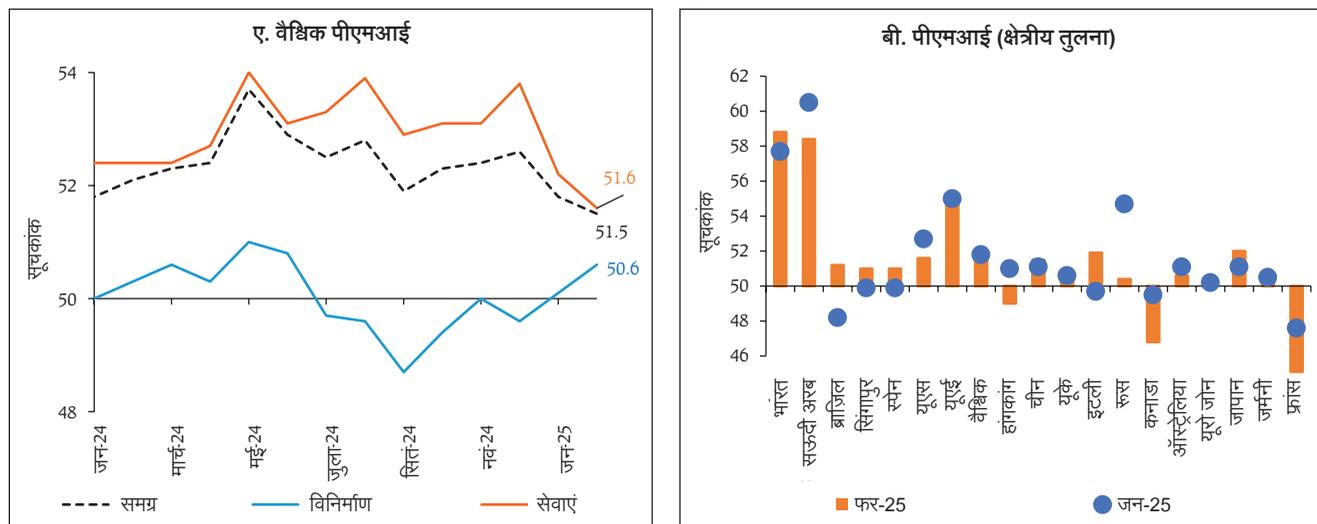
**टिप्पणियाँ:** 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे का स्कोर उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है, और 50 तटस्थता को दर्शाता है।  
 2. यूरोजोन और यूके: -100 अत्यधिक अविश्वास को दर्शाता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है, और 100 अत्यधिक आत्मविश्वास को दर्शाता है।  
 3. भारत और अमेरिका: सूचकांक मूल्य जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।  
 4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (मॉडलमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे का मान समायोजनात्मक है और इसके विपरीत। ईई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक सकारात्मक मूल्य समायोजनात्मक/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

क्षेत्र में तेजी की भरपाई सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि में मंदी से हुई (चार्ट II.5ए)। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई ने उत्पादन

और नए ऑर्डर की वृद्धि के रूप में गति पकड़ी, जबकि नए ऑर्डर की धीमी वृद्धि और व्यापार आशावाद में कमी के कारण वैश्विक

**चार्ट II.5: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)**



**टिप्पणी:** 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है, तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

सेवा पीएमआई में मंदी आई। सभी क्षेत्रों में, भारत ने अन्य प्रमुख उभरते बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि यूरोप में विकास कमजोर रहा और कनाडा में मंदी तेज हुई (चार्ट 11.5बी)।

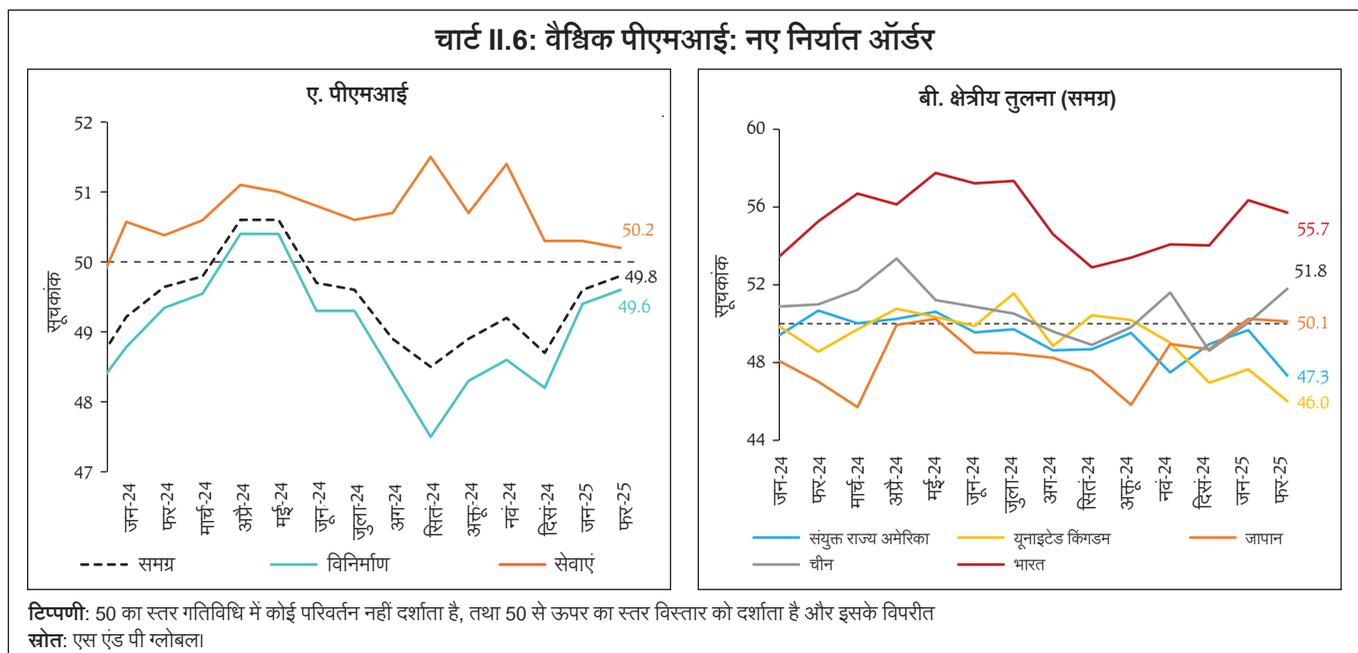
नए निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई ने क्रमिक वृद्धि दर्ज की, हालांकि यह ऋणात्मक क्षेत्र में रहा, क्योंकि विनिर्माण निर्यात ऑर्डर में संकुचन की दर कम हो गई। क्रमिक मंदी के बावजूद सेवा निर्यात ऑर्डर में विस्तार जारी रहा। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, जापान, भारत और चीन ने निर्यात ऑर्डर में विस्तार दर्ज किया, जबकि अमेरिका और यूके में संकुचन देखा गया (चार्ट 11.6ए और 11.6बी)। जनवरी के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का माल व्यापार बैरोमीटर सूचकांक 102.8 पर है, जो संभावित व्यापार नीति परिवर्तनों की प्रत्याशा में त्वरित आयात द्वारा संचालित प्रवृत्ति से ऊपर के व्यापारिक व्यापार विकास को इंगित करता है।

ब्लूमबर्ग पण्य सूचकांक के संकेत के अनुसार, फरवरी में वैश्विक पण्य की कीमतें अस्थिर रहीं, जिसमें महीने-दर-महीने (माह-दर-माह) आधार पर 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 11.7ए)। एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में फरवरी 2025 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई,

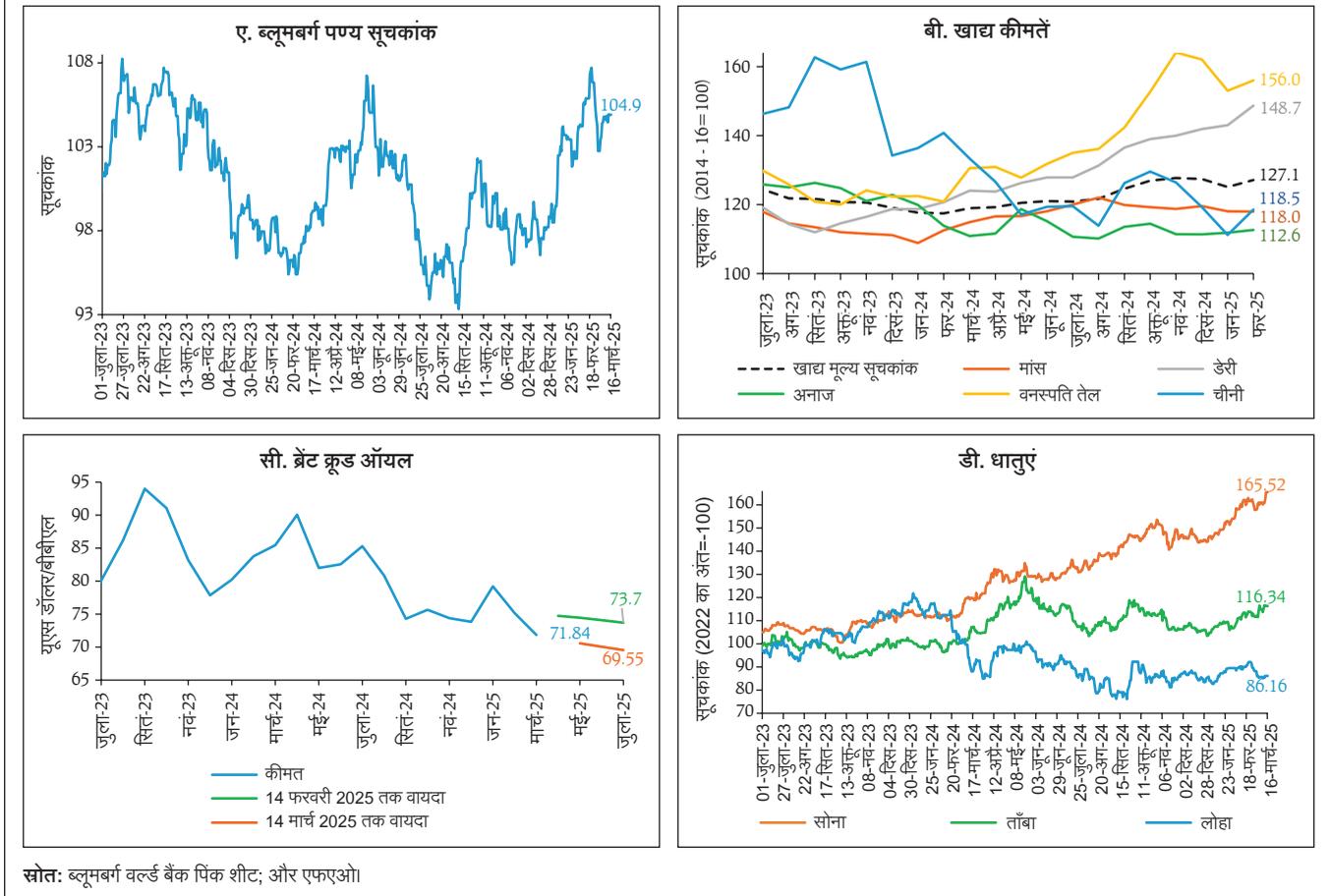
जो मुख्य रूप से चीनी, डेयरी और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, जो मांस की कीमतों में कमी से आंशिक रूप से ऑफसेट हो गई (चार्ट 11.7बी)। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि और टैरिफ अनिश्चितता के कारण वैश्विक विकास की चिंताएं बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में 4.6 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट 11.7सी)। ओपेक प्लस द्वारा अप्रैल में अपने उत्पादन में वृद्धि के साथ आगे बढ़ने के निर्णय के बाद मार्च में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। फरवरी और मार्च की शुरुआत में बेस मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसे चीन में अतिरिक्त प्रोत्साहन की उम्मीदों और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से बल मिला। फरवरी में सोने की कीमतों में भी उछाल आया (चार्ट 11.7डी), जिसे सुरक्षित निवेश की मांग और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से बल मिला।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के अवस्फीति के अंतिम पड़ाव में हेडलाइन मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी के 3.0 प्रतिशत से फरवरी में कम होकर 2.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी के 2.5 प्रतिशत से फरवरी में कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गई। जापान में मुद्रास्फीति (ताजे भोजन को छोड़कर सीपीआई)

चार्ट 11.6: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात ऑर्डर



चार्ट II.7: पण्य और खाद्य कीमतें



जनवरी में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई, जबकि यूके में इसमें 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट II.8ए)। ईएमई में, चीन में सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में (-)0.7 प्रतिशत पर अपस्फीति क्षेत्र में लौट आई, जो कमजोर घरेलू मांग के कारण एक वर्ष से अधिक समय में इसका निम्नतम स्तर है (चार्ट II.8बी)। फरवरी में रूस और ब्राजील में और जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकांश ईई में कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति हेडलाइन से ऊपर बनी हुई है (चार्ट II.8सी और II.8डी)।

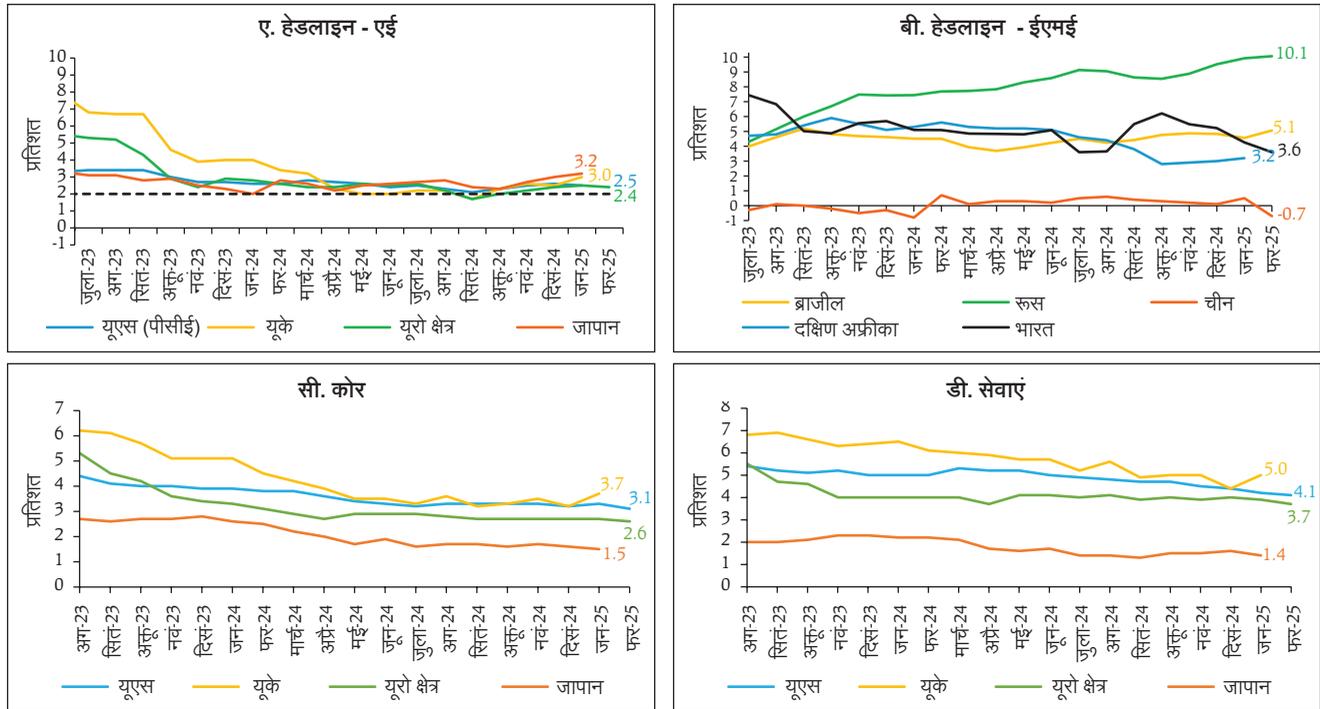
मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व इक्विटी सूचकांक फरवरी में 0.7 प्रतिशत (माह-दर-माह) गिर गया क्योंकि ईई में नुकसान ईएमई में लाभ से अधिक था। सूचकांक फरवरी के पहले भाग में बढ़ा, जिसे अमेरिका में मजबूत तिमाही कॉरपोरेट आय का समर्थन मिला, लेकिन इसके बाद गिरावट

आई और अब तक मार्च (14 तारीख तक) में गिरावट जारी रही क्योंकि उम्मीद से कमजोर आर्थिक डेटा<sup>10</sup> जारी होने और व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितता बढ़ने से आशावाद कम हुआ (चार्ट II.9ए)। अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ इन घटनाक्रमों को ट्रैक करने वाले नरम पूर्वाग्रह के साथ अस्थिर रही (चार्ट II.9बी)। अमेरिकी विकास पर व्यापार प्रतिबंधों के संभावित नकारात्मक प्रभाव ने अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाला और अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) फरवरी में 0.7 प्रतिशत कमजोर हुआ

केंद्रीय बैंकों ने या तो अपनी नीतिगत दरें कम कर दी हैं या अपनी ताजा नीति बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी है। ईई केंद्रीय बैंकों में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और कनाडा ने मार्च में अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस की कटौती की और यूके,

<sup>10</sup> इनमें निराशाजनक फ्लैश पीएमआई और सुस्त उपभोक्ता भावना सूचकांक शामिल हैं।

चार्ट II.8: मुद्रास्फीति एईएस और ईएमई

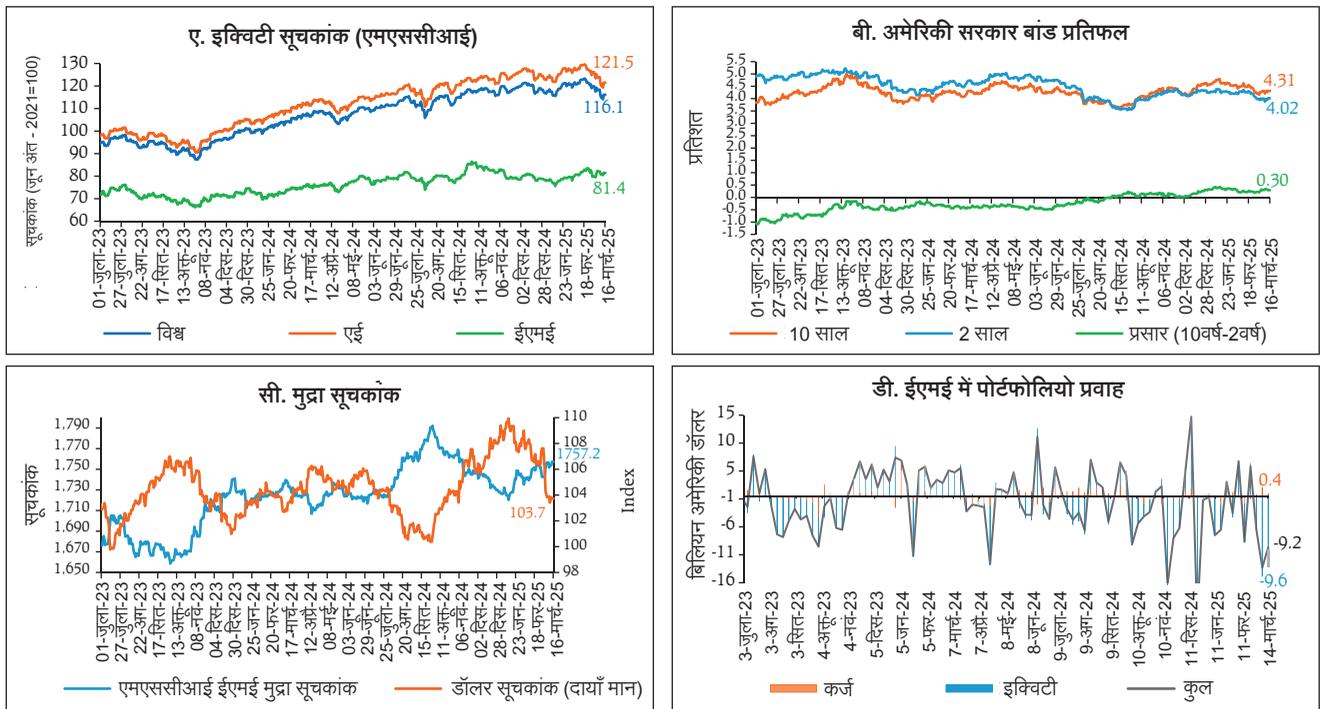


स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी

चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने फरवरी में अपनी प्रमुख दरों में 25 बीपीएस की कमी की। आइसलैंड और

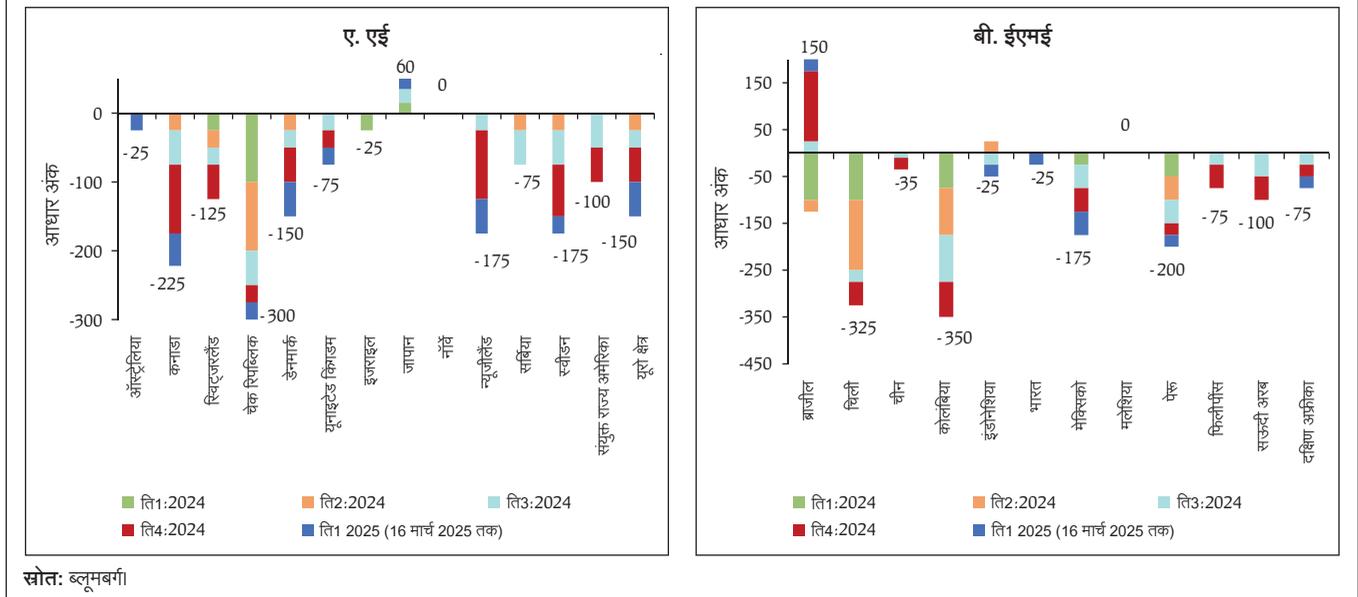
न्यूजीलैंड ने फरवरी में अपनी दरों में कटौती को बढ़ाकर 50 बीपीएस कर दिया (चार्ट II.10ए)। हालांकि, इजराइल ने अपनी

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाज़ार



स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी

चार्ट II.10: नीति दरों में परिवर्तन

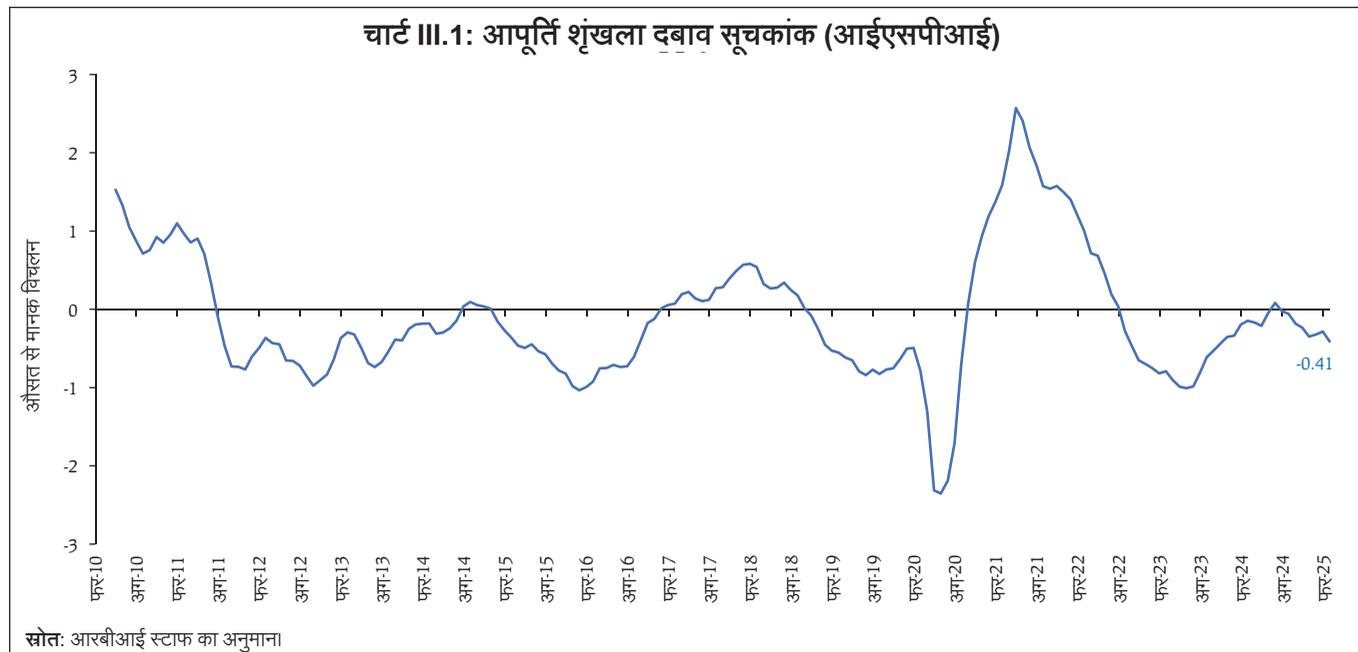


नीति दर को अपरिवर्तित रखा। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, चीन, रूस, हंगरी, फिलीपींस, इंडोनेशिया और रोमानिया ने फरवरी में अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा। मलेशिया, पेरू और पोलैंड ने मार्च में अपनी नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि थाईलैंड ने अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती की, और मेक्सिको ने अपनी बेंचमार्क दर में 50 आधार अंकों की कटौती की (चार्ट II.10बी)।

### III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने निजी खपत और सरकारी खर्च के कारण 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि में क्रमिक वृद्धि दर्ज की। फरवरी में मामूली वृद्धि के बावजूद आपूर्ति शृंखला दबाव ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा (चार्ट III.1)।

चार्ट III.1: आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (आईएसपीआई)



## समग्र मांग

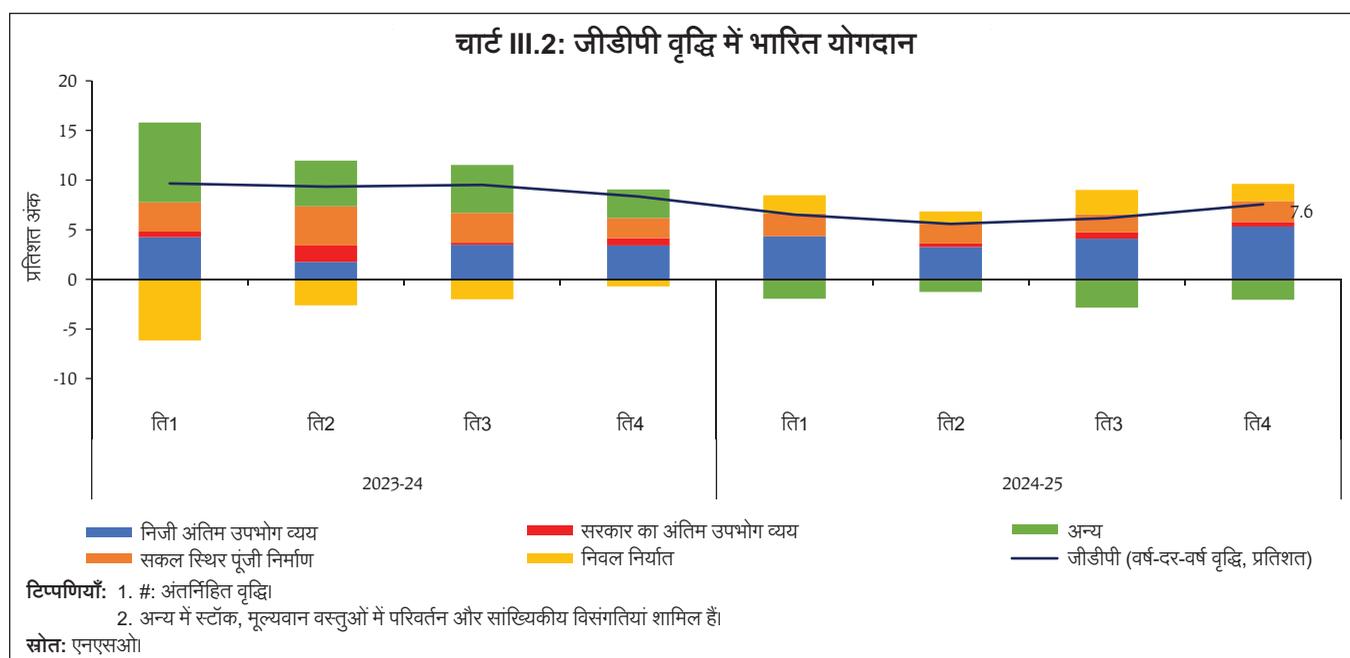
2025 को जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है - जो उच्च आधार के बावजूद पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) से 10 बीपीएस की वृद्धि दर्शाता है। यह निवल निर्यात में 120 बीपीएस की वृद्धि को 7.1 प्रतिशत और निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 30 बीपीएस की वृद्धि को 7.6 प्रतिशत पर दर्शाता है। 2023-24 के लिए वृद्धि दर को भी अनंतिम अनुमान (पीई) से 100 बीपीएस बढ़ाकर 9.2 प्रतिशत कर दिया गया।

तिमाही प्रक्षेपवक्र के संदर्भ में, विकास दर 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण उपभोग में निरंतर गति और शहरी उपभोग में पुनरुद्धार के कारण तीसरी तिमाही के दौरान पीएफसीई वृद्धि बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा व्यय में वृद्धि के कारण सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) की वृद्धि तीसरी तिमाही के दौरान सुधरकर 8.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि, स्थिर निवेश में वृद्धि 5.7 प्रतिशत तक कम हो गई, जैसा कि इसके निकटतम संकेतकों - स्टील की खपत और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में परिलक्षित होता है। वैश्विक

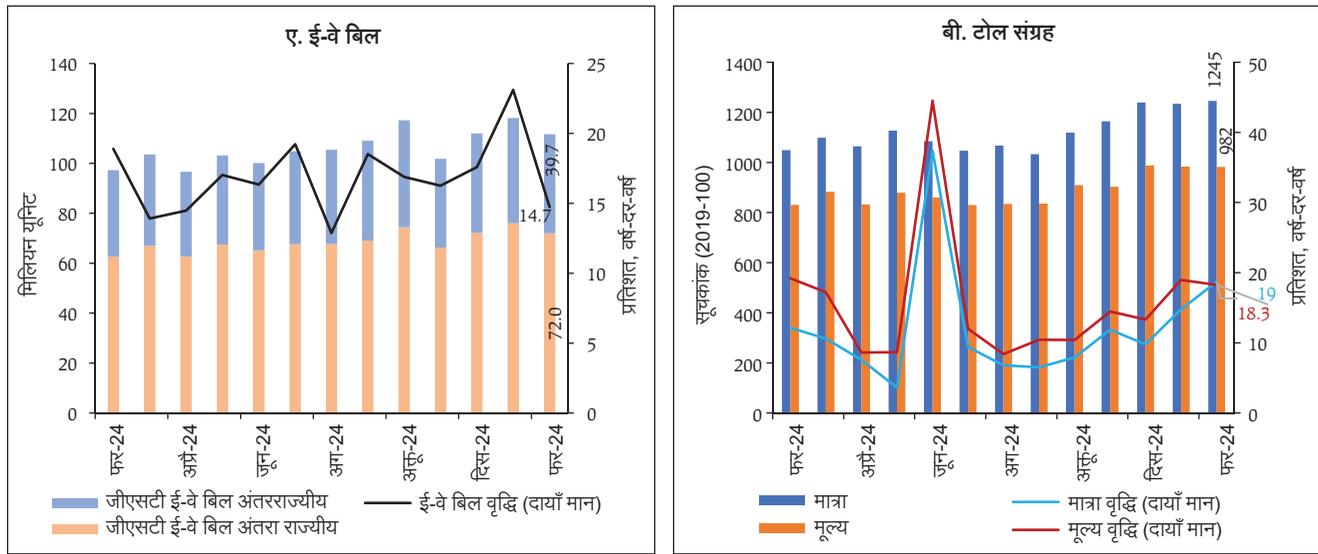
व्यापार और विश्व मांग में बाधाओं के बावजूद, निर्यात में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे मुख्य रूप से सेवाओं का समर्थन प्राप्त हुआ। आयात के मुकाबले निर्यात में वृद्धि के साथ, 2024-25 की तीसरी तिमाही में निवल निर्यात में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 2.5 प्रतिशत अंकों का धनात्मक योगदान दिया (चार्ट III.2)।

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि 2024-25 की चौथी तिमाही में कुल मांग सुदृढ़ बनी रहेगी। ई-वे बिल और टोल संग्रह जैसे गतिविधि संकेतकों ने फरवरी 2025 में दोहरे अंकों (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.3ए और चार्ट III.3बी)।

फरवरी में थोक ऑटोमोबाइल बिक्री में 6.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट III.4ए)। दोपहिया वाहनों के खंड में 9.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मोटरसाइकिल की बिक्री में गिरावट थी (चार्ट III.4बी)। ट्रैक्टर की बिक्री में लगातार तीसरे महीने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। फरवरी में वाहन पंजीकरण में संकुचन दर्ज किया गया, जो गैर-परिवहन और परिवहन वाहन दोनों खंडों में गिरावट के कारण हुआ (चार्ट III.4सी)। फरवरी में पेट्रोलियम की खपत में 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की कमी आई (चार्ट III.4डी)।



**चार्ट III.3: ई-वे बिल और टोल संग्रह**

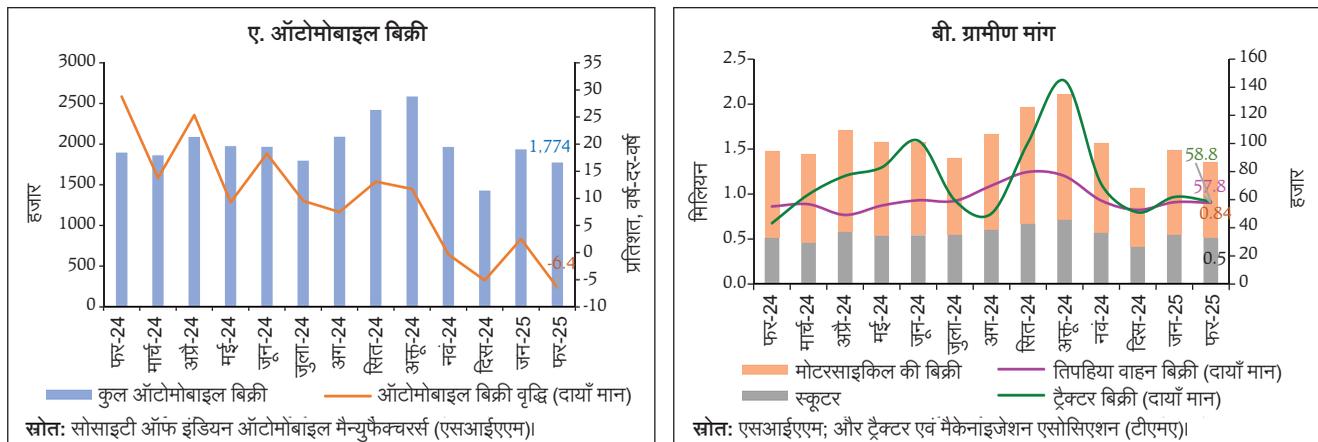


स्रोत: जीएसटीएन; और आरबीआई

फरवरी 2025 में, संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन ने पीएमआई सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से विस्तार की दूसरी

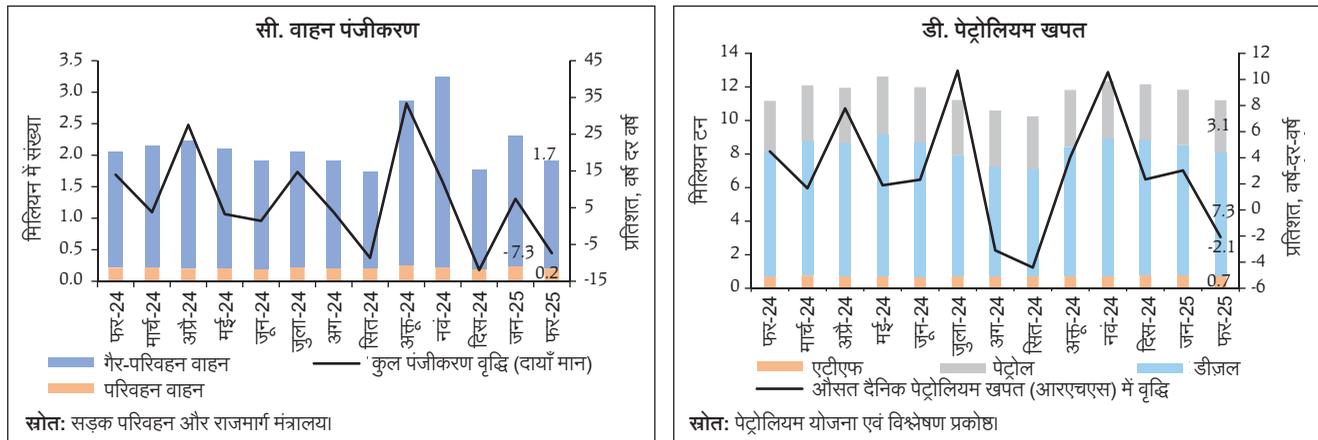
सबसे तेज़ दर दर्ज की। सेवा क्षेत्र में भी रोजगार में तेज़ गति से वृद्धि जारी रही (चार्ट III.5)

**चार्ट III.4: ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक**

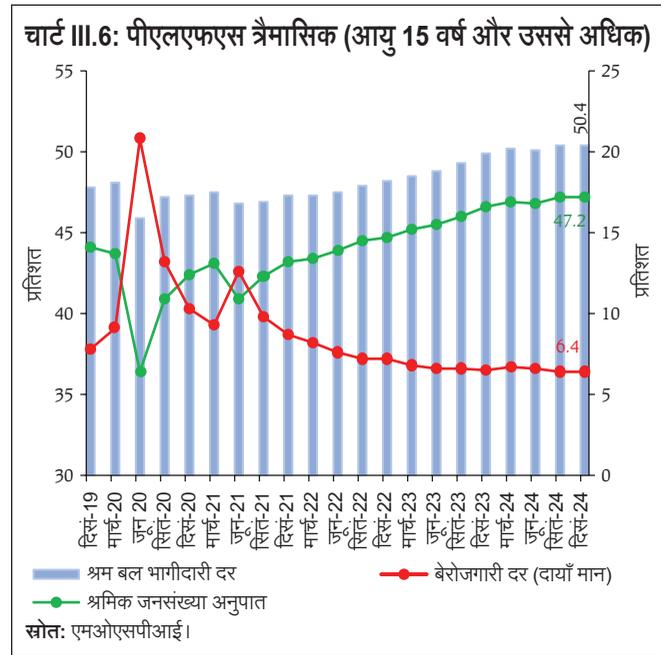
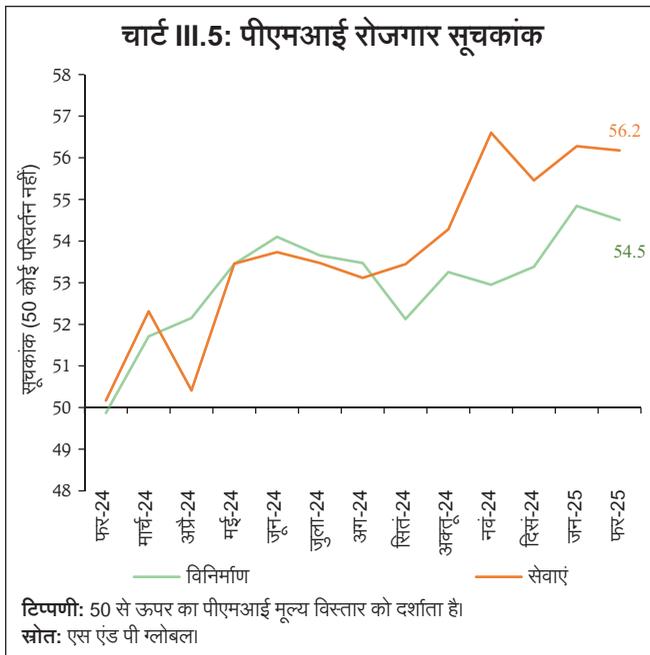


स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएमए)

स्रोत: एसआईएमए; और ट्रैक्टर एवं मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए)



स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ



नवीनतम तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान शहरी बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत थी, जो पिछली तिमाही से अपरिवर्तित थी और पीएलएफएस शृंखला में सबसे कम थी। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआई) स्थिर रहे (चार्ट III.6)।

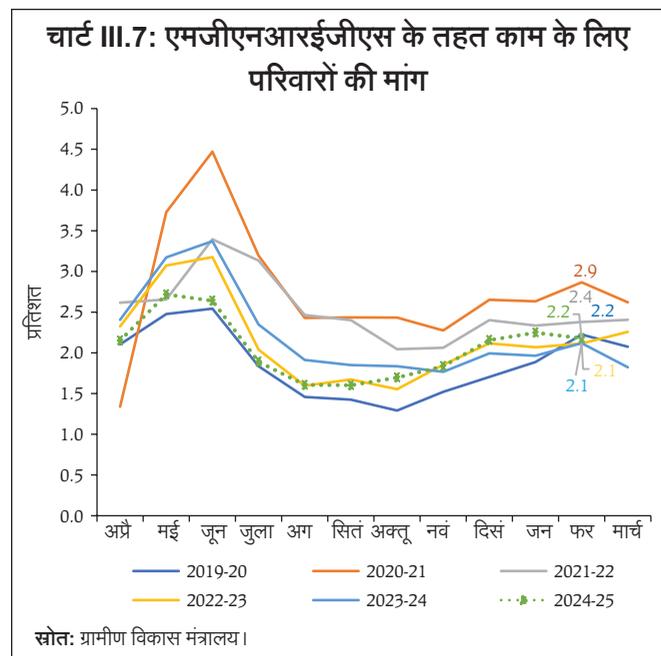
लगातार चार महीनों तक क्रमिक वृद्धि दर्ज करने के बाद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग फरवरी 2025 में 3.1 प्रतिशत (मासिक) घट गई, जो रबी की कटाई की शुरुआत के साथ मेल खाती है (चार्ट III.7)।

फरवरी 2025 में भारत का वस्तु निर्यात 10.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) घटकर 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुआ, जिसने धनात्मक गति को संतुलित कर दिया (चार्ट III.8)।

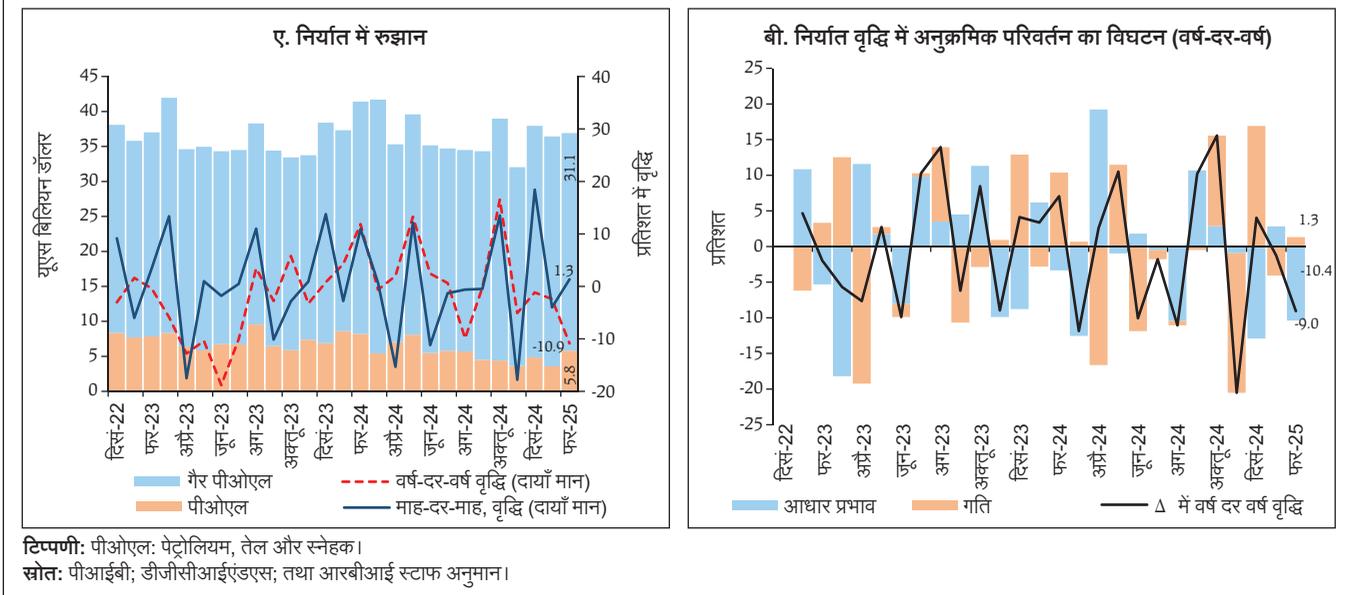
फरवरी में 30 प्रमुख वस्तुओं में से 17 (जो 2023-24 में निर्यात टोकरी का 75.3 प्रतिशत हिस्सा हैं) के निर्यात में साल-दर-साल आधार पर कमी आई। पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और रत्नों और आभूषणों ने नकारात्मक

योगदान दिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्कों ने फरवरी में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया (चार्ट III.9)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 0.1 प्रतिशत बढ़कर 395.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य भाग इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स ने किया,



**चार्ट III.8: भारत का पण्य निर्यात**

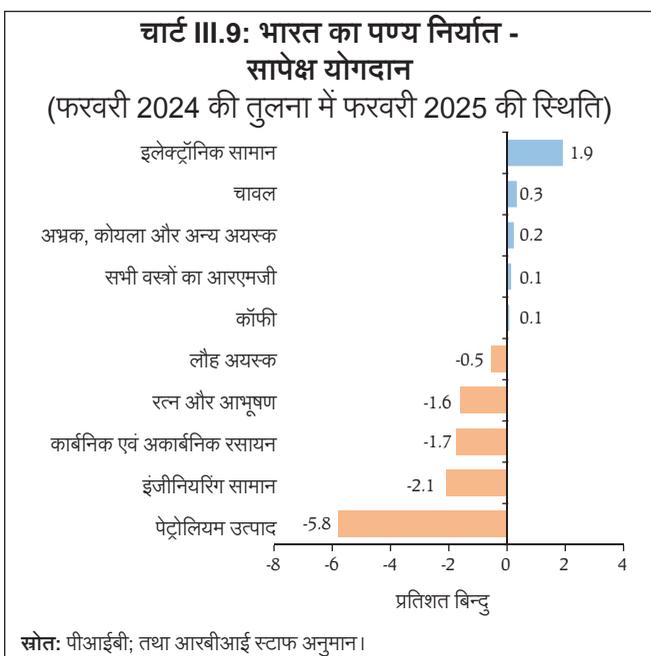


जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे कर दिया।

फरवरी 2025 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 14 को निर्यात में कमी आएगी, जबकि अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 को निर्यात में वृद्धि होगी, जिसमें अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य होंगे।

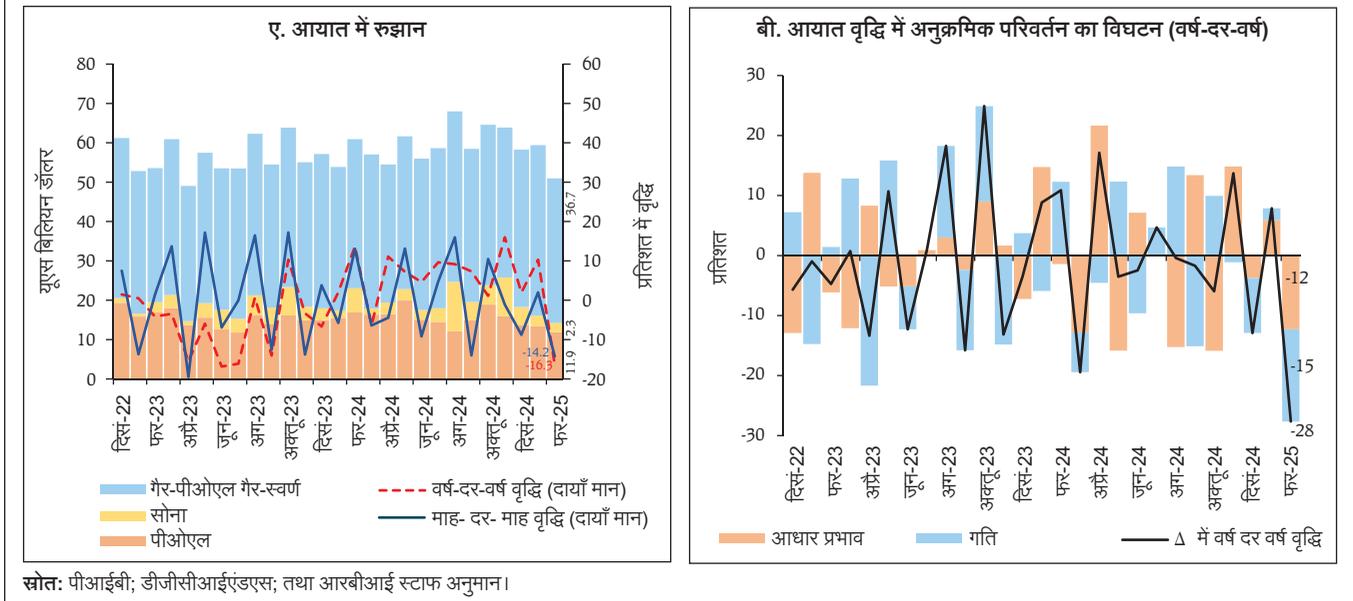
फरवरी में माल आयात 51.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 16.3 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट दर्शाता है। ऐसा मुख्य रूप से तेल और सोने के आयात में गिरावट के कारण हुआ, जो लगातार 10 महीनों तक बढ़ा था। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 12 वस्तुओं (आयात समूह का 56.8 प्रतिशत हिस्सा) में वर्ष दर वर्ष आधार पर संकुचन दर्ज किया गया (चार्ट III.10)।

पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, सोना, चांदी, कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, और मोती, और कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने आयात को नीचे खींच लिया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, रासायनिक सामग्री और उत्पाद, वनस्पति तेल, मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत, एवं अलौह धातुओं ने धनात्मक योगदान दिया (चार्ट III.11)।



अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का व्यापारिक आयात 5.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 656.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें मुख्य रूप से सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, तथा मशीनरी का योगदान रहा, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, तथा लोहा और इस्पात का योगदान ऋणात्मक रहा।

**चार्ट III.10: भारत का पण्य आयात**



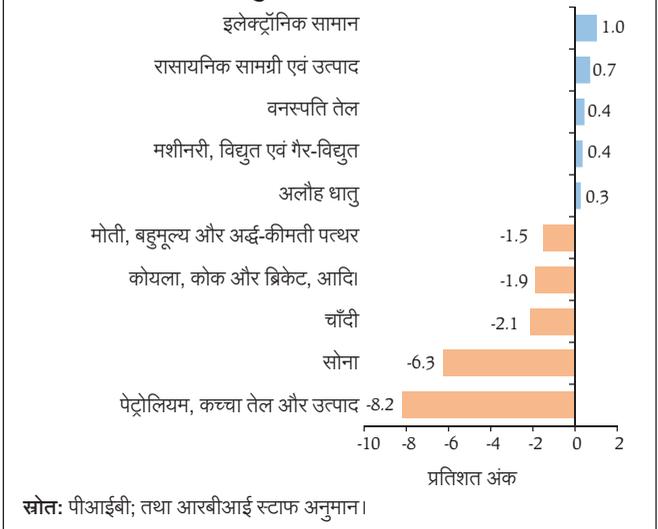
फरवरी 2025 में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात में कमी आई, जबकि अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 11 से आयात में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान प्रमुख आयात स्रोत देशों, जैसे चीन, रूस और यूई में आयात में वृद्धि देखी गई।

तेल और गैर-तेल घाटे में कमी के कारण व्यापारिक व्यापार घाटा अगस्त 2021 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर 14.1

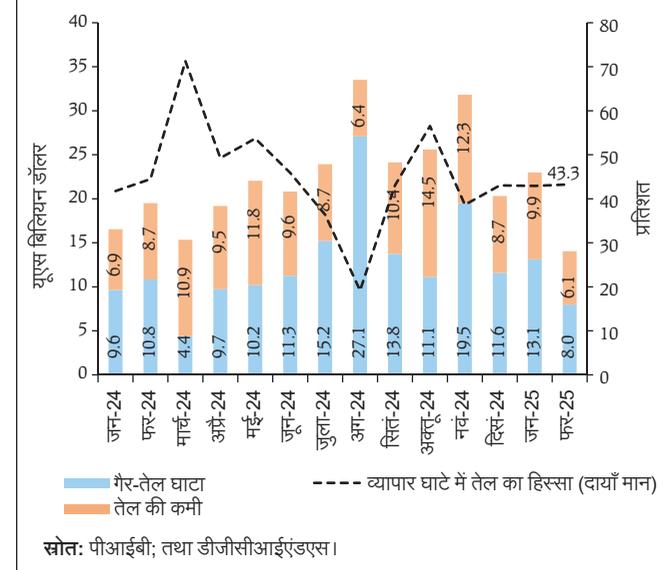
बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया। व्यापार घाटे में तेल घाटे की हिस्सेदारी फरवरी में 43.3 प्रतिशत पर आ गई, जो एक साल पहले 44.5 प्रतिशत थी। यह बड़ी गिरावट के कारण हुआ (चार्ट III.12)।

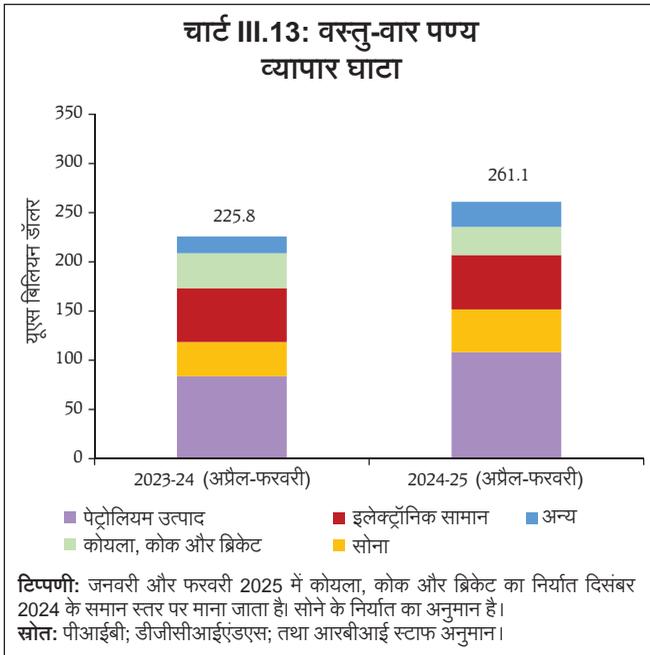
अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, भारत का पण्य व्यापार घाटा एक साल पहले के 225.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 261.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम

**चार्ट III.11: भारत का व्यापारिक आयात - सापेक्ष योगदान**  
(फरवरी 2024 की तुलना में फरवरी 2025 की स्थिति)



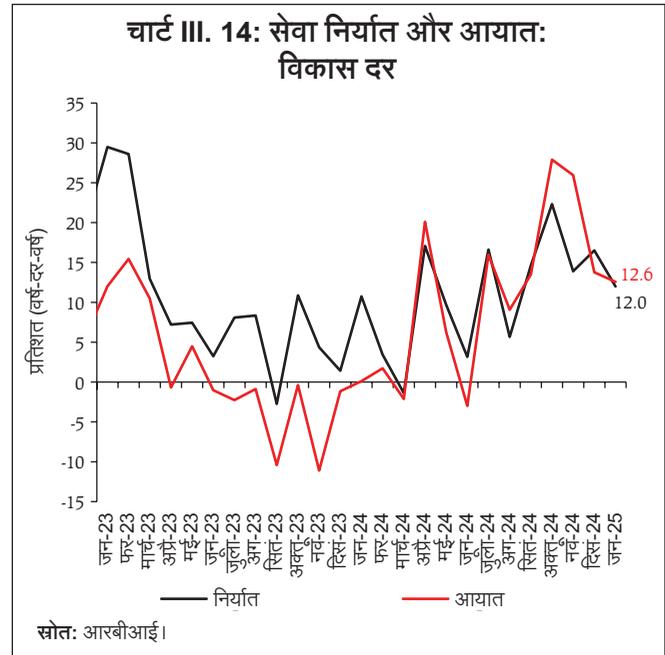
**चार्ट III.12: भारत के व्यापारिक कारोबार घाटे का अपघटन**





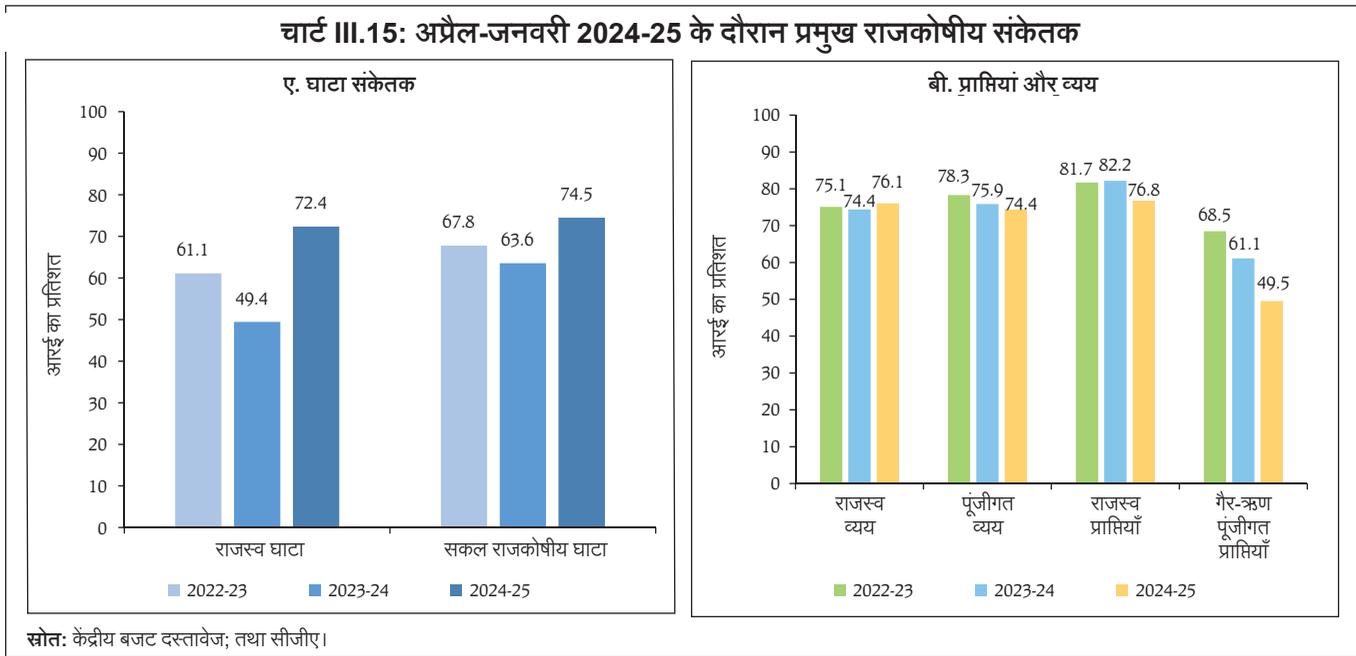
उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना (चार्ट III.13) का स्थान था।

जनवरी 2025 में, सेवाओं का निर्यात 12.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और सेवाओं का आयात 12.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.14)। जनवरी में निवल



सेवा निर्यात आय में 11.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, संशोधित अनुमान (आरई) के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और राजस्व घाटा (आरडी) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा, जिसका मुख्य कारण हाल के महीनों में केंद्र सरकार के राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में वृद्धि है (चार्ट III.15ए)।<sup>11</sup>



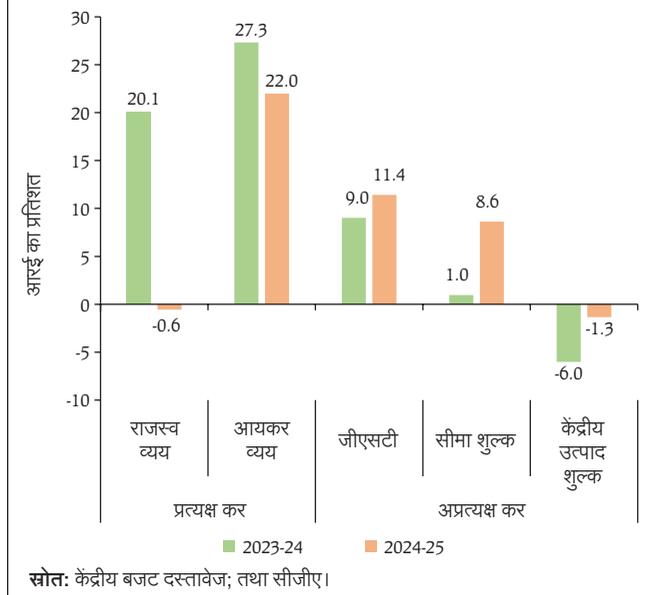
<sup>11</sup> लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।

कर संग्रह भी मजबूत बना रहा। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय जैसे प्रमुख राजकोषीय संकेतक मोटे तौर पर पिछले वर्ष (आरई के प्रतिशत के रूप में) के अनुरूप रहे, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर जो पिछले वर्ष की तुलना में कम रही हैं (चार्ट III.15बी)।

केंद्र सरकार का कुल व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.9 प्रतिशत की तुलना में 6.4 प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि पूंजी और राजस्व व्यय दोनों में वृद्धि हुई। केंद्र के राजस्व व्यय के भीतर, प्रमुख सब्सिडी पर व्यय में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 21.0 प्रतिशत की कमी की तुलना में अधिक खाद्य सब्सिडी के कारण हुआ।

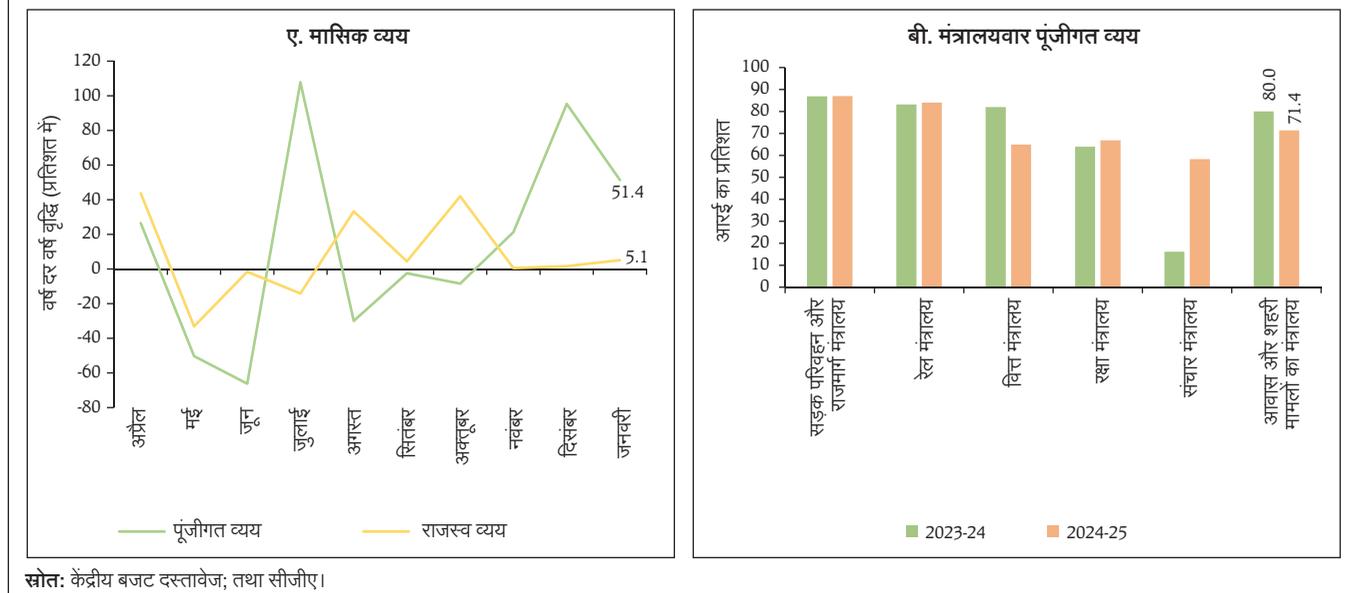
अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान का 74.4 प्रतिशत रहा, जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के अनुरूप है। अक्टूबर 2024 से केंद्र के पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई, जिसने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान देखी गई सुस्ती की भरपाई की (चार्ट III.16ए)। 2024-25 के लिए उच्चतम बजटीय पूंजीगत व्यय लक्ष्य वाले मंत्रालयों ने 2024-25 के अपने संशोधित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्याप्त प्रगति की है (चार्ट III.16बी)।

**चार्ट III.17: अप्रैल-जनवरी के दौरान कर राजस्व**

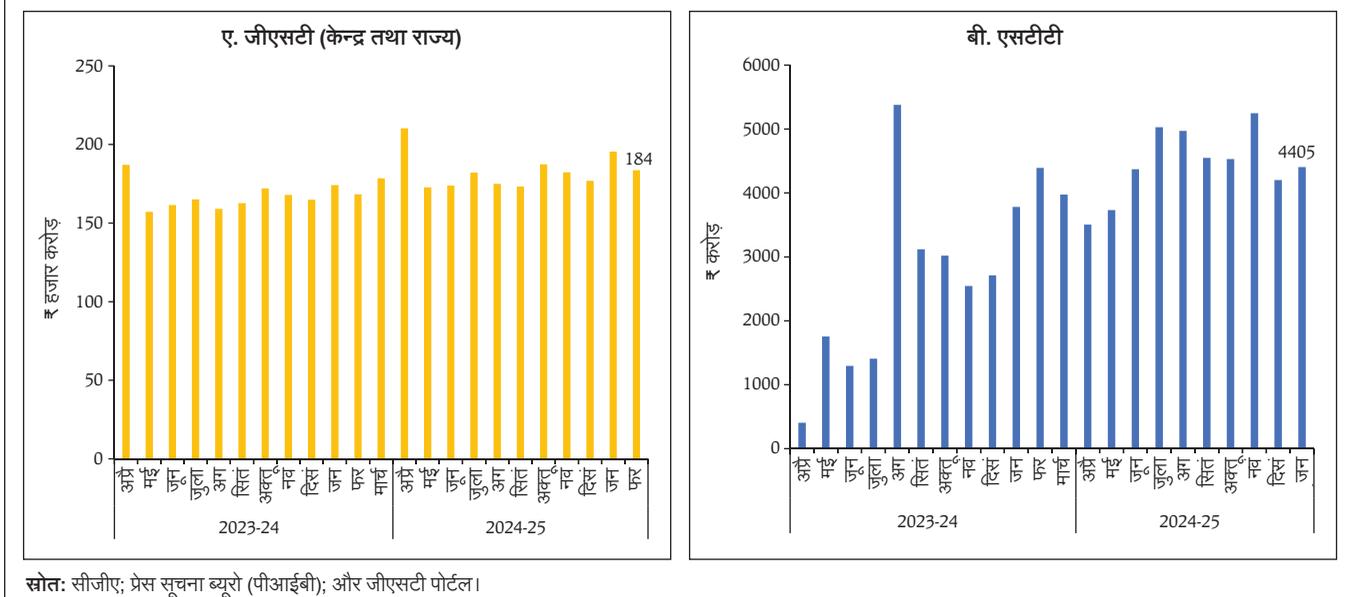


अप्रैल-जनवरी 2024-25 में केंद्र के सकल कर राजस्व और कुल प्राप्तियों में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयकर और जीएसटी 2024-25 में केंद्र के मजबूत कर संग्रह के लिए प्रमुख चालक बने रहे। जबकि निगम कर का प्रदर्शन कमतर रहा, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वृद्धि में सुधार हुआ है (चार्ट III.17)।

**चार्ट III.16: अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार का व्यय**



**चार्ट III.18: एसटीटी और जीएसटी में मासिक रुझान**



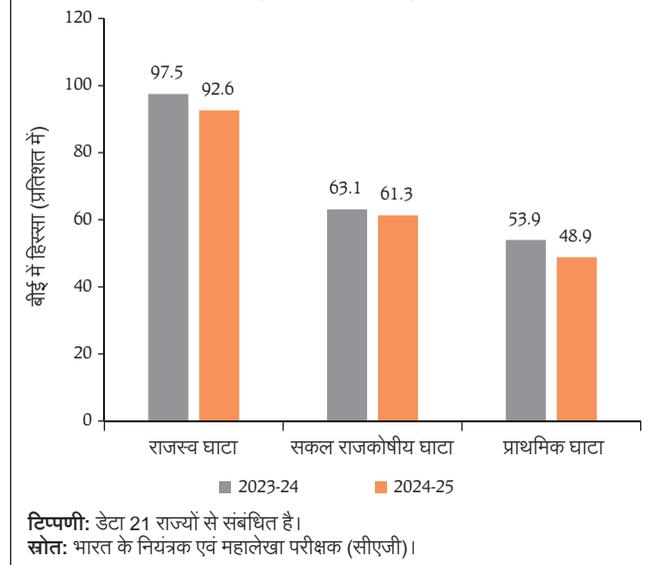
फरवरी 2025 में जीएसटी प्राप्तियां (केंद्र और राज्य) 9.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ीं (चार्ट III.18ए)। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के लिए संचयी जीएसटी संग्रह ₹20.13 लाख करोड़ रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से कर संग्रह में 75.3 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में इसका हिस्सा पिछले वर्ष के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया है (चार्ट III.18बी)।

भारतीय रिज़र्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण गैर-कर राजस्व संग्रह में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का प्रदर्शन धीमा रहा, जिसका आंशिक कारण विनिवेश प्राप्तियां कम होना है।

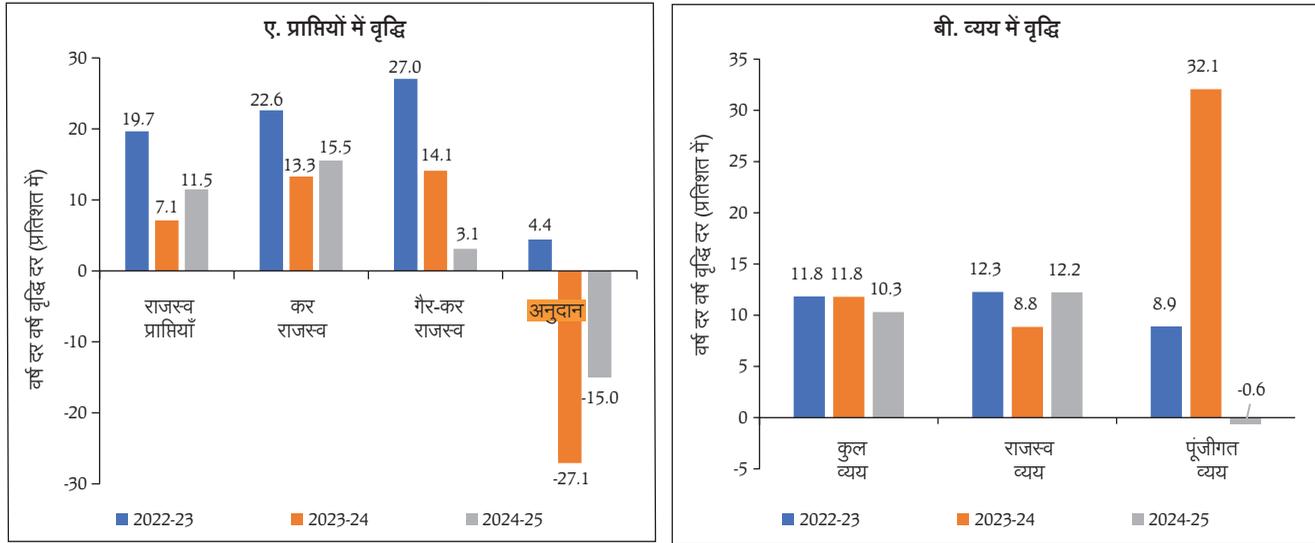
अप्रैल-जनवरी 2024-25 के अनंतिम लेखा आंकड़ों के अनुसार, राजस्व प्रदर्शन में सुधार और पूंजीगत व्यय में कमी के कारण बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में राज्यों का जीएफडी पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम था (चार्ट III.19)। राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिसे उच्च कर राजस्व का

समर्थन प्राप्त था, जबकि गैर-कर राजस्व में वृद्धि धीमी रही (चार्ट III.20ए)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में मजबूत वृद्धि देखी गई और बिक्री कर/वैट संग्रह में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संकुचन से सुधार के संकेत दिखे।

**चार्ट III. 19: राज्यों के राजकोषीय संकेतक (अप्रैल-जनवरी)**



**चार्ट III.20: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-जनवरी)**



टिप्पणी: डेटा 21 राज्यों से संबंधित है।  
 स्रोत: सीएजी।

व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय में वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान बढ़ी, जबकि पूंजीगत व्यय में गिरावट आई (चार्ट III.20बी)। राजस्व व्यय में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय में संकुचन ने राज्यों के खर्च की गुणवत्ता को कमजोर कर दिया है, पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) के लिए राजस्व व्यय का अनुपात अप्रैल-जनवरी 2024-25 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.1 से बढ़कर 7.1 हो गया है।

में सबसे अधिक योगदान दिया, जो कुल जीवीए में 38 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत, लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम और सीमेंट उद्योगों ने समग्र जीवीए वृद्धि में ऋणात्मक योगदान दिया (चार्ट III.22)।

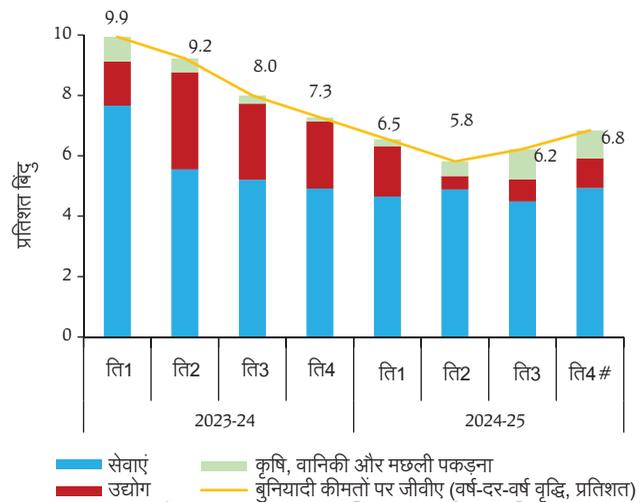
खाद्यान्न उत्पादन में मजबूती और बागवानी उत्पादन में वृद्धि के कारण कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में 2024-25 की

**समग्र आपूर्ति**

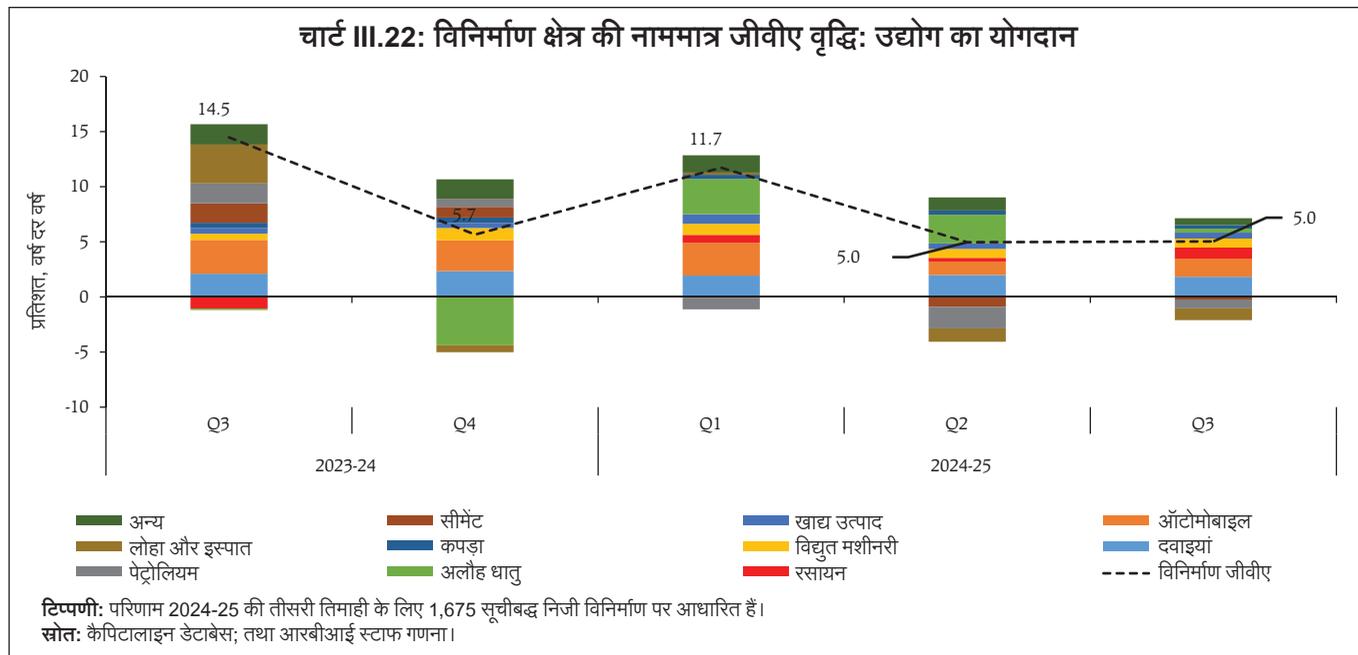
एसएई के अनुसार, वर्ष 2024-25 में मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो एफएई के समान है। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, वास्तविक जीवीए वृद्धि पिछली तिमाही के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई (चार्ट III.21)। विकास को कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा बढ़ावा दिया गया, जबकि उद्योग क्षेत्र ने मामूली प्रदर्शन किया।

सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की नाममात्र जीवीए वृद्धि पिछली तिमाही से अपरिवर्तित रही, जो कि 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 5.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही। फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और रसायन उद्योगों ने वृद्धि

**चार्ट III.21: जीवीए वृद्धि में भारत योगदान**



टिप्पणी : #: अंतर्निहित वृद्धि।  
 स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।<sup>12</sup> पिछली तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने तीसरी तिमाही में मामूली सुधार दिखाया। विनिर्माण क्षेत्र - औद्योगिक जीवीए वृद्धि का प्राथमिक चालक - ने 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसे सूचीबद्ध कॉरपोरेट विनिर्माण फर्मों की बेहतर लाभप्रदता से सहायता मिली। खनन और उत्खनन में गतिविधि में सुधार हुआ, 2024-25 की तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही की तुलना में संकुचन के मुकाबले 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सेवा क्षेत्र 2024-25 की तीसरी तिमाही में स्थिर रहा। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर पिछली तिमाही की तुलना में 7.0 प्रतिशत रही, जैसा कि इस्पात की खपत में कमी से पता चलता है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संबंधित सेवाओं में वृद्धि दर बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो मजबूत व्यापारिक गतिविधि के कारण संभव हुई। वित्तीय, रियल एस्टेट और

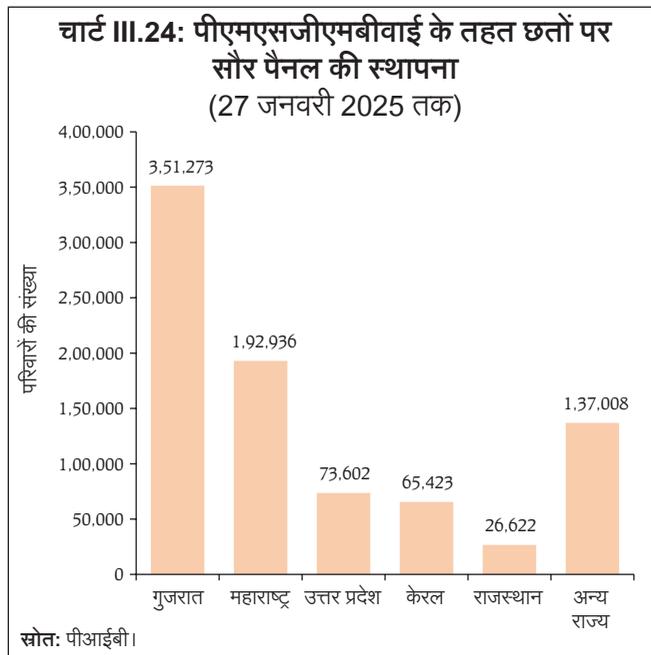
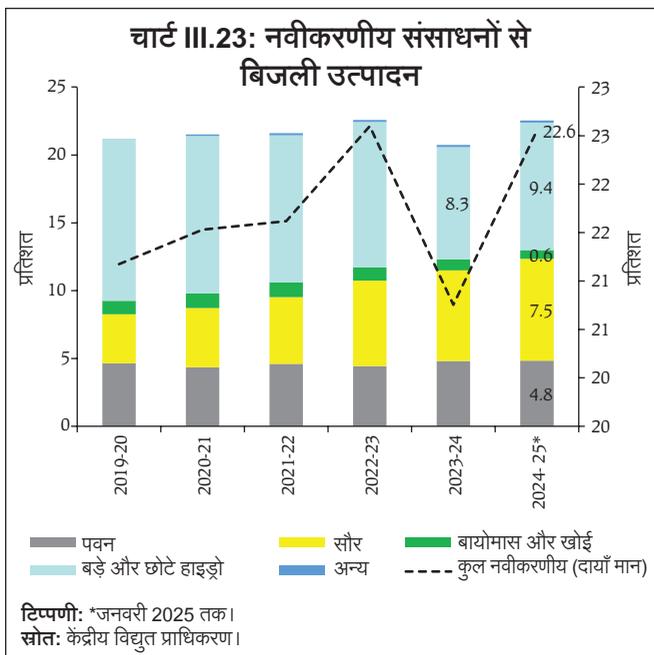
पेशेवर सेवाओं में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर बनी रही, जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे अन्य सेवाओं में मजबूत वृद्धि का समर्थन मिला।

गर्मी के मौसम के दौरान मौसमी तापमान के अपने पूर्वानुमान में, आईएमडी ने मार्च से मई 2025 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान का अनुमान लगाया है। सामान्य से अधिक तापमान के कारण बिजली की मांग में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, अक्षय स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन पर भारत का बढ़ता ध्यान, गर्मी के मौसम में बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने में मदद कर सकता है (चार्ट III.23)।

सौर ऊर्जा कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का 47 प्रतिशत हिस्सा लेकर प्रमुख योगदानकर्ता बनी हुई है। हाल ही में, भारत ने 100 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया जो 2014 में 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावॉट हो गया।<sup>13</sup> मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के उद्देश्य

<sup>12</sup> खरीफ खाद्य उत्पादन में 2024-25 में 6.8 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के दौरान बागवानी फसलों का उत्पादन 362.1 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 2.1 प्रतिशत अधिक और 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमानों से 1.9 प्रतिशत अधिक है।

<sup>13</sup> <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2100603>

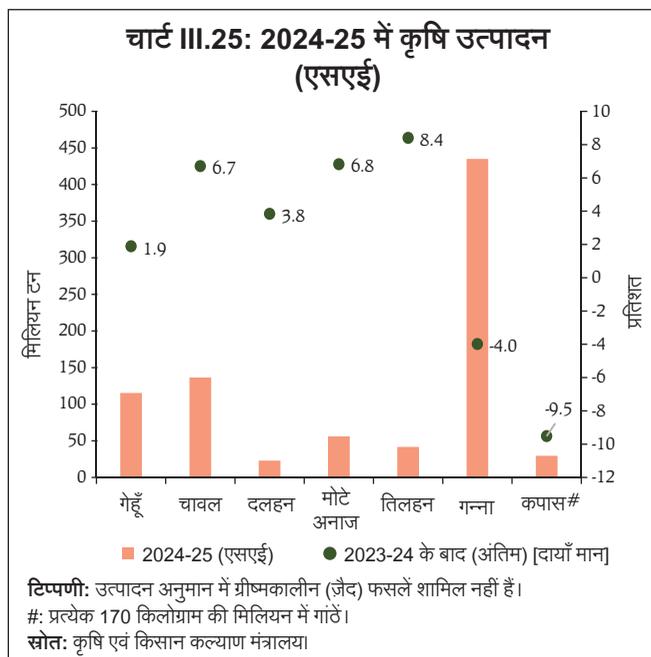


से, पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान करती है। 10 मार्च 2025 तक, 10.09 लाख घरों में छत पर सौर पैनल लगे हुए थे। 27 जनवरी 2025 तक उपलब्ध राज्यवार आंकड़ों के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान मिलकर कुल प्रतिष्ठानों का 84 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं (चार्ट III.24)।

अंतर्गत रकबा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था, तिलहन को छोड़कर, जिसके लिए यह एक वर्ष पहले की तुलना में थोड़ा कम स्तर पर था (चार्ट III.26)।

जलाशय स्तर (155 प्रमुख जलाशयों के आधार पर) कुल जलाशय क्षमता (13 मार्च, 2025 तक) के 47 प्रतिशत पर एक

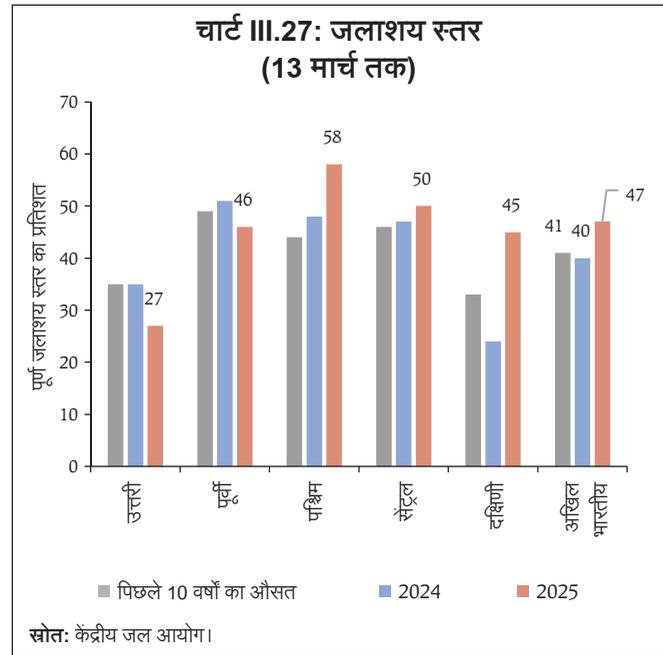
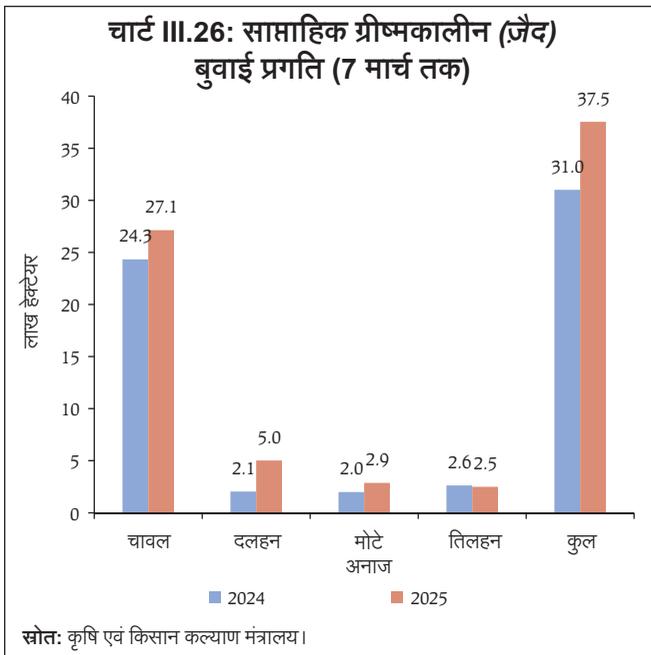
कृषि फसल उत्पादन (खरीफ और रबी)<sup>14</sup> के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.9 मिलियन टन रखा गया है, जो खरीफ और रबी दोनों उत्पादन में क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 4.8 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.25)। गेहूँ (प्रमुख रबी प्रधान अनाज) उत्पादन रिकॉर्ड 115.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया है जो पिछले वर्ष के अंतिम अनुमानों से 1.9 प्रतिशत अधिक है।



07 मार्च, 2025 तक ग्रीष्मकालीन रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 21.1 प्रतिशत अधिक था। सभी प्रमुख फसलों के

<sup>14</sup> इन अनुमानों में ग्रीष्म (जैद) ऋतु का उत्पादन शामिल नहीं है, जिसकी बुवाई अभी चल रही है।

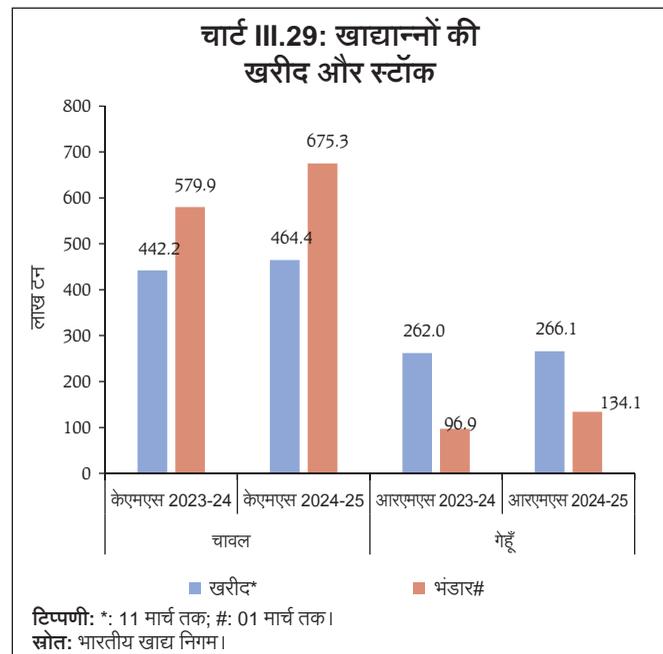
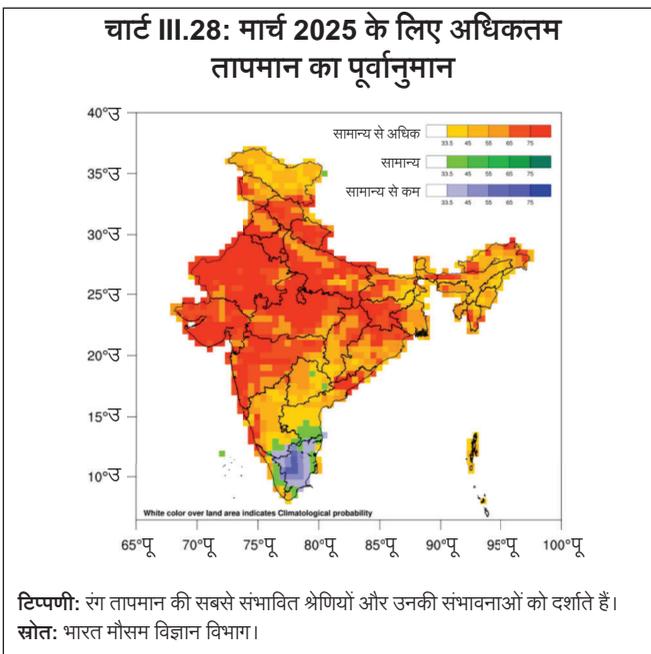
<sup>15</sup> <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2102149>

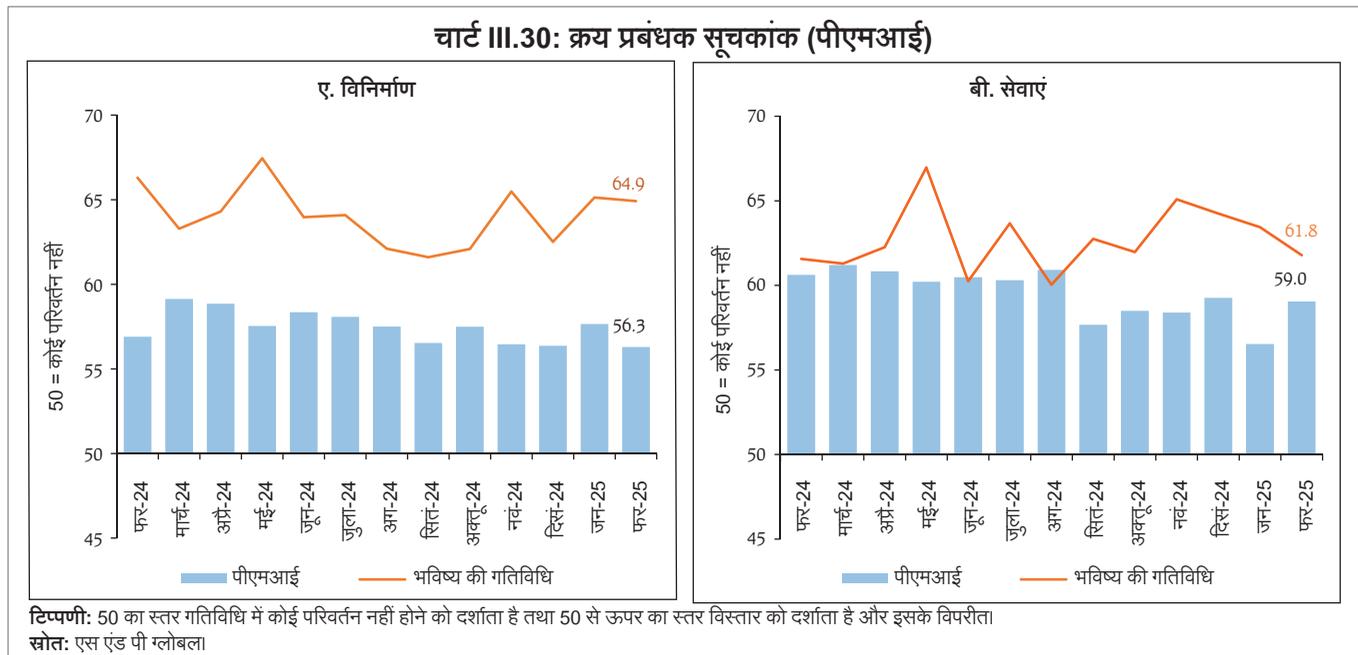


संतोषजनक स्थिति में हैं, जो पिछले वर्ष के साथ-साथ दशकीय औसत स्तरों (चार्ट III.27) से भी अधिक है। यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा देश के अधिकांश हिस्सों में पूरे गर्मी के मौसम (मार्च से मई) के लिए तापमान में असामान्यता और सामान्य से अधिक हीटवेव दिनों के अनुमान से उत्पन्न खड़ी

रबी फसलों के लिए चिंताओं को आंशिक रूप से कम करता है (चार्ट III.28)।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा रखे गए खाद्यान्नों का कुल सार्वजनिक स्टॉक बफर आवश्यकताओं से 3.8 गुना अधिक है, जिसका मुख्य कारण चावल का अधिक स्टॉक है





(चार्ट III.29)। चावल का स्टॉक बफर आवश्यकता से 8.9 गुना अधिक है। गेहूं का स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में 38.3 प्रतिशत अधिक है और बफर मानदंड से ऊपर है। चालू विपणन सत्र के दौरान चावल की खरीद 464.4 लाख टन (11 मार्च, 2025 तक) है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.0 प्रतिशत अधिक है।

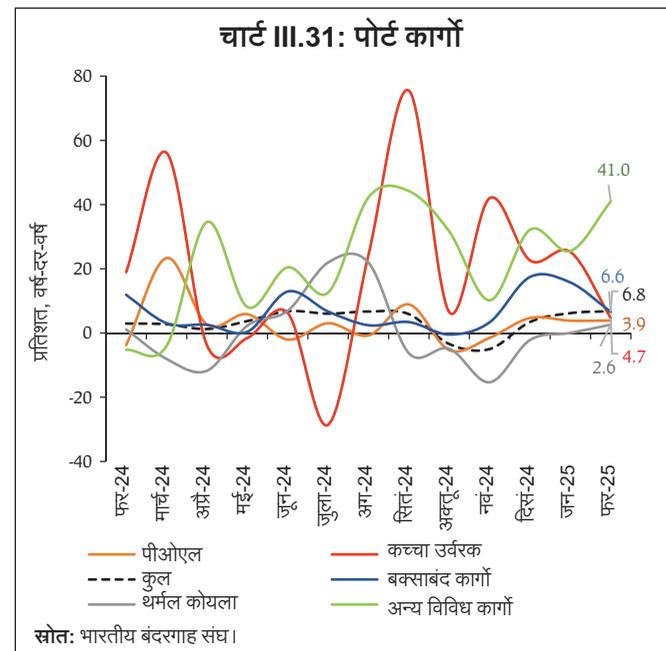
01 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले आगामी रबी विपणन सीजन (2025-26) के लिए गेहूं खरीद का अनुमान 310 लाख टन तय किया गया है।<sup>16</sup> इसी तरह, रबी चावल खरीद और रबी मोटे अनाज (बाजरा सहित) के अनुमान क्रमशः 70 लाख टन और 16 लाख टन तय किए गए हैं।

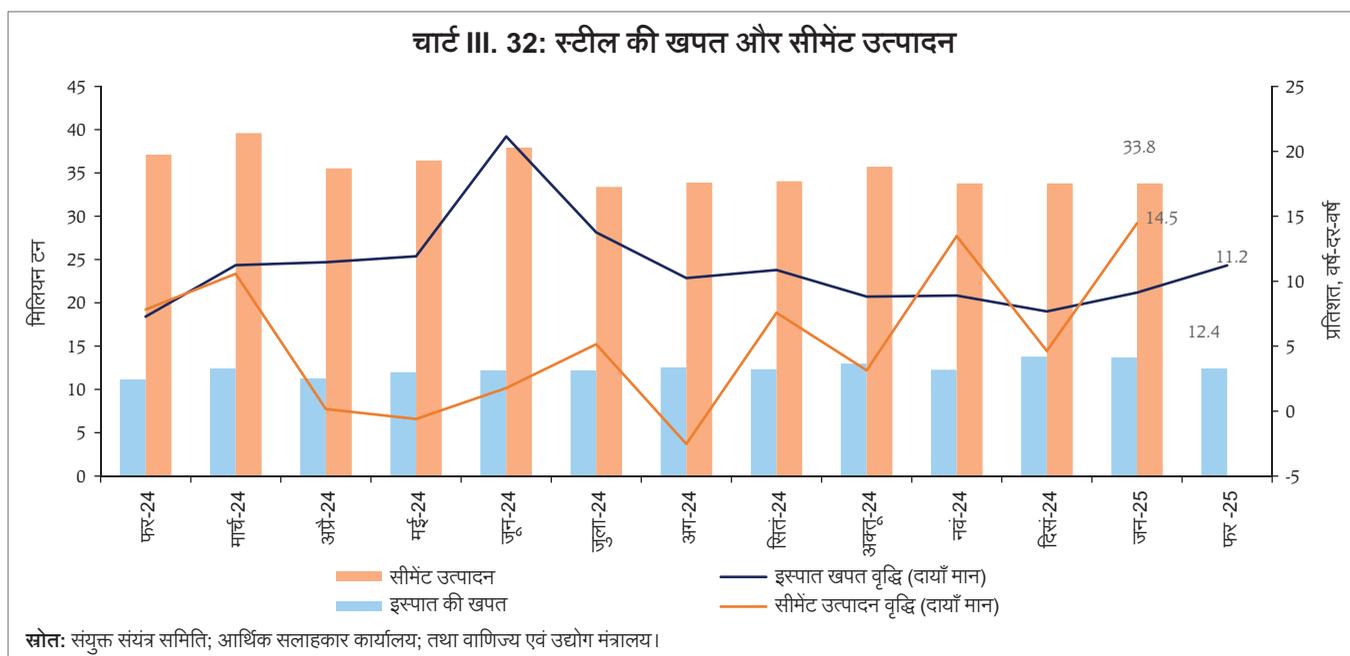
नए ऑर्डर और उत्पादन में मंदी के कारण भारत का विनिर्माण पीएमआई फरवरी में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया (चार्ट III.30ए)। नए कारोबार में मजबूत वृद्धि से सहायता प्राप्त सेवा पीएमआई ने फरवरी में क्रमिक वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.30बी)।

<sup>16</sup> <https://pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2107076@=3&lang=1>

औद्योगिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में, बंदरगाह यातायात में वृद्धि फरवरी 2025 में तेज हुई, जो अन्य विविध कार्गो और कंटेनरयुक्त कार्गो में उच्च वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट III.31)।

निर्माण क्षेत्र में, फरवरी में इस्पात की खपत में वृद्धि बढ़कर 11.2 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) हो गई, जबकि सीमेंट उत्पादन स्तर





जनवरी में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया (चार्ट III.32)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि में सुदृढ़ता को दर्शाते हैं (सारणी III.1)।

### सारणी III .1 : उच्च आवृत्ति संकेतक – सेवाएँ

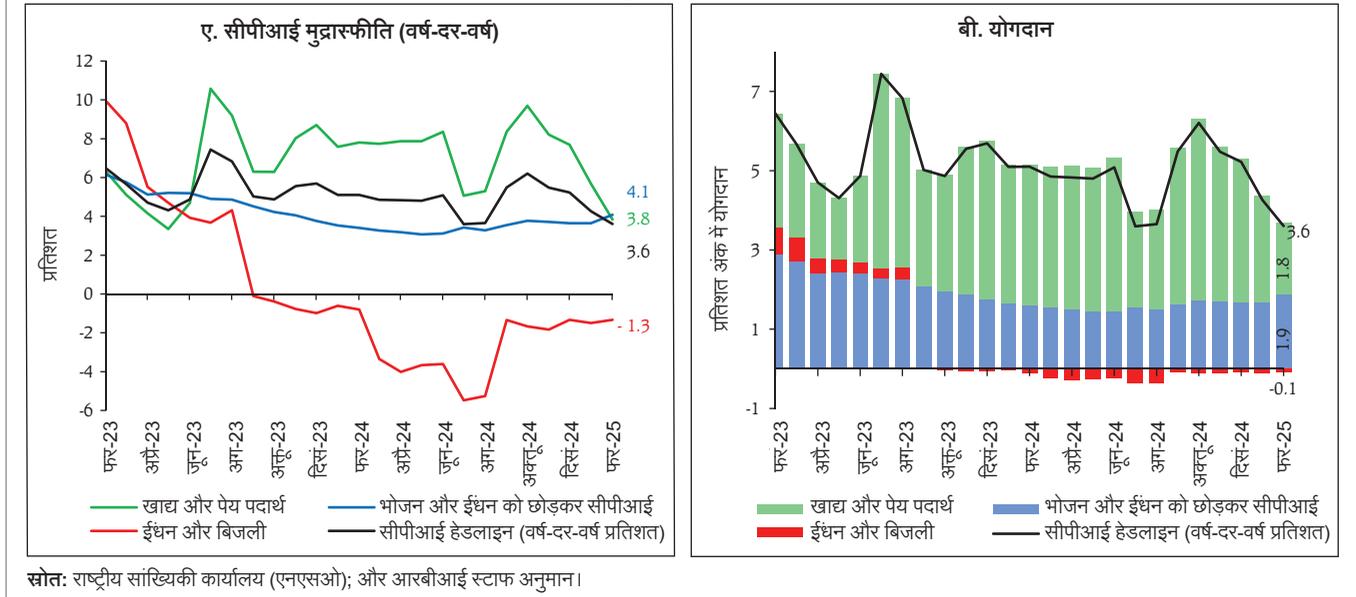
(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुला-24	अग-24	सित-24	अक्टू-24	नव-24	दिस-24	जन-25	फर-25
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	9.5	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.6	-0.4	1.1	4.4	11.4	3.5	3.7
	दोपहिया वाहन बिक्री	34.6	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1	-8.8	2.1	-9.0
	तीन पहिया वाहन बिक्री	8.3	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	6.7	-0.7	-1.3	3.5	8.6	4.7
	ट्रैक्टर बिक्री	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3	14.0	11.4	35.9
ग्रामीण मांग	वाणिज्यिक वाहन बिक्री	-3.8			3.5			-11.0			1.3			
	रेलवे माल ढुलाई यातायात	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0	-5.8	1.5	1.2			
	पोर्ट कार्गो यातायात	3.0	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.4	-4.9	3.4	7.6	6.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	11.5	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	6.9	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	30.2	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	7.1	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	5.8	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1	16.4
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	19.3	15	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	11.1	11.7
	जीएसटी ई-वे बिल्स (कुल)	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1	14.7
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4	17.9	23.3	14.9
	जीएसटी ई-वे बिल्स (अंतर राज्य)	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1	17.1	22.8	14.4
	होटल कमरा बुकिंग दर	1.8	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	1.2	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	7.8	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	10.7	8.9	8.7	
	यात्री आगमन	15.8	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2	0.4	-1.4	-0.1	-6.6		
विनिर्माण	इस्पात खपत	7.3	11.2	11.5	11.9	21.1	13.8	10.3	10.9	8.8	8.9	7.7	9.1	11.2
	सीमेंट उत्पादन	7.8	10.6	0.2	-0.6	1.8	5.1	-2.5	7.6	3.1	13.5	4.6	14.5	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएँ	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5	59.0

<<संकुचन-----विस्तार>>

टिप्पणी: #: आंकड़े स्तरों में हैं। \*: फरवरी 2025 के आंकड़े दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है।  
 स्रोत: एसआईएएम: रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ; आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवी.एस एनारोक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्केट।

चार्ट III.33: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक



## मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)<sup>17</sup> में साल-दर-साल होने वाले बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति जनवरी में 4.3 प्रतिशत से फरवरी 2025 में घटकर सात महीने के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट III.33)। मुद्रास्फीति में 70 बीपीएस की गिरावट लगभग 50 बीपीएस की ऋणात्मक मूल्य गति के कारण थी, जिसे लगभग 20 बीपीएस के अनुकूल आधार से और मदद मिली। खाद्य समूह ने महीने के दौरान लगभग (-)1.6 प्रतिशत की ऋणात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में गति क्रमशः 0.1 और 0.7 प्रतिशत पर धनात्मक रही।

फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी में 5.7 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत (वार्षिक) हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, दालों और अंडों की कीमतों में तेज सुधार दर्ज किया गया और वे अपस्फीति क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जबकि अनाज, मांस और मछली, और दूध और उत्पादों में मुद्रास्फीति कम हुई। दूसरी ओर, तेल और वसा, फल, चीनी और मिष्ठान्न, गैर-

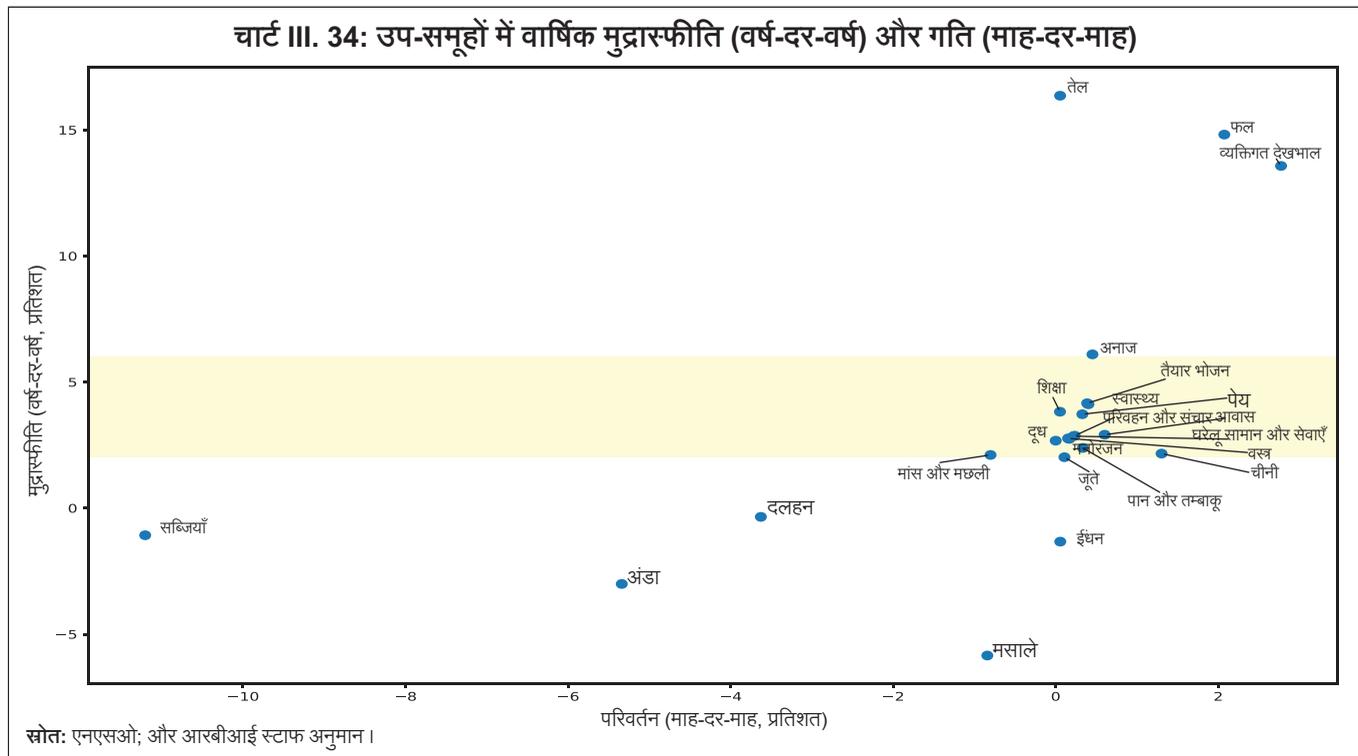
अल्कोहल पेय और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी। मसालों में अपस्फीति बनी रही, हालांकि यह कम दर पर रही (चार्ट III.34)।

ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर (-)1.3 प्रतिशत रह गई, जो जनवरी में (-)1.5 प्रतिशत थी। इसका कारण केरोसिन की कीमतों में कम अपस्फीति और बिजली की कीमतों में उच्च मुद्रास्फीति है। एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति की स्थिर दर दर्ज की गई।

कोर मुद्रास्फीति जनवरी में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 4.1 प्रतिशत हो गई। पान, तम्बाकू और मादक द्रव्यों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, तथा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि यह कपड़े और जूते, घरेलू सामान और सेवाओं, मनोविनोद और मनोरंजन, और शिक्षा जैसे उप-समूहों में अपरिवर्तित रही (चार्ट III.35)।

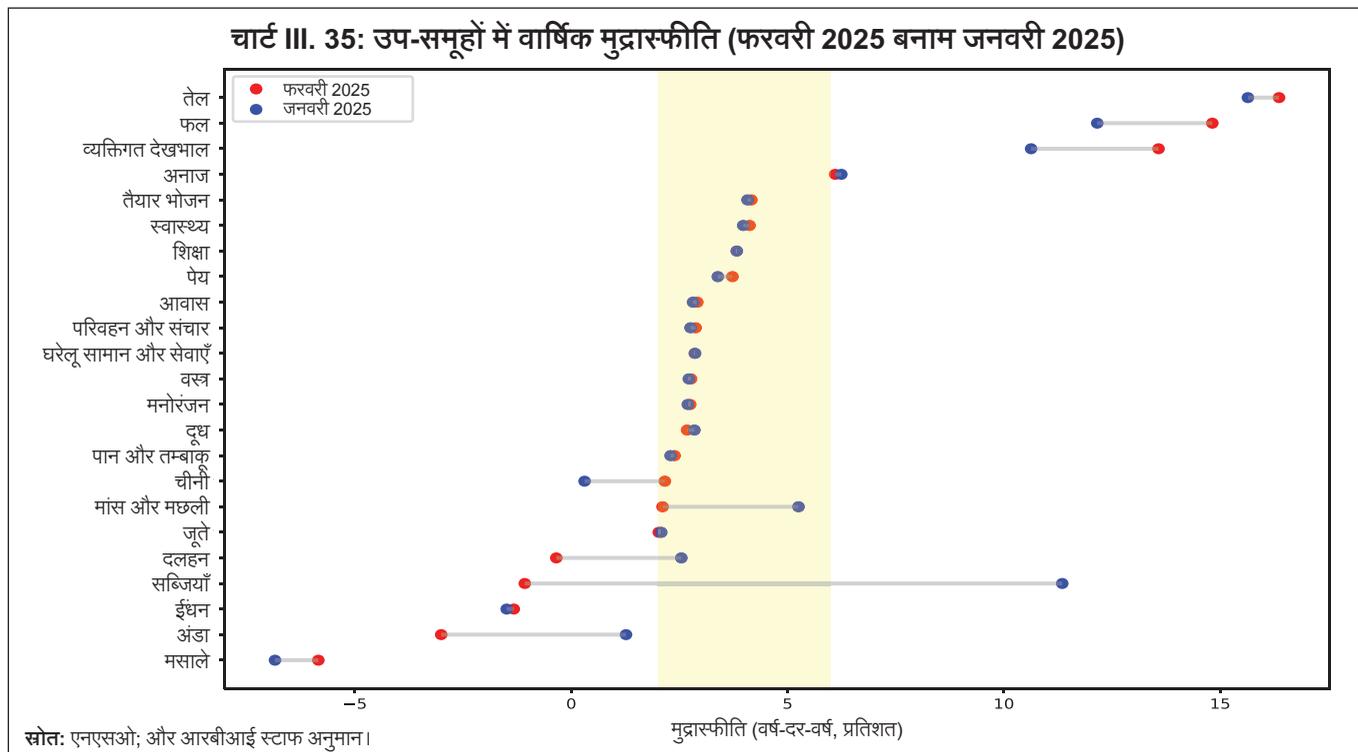
क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, फरवरी 2025 में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत तक कम हो गई। राज्य स्तर पर, मुद्रास्फीति दर 1.3 प्रतिशत से 7.3 प्रतिशत के बीच रही। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.36)।

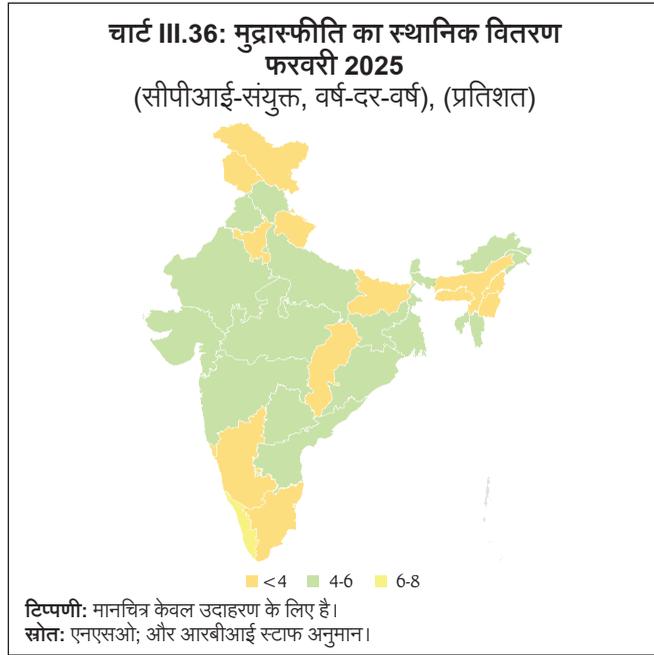
<sup>17</sup> राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 मार्च, 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।



मार्च के लिए अब तक (17 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा चावल और गेहूं दोनों के लिए अनाज की कीमतों में वृद्धि दिखाते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में भी मजबूती आई है - मुख्य रूप से पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से। दूसरी

ओर, दालों की कीमतों में व्यापक आधार पर नरमी जारी रही। आलू, प्याज और टमाटर सहित प्रमुख सब्जियों की कीमतों में और सुधार देखा गया (चार्ट III.37)।





मार्च में अब तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं (17 तारीख तक) जबकि केरोसिन की कीमतों में कमी आई (सारणी III.2)।

### सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जन-25	फर-25	मार्च-25 <sup>^</sup>	फर-25	मार्च-25 <sup>^</sup>
पेट्रोल	₹/लीटर	101.02	101.02	101.02	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.48	90.48	90.48	0.0	0.0
केरोसीन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	43.93	46.37	46.23	5.6	-0.3
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.25	813.25	813.25	0.0	0.0

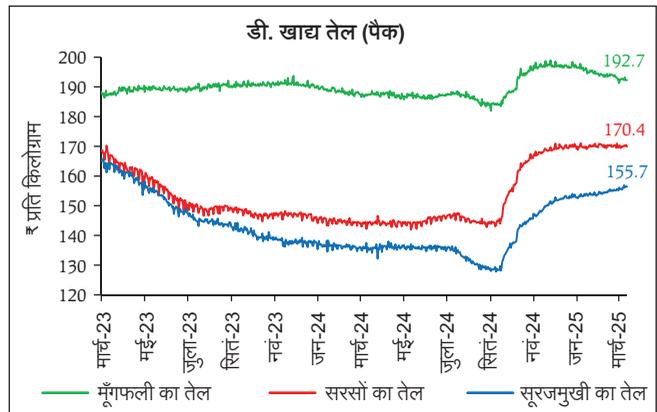
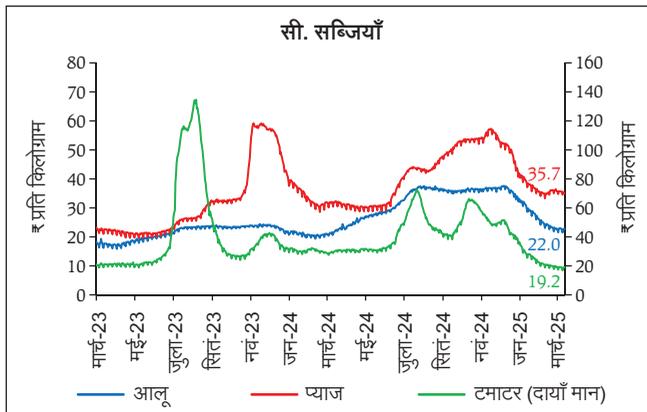
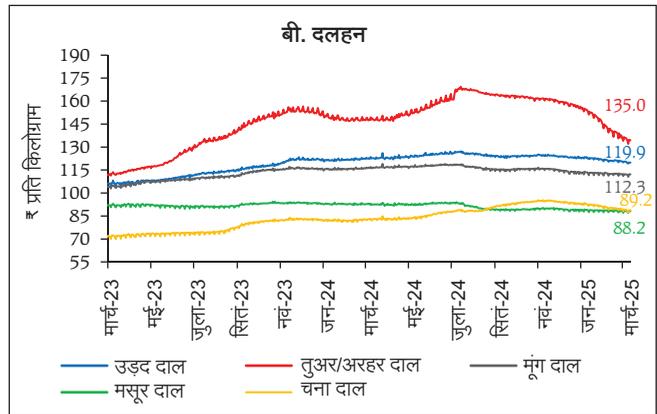
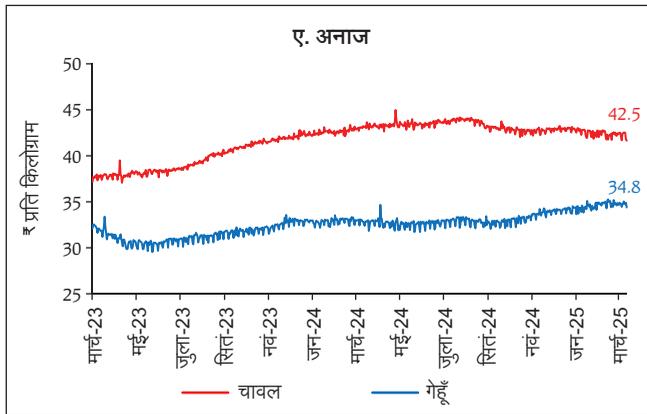
**टिप्पणी:** 1. <sup>^</sup>: 1-17 मार्च, 2025 की अवधि के लिए।

2. केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों का औसत दर्शाती हैं।

**स्रोत:** आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

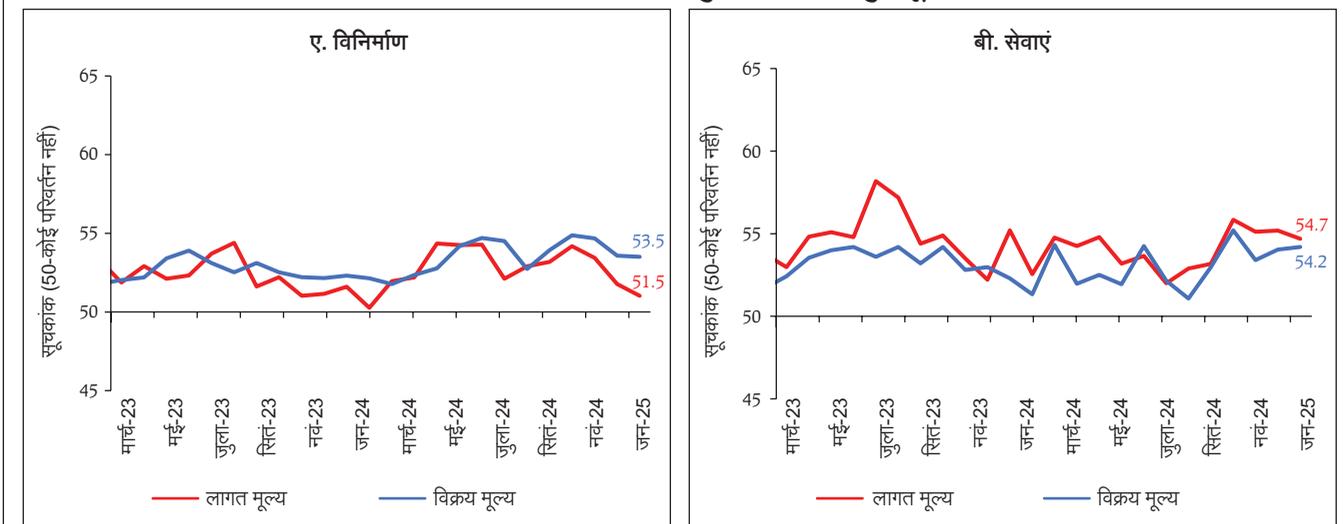
पीएमआई के अनुसार, फरवरी में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए इनपुट लागत में वृद्धि की दर धीमी रही। दूसरी ओर,

### चार्ट III.37: डीसीए आवश्यक वस्तु मूल्य



**स्रोत:** उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

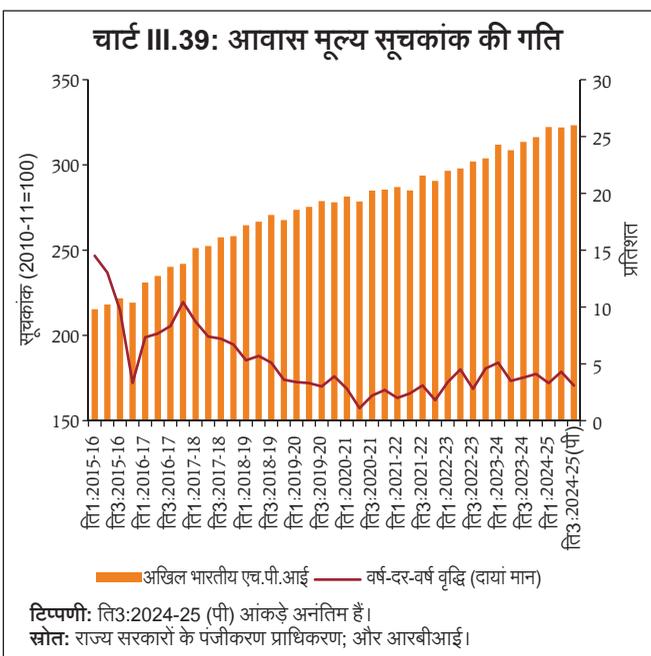
**चार्ट III.38: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट मूल्य**



**टिप्पणी:** 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने को दर्शाता है तथा 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।  
**स्रोत:** एस एंड पी।

विनिर्माण फर्मों में बिक्री मूल्य दबाव मामूली रूप से कम हुआ, लेकिन सेवा फर्मों के लिए बढ़ा (चार्ट III.38)।

दस प्रमुख शहरों से संपत्ति पंजीकरण डेटा के आधार पर अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जबकि पिछली तिमाही में यह 4.3 प्रतिशत और एक वर्ष पहले 3.8 प्रतिशत थी (चार्ट III.39)।



**टिप्पणी:** ति3:2024-25 (पी) आंकड़े अनंतिम हैं।  
**स्रोत:** राज्य सरकारों के पंजीकरण प्राधिकरण; और आरबीआई।

#### IV. वित्तीय स्थिति

प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में मौसमी तेजी के बीच फरवरी के उत्तरार्ध और मार्च की शुरुआत (13 मार्च, 2025 तक) में सिस्टम चलनिधि घाटे में रही। फरवरी के मध्य से, रिजर्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए ₹1.4 लाख करोड़ की संचयी राशि की तीन ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) खरीद नीलामी (20 फरवरी, 12 मार्च और 18 मार्च 2025 को) और 21 फरवरी 2025 को ₹57,951 करोड़ की 45-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी 2025 को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की तीन वर्षीय यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी के माध्यम से रुपये की चलनिधि अंतर्वेशित की गई। अब तक की तिमाही के दौरान, रिजर्व बैंक ने ओएमओ खरीदों, लंबी अवधि की वीआरआर नीलामी और विदेशी मुद्रा विनिमय स्वैप के संयोजन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹5.5 लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित की है (सारणी IV.1)।

इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक चलनिधि की क्षणिक तंगी से निपटने के लिए 16 जनवरी से दैनिक वीआरआर नीलामी आयोजित कर रहा है, जिसमें स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को इन दैनिक नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। 16 फरवरी से 17 मार्च 2025 के दौरान 1 से 8 दिनों

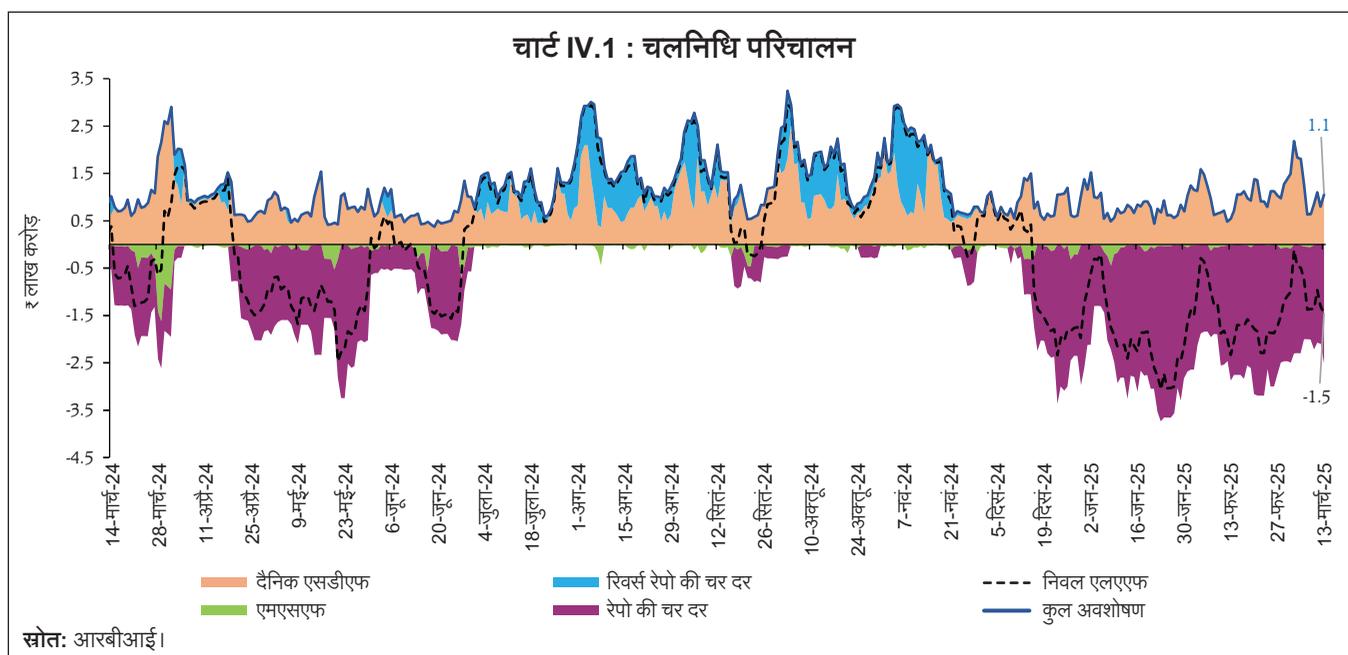
## सारणी IV.1: 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान टिकाऊ चलनिधि उपाय

उपाय	विवरण	नीलामी की तारीख	अंतर्वेशित राशि (₹ करोड़ में)
ओएमओ खरीद	एनडीएस-ओएम के माध्यम से	जनवरी 2025	38.825
ओएमओ खरीद नीलामी		जनवरी 30, 2025	20.020
		फरवरी 13, 2025	40.000
		फरवरी 20, 2025	40.000
		मार्च 12, 2025	50.000
		मार्च 18, 2025	50.000
मीयादी रेपो नीलामी	56-दिवसीय वीआरआर नीलामी	फरवरी 07, 2025	50.010
	49-दिवसीय वीआरआर नीलामी	फरवरी 14, 2025	75.003
	45-दिवसीय वीआरआर नीलामी	फरवरी 21, 2025	57.951
यूएसडी/आईएनआर खरीद बिक्री स्वैप नीलामी	अवधि: 6 महीने	जनवरी 31, 2025	लगभग. 44.000 (यूएसडी 5.10 बिलियन)
	अवधि: 3 वर्ष	फरवरी 28, 2025	लगभग. 88.000 (यूएसडी 10.06 बिलियन)
		<b>कुल</b>	<b>लगभग. 5,53,809</b>

स्रोत: आरबीआई।

तक की परिपक्वता अवधि के दो मुख्य और 22 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर आयोजन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 9.68 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि अंतर्वेशित की गई। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए इन उपायों से चलनिधि घाटे को कम करने में सहायता मिली। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अंतर्वेशन 16 फरवरी से 13 मार्च 2025 के दौरान 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 16 जनवरी से 15 फरवरी 2025 के दौरान यह 1.92 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.1)।

प्रचलित चलनिधि घाटे के बावजूद, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत बैंकों का धन-स्थानन 16 फरवरी 2025 और 13 मार्च 2025 के बीच औसतन 1.15 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले महीने में 0.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। एसडीएफ के तहत चलनिधि घाटे की स्थिति और पर्याप्त धन-स्थानन का सह-अस्तित्व बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता के असममित वितरण के साथ-साथ बैंकों की ओर से बढ़ी हुई तरलता वरीयता का संकेत देता है। इस बीच, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)



के तहत दैनिक औसत उधार 16 फरवरी 2025 और 13 मार्च 2025 के दौरान मामूली रूप से घटकर 0.03 लाख करोड़ रुपये रह गया, जो पिछली अवधि में 0.04 लाख करोड़ रुपये था।

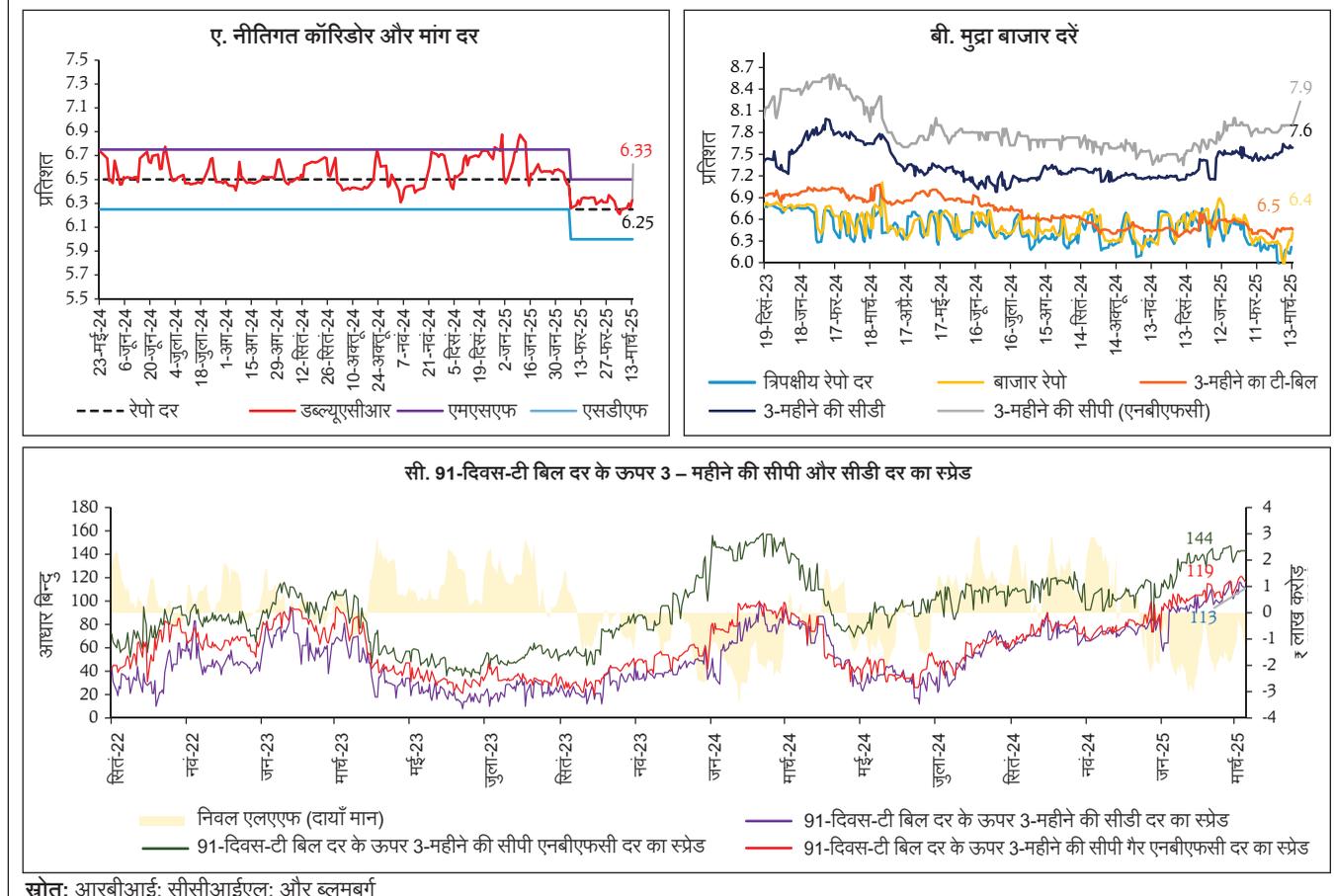
भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - नीतिगत कॉरिडोर के भीतर रही और 16 फरवरी और 13 मार्च 2025 के दौरान डब्ल्यूएसीआर का नीतिगत रेपो दर पर औसत प्रसार 5 आधार अंक (bps) रहा, जो 16 जनवरी से 15 फरवरी, 2025 के जैसा ही था (चार्ट IV.2ए)। हालाँकि, चलनिधि की स्थिति में सुधार के बीच, संपार्श्विक खंड में दरें, नीतिगत रेपो दर से नीचे रहीं।

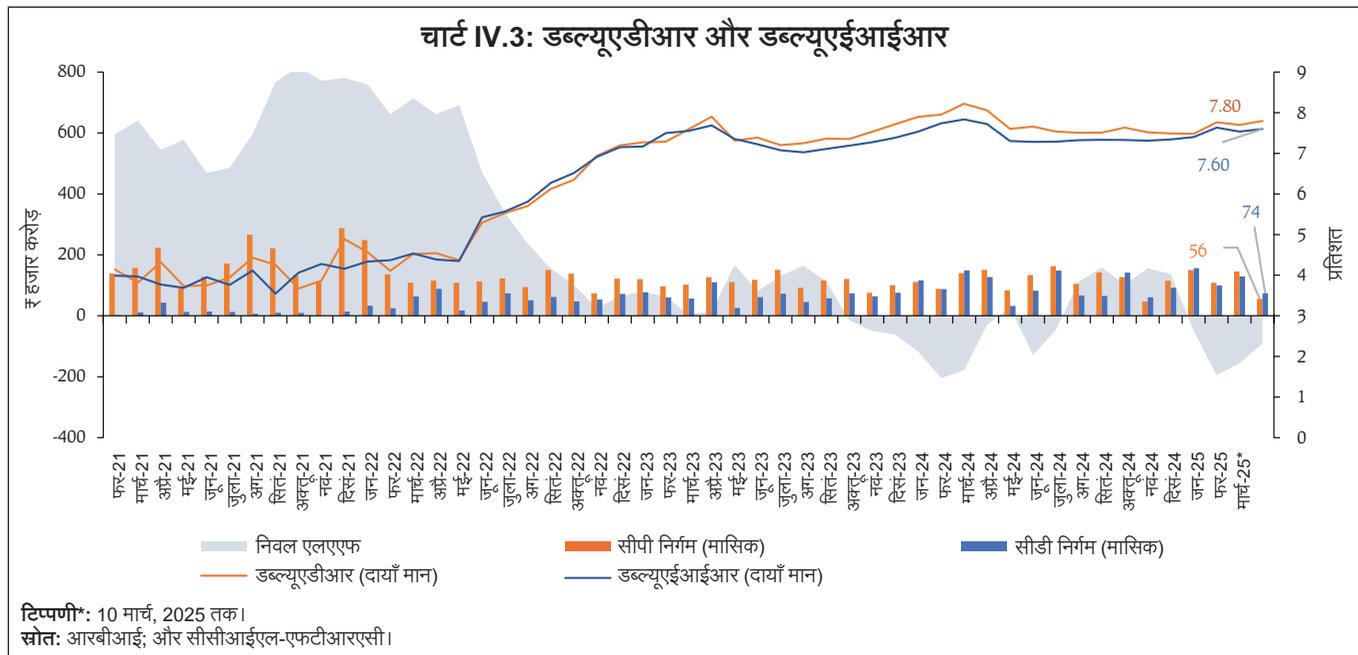
समूचे मीयादी मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा

जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पेपर (सीपी) पर प्रतिफल के साथ दरों में गिरावट आई है, जो पिछले महीने की तुलना में 16 फरवरी - 13 मार्च 2025 के दौरान कम हुई है (चार्ट IV.2 बी)। हालांकि, इसी अवधि के दौरान जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर प्रतिफल 7.49 प्रतिशत से बढ़कर 7.52 प्रतिशत हो गई। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने की सीपी [एनबीएफसी] माइनस 91-दिवसीय टी-बिल) 18 जनवरी - 14 फरवरी 2025 के 137 बीपीएस से बढ़कर 16 फरवरी - 13 मार्च 2025 के दौरान 142 बीपीएस हो गया।

सीपी की भारित औसत छूट दर (डब्ल्यूएडीआर) और सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डब्ल्यूईआईआर) एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों से कम रही (चार्ट IV.3)।

**चार्ट IV.2: नीति कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दर**

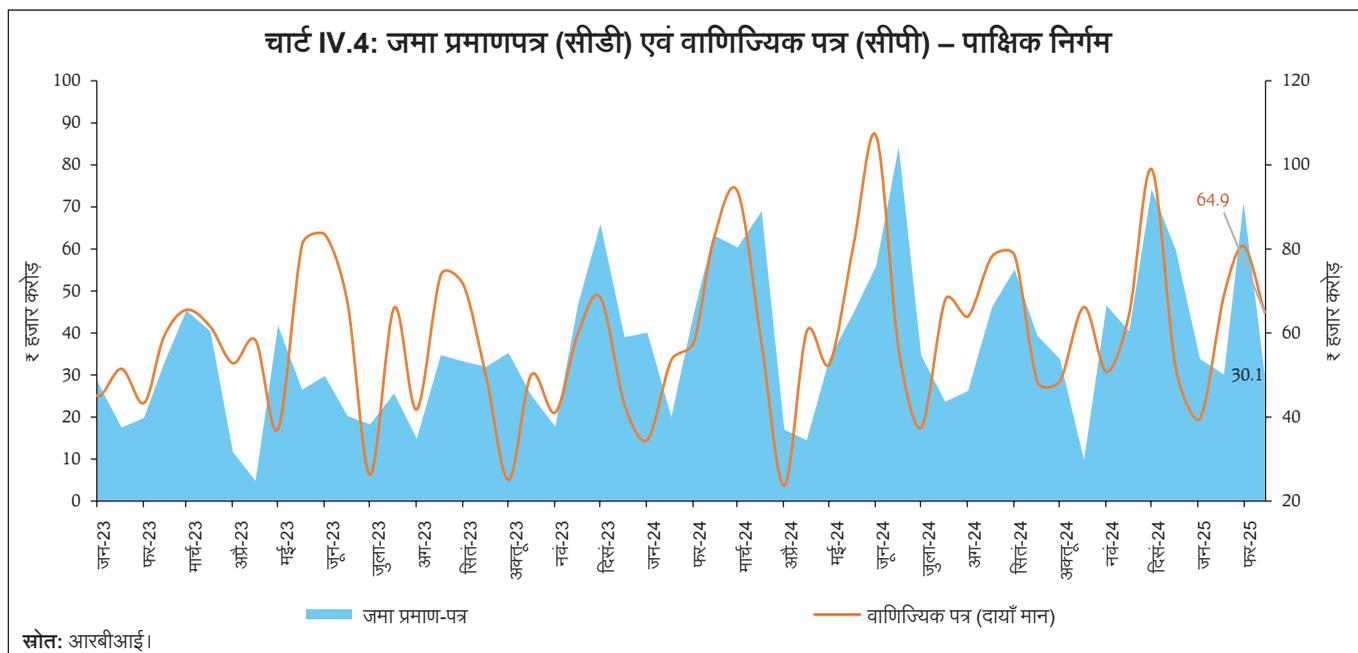


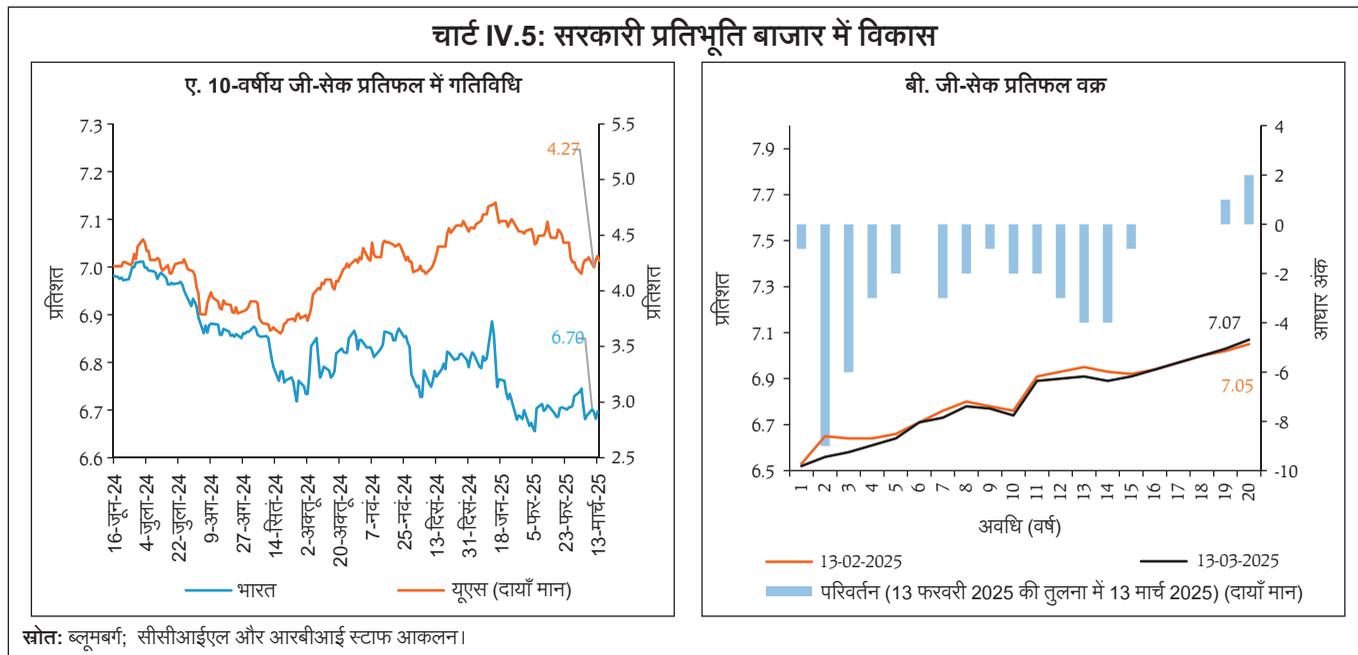


ऋण और जमा वृद्धि में निरंतर अंतर के कारण, बैंक अपनी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीडी पर निर्भर बने हुए हैं। प्राथमिक बाजार में, सीडी निर्गम 2024-25 (7 मार्च 2025 तक) के दौरान 34 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹10.58 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया [चार्ट IV.4]। इसी प्रकार, 2024-25 (28 फरवरी 2025 तक) के

दौरान सीपी निर्गम ₹13.90 लाख करोड़ रहा, जो एक वर्ष पूर्व की इसी अवधि की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है।

10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बेंचमार्क पर प्रतिफल व्यापक स्तर पर सीमित दायरे में रहा और 14 फरवरी 2025 के 6.71 प्रतिशत की तुलना में 13 मार्च 2025 को 6.70 प्रतिशत

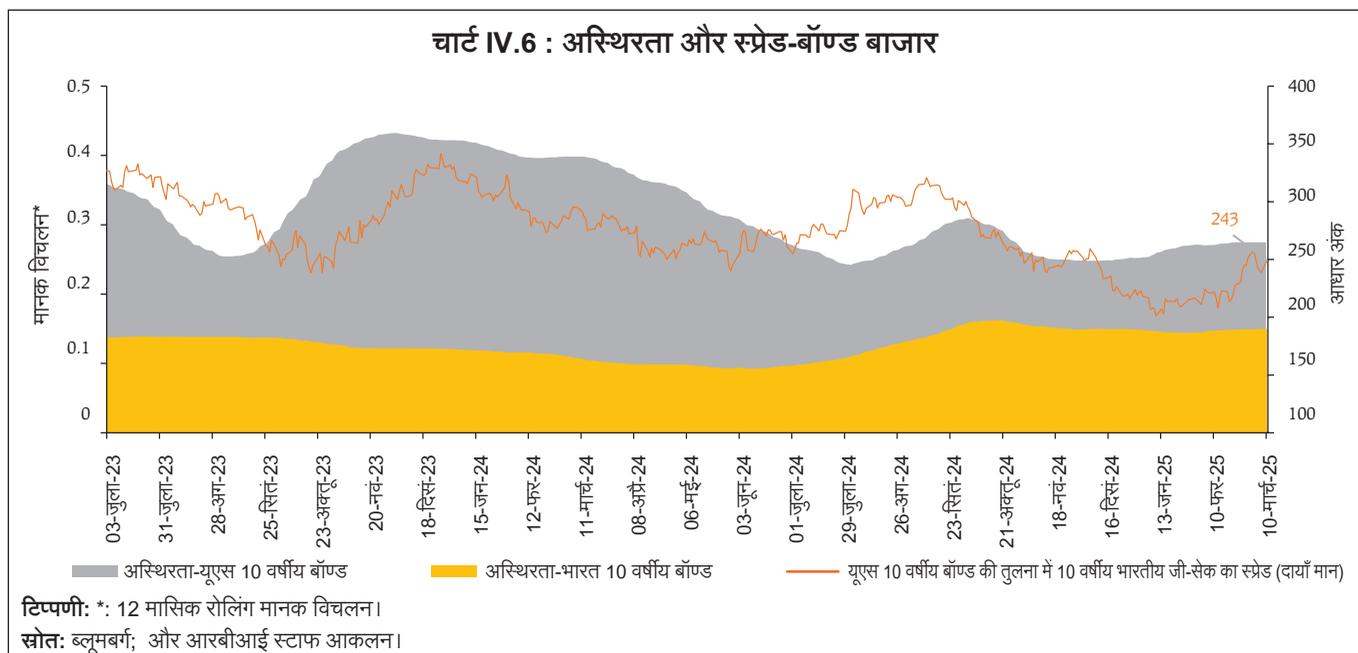




रहा (चार्ट IV.5ए)। घरेलू प्रतिफल वक्र अति लघु और मध्यम अवधि-खंडों में नरम हुआ, जबकि अन्य सभी अवधियों के लिए यह स्थिर रहा (चार्ट IV.5बी)। 16 फरवरी और 13 मार्च 2025 के बीच, औसत अवधि प्रसार (10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल माइनस 91-दिवसीय टी-बिल प्रतिफल) में पिछली अवधि की तुलना में 8 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

फरवरी के उत्तरार्ध में, 10-वर्षीय भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल का 10-वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड पर प्रसार बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट थी। अमेरिकी ट्रेजरी की तुलना में भारत में प्रतिफल की अस्थिरता कम रही (चार्ट IV.6)।

2024-25 (जनवरी तक) के दौरान ₹7.94 लाख करोड़ के कॉरपोरेट बॉण्ड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.0



## सारणी IV.2: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	जन 16, 2025 – फर 15, 2025	फर 16, 2025 – मार्च 12, 2025	विभिन्नता	जन 16, 2025 – फर 15, 2025	फर 16, 2025 – मार्च 12, 2025	विभिन्नता
	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
<b>कॉरपोरेट बॉण्ड</b>						
(i) एएए (1 वर्ष)	7.87	7.86	-1	116	122	6
(ii) एएए (3 वर्षीय)	7.64	7.67	3	90	97	7
(iii) एएए (5 वर्षीय)	7.50	7.62	12	73	85	12
(iv) एए (3 वर्षीय)	8.43	8.44	1	169	175	6
(v) बीबीबी- (3 वर्ष)	12.10	12.09	-1	536	540	4

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के लिए औसत के रूप में की जाती है।

स्रोत: एफआईएमएमडीए; और ब्लूमबर्ग।

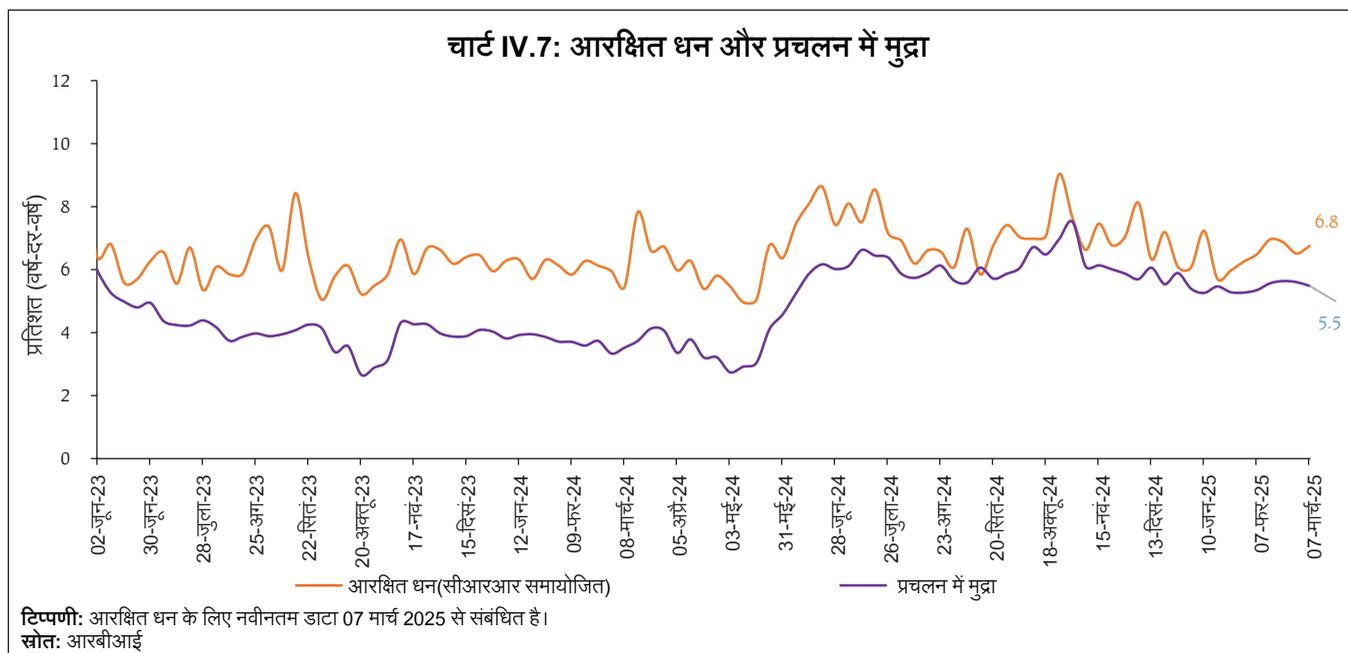
प्रतिशत अधिक थे। कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में मिश्रित रुझान देखने को मिले, जबकि फरवरी के उत्तरार्ध से 12 मार्च 2025 तक सभी रेटिंग और अवधि-स्पेक्ट्रम में संबंधित जोखिम प्रीमियम में वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

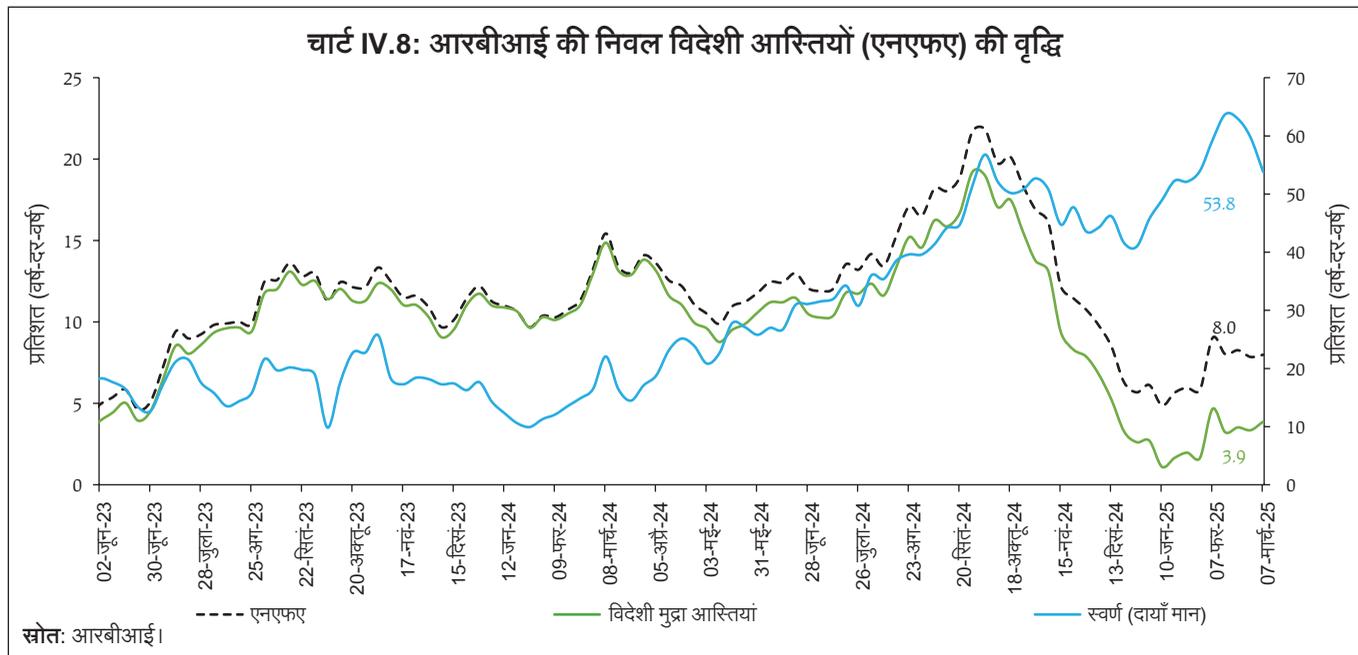
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में बदलाव के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 7 मार्च 2025 तक 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पूर्व 5.5 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। आरक्षित मुद्रा के सबसे बड़े घटक, सीआईसी में 7 मार्च 2025 तक 5.5

प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि रही, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 3.5 प्रतिशत थी।

स्रोत पक्ष (परिसंपत्तियाँ) पर, आरक्षित मुद्रा में रिजर्व बैंक की निवल घरेलू परिसंपत्तियाँ (एनडीए) और निवल विदेशी परिसंपत्तियाँ (एनएफए) शामिल हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में जनवरी 2025 की समाप्ति के 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़कर 7 मार्च 2025 को 3.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट IV.8)। स्वर्ण- एनएफए का एक अन्य प्रमुख घटक - मुख्य रूप से सोने की कीमतों में पुनर्मूल्यांकन लाभ के कारण 53.8 प्रतिशत

चार्ट IV.7: आरक्षित धन और प्रचलन में मुद्रा

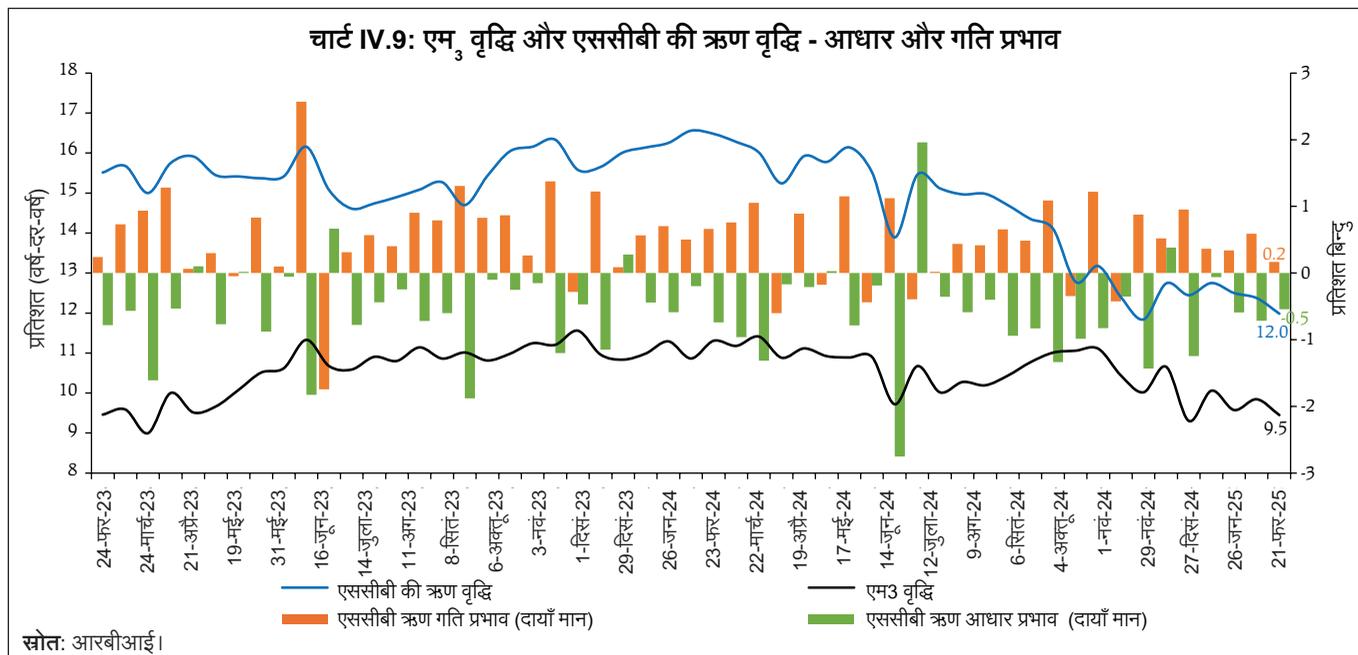




बढ़ा, जिससे एनएफए में इसकी हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत के 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 7 मार्च 2025 तक 11.7 प्रतिशत हो गई।

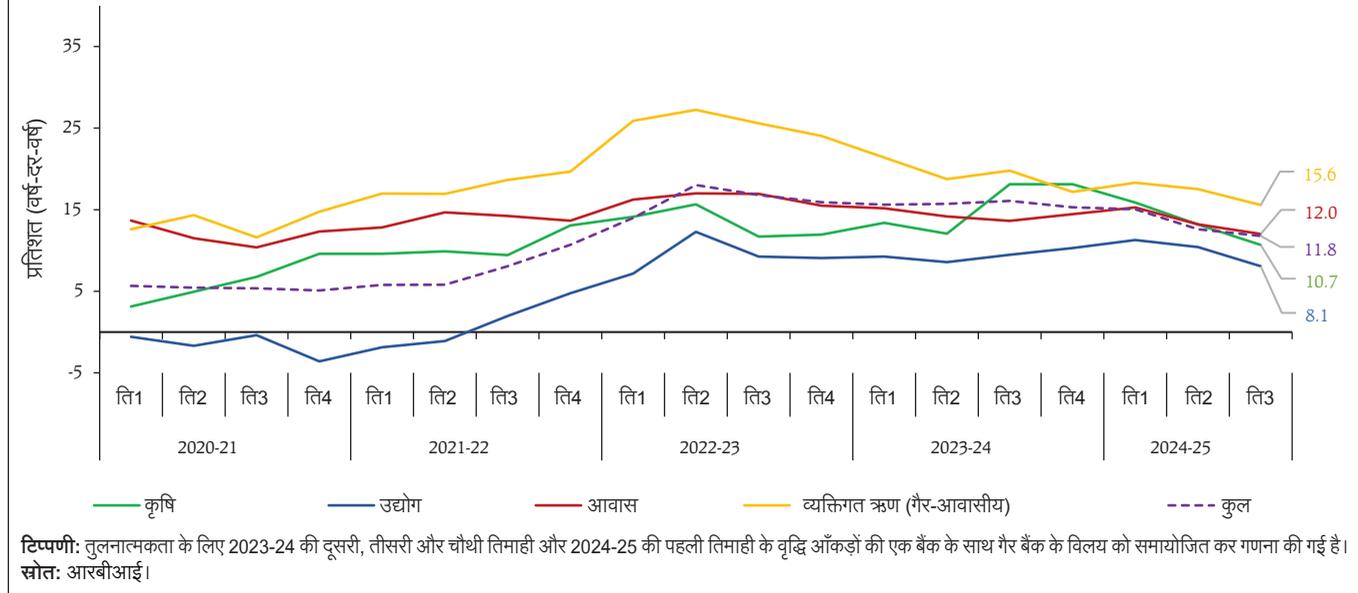
21 फरवरी 2025 तक, मुद्रा आपूर्ति (एम<sub>3</sub>) में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 10.9 प्रतिशत)।<sup>18</sup> बैंकों के पास कुल जमा (जो एम<sub>3</sub> का लगभग 86 प्रतिशत है) में 10.1

प्रतिशत की वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 11.9 प्रतिशत)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण 21 फरवरी 2025 तक 12.0 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 16.6 प्रतिशत) तक कम हो गई, जो आंशिक रूप से सकारात्मक गति से संतुलित हुई (चार्ट IV.9)।



<sup>18</sup> किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई 2023 से लागू)

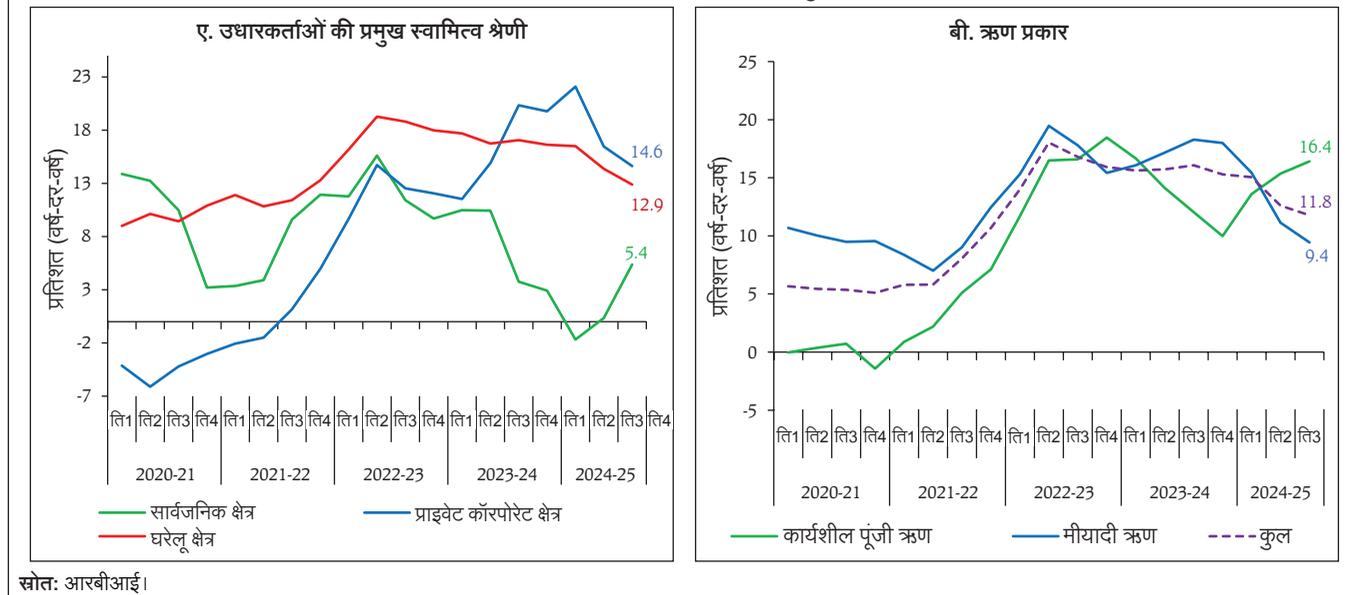
**चार्ट IV.10: बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि - प्रमुख क्षेत्र**

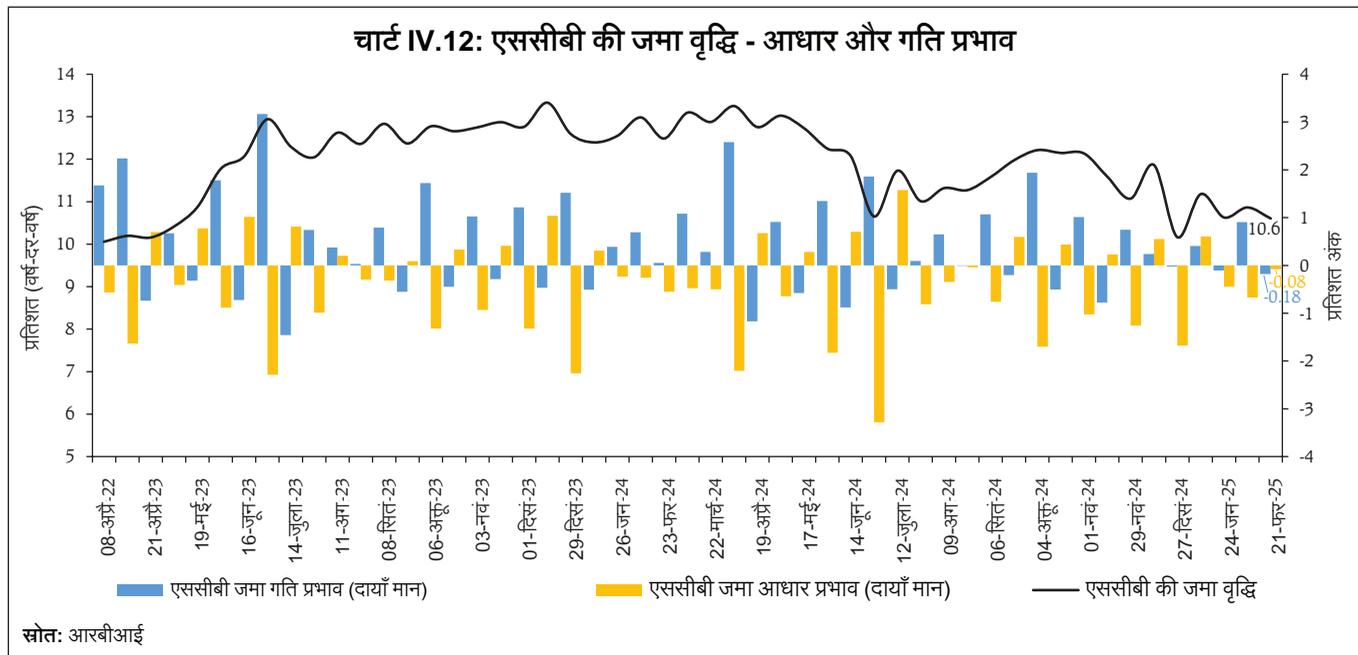


नवीनतम उपलब्ध तिमाही आंकड़ों के आधार पर, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हालिया मंदी के बावजूद, ऋण में अच्छी गति से वृद्धि जारी है (चार्ट IV.10)। नवंबर 2023 में घोषित जोखिम भार में वृद्धि के बाद असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण खंड में कमी आने के बावजूद भी व्यक्तिगत ऋण खंड में ऋण वृद्धि समग्र ऋण विस्तार की अग्रणी चालक रही।

निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को एससीबी द्वारा दिए गए ऋण (जो कुल बैंक ऋण का लगभग एक-चौथाई हिस्सा था), 2024-25 की तीसरी तिमाही में कम हुआ। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को दिए गए ऋण में वृद्धि जारी रही (चार्ट IV.11ए)। कार्यशील पूँजी ऋणों में वृद्धि में तेजी आई, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है (चार्ट IV.11बी)।

**चार्ट IV.11: वार्षिक ऋण वृद्धि**



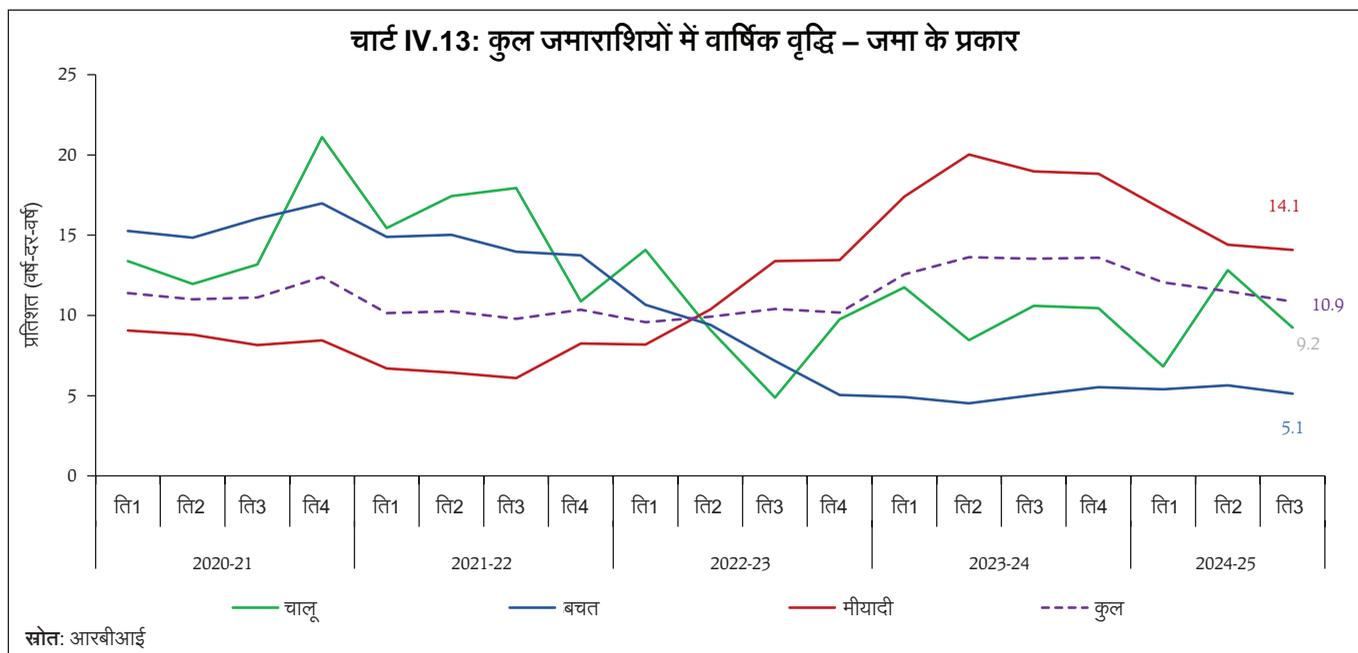


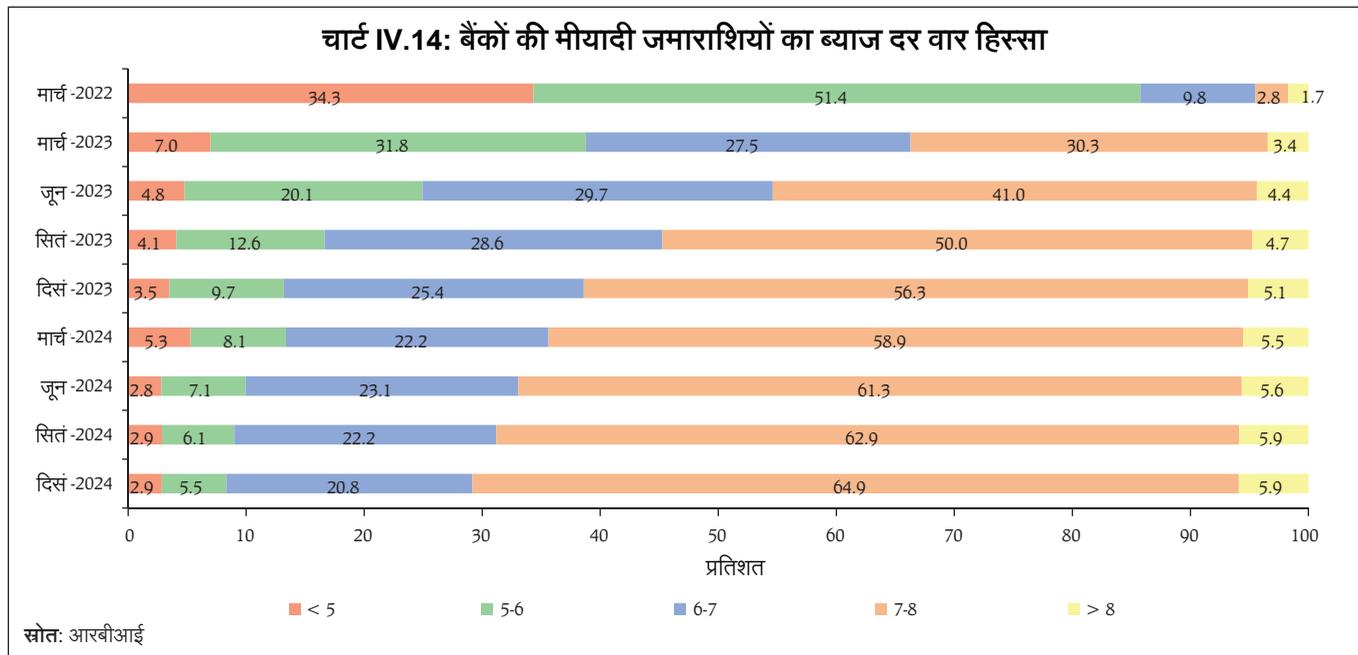
21 फरवरी 2025 तक, एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) जनवरी 2025 के अंत के 10.6 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही (चार्ट IV.12)।

2024-25 की तीसरी तिमाही में सावधि जमाओं की वृद्धि बचत जमाओं की वृद्धि से आगे निकलती रही (चार्ट IV.13)। परिणामस्वरूप, कुल जमाओं में सावधि जमाओं का हिस्सा

एक वर्ष पूर्व के 60.3 प्रतिशत से बढ़कर 62.1 प्रतिशत हो गया।

7 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज दर वाली जमाओं का हिस्सा (कुल सावधि जमाओं में) दिसंबर 2023 के 61.4 प्रतिशत और मार्च 2023 के 33.7 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2024 में 70.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.14)।

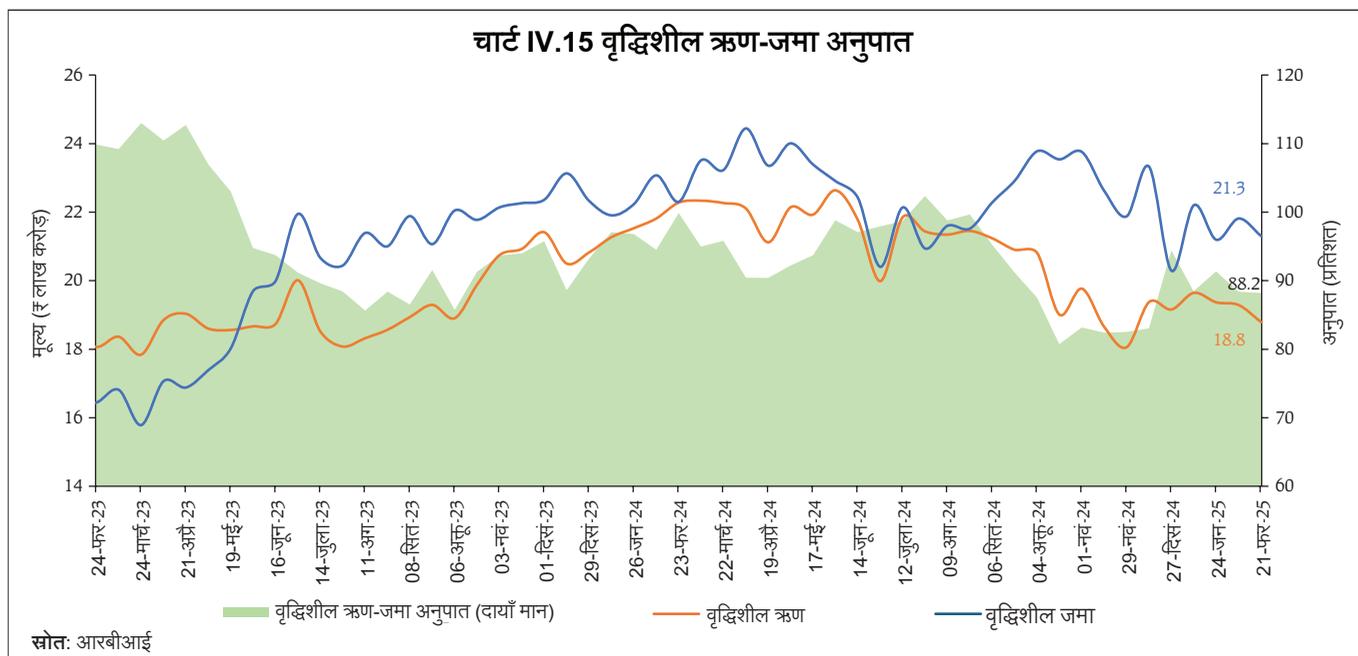


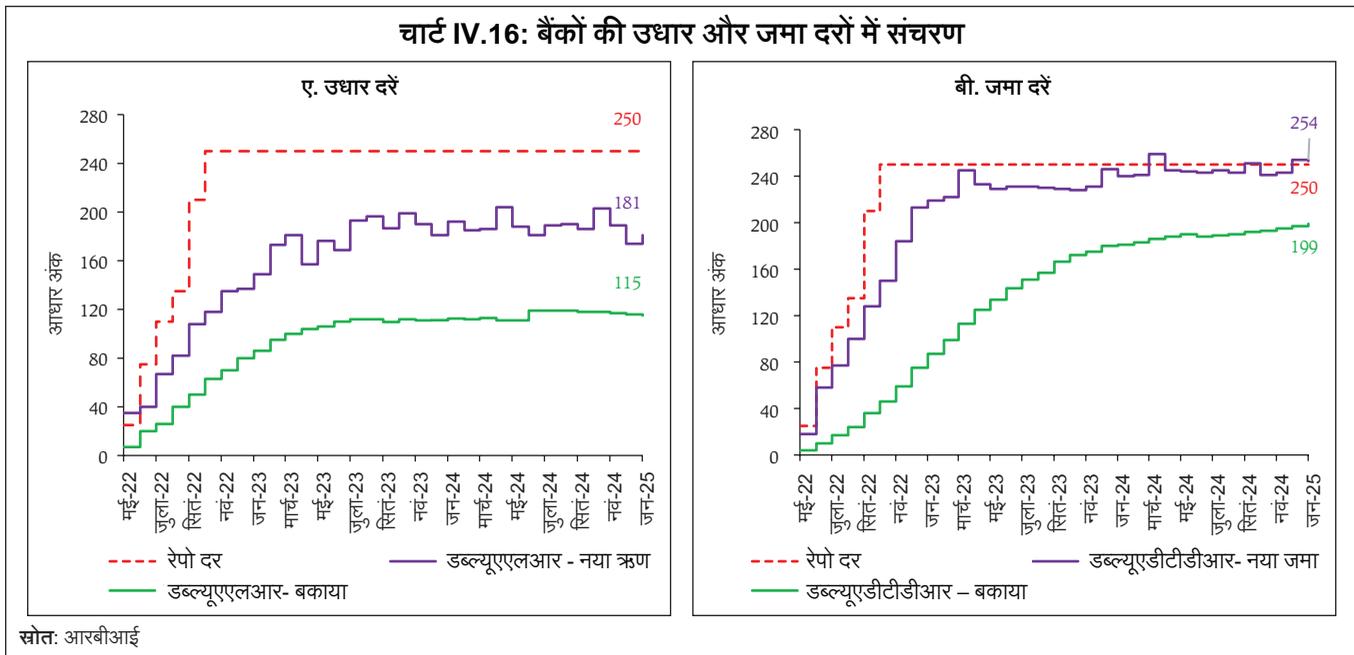


एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात अक्टूबर 2024 के अंत में 80.7 प्रतिशत से बढ़कर 21 फरवरी 2025 तक 88.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.15)।

फरवरी पॉलिसी के दौरान पॉलिसी रेपो दर में 25-बीपीएस की कटौती के जवाब में, बैंकों ने अपनी रेपो-लिंकड एक्सटर्नल बेंचमार्क-आधारित उधार दरों (ईबीएलआर) को समान परिमाण

से कम कर दिया है। एससीबी की 1-वर्षीय सीमांत लागत-आधारित उधार दरों (एमसीएलआर) में मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 178 बीपीएस की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 181 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.16ए)। जमा के मामले में, एससीबी की नई जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर),



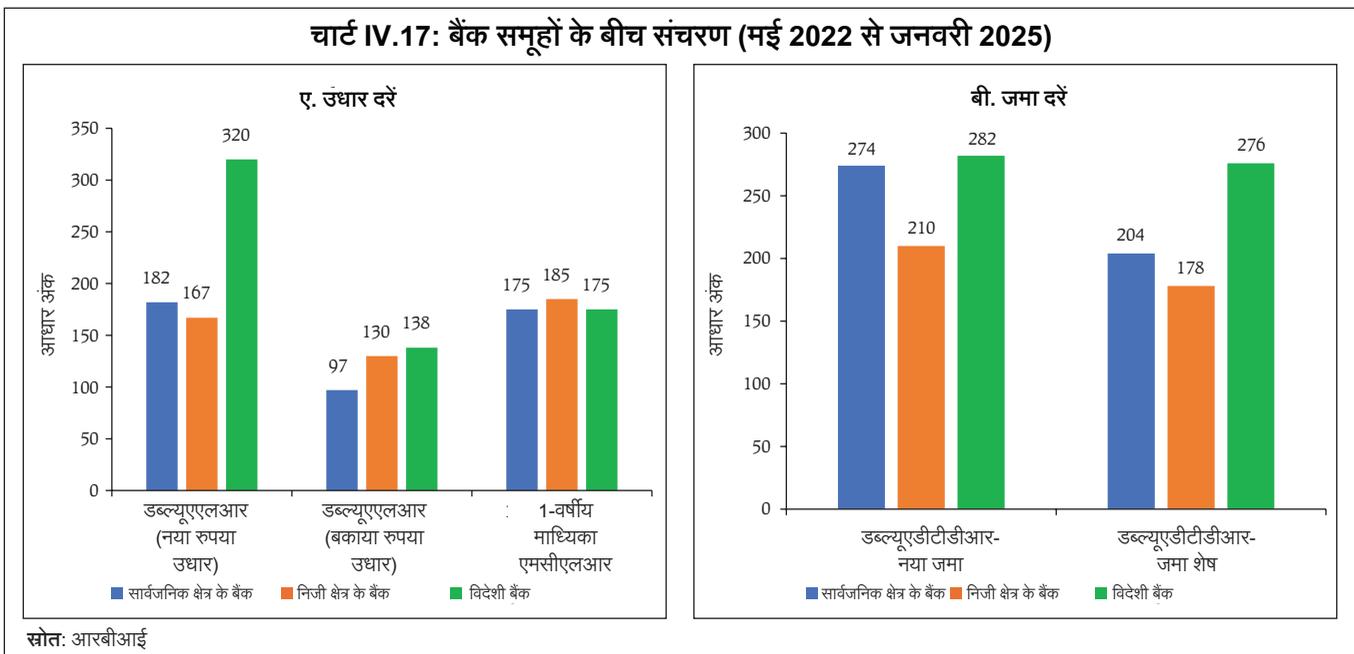


जिसमें खुदरा और थोक जमा दोनों शामिल हैं, में 253 बीपीएस की वृद्धि हुई। बकाया जमा पर डब्ल्यूएडीटीडीआर भी मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान 199 बीपीएस बढ़ गई (चार्ट IV.16बी)।

बैंक समूहों में संचरण से संकेत मिलता है कि नए रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में अधिक थी।

हालाँकि, बकाया रुपया ऋणों के मामले में, पीएसबी में संचरण कम था। दूसरी ओर, मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान पीएसबी के लिए जमा दरों में संचरण अधिक था (चार्ट IV.17ए और बी)।

2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान सुस्त प्रदर्शन के बाद, कॉर्पोरेट क्षेत्र में तीसरी तिमाही के दौरान सुधार के संकेत दिखाई दिए। 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध

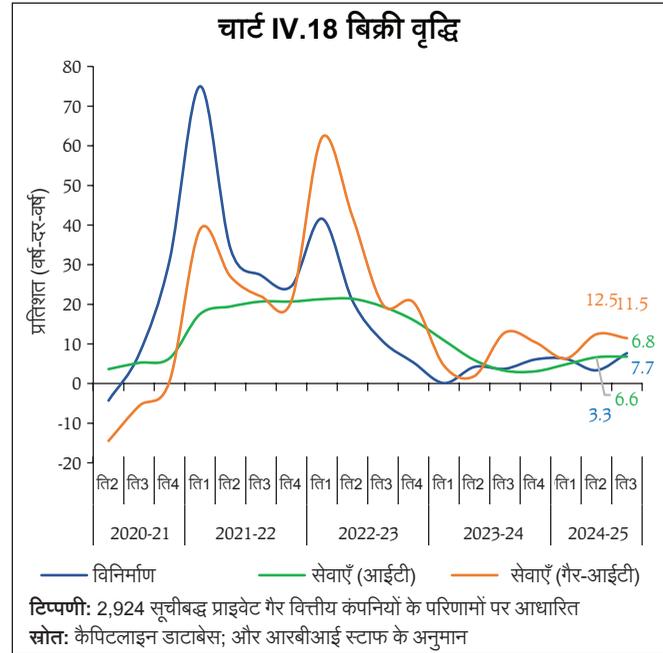


निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री 8.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी, जो पिछली तिमाही के 5.4 प्रतिशत और एक वर्ष पहले की इसी तिमाही के 5.5 प्रतिशत से बेहतर है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में सुधार हुआ (चार्ट IV.18)। वृद्धि में यह बदलाव मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन, खाद्य उत्पाद और विद्युत मशीनरी उद्योगों में बढ़ी बिक्री के कारण हुआ, जबकि पेट्रोलियम, लोहा एवं इस्पात, और सीमेंट उद्योगों की बिक्री में तीसरी तिमाही के दौरान वार्षिक आधार पर गिरावट जारी रही, हालाँकि गिरावट की गति धीमी रही (चार्ट IV.19)।

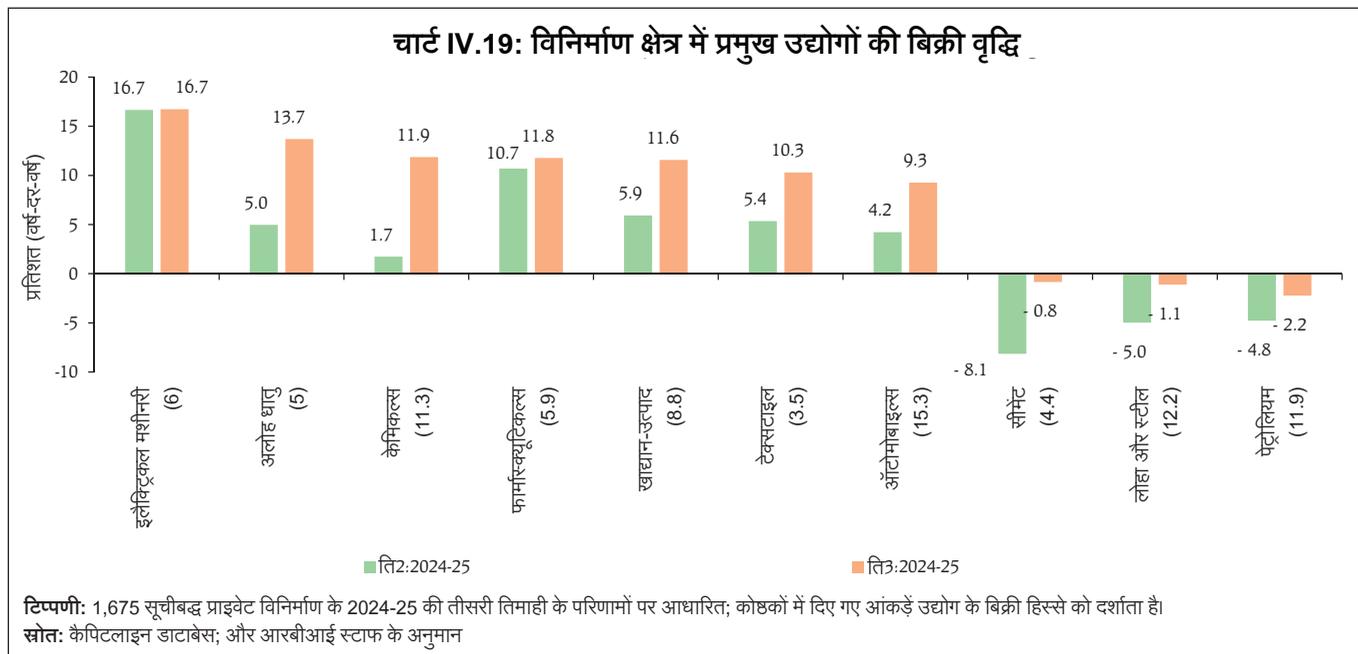
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र ने पिछली तिमाही और एक साल पहले की तुलना में बेहतर बिक्री वृद्धि दर्ज की। गैर-आईटी सेवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि में मंदी के बावजूद दोहरे अंकों में वृद्धि जारी रही। यह वृद्धि मुख्य रूप से 'थोक और खुदरा व्यापार' और 'परिवहन एवं भंडारण सेवाएँ' क्षेत्रों द्वारा संचालित रही।

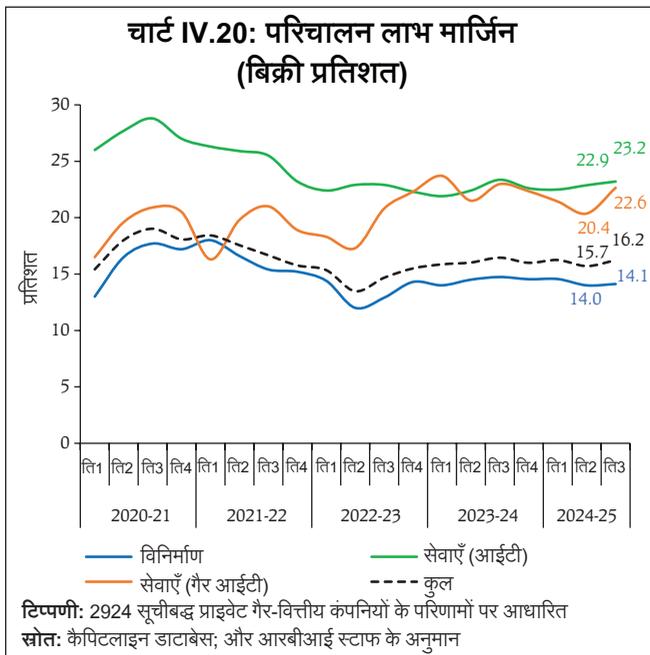
परिचालन व्यय में बिक्री की तुलना में धीमी वृद्धि के साथ, 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान परिचालन लाभ में समग्र



स्तर पर वृद्धि हुई, जिससे परिचालन लाभ मार्जिन में 50 बीपीएस का क्रमिक सुधार हुआ। तिमाही के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में मार्जिन में सुधार हुआ, जो उनकी बेहतर बिक्री वृद्धि के अनुरूप था (चार्ट IV.20)।

फरवरी के उत्तरार्ध और मार्च के प्रारंभ में भारतीय इक्विटी बाजारों पर दबाव जारी रहा, जिसका कारण विदेशी संस्थागत



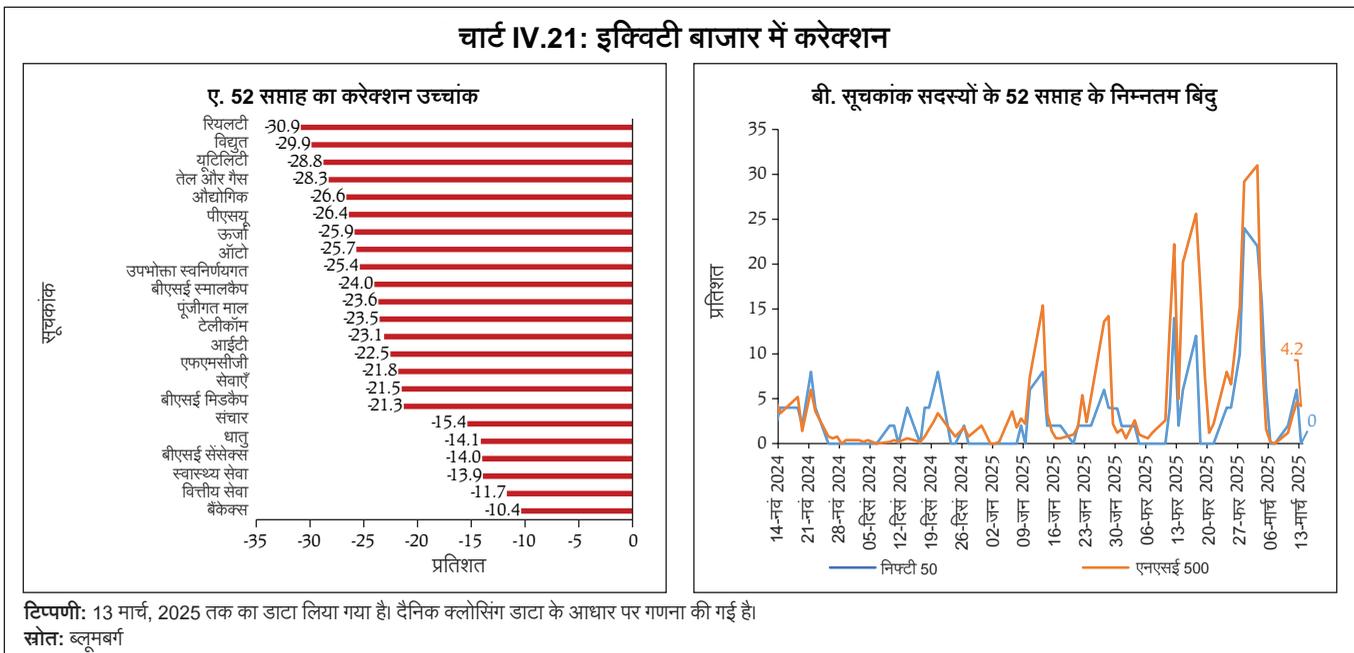


महीनों में इक्विटी बाजार में व्यापक आधार पर करेक्शन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय सूचकांकों में गिरावट आई है (चार्ट IV.21ए)। व्यापक बाजार सूचकांकों में तेज गिरावट हुई है, जो कि हाल की अवधि में उनके घटकों के उच्च अनुपात में 52-सप्ताह के निचले स्तर तक पहुँचने से परिलक्षित होता है और विशेष रूप से, 3 मार्च 2025 को एनएसई 500 सूचकांक के घटक सदस्यों का 31 प्रतिशत, निफ्टी 50 सदस्यों के 22 प्रतिशत के मुकाबले 52-सप्ताह के नए निचले स्तर पर पहुँच गया (चार्ट IV.21बी)।

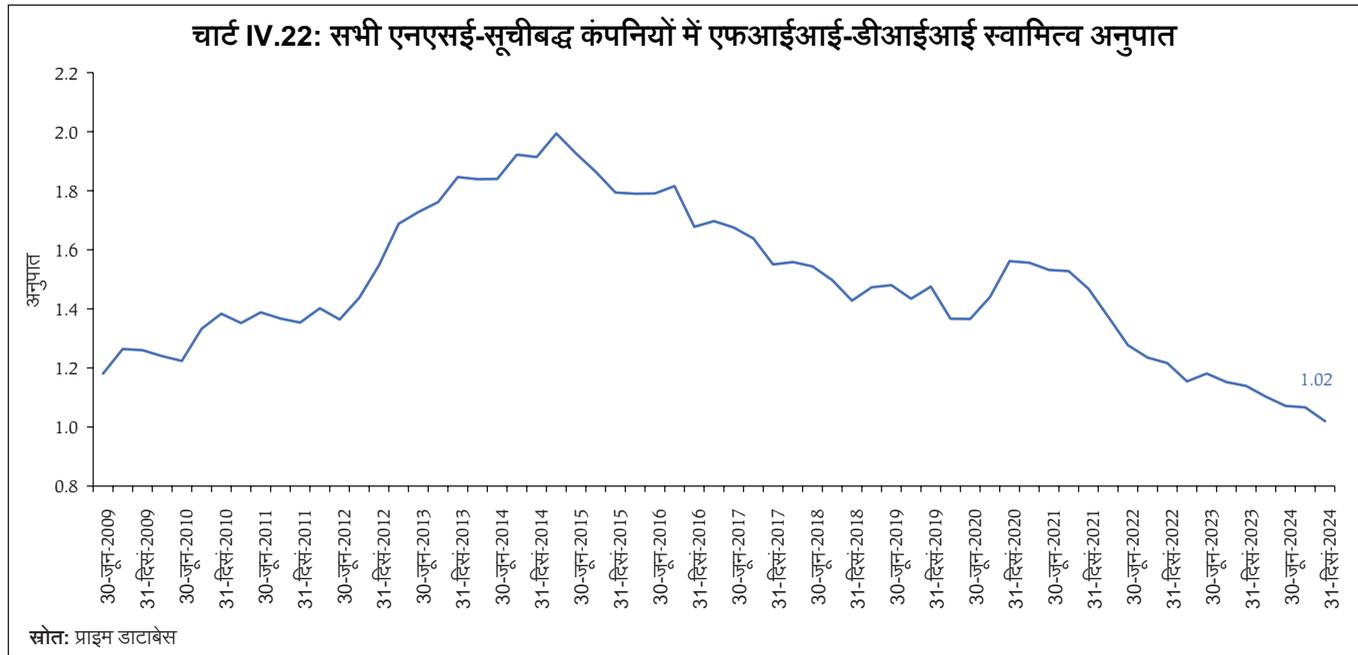
प्राइम डेटाबेस के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिक्री के कारण दिसंबर 2024 के अंत तक एनएसई-सूचीबद्ध कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी घटकर 17.2 प्रतिशत रह गई है, जो कई वर्षों का निचला स्तर है। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिससे एफआईआई-से-डीआईआई स्वामित्व अनुपात जून 2009 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है (चार्ट IV.22)।<sup>19</sup>

हाल ही में बाजार में हुए सुधार और इक्विटी डेरिवेटिव खंड में विनियामक उपायों के कारण हाल के महीनों में इक्विटी

निवेशकों (एफआईआई) द्वारा लगातार बिक्री, अमेरिकी सरकार की टैरिफ नीतियों को लेकर अनिश्चितता और मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच कॉरपोरेट आय को लेकर चिंताएं रहीं। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 14 फरवरी 2025 से 2.3 प्रतिशत गिरकर 17 मार्च 2025 को 74,170 पर बंद हुआ। हाल के

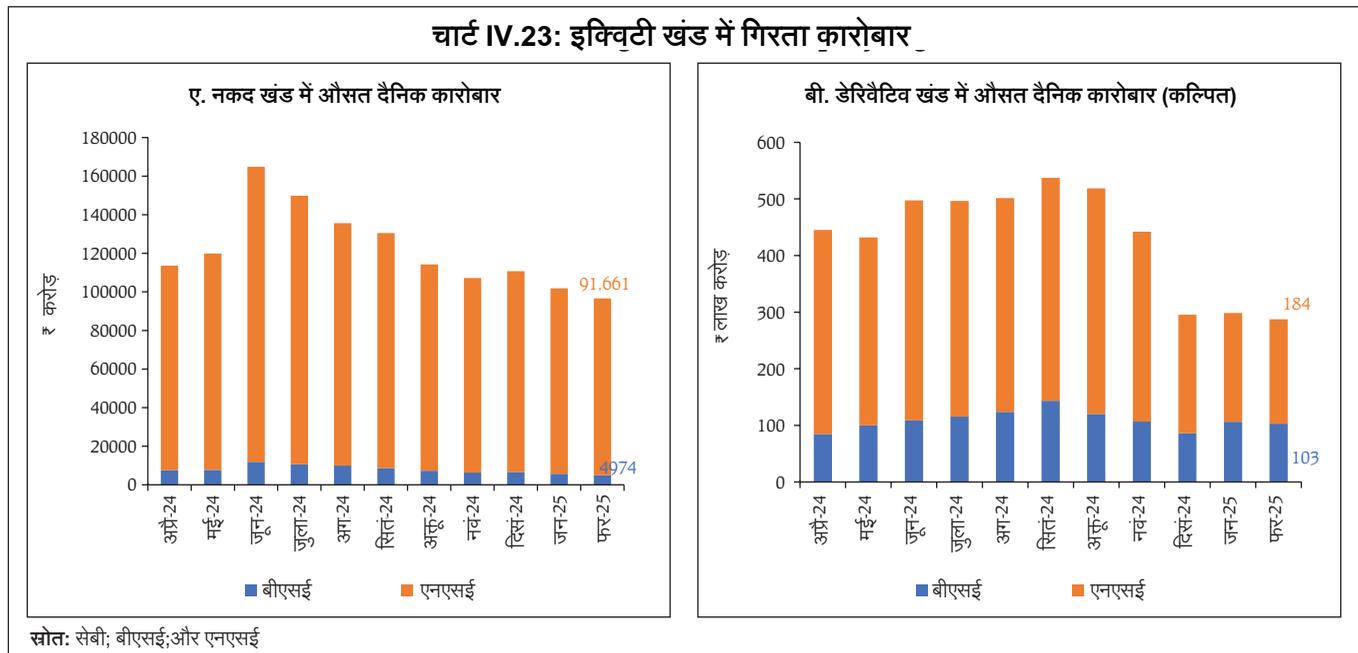


<sup>19</sup> [https://www.business-standard.com/markets/stock-market-news/diis-close-india-inc-ownership-gap-with-foreign-portfolio-investors-125020401430\\_1.html](https://www.business-standard.com/markets/stock-market-news/diis-close-india-inc-ownership-gap-with-foreign-portfolio-investors-125020401430_1.html)



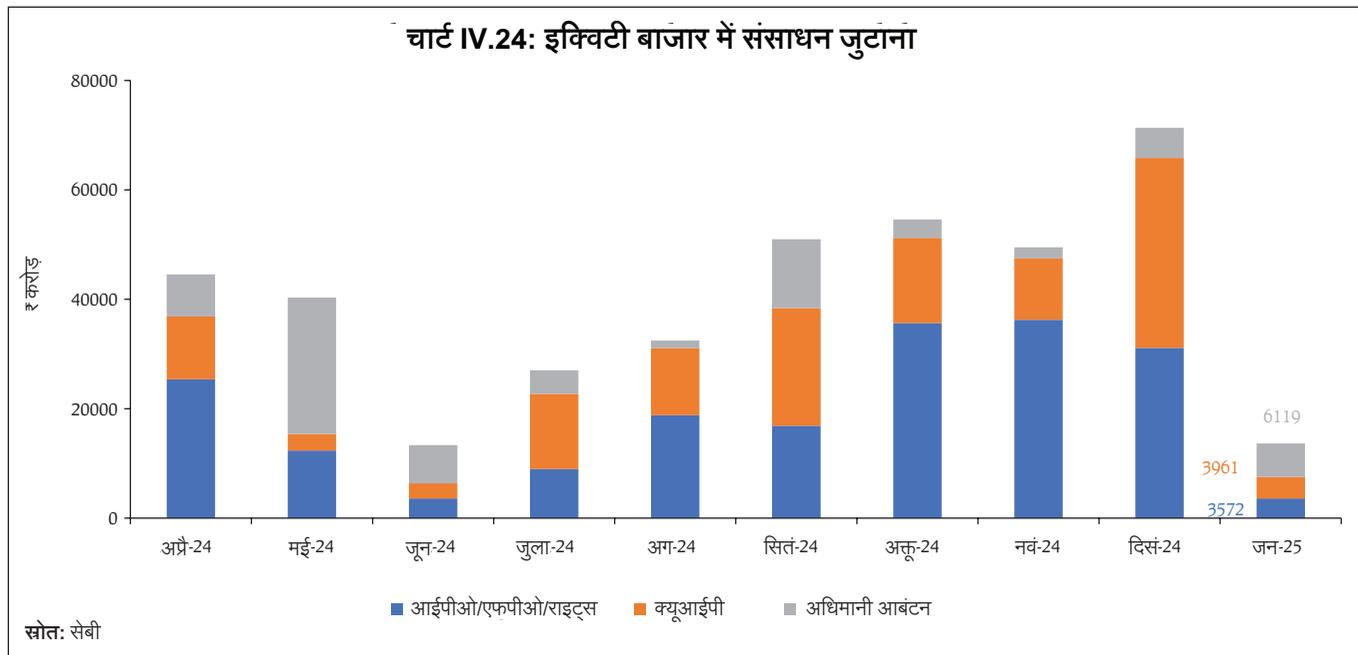
डेरिवेटिव और नकदी खंड दोनों में कारोबार में गिरावट आई है (चार्ट IV.23)<sup>20</sup>

द्वितीयक बाजार में लोक-रुचि में कमी के चलते जनवरी 2025 में प्राथमिक बाजार में धन जुटाने की गतिविधि भी प्रभावित हुई (चार्ट IV.24)<sup>21</sup>



<sup>20</sup> <https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/cash-market-turnover-slips-below-rs1-lakh-crore-in-february-hits-15-month-low-f-o-volume-lowest-since-december-23-12948385.html>

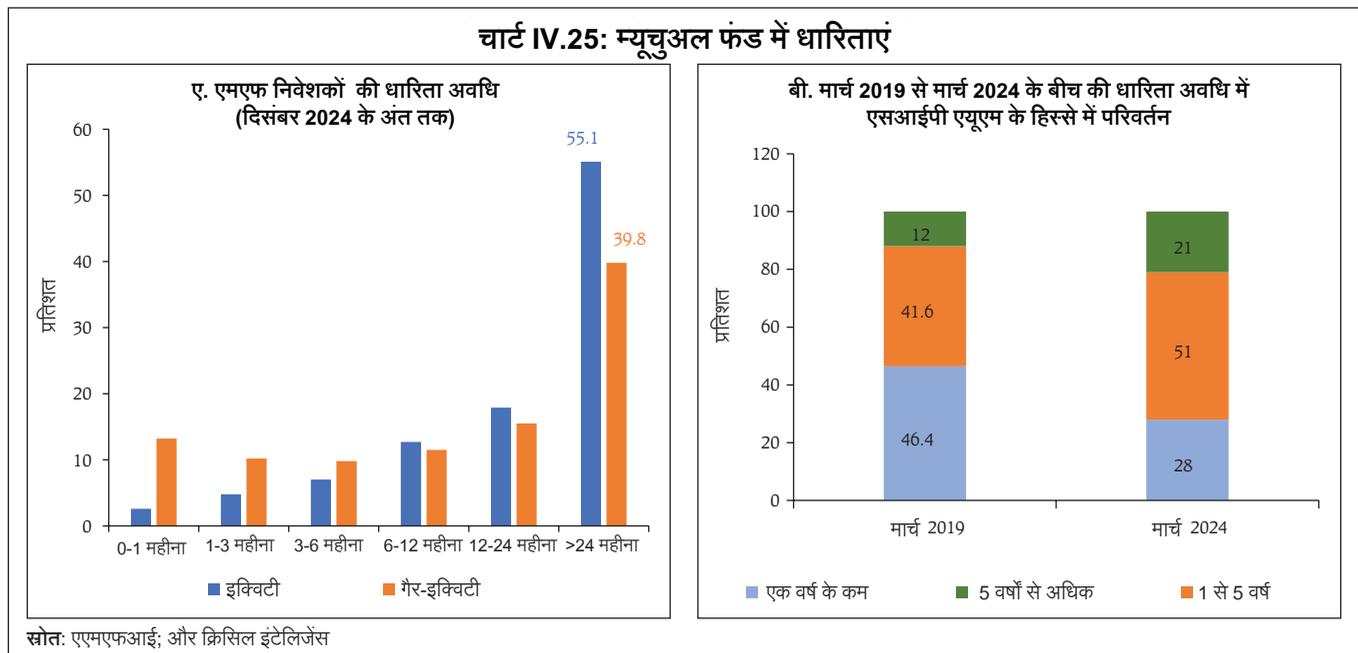
<sup>21</sup> <https://economictimes.indiatimes.com/markets/ipos/fpos/unwilling-to-bear-a-bearscare-companies-halt-ipo-fair/articleshow/118614369.cms?from=mdr>



इक्विटी बाजारों में हाल के सुधार के मद्देनजर, यह उल्लेखनीय है कि खुदरा निवेशकों की 60.8 प्रतिशत इक्विटी परिसंपत्तियां 24 महीने से अधिक समय से रखी गई हैं (चार्ट IV.25)<sup>22</sup> यह दर्शाता है कि खुदरा निवेशकों ने अपने इक्विटी निवेशों को, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड (एमएफ) और व्यवस्थित

निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से, बनाए रखने में दृढ़ता दिखाई है।

घरेलू बचत के वित्तीयकरण को बढ़ाने के लिए तीन हालिया घटनाक्रमों में उल्लेखनीय संभावनाएँ हैं। पहला, माइक्रो एसआईपी योजनाओं<sup>23</sup> की शुरुआत, जो म्यूचुअल फंड उत्पादों को व्यापक



<sup>22</sup> <https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/downloads/home/FolioandTicketSize.pdf>

<sup>23</sup> <https://www.financialexpress.com/money/mutual-funds-explainer-building-the-equity-culture-with-micro-sip-3761507/>

दर्शकों तक पहुँचाएगी। दूसरा, विशेष निवेश फंडों<sup>24</sup> की शुरुआत, जो निवेशकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने और म्यूचुअल फंडों और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के बीच एक सेतु का काम करने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा, कॉरपोरेट बॉण्ड के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना, जो भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड के बारे में जानकारी का एक प्रामाणिक स्रोत प्रदान करेगा<sup>25</sup>

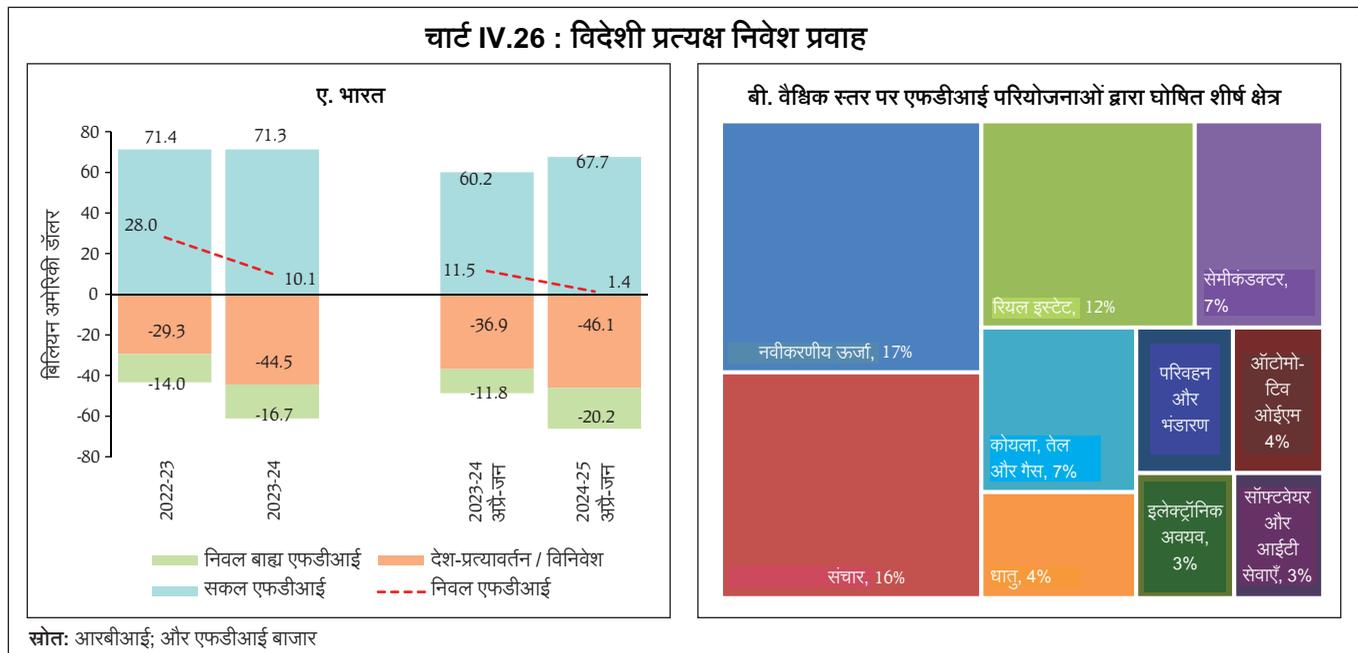
सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मजबूत बना हुआ है, जो 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 12.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर एक वर्ष पहले की इसी अवधि के 60.2 बिलियन यूएस डॉलर से 67.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया(चार्ट IV.26ए)। हालांकि, भारत से अधिक प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई के कारण, निवल एफडीआई 2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान एक वर्ष पहले के 11.5 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। क्षेत्रवार, विनिर्माण क्षेत्र को इक्विटी प्रवाह का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त हुआ, उसके बाद वित्तीय सेवाएं, बिजली और अन्य ऊर्जा, और संचार सेवाएं रहीं - जिनका कुल प्रवाह में 60 प्रतिशत से अधिक

का योगदान रहा। इस अवधि के दौरान 75 प्रतिशत से अधिक प्रवाह सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, यूएई और नीदरलैंड से हुआ।

वैश्विक स्तर पर घोषित ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं के संदर्भ में, 2024 में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जो 2020 में छठे स्थान पर था। 2024 में दुनिया भर में घोषित कुल 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की एफडीआई परियोजनाओं में से, भारत का योगदान लगभग 6 प्रतिशत (100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) था। उभरते क्षेत्र - नवीकरणीय ऊर्जा, संचार, सेमीकंडक्टर और धातु - 2024 के दौरान वैश्विक स्तर पर सबसे आकर्षक एफडीआई क्षेत्र बने रहे (चार्ट IV.26बी)। भारत में, धातु, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर शीर्ष उद्योग थे, जिनका 2024 में घोषित कुल एफडीआई परियोजनाओं में लगभग 60 प्रतिशत योगदान था।

फरवरी 2025 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में लगातार बहिर्वाह जारी रहा। फरवरी में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई बहिर्वाह दर्ज किया गया, जबकि निवल इक्विटी बहिर्वाह 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (चार्ट IV.27ए)। इसके अलावा, मौद्रिक और राजकोषीय

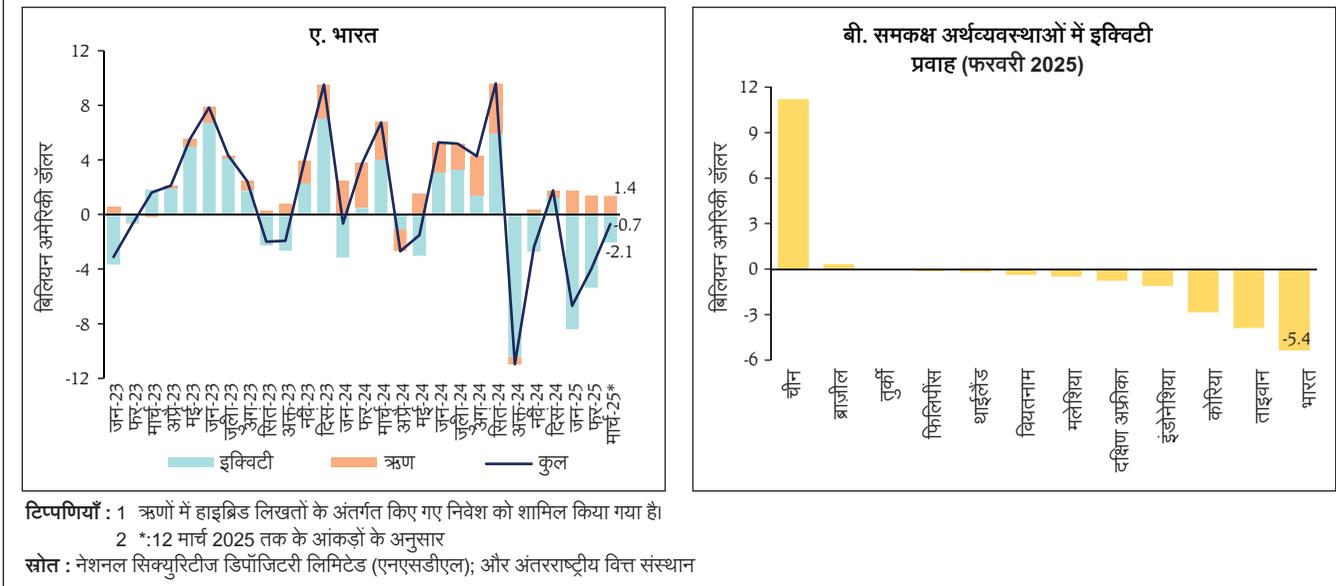
**चार्ट IV.26 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह**



<sup>24</sup> [https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/feb-2025/regulatory-framework-for-specialized-investment-funds-sif-\\_92299.html](https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/feb-2025/regulatory-framework-for-specialized-investment-funds-sif-_92299.html)

<sup>25</sup> [https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/feb-2025/launch-of-bond-central-a-centralised-database-portal-for-corporate-bonds\\_92306.html](https://www.sebi.gov.in/media-and-notifications/press-releases/feb-2025/launch-of-bond-central-a-centralised-database-portal-for-corporate-bonds_92306.html)

**चार्ट IV.27 : निवल पोर्टफोलियो निवेश**



प्रोत्साहन के माध्यम से चीनी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को लेकर बढ़ती आशावादिता के बीच, इस महीने के दौरान वैश्विक एफपीआई प्रवाह चीनी इक्विटी की ओर उल्लेखनीय रूप से पुनर्निर्देशित हुआ (चार्ट IV.27बी)। भारत में, मार्च 2025 में एफपीआई का तीव्र बहिर्वाह 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (17 मार्च तक) के निवल बहिर्वाह के साथ जारी रहा।

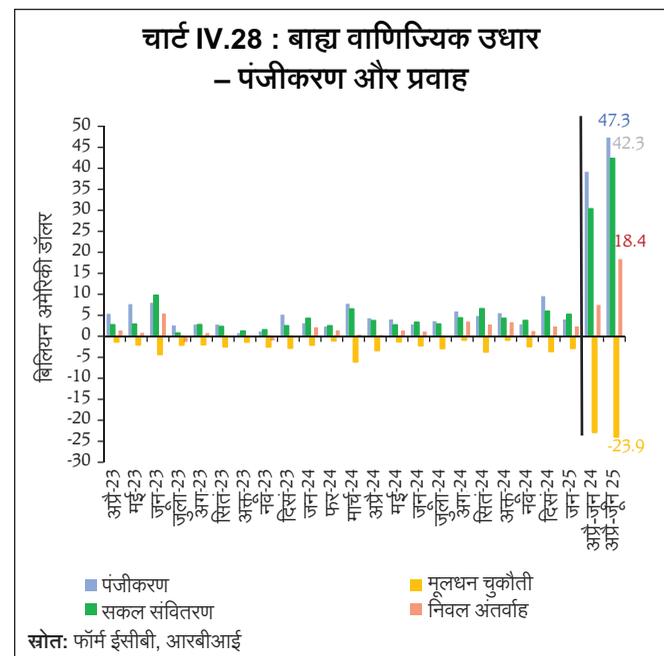
2024-25 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान अनिवासी जमा (एनआरडी) में 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल वृद्धि रही, जो एक वर्ष पहले के 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिक थी, जिसमें सभी तीन खातों यानी अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] खातों में अधिक वृद्धि हुई।

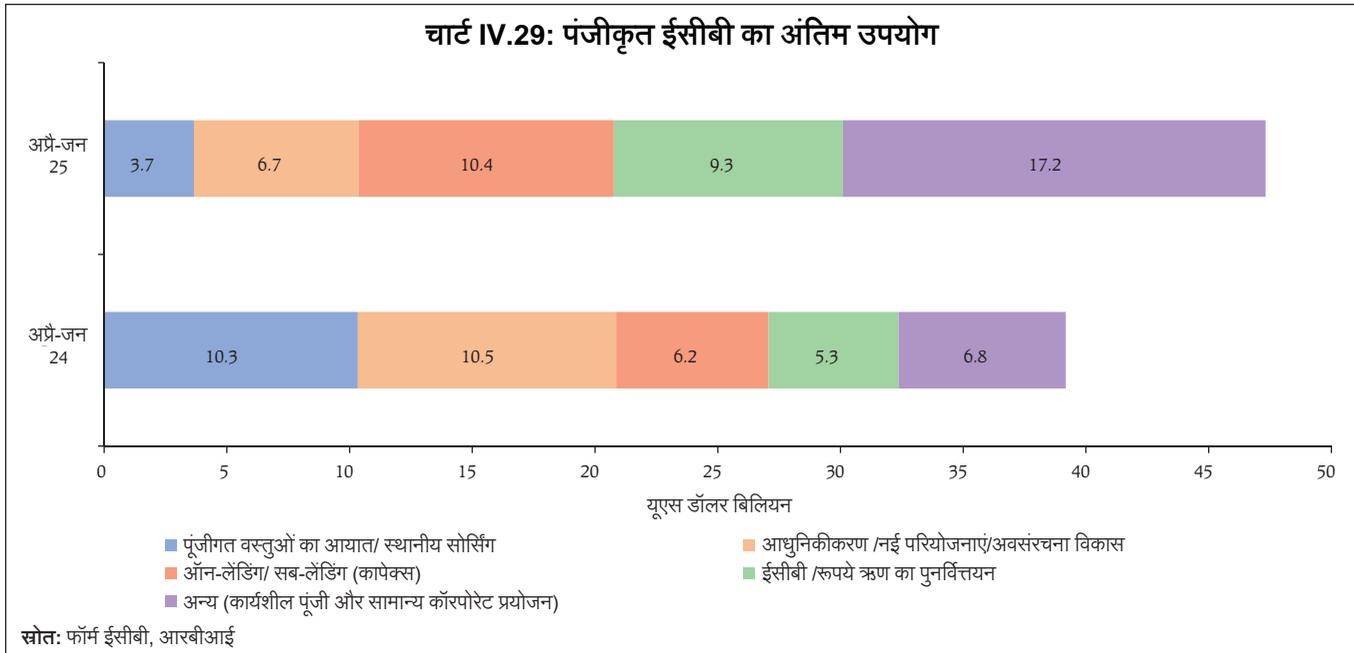
अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दौरान संचयी आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण (47.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (42.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर), पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए संवितरणों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थे। इस अवधि के दौरान मूलधन के पुनर्भुगतान के कारण ईसीबी बहिर्वाह 23.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसके परिणामस्वरूप 18.4 बिलियन अमेरिकी

डॉलर का मजबूत निवल अंतर्वाह हुआ - जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में देखे गए स्तर से दोगुने से भी अधिक है (चार्ट IV.28)।

अप्रैल 2024 - जनवरी 2025 के दौरान कुल पंजीकृत ईसीबी में से लगभग 44 प्रतिशत पूंजीगत व्यय उद्देश्यों के लिए थे (चार्ट IV.29)।

अगस्त 2024 से प्रतिभूतित एक दिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) में निरंतर गिरावट ने ईसीबी की कुल लागत में



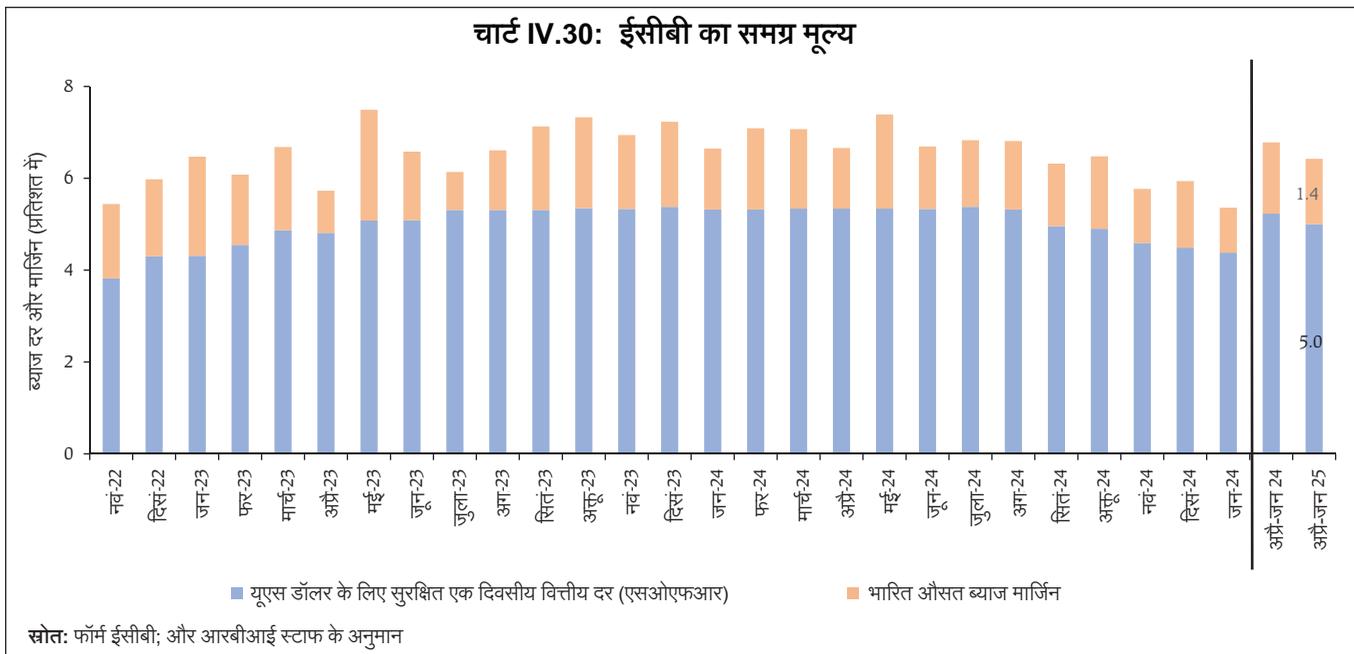


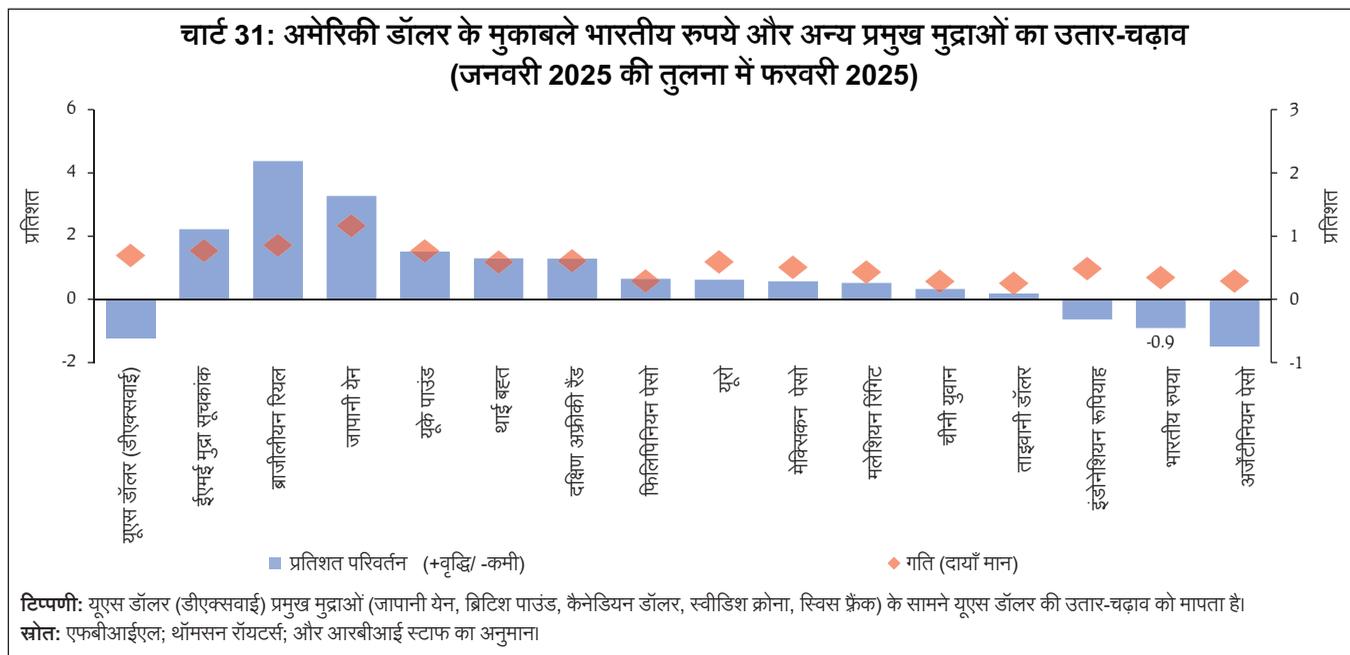
कमी लाने में योगदान दिया है। जनवरी 2025 में, ईसीबी की कुल लागत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 129 बीपीएस की गिरावट हुई (चार्ट IV.30)।

हालाँकि, रुपये के अवमूल्यन की सीमा पिछले महीने की तुलना में कम थी। इसके अलावा, रुपया सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक बना रहा।

फरवरी 2025 के दौरान भारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का बहिर्वाह के चलते भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.9 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई (चार्ट IV.31)।

फरवरी 2025 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भारतीय रुपये में 2.4 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई, जिसका कारण नामित प्रभावी शर्तों





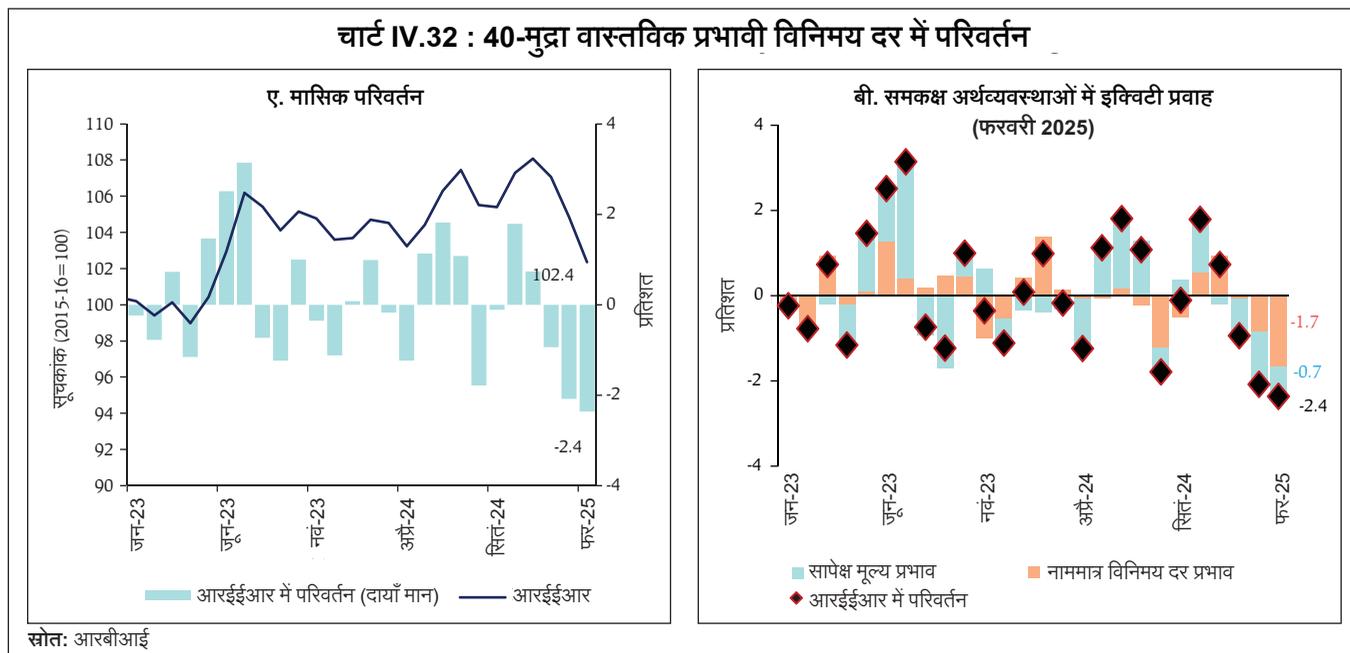
में भारतीय रुपये का मूल्यहास और भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ मुद्रास्फीति अंतर का कम होना है (चार्ट IV.32)।

7 मार्च 2025 तक, भारत के पास 654.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो 11 महीनों से अधिक के आयात और सितंबर 2024 के अंत तक बकाया विदेशी ऋण के 91 प्रतिशत के लिए पर्याप्त है (चार्ट IV.33ए)। 2024-25 की

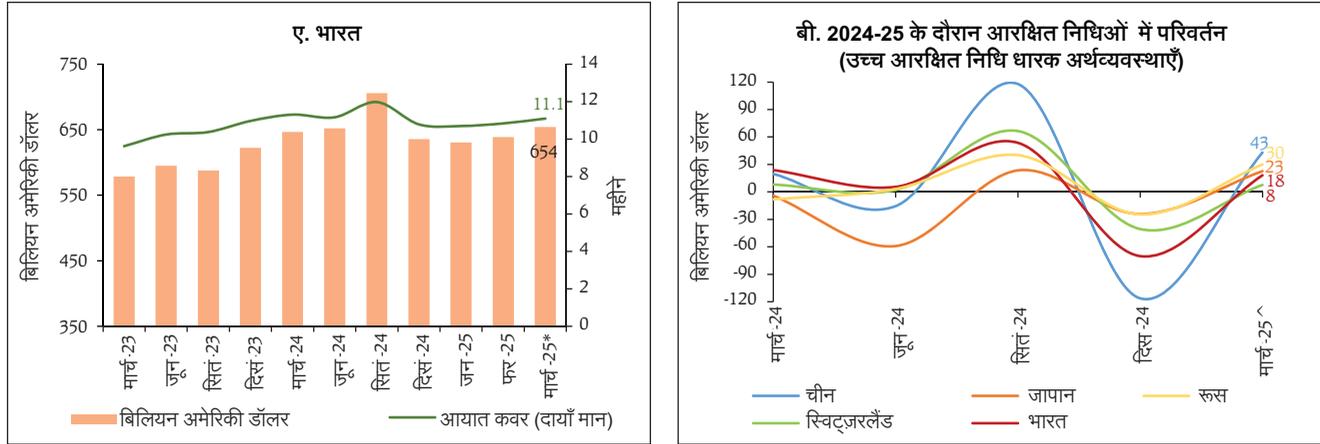
तीसरी तिमाही के दौरान शीर्ष भंडार रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई, जिसमें 2025 में सुधार के कुछ संकेत हैं (चार्ट IV.33बी)।

### भुगतान प्रणालियाँ

फरवरी 2025 में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के कारण भारत के



**चार्ट IV.33 : विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ**



**टिप्पणी:** 1. \*: डाटा 7 मार्च का है।  
 2. दिसंबर 2024 से आयात कवर डाटा भुगतान संतुलन सांख्यिकी के अनुसार सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक माल आयात पर आधारित है।  
 3. ^: भारत और रूस के लिए डाटा 7 मार्च, 2025, स्विट्ज़रलैंड के लिए जनवरी 2025 की समाप्ति और अन्य देशों के लिए फरवरी 2025 की समाप्ति के अनुसार है।  
**स्रोत:** आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार हुआ (सारणी IV.4)। भारत में उद्यमिता और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने में डिजिटल भुगतान की बढ़ती भूमिका पर्सन-टू-मर्चेण्ट(पी2एम) लेनदेन में वृद्धि से स्पष्ट है, जो फरवरी 2025 में कुल यूपीआई लेनदेन का 62.5 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 60.8 प्रतिशत थी।

डिजिटल वित्त खंड में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ट्रेड

रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के माध्यम से तेजी से पूरा किया जा रहा है, जैसा कि वित्तपोषित फैक्ट्रिंग यूनिट्स<sup>26</sup> (एफयू) में तेज वृद्धि से परिलक्षित होता है - जिसने जनवरी 2025 में मात्रा में 78 प्रतिशत और मूल्य (वर्ष-दर-वर्ष) में 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। टीआरईडीएस पर पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं<sup>27</sup> की औसत संख्या एक साल पहले के 24,081 से बढ़कर जनवरी 2025 में 41,094 हो गई। यह

**सारणी IV.4 : चुनिन्दा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि**

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

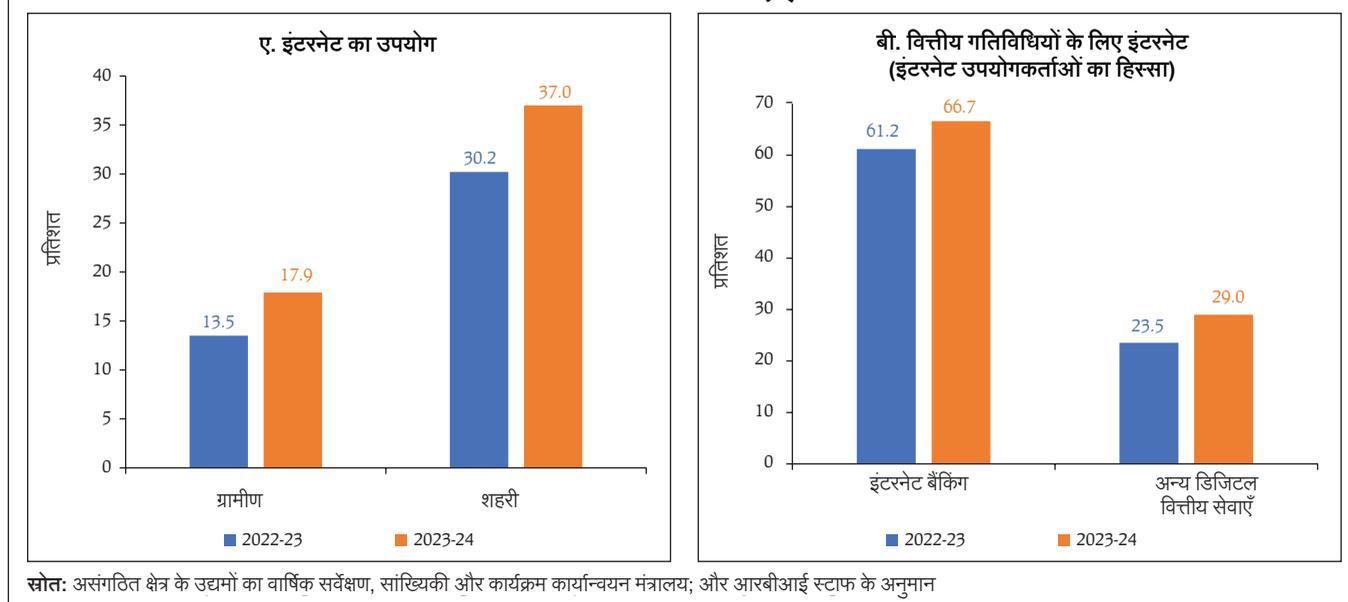
भुगतान प्रणाली	लेनदेन मात्रा				लेनदेन मात्रा			
	जन-24	जन-25	फर-24	फर-25	जन-24	जन-25	फर-24	फर-25
आरटीजीएस	13.1	16.1	18.8	2.5	17.1	19.1	21.2	10.2
एनईएफटी	43.4	24.5	47.3	11.0	19.8	14.3	25.1	2.0
यूपीआई	51.8	39.3	60.6	33.1	41.7	27.5	47.9	20.2
आईएमपीएस	7.2	-12.7	19.4	-24.3	18.6	7.1	21.2	-0.9
एनएसीएच	22.8	17.2	13.1	6.8	21.5	22.5	15.6	20.0
एनईटीसी	10.2	14.8	12.1	18.7	15.5	19.0	19.2	18.3
बीबीपीएस	24.6	97.4	29.8	87.3	75.4	276.4	85.8	240.6

**टिप्पणी:** आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, यूपीआई: यूपीआई इंटरफेस, आईएमपीएस: इमिडियट पेमेंट सर्विस, एनएसीएच: नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनईटीसी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, बीबीपीएस: भारत बिल पेमेंट सिस्टम  
**स्रोत:** आरबीआई

<sup>26</sup> फैक्ट्रिंग यूनिट (एफयू) एक नाम है जिसका उपयोग टीआरईडीएस में चालान या विनिमय पत्र के लिए किया जाता है। प्रत्येक एफयू, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों सहित, कॉरपोरेट या अन्य खरीदारों के एक निश्चित दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

<sup>27</sup> एमएसएमई विक्रेताओं की औसत संख्या की गणना टीआरईडीएस के अंतर्गत शीर्ष तीन संस्थाओं के साथ पंजीकृत एमएसएमई विक्रेताओं की कुल संख्या को तीन से विभाजित करके की जाती है।

**चार्ट IV.34: उद्यमी प्रयोजनों के लिए इंटरनेट का उपयोग**



परिवर्तन उद्यमी गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के बढ़ते अनुपात में भी परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेट अपनाने की दर 2022-23 के 21 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 26.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें शहरी उद्यमों में तेजी से वृद्धि देखी गई (चार्ट IV.34ए)। इसके अतिरिक्त, वित्तीय गतिविधियों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने वाले उद्यमों की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है (चार्ट IV.34बी)।

नीतिगत मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम (एसआरओ-ए) के लिए स्व-नियामक संगठनों (एसआरओ) को मान्यता देने के लिए रूपरेखा जारी की है और उनकी मान्यता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं<sup>28</sup> भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई लाइट कार्यक्षमता में सुधार के लिए अनुशिष्ट प्रस्तुत किए हैं, जिनमें ट्रांसफर-आउट, बैलेंस समाधान, ऐप पासकोड और उन्नत यूपीआई सीमाएँ शामिल हैं, जो विशेष

रूप से ऑफलाइन<sup>29</sup> संव्यवहार<sup>30, 31</sup> के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाती है।

### V. निष्कर्ष

वैश्विक अर्थव्यवस्था की तात्कालिक दिशा बढ़ते व्यापार तनावों, टैरिफ़ से उत्पन्न मुद्रास्फीति के दबावों और उससे जुड़ी वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता से प्रभावित हो सकती है। हाल ही में घोषित राजकोषीय प्रोत्साहन से यूरो क्षेत्र में विकास को अल्पकालिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, हालाँकि ऐसी घोषणाओं के बाद प्रतिफल में हुई तेज़ वृद्धि से संकेत मिलता है कि दीर्घकालिक उधारी लागत में हुई वृद्धि से बड़े विस्तार में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। विकास में मंदी के माहौल में माँग में अपेक्षित कमी के अनुरूप, कोमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का आधार बन सकती है। हालाँकि, उपभोक्ता कीमतों पर उच्च टैरिफ़ का प्रभाव मुद्रास्फीति के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ

<sup>29</sup> 'ऑफलाइन' जैसा कि आरबीआई परिपत्र संख्या . RBI/2021-22/146 CO.DPSS. POLC.No.S1264/02-14-003/2021-2022, दिनांक 04 दिसंबर 2024 में परिभाषित किया गया है - 'ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए ढांचा'

<sup>30</sup> एनपीसीआई परिपत्र, 21 फरवरी 2025। यूपीआई लाइट की शुरुआत के लिए अनुशिष्ट।

<sup>31</sup> एनपीसीआई परिपत्र, 27 फरवरी 2025। यूपीआई लाइट सीमाओं में वृद्धि का अनुशिष्ट।

<sup>28</sup> आरबीआई प्रेस विज्ञप्तियाँ, 12 मार्च 2025। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए स्व-विनियामक संस्था(ओं) की मान्यता हेतु आवेदन आमंत्रित।

है, जो पहले से ही कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दृढ़ता के संकेत प्रदर्शित कर रही है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों को विकास में संभावित मंदी के माहौल में नीतिगत प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते समय ऐसे दबावों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी ओर, उभरती अर्थव्यवस्थाएँ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अपने समकक्षों की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज करने की संभावना रखती हैं, हालाँकि पूँजी बहिर्वाह और संभावित मुद्रा अवमूल्यन प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

घरेलू स्तर पर, समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे मजबूत बने हुए हैं, और मजबूत घरेलू माँग, स्थिर निवेश गतिविधि, और चालू नीति-संचालित अवसंरचना विकास के साथ-साथ सरकारी खर्च में वृद्धि से आर्थिक विकास की गति बनी रहेगी। हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 के 6 प्रतिशत से अधिक से घटकर

फरवरी 2025 में 3.6 प्रतिशत हो गई है। मजबूत खरीफ उत्पादन, बेहतर रबी बुआई के साथ-साथ उच्च जलाशय स्तर और सब्जियों की कीमतों में मौसमी सर्दी के चलते सुधार खाद्य मुद्रास्फीति के लिए शुभ संकेत हैं, हालाँकि कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी विसंगतियाँ समग्र मुद्रास्फीति परिदृश्य के लिए संभावित रूप से जोखिम बने हुए हैं।

कमजोर होते वैश्विक व्यापार और टैरिफ अनिश्चितता से चुनौतियों का सामना करते हुए, भारत के बाह्य क्षेत्र को आघात-सहनीय सेवा निर्यात से समर्थन मिल रहा है, जो वैश्विक व्यवधानों से कम प्रभावित हैं। भविष्य में, भारत की संरचनात्मक शक्तियाँ—मजबूत राजकोषीय नीतियाँ, एक सुसंतुलित मौद्रिक ढाँचा, और डिजिटल परिवर्तन पहल—दीर्घकालिक सतत आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगी।

## मानसून और कृषि उत्पादन का स्थानिक वितरण

अभिनव नारायणन और  
हरेंद्र कुमार बेहेरा<sup>^</sup>

यह अध्ययन भारत में वर्षा के स्थानिक वितरण और खरीफ फसलों की खेती पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। जिला स्तर पर वर्षा और कृषि उत्पादन पर सुमेलित लॉन्ग-टर्म डेटा का उपयोग करके, यह अध्ययन फसल उत्पादन पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए वर्षा में भिन्नताओं का उपयोग करता है। निष्कर्ष सभी फसलों के लिए वर्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं; हालाँकि, चरम मौसम की घटनाएँ - जैसे कि अत्यधिक या अपर्याप्त वर्षा उत्पादन प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है और उपज की गुणवत्ता कम हो जाती है। अलग-अलग फसल उत्पादन चक्रों के कारण इन चरम मौसम की घटनाओं का समय भी महत्वपूर्ण है। जून और जुलाई में अपर्याप्त वर्षा होने से अनाज और दलहन उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि तिलहन फसल कटाई के दौरान अत्यधिक वर्षा होने से खराब हो सकती है।

### परिचय

खरीफ फसलों के उत्पादन में वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि केवल सिंचाई इन फसलों की जल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। उच्च उपज वाली फसल किस्मों, जलवायु-क्षम किस्मों और फसल प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दशकों के अनुसंधान के बावजूद, अधिकांश उत्पादन अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर मौसम के मिजाज को बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में भारत में बाढ़, सूखा और लू जैसी चरम स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में, यह अध्ययन फसल उत्पादन में वर्षा की भूमिका का विश्लेषण करता है, जिसमें विशेष रूप से अत्यधिक और अपर्याप्त वर्षा, दोनों के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कृषि उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18.2 प्रतिशत का योगदान

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

देता है और 42.3 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है।<sup>1</sup> अतः, वर्षा समष्टि आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। राजकोषीय नीति विभिन्न मूल्य समर्थन प्रणालियों और कृषि सब्सिडी से जुड़ी होती है, जबकि मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाए गए तंत्रों से प्रभावित होती है, जो खाद्य कीमतों से प्रभावित होते हैं।

भारत जैसे विशाल भूभाग और विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देश में विभिन्न क्षेत्रों में फसल उत्पादन में काफी भिन्नता होती है। यद्यपि समय के साथ विभिन्न नीतियों ने किसानों को विशिष्ट फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है, फिर भी उत्पादन काफी हद तक स्थानीय कृषि-जलवायु कारकों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, धान, कुछ दलहनों और तिलहनों जैसी फसलें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून में पर्याप्त वर्षा होती है। अन्यथा, उत्पादन प्रक्रिया बहुत अधिक सिंचाई पर निर्भर होगी जिससे जल के वैकल्पिक स्रोतों (भूजल, जलाशयों, आदि) पर दबाव पड़ता है। इस अध्ययन में जिलों में वर्षा की स्थानिक भिन्नता का उपयोग किया गया है और विभिन्न खरीफ फसलों की उत्पादन प्रक्रिया पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। यह अध्ययन इन फसलों की खेती करने वाले जिलों में कम या अधिक वर्षा के प्रभावों का भी अनुमान लगाता है, और किस प्रकार ये विविधताएं उत्पादन प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं। इन फसलों की प्रकृति के कारण, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बुवाई या कटाई के चरणों के दौरान अपर्याप्त या अत्यधिक वर्षा अंतिम उत्पादन परिणामों पर अलग-अलग प्रभाव डाल सकती है। इस प्रकार, यह अध्ययन विशिष्ट महीनों में चरम मौसम की घटनाओं की पहचान करने की कोशिश करता है जो विभिन्न फसलों पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह देखते हुए कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा जून से सितंबर तक होती है, हम उत्पादन पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए इस समय सीमा और विशिष्ट महीनों में वर्षा के स्थानिक वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

लेख का शेष भाग मोटे तौर पर इस प्रकार संरचित है। खंड II में वर्षा-कृषि संबंध पर प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। खंड III में भारत में वर्षा के स्थानिक वितरण और कृषि उत्पादन से

<sup>1</sup> <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2034943>

संबंधित शैलीगत तथ्यों का परीक्षण किया गया है। कृषि उत्पादन पर वर्षा के स्थानिक और वास्तविक वितरण के प्रभाव का अध्ययन करने की पद्धति पर खंड IV में चर्चा की गई है, तथा अनुभवजन्य परिणाम खंड V में प्रस्तुत किए गए हैं। खंड VI अध्ययन का समापन खंड है।

## II. चयनित जानकारी

भारत में वर्षा और कृषि के बीच संबंधों का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया। संक्षिप्तता के लिए हम उन चुनिंदा अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें इस विषय का अध्ययन करने के लिए विस्तृत आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्रसन्ना (2014) ने पाया कि मानसूनी वर्षा का खरीफ मौसम में पैदावार पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि मानसून के बाद की वर्षा जल और मिट्टी की नमी को प्रभावित करके रबी फसलों को प्रभावित करती है। गैल और काज़ेनबर्गर (2024) ने फसल की पैदावार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए वैश्विक जलवायु मॉडल की भविष्यवाणियों का इस्तेमाल किया और पाया कि, वर्षा और तापमान को प्रभावित करने वाले विभिन्न उत्सर्जन परिदृश्यों के आधार पर, 2021-2100 के बीच चावल की पैदावार में 3-22 प्रतिशत की कमी हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जकारिया एवं अन्य (2020) ने पाया कि बढ़ते तापमान की तुलना में वर्षा की कमी का फसल उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। घोष और कौस्तुभ (2023) ने पाया कि वर्षा का मुद्रास्फीति के साथ एक अ-रैखिक संबंध है, मुख्य रूप से कृषि जीवीए पर इसके प्रभावों के माध्यम से। गुप्ता और अन्य (2023) ने सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार के संदर्भ में खरीफ फसलों पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए राज्य-स्तरीय उत्पादन और वर्षा के आँकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि सिंचाई के माध्यम से अल्प वर्षा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वर्षा और कृषि फसल उत्पादन के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य अध्ययनों में मेहर एवं अन्य (2015); ऑफहैमर एवं अन्य (2012); फिशमैन (2016); रेवाडेकर और प्रीति (2012) शामिल हैं। कपूर (2018) का मत है कि समग्र स्तर पर अत्यधिक/अल्प वर्षा का कृषि गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह शोधपत्र मानसून ऋतु के दौरान अपर्याप्त और अत्यधिक वर्षा, दोनों के

प्रभावों की पड़ताल करके विश्लेषण को आगे बढ़ाता है, और वर्षा के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए जिला-स्तरीय आँकड़ों का उपयोग करता है। इसके अलावा, हमारा उद्देश्य विभिन्न फसलों के अलग-अलग फसल चक्रों को ध्यान में रखते हुए मानसून ऋतु के विशिष्ट महीनों में वर्षा के प्रभावों की पहचान करना है।

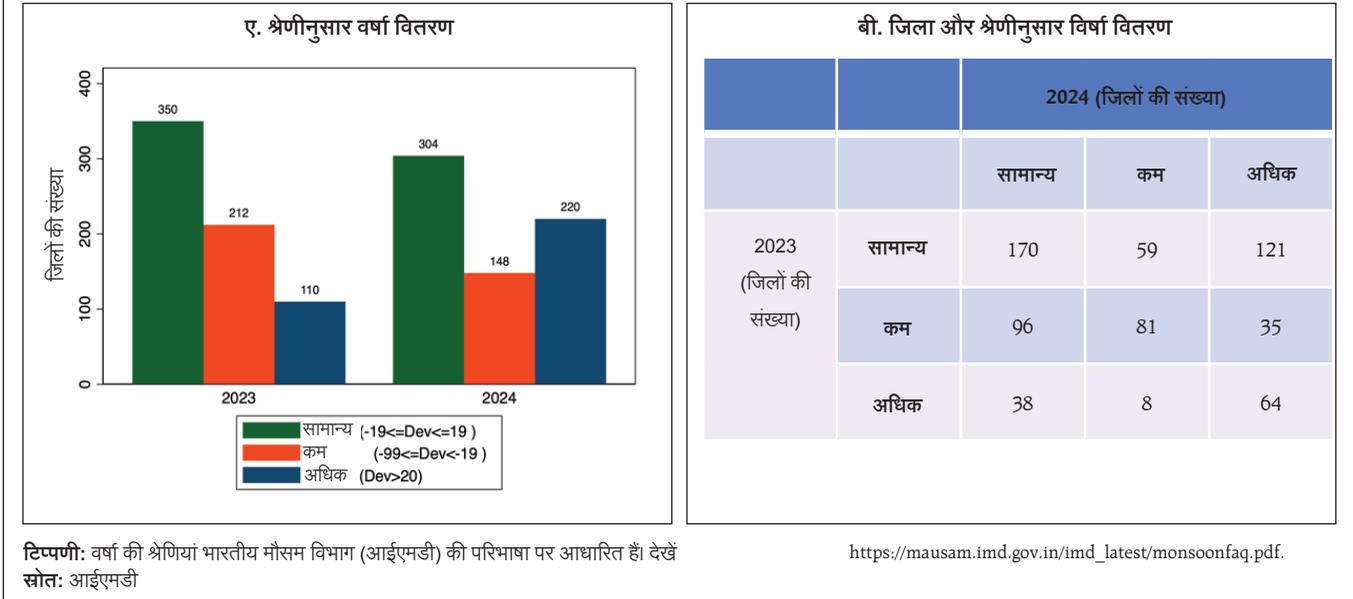
## III. आँकड़े और शैलीबद्ध तथ्य

यह शोधपत्र वर्षा के स्थानिक विश्लेषण के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आँकड़ों का उपयोग करता है, जो दैनिक और मासिक आवृत्ति पर उपलब्ध हैं। जिला-स्तरीय कृषि उत्पादन आँकड़े भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से हैं और विभिन्न वर्षों और जिलों में एकरूपता बनाए रखने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के कमोडिटी डेटाबेस से एकत्र किए गए हैं।

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाओं का एक मौसमी स्वरूप है जो जून और सितंबर के बीच देश की अधिकांश वार्षिक वर्षा लाता है। यह हिंद महासागर से उत्पन्न होता है और गर्मियों के दौरान भूभाग की गर्मी से आकर्षित होकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ता है। यह मानसून भारत की जलवायु और कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो फसलों के लिए आवश्यक वर्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से खरीफ मौसम (जून से अक्टूबर) के दौरान, जिसमें चावल, कपास और दालें जैसी फसलें शामिल हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान अत्यधिक गर्मी के दौर के बाद, 2024 में दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम जून 2024 में कम वर्षा के साथ शुरू हुआ और उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में अधिक वर्षा हुई। पहले दो महीनों के दौरान वर्षा का स्थानिक वितरण असमान था, लेकिन अगले दो महीनों के दौरान इसमें सुधार हुआ। 2024 में अधिक वर्षा वाले जिलों में वृद्धि हुई, जबकि कम और सामान्य वर्षा वाले जिलों में 2023 की तुलना में कमी आई है।

भारत में 2023 और 2024 के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण दर्शाता है कि 2023 की तुलना में 2024 में सामान्य वर्षा वाले जिलों की संख्या में कमी आई है (चार्ट 1ए)। हालाँकि, 2024 में कम वर्षा वाले जिलों की संख्या

**चार्ट 1 : 2023 की तुलना में 2024 में वर्षा वितरण**

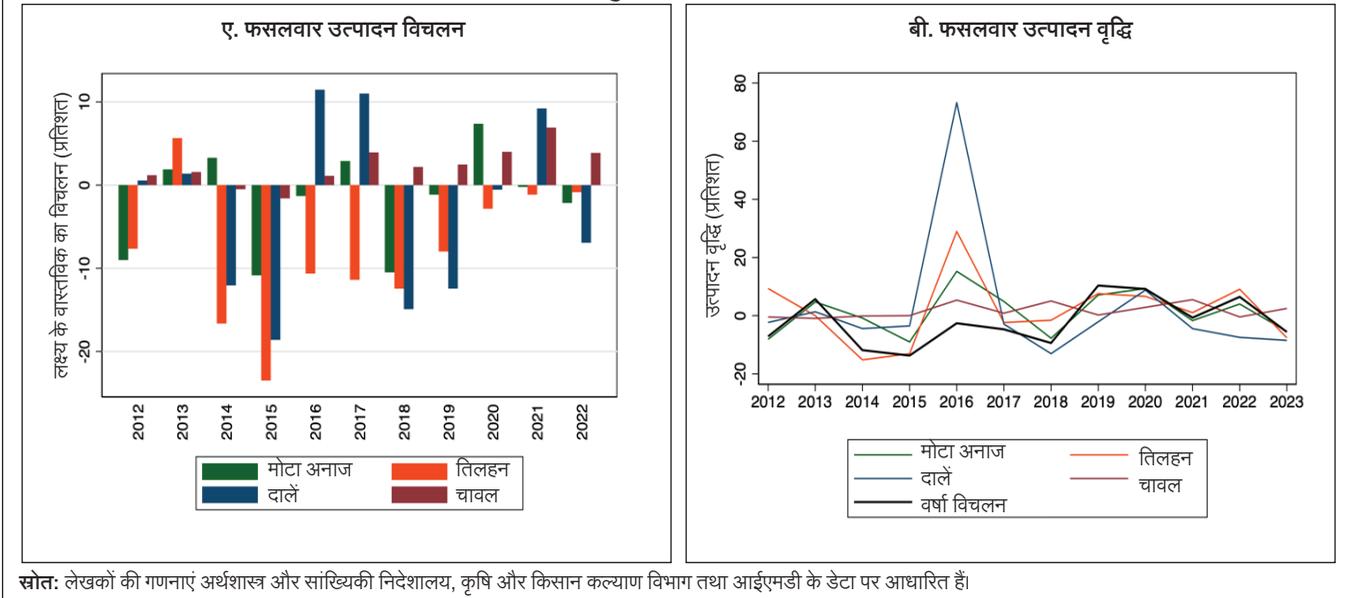


कम हो गई, जबकि अधिक वर्षा वाले जिलों की संख्या बढ़ गई। जिला आंकड़े दर्शाते हैं कि 2023 में सामान्य वर्षा वाले 59 जिलों में 2024 में कम वर्षा हुई, जबकि 2023 में सामान्य वर्षा वाले 121 जिलों में 2024 में अधिक वर्षा हुई (चार्ट 1बी)। दूसरी ओर, 2023 में कम वर्षा वाले 96 जिलों में 2024 में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। स्थानिक वितरण की अंतर्निहित गतिशीलता के आधार पर, 2023 की तुलना में 2024 में अल्प वर्षा वाले जिले जिनमें

सामान्य वर्षा हुई, उनमें निवल वृद्धि 37 है जबकि सामान्य वर्षा वाले जिले, जिनमें अधिक वर्षा हुई, उनमें निवल कमी 83 है।

विभिन्न फसल समूहों के उत्पादन पैटर्न और उनके लक्ष्यों में पाया गया अंतर यह दर्शाता है कि चावल ही एकमात्र ऐसी फसल है जो लगभग हर साल लक्ष्य उत्पादन को पूरा करती है (चार्ट 2ए)। दूसरी ओर, तिलहन और दलहन लगातार लक्ष्य उत्पादन से नीचे रहते हैं। खरीफ मौसम के दौरान इन चार फसल समूहों के

**चार्ट 2 : उत्पादन (लक्ष्य की तुलना में वास्तविक) और वर्षा विचलन**



उत्पादन में होने वाली वार्षिक वृद्धि दर्शाती है कि उन वर्षों में उच्च उत्पादन का एक सामान्य रुझान है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून सभी फसलों के लिए बेहतर होता है (चार्ट 2बी)। चावल उत्पादन एक सुसंगत पैटर्न के अनुसार होता दिखाई देता है, जबकि अन्य फसलें, विशेष रूप से तिलहन और दलहन, मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह भारतीय कृषि पैटर्न पर आधारित एक ज्ञात तथ्य है, जबकि चावल उत्पादन की स्थिरता का श्रेय चावल उत्पादन के लिए सिंचित भूमि के उच्च उपलब्धता को दिया जा सकता है।

उक्त अवलोकन दर्शाते हैं कि वर्षा के स्थानिक वितरण में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव होता रहता है। यह स्पष्ट है कि खरीफ फसलों के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्षा की मात्रा और पैटर्न के आधार पर विभिन्न फसलों के बीच उत्पादन पर इसका प्रभाव भिन्न होता है। इस अध्ययन का उद्देश्य वर्षा के स्थानिक वितरण का विश्लेषण करना तथा यह बताना है कि यह विभिन्न फसलों के उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करता है।

#### IV. अनुभवजन्य रणनीति

हम मानसून ऋतु के दौरान प्रत्येक फसल के वार्षिक उत्पादन आँकड़ों का मिलान जिला स्तर पर वर्षा से करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम उन माह-वर्ष संयोजनों की पहचान करते हैं जिनमें वर्षा कम या अधिक रही। फसल उत्पादन पर वर्षा के स्थानिक पैटर्न के प्रभाव का आकलन करने के लिए, हम पहले निम्नलिखित विनिर्देश का उपयोग करते हैं:

$$\begin{aligned} & \ln(\text{production})_{dst} \\ &= \alpha_d + \theta_{st} + \beta_1 * \ln(\text{Rainfall})_{dst} + \beta_2 * \ln(\text{Rainfall})_{dst} * \\ & \text{Deficient}_{dst} + \beta_3 * \ln(\text{Rainfall})_{dst} * \text{Excess}_{dst} + \beta_4 * \\ & \ln(\text{Area Sown})_{dst} + \epsilon_{dst} \quad \dots (1) \end{aligned}$$

जहाँ  $\ln(\text{production})_{dst}$  वर्ष  $t$  में जिला  $d$ , राज्य  $s$  में फसल  $c$  के उत्पादन (लॉग) को दर्शाता है।  $\ln(\text{Rainfall})_{dst}$  और  $\ln(\text{Area Sown})_{dst}$  जिला  $d$ , राज्य  $s$  और वर्ष  $t$  में वास्तविक वर्षा और बुआई क्षेत्र को दर्शाते हैं। यदि वर्ष  $t$  में जिला  $d$  में कम या अधिक वर्षा होती है, तो  $\text{Deficient}_{dst}$  और  $\text{Excess}_{dst}$  का मान क्रमशः 1 होता है, अन्यथा शून्य होता है। वेरिएबल ऑफ इंटररेस्ट  $\beta_1$  है जो हमें फसल उत्पादन पर वर्षा के सीमांत प्रभाव को बताता है।

गुणांक  $\beta_2$  और  $\beta_3$ , किसी जिले में किसी विशेष वर्ष में कम या अधिक वर्षा होने पर वर्षा के सीमांत प्रभाव को दर्शाते हैं। अतः, यदि किसी विशेष वर्ष में सभी जिलों में सामान्य वर्षा हुई, तो वर्षा का सीमांत प्रभाव  $\beta_1$  होगा। लेकिन यदि कोई ऐसे जिले हैं जहाँ उस वर्ष कम (या अधिक) वर्षा हुई है, तो वर्षा का प्रभाव  $\beta_1 + \beta_2$  (या  $\beta_1 + \beta_3$ ) होगा।

हम जिला स्थिर प्रभावों ( $\alpha_d$ ) को शामिल करते हैं जो किसी भी समय अपरिवर्तनीय विशेषताओं (जैसे, मिट्टी की विशेषताएँ, दीर्घकालिक कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ) और किसी भी अप्रत्याशित जिला-स्तरीय परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं जो किसी विशेष फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। विनिर्देश में राज्य-विशिष्ट वर्ष स्थिर प्रभाव ( $\theta_{st}$ ) शामिल हैं जो किसी भी व्यापक आर्थिक घटनाओं जैसे नीतिगत परिवर्तन (जैसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक सब्सिडी, व्यापार नीतियाँ) या जलवायु परिवर्तन (जैसे, अल नीनो, ला नीना) को नियंत्रित करते हैं जो किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष राज्य में घटित हो सकते हैं और एक ही समय में राज्य के सभी जिलों को प्रभावित करते हैं। राज्य-विशिष्ट वर्ष के निश्चित प्रभाव उन सभी राज्य-स्तरीय चरों (जैसे, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ऋण, राज्य-स्तर पर सिंचाई अवसंरचना, आदि) को भी नियंत्रित करते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।

चूँकि विभिन्न फसलों का फसल चक्र अलग-अलग होता है, इसलिए हम प्रत्येक फसल के लिए किसी विशेष महीने में कम या अधिक वर्षा के प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने के लिए, हम महीनेवार अंतःक्रियात्मक पदों को शामिल करके पहले विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) को और विस्तृत करते हैं:

$$\begin{aligned} & \ln(\text{production})_{dst} \\ &= \alpha_d + \theta_{st} + \beta_1 * \ln(\text{Rainfall})_{dst} + \sum_{m = \text{Jun, Jul, Aug, Sep}} \beta_{2,m} \\ & * \ln(\text{Rainfall})_{dst} * \text{Deficient}_{dstm} + \sum_{m = \text{Jun, Jul, Aug, Sep}} \beta_{3,m} * \\ & \ln(\text{Rainfall})_{dst} * \text{Excess}_{dstm} + \beta_4 * \ln(\text{Area Sown})_{dst} + \epsilon_{dst} \quad \dots (2) \end{aligned}$$

यहाँ, वर्ष 't' में यदि जिला 'd' में जून के महीने में कम वर्षा हुई है, तो  $\text{Deficient}_{dstm}$  (यदि  $m = \text{jun}$ ) का मान 1 होगा। अन्य महीनों और अधिक वर्षा के लिए भी यही बात लागू होती है। शेष

चरों की व्याख्या समीकरण 1 के समान ही है। इस विनिर्देश में, हम यह देखने के लिए गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि क्या मानसून ऋतु के दौरान किसी विशेष महीने में अधिक कम वर्षा फसल उत्पादन के लिए मायने रखती है। विशेष रूप से, यदि जिलों में जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में कम या अधिक वर्षा होती है, तो फसल उत्पादन पर वर्षा का कुल सीमांत प्रभाव क्या है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न फसलों के लिए जल और मृदा नमी की आवश्यकता अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, कटाई के मौसम में अत्यधिक वर्षा आमतौर पर फसलों को नुकसान पहुँचाती है और अधिकांश फसलों के लिए हानिकारक होती है। वास्तव में, दलहन फसलों के लिए पुष्पन के मौसम में अत्यधिक वर्षा और बुवाई के मौसम में कम वर्षा फसलों के लिए हानिकारक होती है। चूँकि इस विश्लेषण के लिए जिला स्तर पर उत्पादन और वर्षा दोनों के आँकड़े आवश्यक हैं, इसलिए जिलों में उपलब्ध निरंतर आँकड़ों के आधार पर समयावधि 2012-2022 तक सीमित है। ऐतिहासिक आँकड़ों की तुलना में हाल की अवधि के आँकड़े रखने का एक लाभ यह है कि जिला स्तर पर फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले किसी भी दीर्घकालिक परिवर्तन को ध्यान में रखा जा सकता है। हमारे सभी विनिर्देशों में, हम जिलों के भीतर किसी भी क्रमिक सहसंबंध को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर मानक त्रुटियों को समूहीकृत करते हैं।

चूँकि किसी जिले में किसी फसल का वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन पर निर्भर हो सकता है, इसलिए एक गतिशील पैनल विनिर्देश का उपयोग एक सुदृढ़ता जाँच के रूप में किया जाता है जिसमें उत्पादन का विलंबित मान शामिल होता है। इस विनिर्देश के परिणाम परिशिष्ट सारणी ए.1-ए.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

## V. परिणाम

हम कुल अनाज उत्पादन और दो प्रमुख फसलों: धान और मक्का के लिए समीकरण 1 का अनुमान लगाते हैं। परिणाम बताते हैं कि कृषि उत्पादन को प्रभावित करने में वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हालाँकि इसका प्रभाव विभिन्न फसलों पर अलग-अलग होता है (सारणी 1)। एक प्रतिशत अधिक वर्षा से अनाज उत्पादन में 0.04 प्रतिशत, धान उत्पादन में 0.03 प्रतिशत और मक्का उत्पादन में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि होती

**सारणी 1: फसल उत्पादन पर वर्षा का असर (अनाज)**

	(1)	(2)	(3)
	अनाज	धान	मक्का
In Rainfall(Actual)	0.038* (0.019)	0.031* (0.017)	0.159** (0.071)
In Rainfall*Deficient	-0.007*** (0.002)	-0.005** (0.002)	0.0002 (0.006)
In Rainfall*Excess	-0.003 (0.002)	0.002 (0.002)	-0.011* (0.006)
In AreaSown	1.049*** (0.040)	1.066*** (0.040)	1.065*** (0.026)
Constant	14.205*** (0.245)	14.245*** (0.229)	13.511*** (0.499)
District FE	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां
N	4165	3807	3278
R <sup>2</sup>	0.95	0.96	0.97

टिप्पणियाँ: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।

है। ये परिणाम दर्शाते हैं कि धान की तुलना में वर्षा में परिवर्तन के प्रति मक्का अधिक संवेदनशील है, जो संभवतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोतों पर इस फसल की निर्भरता के कारण है।

परिणाम वर्षा परिवर्तनों से होने वाले अलग-अलग प्रभावों को भी उजागर करते हैं। कम वर्षा का कुल अनाज और धान उत्पादन पर मामूली नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्षा की कमी का धान पर कम प्रभाव पड़ता है जिसका कारण धान की खेती में सिंचाई प्रणालियों का व्यापक उपयोग हो सकता है, जिससे फसल पर कम वर्षा का बड़ा प्रभाव नहीं होता। जबकि, मक्का का उत्पादन कम वर्षा से अप्रभावित रहता है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता और मिट्टी की नमी या कम वर्षा वाली परिस्थितियों के अनुकूल कृषि पद्धतियों पर संभावित निर्भरता को दर्शाता है।

दूसरी ओर, अत्यधिक वर्षा, विशेष रूप से मक्का के लिए, एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरती है। अत्यधिक वर्षा मक्का उत्पादन को आधार रेखा से 0.011 प्रतिशत कम कर देती है, जिससे यह पता चलता है कि जलभराव या लंबे समय तक पानी का जमा रहना इस फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह मक्का की भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप है, क्योंकि

यह खराब जल निकासी और जल संचय के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

सारणी 2 दलहन के संबंध में समीकरण 1 से प्राप्त रिग्रेशन परिणामों को दर्शाती है। कॉलम 1 समग्र दलहन उत्पादन के परिणामों दर्शाता है जबकि कॉलम 2, 3 और 4 खरीफ मौसम के दौरान उगाई गई तीन प्रमुख दालों, अर्थात् अरहर, मूंग और उड़द के परिणामों को दर्शाते हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि मूंग को छोड़कर सभी दालों पर वर्षा का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि मूंग के लिए वर्षा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। वर्षा में 1 प्रतिशत की वृद्धि से समग्र दलहन उत्पादन में 0.33 प्रतिशत की वृद्धि होती है। कम वर्षा से समग्र दलहन और अरहर उत्पादन प्रभावित होता है और मूंग पर इसका नकारात्मक लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन प्रभाव पड़ता है। कम वर्षा का उड़द उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अधिक वर्षा सभी प्रकार की दालों के लिए काफी हानिकारक प्रतीत होती है। अरहर और मूंग की सफलता के लिए एक पूर्वा-पेक्षा यह है कि उसके लिए उचित जल निकासी हो। उन क्षेत्रों में मेड़ स्थापन प्रभावी है जहां उप-सतही जल निकासी खराब है। कुल मिलाकर, दालों का उत्पादन कम और अधिक वर्षा, दोनों के प्रति काफी संवेदनशील प्रतीत होता है। इसलिए, इसके लिए सही

मात्रा में वर्षा की ज़रूरत होती है, जो न ज्यादा हो और न ही कम।

हम तिलहनों के भी लिए समीकरण 1 का अनुमान लगाते हैं, जिसमें तीन प्रमुख खरीफ तिलहनों, अर्थात् सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी (सारणी 3) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुल तिलहन उत्पादन के लिए वर्षा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। वर्षा में एक प्रतिशत की वृद्धि से उत्पादन में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होती है। हालाँकि, प्रत्येक फसल पर व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएँ अपेक्षाकृत कमजोर हैं। कम वर्षा तिलहनों (सूरजमुखी को छोड़कर) पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अत्यधिक वर्षा समग्र तिलहन उत्पादन, विशेष रूप से सोयाबीन, को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है।

सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है जिसकी खेती खरीफ मौसम में की जाती है और इसे मानसून आने के बाद ही बोया जाता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उचित अंकुरण और स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 100 मिमी वर्षा होने के बाद ही अपनी फसल बोएँ। तथापि, फसल पकने के दौरान अत्यधिक वर्षा सोयाबीन की गुणवत्ता को कम कर सकती है। जहाँ गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, वहीं

सारणी 2: फसल उत्पादन पर वर्षा का असर (दालें)

	(1)	(2)	(3)	(4)
	दालें	अरहर	मूंग	उड़द
ln Rainfall(Actual)	0.333*** (0.107)	0.345*** (0.133)	0.203 (0.206)	0.466*** (0.130)
ln Rainfall*Deficient	-0.017** (0.008)	-0.018* (0.010)	-0.025 (0.019)	0.024*** (0.009)
ln Rainfall*Excess	-0.033*** (0.010)	-0.017* (0.010)	-0.054*** (0.020)	-0.038*** (0.009)
ln AreaSown	1.023*** (0.023)	1.034*** (0.039)	1.048*** (0.071)	1.016*** (0.030)
Constant	11.246*** (0.700)	11.253*** (0.894)	11.623*** (1.313)	9.982*** (0.875)
District FE	हां	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां	हां
N	3307	2519	1827	2603
R <sup>2</sup>	0.95	0.96	0.97	0.96

टिप्पणियां: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।

सारणी 3: फसल उत्पादन पर वर्षा का असर (तिलहन)

	(1)	(2)	(3)	(4)
	तिलहन	सोयाबीन	मूंगफली	सूरजमुखी
ln Rainfall(Actual)	0.303** (0.143)	0.089 (0.084)	0.197 (0.184)	0.382 (0.316)
ln Rainfall*Deficient	-0.005 (0.010)	-0.013 (0.009)	-0.023 (0.025)	0.005 (0.020)
ln Rainfall*Excess	-0.036*** (0.010)	-0.036*** (0.009)	-0.001 (0.014)	0.0001 (0.016)
ln AreaSown	0.911*** (0.051)	0.910*** (0.042)	1.075*** (0.093)	1.028*** (0.046)
Constant	12.350*** (0.963)	13.710*** (0.585)	12.642*** (1.281)	11.171*** (1.888)
District FE	हां	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां	हां
N	2237	1160	1937	315
R <sup>2</sup>	0.92	0.92	0.95	0.96

टिप्पणियां: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

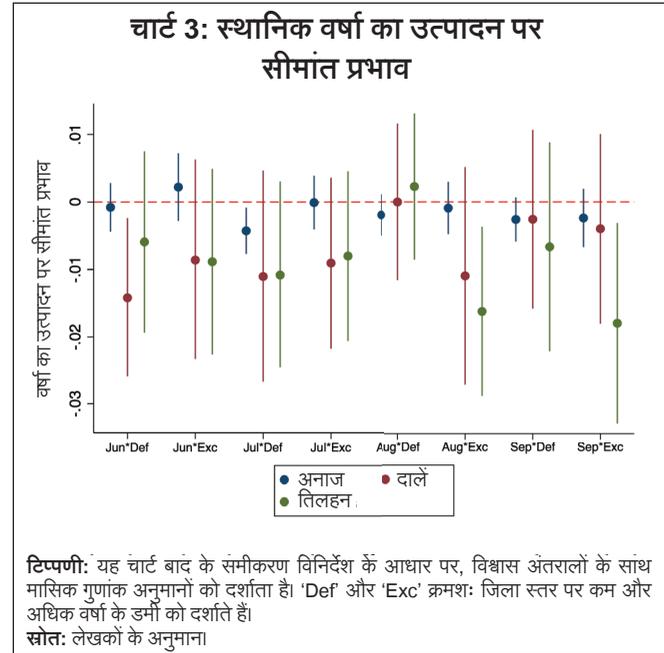
\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।

ठंडा और गीला मौसम अंकुरण में बाधा डालता है और बीज सड़ने का जोखिम बढ़ाता है। हालाँकि हमें मूंगफली पर कम या ज्यादा बारिश का कोई खास असर नहीं दिखता, लेकिन इसका उत्पादन पाले, भयंकर सूखे या रुके हुए पानी जैसी चरम स्थितियों के प्रति संवेदनशील होता है। अधिकतम उपज और उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली प्राप्त करने के लिए फूल आने, फलियाँ बनने और फलियाँ बनने के दौरान पर्याप्त वर्षा बेहद जरूरी है।

सारणियां ए.1-ए.3 एक गतिशील पैनल विनिर्देशन के परिणाम प्रस्तुत करती हैं। उत्पादन पर वर्षा का प्रभाव हमारे आधारभूत विनिर्देशन के अनुरूप प्रतीत होता है। कम या अधिक वर्षा का प्रभाव, प्रभाव की दिशा में सुसंगत होते हुए भी, सांख्यिकीय महत्व की दृष्टि से मामूली विचलन हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ हमारे आधारभूत परिणामों में अत्यधिक वर्षा का दलहन उत्पादन पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं गतिशील पैनल अनुमान के परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं। दूसरी ओर, कम वर्षा का हमारे आधारभूत विनिर्देशन में तिलहन उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गतिशील पैनल विनिर्देशन में इसका नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन मामूली विचलनों को ध्यान में रखते हुए, कुल मिलाकर परिणाम दोनों प्रकार के विनिर्देशनों में एक समान पाए जाते हैं।

सारणी 1, 2 और 3 के परिणाम दर्शाते हैं कि समग्र वर्षा विभिन्न फसलों के उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है और साथ ही कम या अधिक वर्षा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। ये अनुमान पूरे मानसून ऋतु के दौरान कम या अधिक वर्षा के प्रभाव का औसत दर्शाते हैं। हालाँकि, पानी की आवश्यकता, मिट्टी की नमी और उत्पादन चक्र की अवधि के आधार पर प्रत्येक फसल के लिए फसल चक्र अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, धान के खेतों को फसल जीवन चक्र के बढ़ते मौसम के दौरान कम से कम 10 सप्ताह तक पर्याप्त पानी से भरा रहना चाहिए। दूसरी ओर, मक्का की बुवाई उस इष्टतम समय पर की जानी चाहिए जब जलभराव की संभावना कम हो। इसी प्रकार, दलहन और तिलहन खरीफ मौसम में उगाए जाते हैं, हालाँकि ये वर्षा पर निर्भर होते हैं, इसलिए वर्षा का समय और तीव्रता महत्वपूर्ण होती है।



वर्षा के स्थानिक परिवर्तन को बनाए रखते हुए, इसके कालिक पहलू को समझने के लिए, समीकरण 2 दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान कम या अधिक वर्षा के लिए मासिक डमी चर प्रस्तुत करता है। मासिक गुणांक किसी विशेष माह में कम या अधिक वर्षा के सीमांत प्रभाव को दर्शाते हैं (चार्ट 3)। बिंदु बिंदु अनुमानों को दर्शाते हैं जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाएँ 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाती हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि वर्षा का स्थानिक और कालिक वितरण फसल उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अनाज उत्पादन के लिए, जुलाई में कम वर्षा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बुवाई के मौसम में दलहन उत्पादन कम वर्षा के प्रति संवेदनशील होता है, जबकि अगस्त और सितंबर में अधिक वर्षा तिलहन उत्पादन के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार, फसलों की बुवाई, अंकुरण और कटाई के समय के आधार पर, कम या अधिक वर्षा का उत्पादन पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

## VI. निष्कर्ष

यह लेख दक्षिण-पश्चिम मानसून के स्थानिक वितरण पर जोर देते हुए, खरीफ फसल उत्पादन पर वर्षा के प्रभाव की जाँच करता है। हमारा विश्लेषण विभिन्न फसलों के उत्पादन परिणामों को निर्धारित करने में वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, और समय, तीव्रता और वितरण के विभेदक प्रभावों

पर जोर देता है। निष्कर्ष बताते हैं कि औसत वर्षा फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ अनाज, दलहन और तिलहन को समय पर और पर्याप्त वर्षा से लाभ होता है, वहीं प्रमुख विकास चरणों के दौरान कमी या अधिकता के रूप में विचलन से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। चूँकि विभिन्न फसलों के फसल चक्र अलग-अलग होते हैं, इसलिए बुवाई और कटाई के समय अपर्याप्त या अत्यधिक वर्षा समग्र उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल्दी बुवाई की सलाह दी जाती है ताकि मक्के के पौधे विकास की अधिक मजबूत अवस्था तक पहुँच सकें, जिससे वे ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम हो सकें। दिलचस्प बात यह है कि धान की उच्च जल आवश्यकता को देखते हुए, अत्यधिक वर्षा उसके उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकती है। धान की स्थिर जल को सहन करने की क्षमता अत्यधिक वर्षा के प्रति उसके लचीलेपन का कारण हो सकती है।

कुल मिलाकर, परिणाम क्षेत्र-विशिष्ट और फसल-विशिष्ट जल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। जहाँ वर्षा आम तौर पर उत्पादन को बढ़ावा देती है, वहीं अत्यधिक वर्षा, विशेष रूप से मक्का, दलहन और तिलहन के लिए, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती है। नीति निर्माता और कृषि विस्तार सेवाएँ इन जानकारियों का उपयोग फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, जल निकासी के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने और जलभराव के जोखिमों को कम करने वाली रोपण रणनीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रति लचीलापन बढ़ेगा। नीति निर्माताओं और कृषि व्यवसायियों को वर्षा परिवर्तनशीलता के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सिंचाई प्रणालियों में सुधार और लचीली फसल किस्मों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन चुनौतियों का समाधान करके, किसान बदलते मानसून पैटर्न से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बावजूद अधिक स्थिर और टिकाऊ फसल पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

चूँकि जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं का कारण बनता है, इसलिए फसल उत्पादन के लिए जोखिम बढ़ते हैं जा

रहे हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होगा। इसलिए, यह पता लगाने के लिए और अधिक शोध आवश्यक है कि इन चरम घटनाओं का स्थानिक वितरण कृषि उत्पादन और फसल चक्रों को कैसे प्रभावित करता है। यह अध्ययन इसी दिशा में एक प्रयास है।

### संदर्भ

- Auffhammer, M., Ramanathan, V. and Vincent, J.R. (2012). Climate change, the monsoon, and rice yield in India. *Climatic Change* 111, 411–424 (2012).
- Fishman, R. (2016). More uneven distributions overturn benefits of higher precipitation for crop yields. *Environmental Research Letters*, 11(2), 024004.
- Gallé, J., and Katzenberger, A. (2024). Indian agriculture under climate change: The competing effect of temperature and rainfall anomalies. *Economics of Disasters and Climate Change*, 1-53.
- Gupta, K., Kumar, S., and Gulati, S. (2023). Agriculture's dependency on monsoon rainfall in India. Reserve Bank of India Bulletin. August.
- Ghosh, S., Kaustubh. (2023). Weather events and their impact on growth and inflation in India. Reserve Bank of India Bulletin. June.
- Kapur, M. (2018). Macroeconomic policies and transmission dynamics in India. MPRA Working Paper No. 88566, August.
- Meher, J. K., Das, L., and Dutta, M. (2015). Recent trends in monsoon rainfall and its effect on yield of Kharif rice in five subdivisions of North India. *Journal of Agroecology and Nature Resource Management*, 2(3), 192-196.
- Prasanna, V. (2014). Impact of monsoon rainfall on the total foodgrain yield over India. *Journal of Earth System Science*, 123(5), 1129-1145.

Revadekar, J. V., and Preethi, B. (2012). Statistical analysis of the relationship between summer monsoon precipitation extremes and foodgrain yield over India. *International Journal of Climatology*, 32(3), 419-429.

Zachariah, M., Mondal, A., Das, M., AchutaRao, K. M., and Ghosh, S. (2020). On the role of rainfall deficits and cropping choices in loss of agricultural yield in Marathwada, India. *Environmental Research Letters*, 15(9), 094029.

## परिशिष्ट

सारणी ए.1: फसल उत्पादन (अनाज) पर वर्षा का प्रभाव: गतिशील पैनेल अनुमान

	(1)	(2)	(3)
	अनाज	धान	मक्का
In Production(lagged)	0.929*** (0.009)	0.954*** (0.009)	0.888*** (0.024)
In Rainfall(Actual)	0.058*** (0.018)	0.034* (0.020)	0.181*** (0.052)
In Rainfall*Deficient	-0.008*** (0.003)	-0.004* (0.002)	-0.007 (0.009)
In Rainfall*Excess	-0.000 (0.003)	0.003 (0.004)	-0.007 (0.008)
In AreaSown	0.206*** (0.020)	0.133*** (0.016)	0.287*** (0.035)
District FE	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां
N	3575.00	3248.00	2737.00

टिप्पणियां: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।

सारणी ए.2: फसल उत्पादन (दालें) पर वर्षा का प्रभाव: गतिशील पैनेल अनुमान

	(1)	(2)	(3)	(4)
	दालें	अरहर	मूंग	उड़द
In Production(lagged)	0.797*** (0.041)	1.021*** (0.069)	0.894*** (0.084)	0.809*** (0.078)
In Rainfall(Actual)	0.245*** (0.094)	-0.162 (0.152)	0.004 (0.179)	0.292* (0.168)
In Rainfall*Deficient	-0.026** (0.011)	-0.050*** (0.016)	-0.046** (0.020)	0.027** (0.011)
In Rainfall*Excess	-0.010 (0.011)	0.005 (0.017)	-0.005 (0.022)	-0.026* (0.015)
In AreaSown	0.480*** (0.043)	0.205*** (0.069)	0.314*** (0.084)	0.323*** (0.064)
District FE	हां	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां	हां
N	2741.00	2078.00	1447.00	2149.00

टिप्पणियां: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।

**सारणी ए.3: फसल उत्पादन (तिलहन) पर वर्षा का प्रभाव: गतिशील पैनल अनुमान**

	(1)	(2)	(3)	(4)
	तिलहन	सोयाबीन	मूंगफली	सूरजमुखी
ln Production(lagged)	0.940*** (0.042)	0.768*** (0.054)	1.157*** (0.094)	0.721*** (0.050)
ln Rainfall(Actual)	0.118 (0.083)	0.362*** (0.114)	-0.292 (0.188)	0.534*** (0.104)
ln Rainfall*Deficient	-0.020* (0.012)	-0.002 (0.012)	-0.085** (0.041)	-0.071*** (0.024)
ln Rainfall*Excess	-0.014 (0.010)	-0.050*** (0.012)	0.057* (0.031)	0.005 (0.022)
ln AreaSown	0.183*** (0.051)	0.340*** (0.059)	-0.073 (0.099)	0.614*** (0.068)
District FE	हां	हां	हां	हां
State*Year FE	हां	हां	हां	हां
N	2426.00	966.00	1564.00	238.00

टिप्पणियां: मानक त्रुटियों को जिला\*वर्ष स्तर पर समूहीकृत किया गया है।

\* p<0.10, \*\* p<0.05, \*\*\* p<0.01

स्रोत: लेखकों की गणनाएं।



## भारत के धन विप्रेषण की बदलती गतिकी - भारत के विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि

धीरेंद्र गजभिए, सुजाता कुंडू, अलीशा जॉर्ज, ओमकार विन्हेरकर, युसरा अनीस और जितिन बेबी द्वारा ^

यह आलेख 2023-24 के लिए आयोजित भारत के धन विप्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणामों का विश्लेषण करता है। प्रमुख निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारत के आवक धन विप्रेषणों में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और इसने खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी को पीछे छोड़ दिया है, जो कुशल प्रवासी भारतीयों की ओर प्रवासन स्वरूप में बदलाव को दर्शाता है। महाराष्ट्र, इसके बाद केरल और तमिलनाडु प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य बने हुए हैं। भारत में धन विप्रेषण भेजने की लागत डिजिटलीकरण के कारण वैश्विक औसत लागत से कम है, लेकिन फिर भी 200 अमेरिकी डॉलर के लिए 3 प्रतिशत के सतत विकास लक्ष्य से अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, फिनटेक कंपनियां किफायती सीमा-पार धन विप्रेषण सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे विभिन्न धन विप्रेषण सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

### परिचय

भारत का धन विप्रेषण वर्ष 2010-11 के 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दोगुने से भी अधिक बढ़कर 2023-24 में

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। श्री मनीष कपूर और डॉ. सुनील कुमार की महत्वपूर्ण टिप्पणियों और मार्गदर्शन के लिए लेखक उनके प्रति कृतज्ञ हैं। लेखक, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के प्राधिकृत व्यक्तियों एवं विप्रेषण प्रभाग और बाह्य भुगतान प्रभाग से प्राप्त सुझावों के लिए भी आभारी हैं।

1 भारत की निवल विप्रेषण प्राप्तियों ने 2010-11 से 2023-24 (महामारी वर्ष 2020-21 को छोड़कर) के दौरान वार्षिक औसत आधार पर पण्य व्यापार घाटे के लगभग 42.0 प्रतिशत का वित्तपोषण किया है।

118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत के व्यापारिक घाटे<sup>1</sup> के लगभग आधे हिस्से का वित्तपोषण करते हुए, निवल धन विप्रेषण प्राप्तियां इस अवधि के दौरान बाह्य आघातों को अवशोषित करने में एक महत्वपूर्ण साधन रही हैं। इसके अलावा, भारत की धन विप्रेषण प्राप्तियां आम तौर पर भारत के सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह से अधिक रही हैं, जिससे बाह्य वित्तपोषण के एक स्थिर स्रोत के रूप में उनका महत्व स्थापित होता है। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान महामारी-प्रेरित 3.6 प्रतिशत के संकुचन के बाद, महामारी के बाद की अवधि (2021-22 से 2023-24) में भारत में धन विप्रेषण में 14.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ पुनरुत्थान दर्ज किया गया।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख 2023-24 के लिए भारत के आवक धन विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणाम प्रस्तुत करता है।<sup>2</sup> यह भारत में आवक धन विप्रेषण के विभिन्न आयामों को दर्शाता है - देश-वार विप्रेषण का स्रोत, राज्य-वार विप्रेषण का गंतव्य स्थान, लेन-देन के अनुसार विप्रेषण का आकार, अग्रेशन के प्रचलित तरीके, भारत में विप्रेषण भेजने की लागत और नकदी की तुलना में डिजिटल मोड के माध्यम से प्रेषित विप्रेषण का हिस्सा। सर्वेक्षण के परिणाम 30 प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं (परिवार के निर्वाह और बचत<sup>3</sup> के तहत रिपोर्ट किए गए आवक विप्रेषण के कुल मूल्य का लगभग 99 प्रतिशत शामिल करते हुए) पर आधारित हैं। सर्वेक्षण में दो प्रमुख मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ)<sup>4</sup> और दो फिनटेक कंपनियां<sup>5</sup> भी शामिल हैं (ii) रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के कवरेज को एक्सचेंज हाउस/एमटीओ और फिनटेक में वर्गीकृत करना; (iii) धन विप्रेषण आकार ब्रैकेट की सीमा और संख्या का विस्तार करना; (iv) एमटीओ द्वारा किए गए नकद/

<sup>2</sup> 2020-21 के लिए किए गए सर्वेक्षण के पाँचवें दौर के परिणाम आरबीआई मासिक बुलेटिन के जुलाई 2022 अंक में प्रकाशित हुए। इससे पहले सर्वेक्षण के परिणाम आरबीआई मासिक बुलेटिन के नवंबर 2006, अप्रैल 2010, दिसंबर 2013 और नवंबर 2018 के अंकों में प्रकाशित हुए थे।

<sup>3</sup> विदेशी मुद्रा कारोबार - इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीईआरएस) से संबंधिता

<sup>4</sup> वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इन्कॉर्पोरेशन और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इन्कॉर्पोरेशन

<sup>5</sup> रेमिटली इन्कॉर्पोरेशन और रेमिटबी।

डिजिटल हस्तांतरण को शामिल करना; और v) डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव का आकलन करने के लिए सीमा पार धन विप्रेषण सेवाएं प्रदान करने वाली दो अग्रणी फिनटेक कंपनियों को शामिल करना।

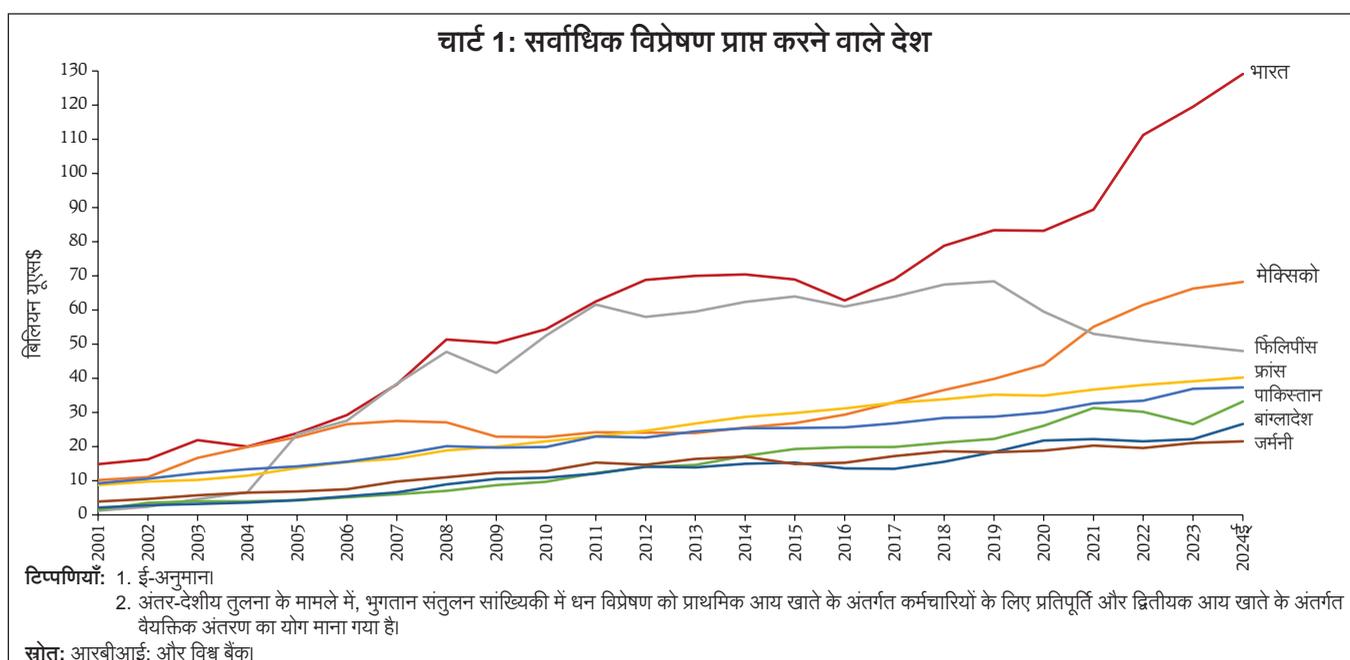
विश्व स्तर पर, आवक धन-विप्रेषण सीमा-पार घरेलू आय के प्रवाह को दर्शाते हैं, जो लोगों के विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में अस्थायी या स्थायी प्रवास से उत्पन्न होता है। इसके अलावा, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ, 2009) द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन (बीओपी) के आँकड़ों में दो मर्दे धन-विप्रेषण से संबंधित होती हैं - प्राथमिक आय खाते के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति और द्वितीयक आय खाते के अंतर्गत वैयक्तिक हस्तांतरण। भारत के संदर्भ में, वैयक्तिक हस्तांतरण, जिनमें मुख्य रूप से विदेश में रहने वाले भारतीय श्रमिकों द्वारा परिवार के भरण-पोषण के लिए आवक धन-विप्रेषण और अनिवासी जमा खातों से स्थानीय आहरण शामिल हैं, सीमा-पार आवक धन-विप्रेषण का एक मुख्य हिस्सा बनते हैं।

आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है - भाग II में वैश्विक और भारत के आवक विप्रेषणों के बारे में शोधपरक तथ्य

प्रस्तुत किए गए हैं। भाग III में भारत में धन विप्रेषण प्राप्त करने के विभिन्न माध्यमों का वर्णन किया गया है। भाग IV में सर्वेक्षण के छठे दौर के निष्कर्षों का विवरण दिया गया है। भाग V में कुछ नीतिगत सुझावों के साथ आलेख का समापन किया गया है।

## II. शोधपरक तथ्य

विश्व विप्रेषण के वर्ष 2024 में 905 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) को 75 प्रतिशत से अधिक (लगभग 685 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त होगा [रथ एवं अन्य, 2024]। विश्व बैंक के अनुसार, भारत 2008 से विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है, विश्व विप्रेषण में इसका हिस्सा 2001 के लगभग 11 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 14 प्रतिशत हो गया है। आगे चलकर, भारत में विप्रेषण का उच्च स्तर बने रहने की संभावना है और वर्ष 2029 में इसके लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का पूर्वानुमान है (आरबीआई, 2024)।<sup>6</sup> विप्रेषण के अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ताओं में मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं (चार्ट 1)। यद्यपि भारत में धन विप्रेषण का प्रवाह महामारी वर्ष 2020-21 के दौरान थोड़े-बहुत वर्ष-दर-वर्ष संकुचन के साथ सुदृढ़ बना रहा, तथापि



<sup>6</sup> अध्याय 4 - खुली अर्थव्यवस्था डिजिटलीकरण: चुनौतियां और अवसर, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट (आरसीएफ), 2023-24, आरबीआई।

उसके बाद से इसका पुनरुत्थान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में रोजगार की स्थिति में सुधार से प्रेरित है।

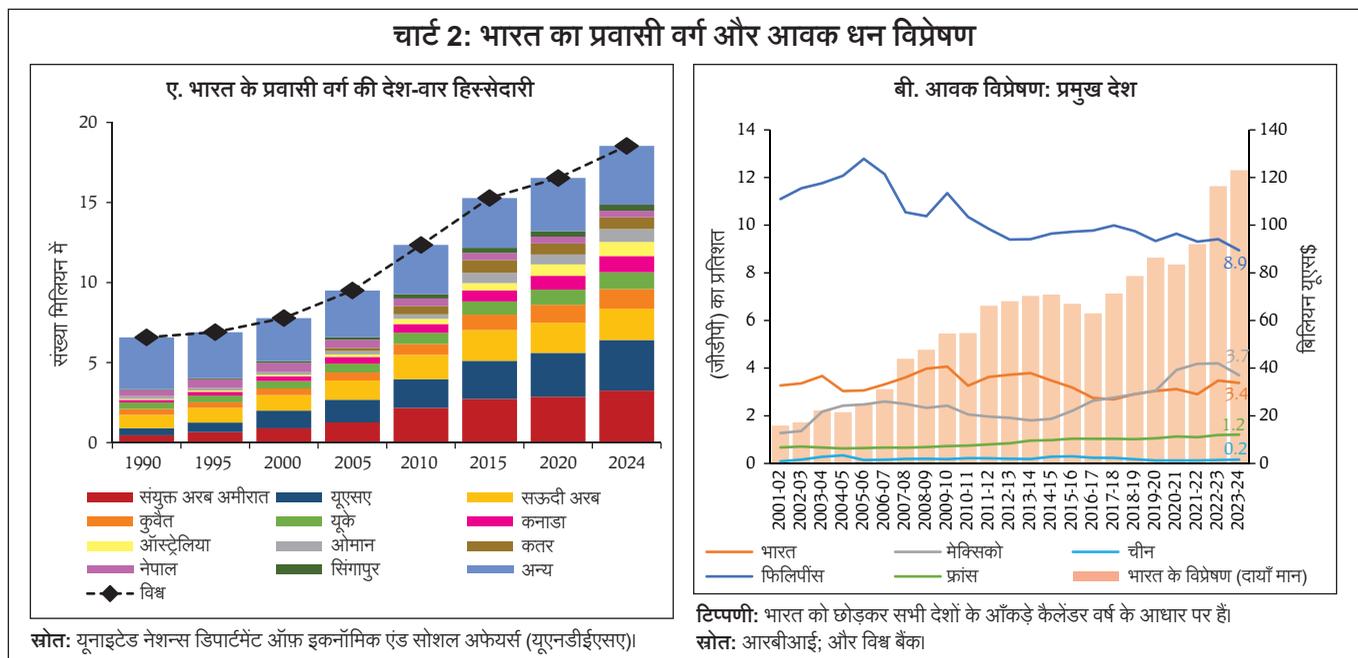
भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 1990 के 66 लाख (6.6 बिलियन) से तीन गुना बढ़कर 2024 में 185 लाख हो गई है और इसी अवधि में वैश्विक प्रवासियों में इसकी हिस्सेदारी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।<sup>7</sup> खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में भारतीय प्रवासी, दुनिया के कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा हैं (चार्ट 2ए)। सदी की शुरुआत में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और विदेशों में भारतीय आईटी सेवाओं की पहुंच के बाद, उन्नत आर्थिक क्षेत्रों (ईई) में, विशेष रूप से अमेरिका में कुशल प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चक्रवर्ती एवं अन्य, 2016; खन्ना एंड मोराल्स, 2023)। इस प्रकार, जीसीसी देशों के अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (ईई) भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में आवक धन विप्रेषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं, जो भारत के प्रवासी समुदाय की बदलती गतिशीलता को दर्शाता है। चूंकि भारत की कार्यशील आयु वर्ग वाली जनसंख्या के वर्ष 2048 तक बढ़ने की उम्मीद है, भारत दुनिया का अग्रणी श्रम आपूर्तिकर्ता होगा (आरबीआई, 2024)। इसलिए, कार्यबल का निरंतर कौशल विकास और पुनर्कौशलिकरण इसकी क्षमता का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

जीडीपी के अनुपात के रूप में, भारत का धन विप्रेषण वर्ष 2000 से सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहा है, जबकि चीन के मामले में यह अनुपात 0.3 प्रतिशत से कम बना हुआ है (चार्ट 2बी)। दूसरी ओर, फिलीपींस को पिछले दस वर्षों के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कहीं अधिक धन विप्रेषित हुआ है।

विभिन्न देशों में श्रम के बढ़ते प्रवाह के साथ, कई विकासशील देशों, विशेषकर छोटे देशों, जहाँ ये उनके सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा हैं, के लिए धन विप्रेषण विदेशी आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया है (रथ एवं अन्य, 2024)। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत के संदर्भ में आवक धन विप्रेषण पण्य व्यापार घाटे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का वित्तपोषण करता है (चार्ट 3ए)। इसके अलावा, सदी की शुरुआत से आवक धन विप्रेषण सामान्य तौर पर भारत के सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से आगे निकल गया है और इसलिए यह विदेशी आय का एक स्थिर स्रोत बनकर उभरा है (चार्ट 3बी)।

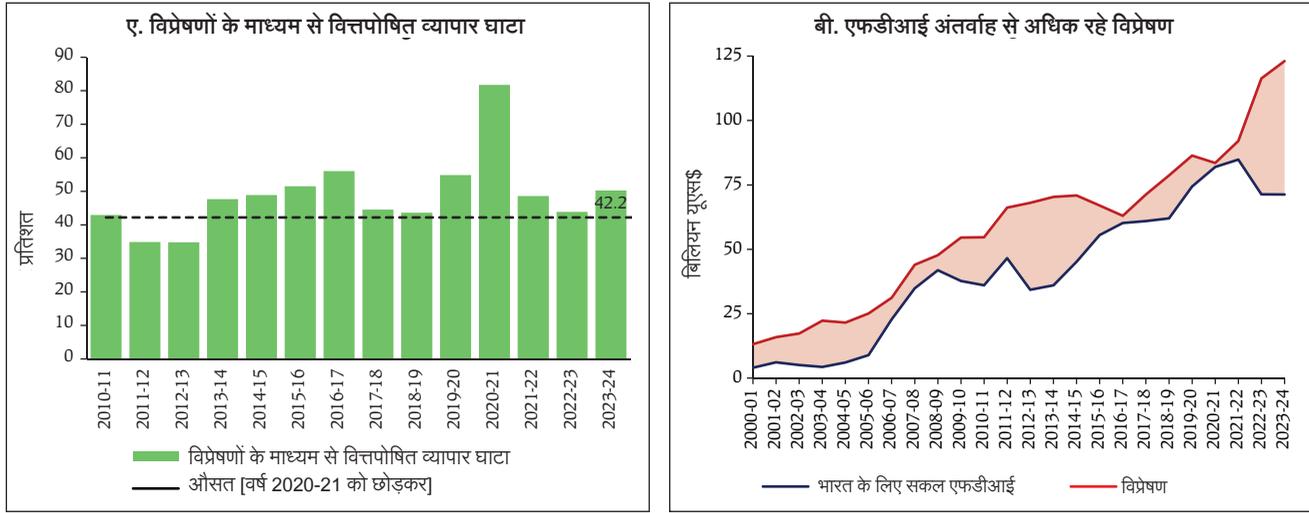
### विप्रेषण की लागत

धन विप्रेषण लेनदेन की लागत में दो तत्व शामिल होते हैं - लेनदेन के किसी भी चरण पर लिया जाने वाला शुल्क और



<sup>7</sup> डिपार्टमेंट ऑफ़ इकॉनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डेटाबेस (2024), संयुक्त राष्ट्र।

**चार्ट 3: भारत का आवक विप्रेषण बनाम पण्य व्यापार घाटा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह**



स्रोत: आरबीआई

स्थानीय मुद्रा से प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा में विनिमय दर रूपांतरण (विश्व बैंक और बीआईएस, 2007)। इस तथ्य को देखते हुए कि आवक धन विप्रेषण बड़े पैमाने पर परिवार के भरण-पोषण के लिए होते हैं, सीमा-पार धन भेजने की लागत का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है और इसलिए, इस लागत को कम करना - एक दशक से अधिक समय से वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत एजेंडा रहा है। विश्व बैंक का रेमिटेंस प्राइस वर्ल्डवाइड (आरपीडब्ल्यू) डेटाबेस, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रयोजन की दिशा में प्रगति को मापने के लिए 350 से अधिक कॉरिडोर की निगरानी करता है।<sup>8</sup> 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की वैश्विक औसत लागत में 2009 की पहली तिमाही के 9.67 प्रतिशत से 2024 की दूसरी तिमाही में 6.65 प्रतिशत तक एक निरंतर गिरावट देखी गई, हालाँकि भारत के मामले में यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2023 में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत 4.9 प्रतिशत होने के साथ, भारत में

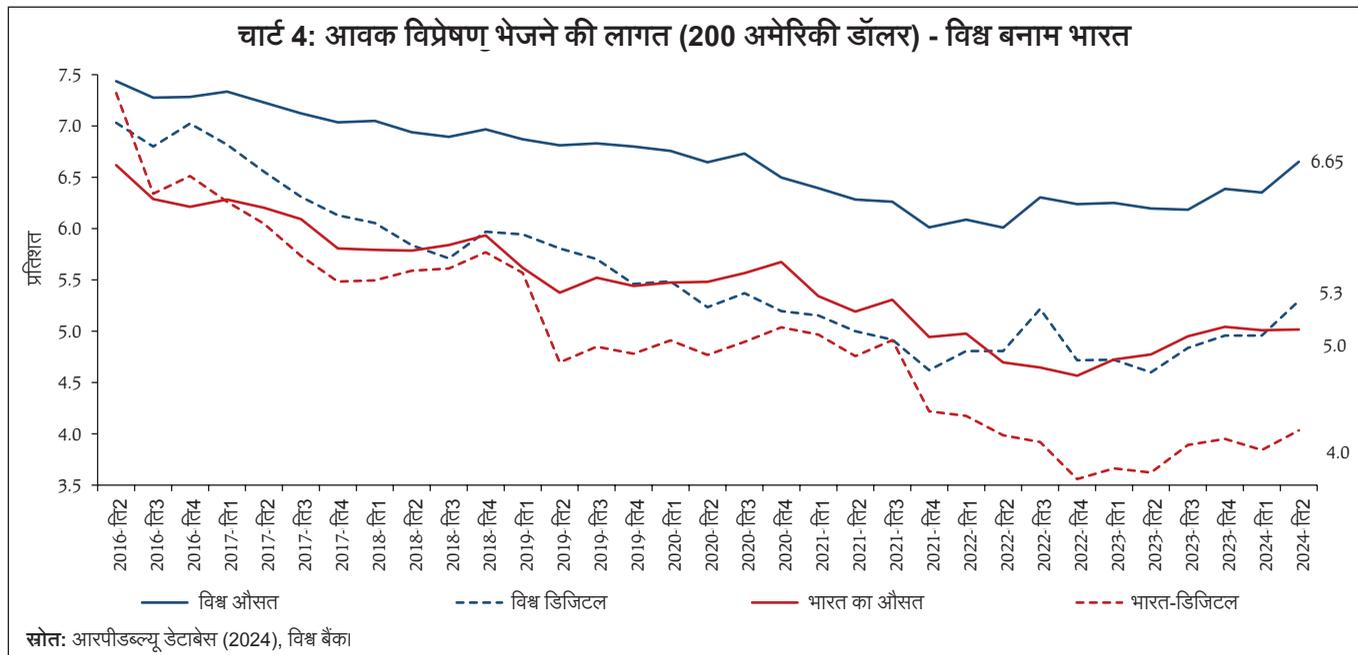
<sup>8</sup> प्रवासी धन विप्रेषण की अल्प लागत के महत्व को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में शामिल करने के साथ और भी बल मिला है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रवासी धन विप्रेषण की औसत लागत को 3 प्रतिशत या उससे कम तक लाना और उन कॉरिडोर को समाप्त करना है जहाँ लागत 5 प्रतिशत से अधिक है। लक्षित संकेतक 200 अमेरिकी डॉलर (या स्थानीय विप्रेषण मुद्रा में समतुल्य) भेजने की वैश्विक औसत लागत है, जिसे भेजी गई राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

धन विप्रेषण भेजने की लागत न केवल विश्व औसत लागत से कम है, बल्कि धन विप्रेषण लागत की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हुए, प्रारंभिक जी20 लक्ष्य<sup>9</sup> को भी पूरा कर चुकी है। इसके अलावा, भारत 200 अमेरिकी डॉलर भेजने के लिए अल्प लागत वाले देशों में से एक बना हुआ है।

### नकद और डिजिटल अंतरण

डिजिटल विप्रेषण की विश्व बैंक की परिभाषा में ऐसे सभी लेनदेन शामिल हैं जिनमें भुगतान ऑनलाइन या स्व-सहायता प्राप्त तरीके से किया जाता है और लेनदेन खाते (बैंक या गैर-बैंक जमाराशि स्वीकार करने वाली संस्था), मोबाइल मनी या ई-मनी खाते में प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल विप्रेषण का प्रसार तेजी से हुआ है। एमटीओ ने डिजिटल निधीयन और संवितरण को और सक्षम किया है। मोबाइल मनी-सक्षम अंतरराष्ट्रीय विप्रेषण अंतरण ने वैश्विक स्तर पर महामारी की अवधि के दौरान गति पकड़ी, और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन

<sup>9</sup> 2024 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में भारत में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत क्रमशः 5.01 प्रतिशत और 5.02 प्रतिशत रही (विश्व बैंक, 2024)।



(जीएसएमए) ने अनुमान लगाया कि उनका मूल्य 2019 के 8 बिलियन यूएस\$ के दोगुने से अधिक होकर 2021 में 17 बिलियन यूएस\$ हो गया, और 2023 में यूएस\$ 29 बिलियन हो गया (जीएसएमए, 2024)। डिजिटल धन हस्तांतरण की लागत, जो 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान आरपीडब्ल्यू डेटाबेस में कुल लेनदेन का 30 प्रतिशत थी, 5.3 प्रतिशत थी, जो वैश्विक औसत लागत से 136 आधार अंक कम थी (चार्ट 4)। इसी प्रकार, भारत में डिजिटल धन विप्रेषण की लागत 2024 की दूसरी तिमाही तक 4.0 प्रतिशत थी, जो भारत के 5.0 प्रतिशत की औसत लागत से लगभग 100 आधार अंक कम है, जो धन विप्रेषण लागतों के अनुकूलन में डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह देश और विदेश में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाने के महत्व को रेखांकित करता है। भारत दुनिया भर में अन्य तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को जोड़ने के लिए कई द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के साथ सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के प्रयासों में अग्रणी रहा है और चार आसियान देशों (मलेशिया,

फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के एफपीएस के बहुपक्षीय संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस में इसकी भागीदारी है [आरबीआई, 2025]।

### III. भारत में आवक विप्रेषण के विभिन्न चैनल

धन विप्रेषण करने वाला देश तीन चैनलों के माध्यम से भारत में धन हस्तांतरित कर सकता है - (i) विदेशी बैंक; (ii) मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ); और (iii) फिनटेक (जिन्हें रेमटेक या केवल डिजिटल एमटीओ<sup>11</sup> भी कहा जाता है) [चार्ट 5]। विदेशी बैंक या तो प्रतिनिधि बैंक का एक नोस्ट्रो खाता बनाये रख सकते हैं या भारत में अपने सहभागी बैंक के साथ एक वोस्ट्रो खाता खोल सकते हैं। धन हस्तांतरित करने का निर्देश सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) मैसेजिंग सेवा या बैंक के अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करके भेजा जा सकता है। प्रतिनिधि बैंक/सहभागी बैंक द्वारा प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और

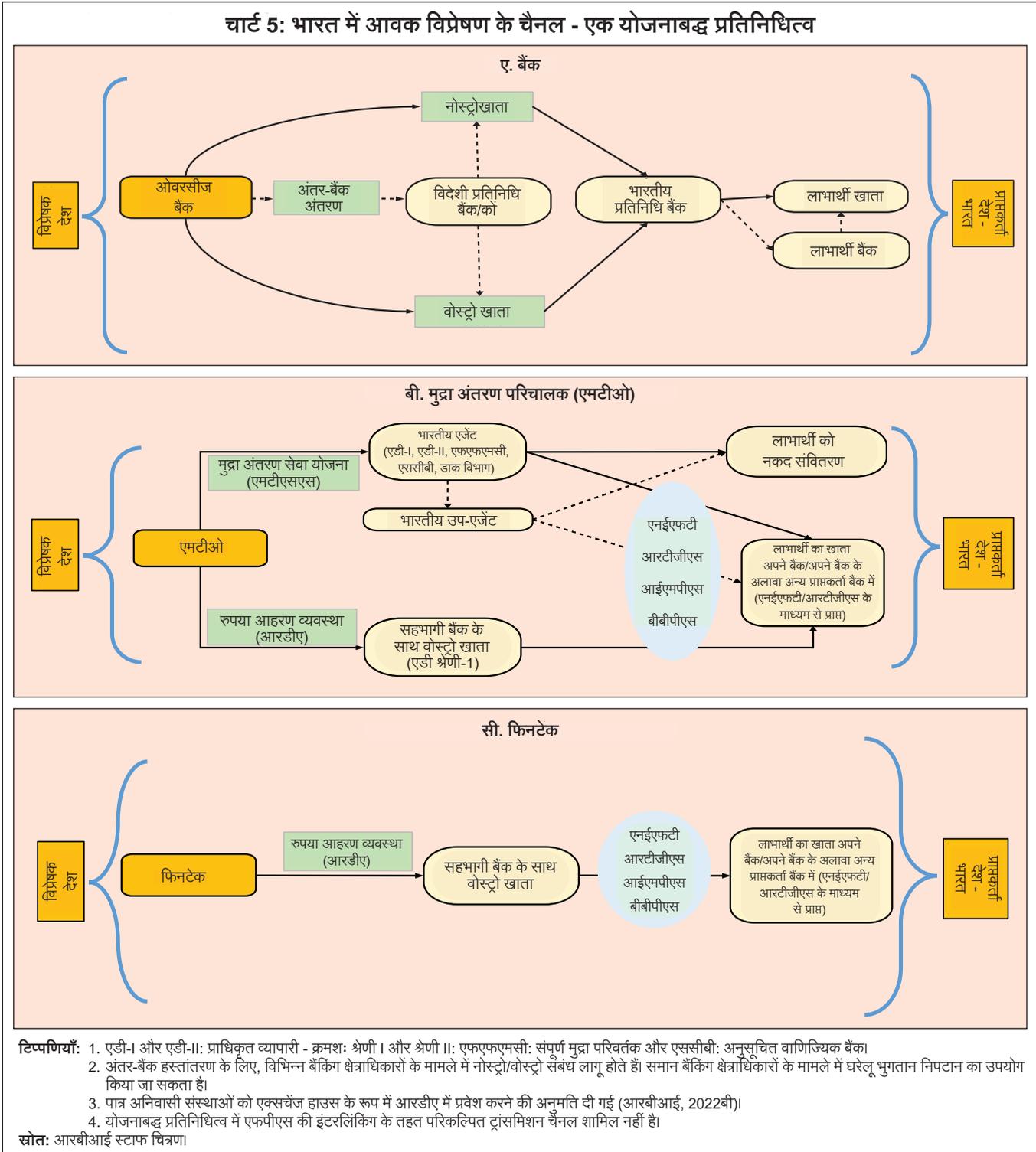
<sup>10</sup> धन विप्रेषण हस्तांतरण में विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियाँ।

<sup>11</sup> डिजिटल-ओनली एम.टी.ओ. से तात्पर्य ऐसे मुद्रा अंतरण परिचालकों से है जो डिजिटल चैनलों के माध्यम से धन विप्रेषण भेजते हैं (विश्व बैंक, 2024)।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) जैसी विभिन्न भुगतान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजा जा सकता

है। एमटीओ दो योजनाओं के माध्यम से भारत में धन हस्तांतरित करते हैं - मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)<sup>12</sup> और रुपया

**चार्ट 5: भारत में आवक विप्रेषण के चैनल - एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व**



<sup>12</sup> एमटीएसएस में केवल वैयक्तिक धन विप्रेषण अनुमत हैं, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 2,500 अमेरिकी डॉलर और प्रति लाभार्थी सालाना 30 धन विप्रेषण है। व्यापार, संपत्ति खरीद, निवेश या धर्मार्थ दान के लिए धन विप्रेषण निषिद्ध है। इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई द्वारा अधिकृत विदेशी मुद्रा अंतरण कंपनियों (विदेशी प्रमुख) और घरेलू संस्थाओं (भारतीय एजेंटों) के बीच समझौता शामिल है।

आहरण व्यवस्था (आरडीए)<sup>13</sup>, जबकि फिनटेक<sup>14</sup> केवल आरडीए चैनल के माध्यम से ही संचालन कर सकते हैं।<sup>15</sup>

#### IV. भारत का आवक धन विप्रेषण: सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि

आवक विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर<sup>16</sup> में 30 एडी बैंक (परिवार के भरण-पोषण और बचत के उद्देश्य से रिपोर्ट किए गए कुल आवक विप्रेषण के मूल्य का लगभग 99 प्रतिशत), दो प्रमुख एमटीओ और सीमा पार विप्रेषण कारोबार में कार्यरत दो फिनटेक कंपनियां शामिल थीं। विप्रेषण के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष - विप्रेषण के हस्तांतरण या प्राप्ति के तरीके को बदल रहे हैं।

##### विप्रेषण का स्रोत

सर्वेक्षण के परिणाम जीसीसी देशों से आई (विशेष रूप से अमेरिका, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो 2023-24 में आधे से अधिक विप्रेषण के लिए जिम्मेदार थे) में भारत के विप्रेषण के प्रभुत्व में क्रमिक बदलाव को उजागर करते हैं। भारत के कुल विप्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही, जो 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में

<sup>13</sup> आरडीए भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों और गैर-निवासी विनिमय प्रतिष्ठान के बीच खाड़ी देशों, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया (केवल स्पीड रेमिटेंस प्रक्रिया के तहत मलेशिया के लिए) और अन्य सभी देशों में अपने रुपया वोस्ट्रो खातों के माध्यम से सीमा पार विप्रेषण सक्षम बनाता है जो वित्तीय कार्यवाही कार्यबल (एफएटीएफ) के अनुरूप हैं (केवल स्पीड रेमिटेंस प्रक्रिया के तहत)। हालांकि ऐसे गैर-निवासी विनिमय प्रतिष्ठान विप्रेषण क्षेत्राधिकार में उनके वर्गीकरण के अनुसार फिनटेक भी हो सकते हैं, लेकिन आरडीए योजना में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में फिनटेक की परिकल्पना नहीं की गई है। आरडीए अलग-अलग व्यक्तियों के बीच निजी विप्रेषण की अनुमति देता है, जिसमें व्यापार संबंधी लेनदेन के लिए सीमित प्रावधान हैं, जिनकी सीमा ₹15 लाख है। एमटीएसएस के विपरीत, आरडीए में वैयक्तिक धन विप्रेषण की राशि या आवृत्ति पर कोई सीमा नहीं है और यह केवल आवक हस्तांतरण के लिए है।

<sup>14</sup> फिनटेक कंपनियां जिनके पास संबंधित स्थानीय मौद्रिक/पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस हैं तथा जिनके पास मुद्रा विनिमय/धन हस्तांतरण कारोबार करने के लिए आवश्यक प्राधिकार/लाइसेंस है।

<sup>15</sup> हाल ही में, आरबीआई एफपीएस को आपस में जोड़ने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। उदाहरण के लिए, यूपीआई-पेनाउ लिंकेज इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे सिंगापुर और भारत ने ओपन बैंकिंग एपीआई का लाभ उठाकर संबंधित देशों में भाग लेने वाली वित्तीय संस्थाओं के खाताधारकों को अपने-अपने एफपीएस का उपयोग करके निर्बाध लेनदेन करने की अनुमति दी है। (आरबीआई, 2024)।

<sup>16</sup> शीर्ष धन-विप्रेषण प्राप्त करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के आवक धन-विप्रेषणों की संकलन पद्धति का विवरण, साथ ही उनके धन-विप्रेषण सर्वेक्षण, यदि कोई हो, अनुबंध सारणी ए1 में उल्लिखित हैं।

#### सारणी 1: भारत के आवक विप्रेषण में स्रोत देश-वार हिस्सेदारी (बैंक)

स्रोत देश	2016-17	2020-21	2023-24
संयुक्त राज्य	22.9	23.4	27.7
संयुक्त अरब अमीरात	26.9	18.0	19.2
यूनाइटेड किंगडम	3.0	6.8	10.8
सऊदी अरब	11.6	5.1	6.7
सिंगापुर	5.5	2.4	6.6
कुवैत	6.5	1.5	3.9
कतर	-	5.7	4.1
कनाडा	3.0	1.6	3.8
ओमान	1.0	0.6	2.5
ऑस्ट्रेलिया	-	-	2.3
बहरीन	0.7	0.7	1.5
हांगकांग	-	-	1.3
जर्मनी	0.6	0.6	1.0
बेल्जियम	0.9	1.1	0.4
मलेशिया	-	-	0.6
न्यूजीलैंड	2.3	0.7	0.5
आयरलैंड	-	-	0.4
नीदरलैंड	-	-	0.5
जापान	-	-	0.3
स्विट्जरलैंड	-	-	0.4
फ्रांस	0.1	0.1	0.2
इटली	-	-	0.1
इंडोनेशिया	-	-	0.2
थाईलैंड	-	-	0.2
दक्षिण अफ्रीका	-	-	0.1
स्पेन	-	-	0.1
अन्य	14.8	31.6	4.4

**टिप्पणी:** 2023-24 के लिए, शेयर आवक विप्रेषण के दो प्रमुख घटकों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं - (क) पारिवारिक भरण-पोषण और बचत हेतु अंतरण; (ख) अनिवासी जमा खातों से स्थानीय स्तर पर आहरण।

**स्रोत:** 2016-17 और 2020-21 के लिए आँकड़े क्रमशः आरबीआई के विप्रेषण सर्वेक्षणों - आरबीआई (2018) और आरबीआई (2022ए) से प्राप्त किए गए हैं।

27.7 प्रतिशत हो गई (सारणी 1), जो अमेरिकी नौकरी बाजार में स्थिर सुधार को दर्शाती है। अमेरिकी श्रम बल में, विदेश में जन्मे श्रमिकों की प्रतिशत वृद्धि 2022 में 6.3 प्रतिशत रही, जो 2019 के महामारी-पूर्व वर्ष में 0.7 प्रतिशत थी; हालांकि, मूल रूप से जन्मे श्रमिकों के मामले में हिस्सेदारी मोटे तौर पर 1.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही।<sup>17</sup> इसके अलावा, अमेरिका में 78 प्रतिशत भारतीय प्रवासी प्रबंधन, कारोबार, विज्ञान और कला व्यवसायों जैसे उच्च आय वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं (ग्रीन और बटालोवा,

<sup>17</sup> श्रम सांख्यिकी ब्यूरो, अमेरिकी श्रम विभाग। विदेश में जन्मे श्रमिक: श्रम बल विशेषताएँ

2024)<sup>18</sup> यूके से प्राप्त आवक विप्रेषण का हिस्सा भी 2020-21 में 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.8 प्रतिशत हो गया है, जिसका श्रेय भारत और यूके के बीच 'प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी' (मई 2021) को दिया जा सकता है।<sup>19</sup> प्रत्येक वर्ष यूके जाने वाले भारतीयों की संख्या 2020 के अंत तक 76,000 से तीन गुना से अधिक बढ़कर 2023 के अंत तक लगभग 250,000 हो गई है, जिनमें से लगभग आधे लोग काम से संबंधित उद्देश्य के लिए गए थे।<sup>20</sup> 2023-24 में सिंगापुर (6.6 प्रतिशत), कनाडा (3.8 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (2.3 प्रतिशत) से प्राप्त विप्रेषण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेषकर महामारी वर्ष (2020-21) से तुलना करने पर। हाल के वर्षों में, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों के लिए कनाडा एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। जनवरी 2024 तक, विदेश में पढ़ रहे कुल 13.4 लाख भारतीय छात्रों में से, कनाडा में पढ़ने वाले छात्रों की हिस्सेदारी 32.0 प्रतिशत थी, इसके बाद अमेरिका (25.3 प्रतिशत), यूके (13.9 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (9.2 प्रतिशत) का स्थान था।<sup>21</sup>

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भारत के धन विप्रेषण के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिसका हिस्सा 2020-21 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गया। यूएई मुख्य रूप से ब्लू-कॉलर नौकरियों में संलग्न भारतीय प्रवासी श्रमिकों का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसमें निर्माण उद्योग का प्रभुत्व है, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग हैं।<sup>22</sup> यह अमेरिका के बिल्कुल विपरीत है जहां भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से सफेदपोश नौकरियों में कार्यरत हैं, इस प्रकार यूएई की तुलना में प्रवासियों की कम संख्या के

## सारणी 2: भारत के आवक विप्रेषण की राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश-वार हिस्सेदारी 2023-24

गंतव्य राज्य	2016-17	2020-21	2023-24
महाराष्ट्र	16.7	35.2	20.5
केरल	19.0	10.2	19.7
तमिलनाडु	8.0	9.7	10.4
तेलंगाना	-	-	8.1
कर्नाटक	15.0	5.2	7.7
आंध्र प्रदेश	4.0	4.4	4.4
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	5.9	9.3	4.3
पंजाब	1.7	3.0	4.2
गुजरात	2.1	3.2	3.9
उत्तर प्रदेश	3.1	3.7	3.0
हरियाणा	0.8	1.2	2.9
पश्चिम बंगाल	2.7	1.4	2.3
राजस्थान	1.2	1.2	1.5
बिहार	1.3	1.4	1.3
उत्तराखंड	0.2	0.7	1.1
गोवा	0.8	1.1	0.9
मध्य प्रदेश	0.4	0.5	0.9
ओडिशा	0.4	0.5	0.6
झारखंड	0.3	1.9	0.4
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.3	0.4
चंडीगढ़	0.2	0.4	0.4
पुडुचेरी	0.2	0.2	0.3
हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.2
असम	0.1	0.2	0.2
छत्तीसगढ़	0.1	0.3	0.1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	0.1	0.08
त्रिपुरा	-	1.1	0.04
मणिपुर	-	-	0.03
मेघालय	-	-	0.03
मिजोरम	-	-	0.03
लद्दाख	-	-	0.02
सिक्किम	-	-	0.02
नगालैंड	-	-	0.02
लक्षद्वीप	-	-	0.01
अरुणाचल प्रदेश	-	0.1	0.01
अंडमान और निकोबार	-	-	0.01

**टिप्पणियाँ:** (i) 2023-24 के लिए, आवक विप्रेषण के दो प्रमुख घटकों के आधार पर श्रेय व्युत्पन्न किए गए हैं - (ए) परिवार के रखरखाव और बचत के लिए अंतरण; (बी) अनिवासी जमा खातों से स्थानीय निकासी।  
(ii) 2023-24 में, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डेटा प्रस्तुत किए गए हैं जिन्हें सर्वेक्षण के पिछले दौर में 'अन्य' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

**स्रोत:** 2016-17 और 2020-21 के डेटा क्रमशः आरबीआई (2018) और आरबीआई (2022ए) से प्राप्त किए गए हैं।

बावजूद यह अमेरिका से प्राप्त उच्च विप्रेषण का स्पष्टीकरण देता है। जीसीसी देशों (यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन) ने मिलकर 2023-24 में भारत द्वारा प्राप्त कुल विप्रेषण

<sup>18</sup> <https://datausa.io/profile/soc/management-business-science-arts-occupations>

<sup>19</sup> <https://www.gov.uk/government/news/uk-india-agree-partnership-to-boost-work-visas-for-indian-nationals>

<sup>20</sup> <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisional/yearendingdecember2023>

<sup>21</sup> लोक सभा अतारांकित (अनस्टाई) प्रश्न संख्या-894, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से आँकड़े उपलब्ध हैं।

<sup>22</sup> <https://www.news18.com/business/indian-migrant-workers-middle-east-uae-saudi-arabia-oman-kuwait-jobs-8945228.html>

में 38 प्रतिशत का योगदान दिया, (कोविड-19 महामारी वर्ष) 2020-21 में दर्ज की गई हिस्सेदारी से अधिक है।<sup>23</sup> महामारी वर्ष के दौरान जीसीसी क्षेत्र से कम धन विप्रेषण का कारण इस क्षेत्र से संविदा प्रवासी श्रमिकों का बड़े पैमाने पर भारत वापस लौटना था।

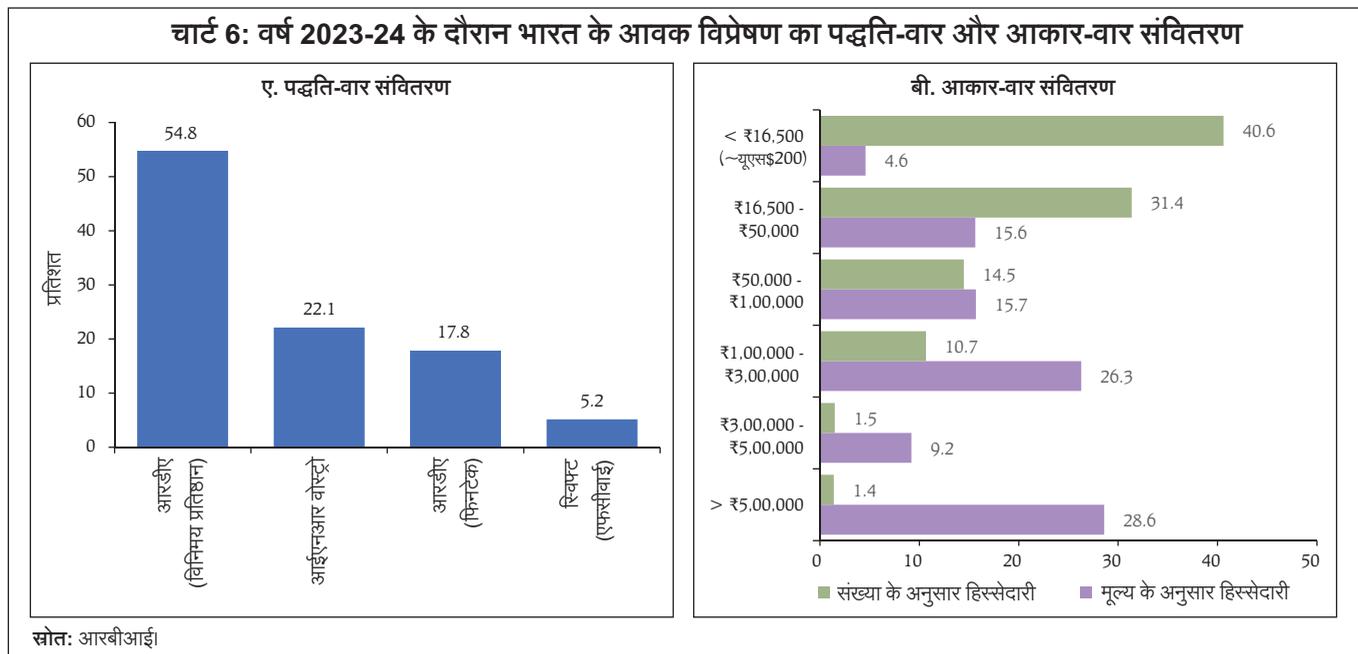
### विप्रेषण का गंतव्य स्थान

वर्ष 2023-24 में राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी)-वार धन विप्रेषण स्थलों की ओर रुख करते हुए, महाराष्ट्र को 20.5 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, हालांकि यह 2020-21 (35.2 प्रतिशत) से कम था [सारणी 2]।<sup>24</sup> केरल का स्थान इसके एकदम बाद रहा और इसी अवधि के दौरान इसकी हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर 19.7 प्रतिशत हो गई, इसके बाद तमिलनाडु (10.4 प्रतिशत), तेलंगाना (8.1 प्रतिशत) और कर्नाटक (7.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब से शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले और

रोजगार के अवसरों के लिए यहीं रुकने वाले भारतीय छात्रों की सबसे बड़ी संख्या है, जो भारत के आवक धन विप्रेषण में इन राज्यों की बढ़ती हिस्सेदारी में परिलक्षित होता है। केरल प्रवासन सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि 2023 में केरल से कुल प्रवासियों में छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट बताती है कि छात्रों के प्रवासन स्वरूप में उल्लेखनीय बदलाव आया है और गैर-जीसीसी देशों को गंतव्य के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक से भी बड़ी संख्या में छात्र और श्रमिक विदेश जाते हैं।

### विप्रेषण: माध्यम और आकार

जैसा कि खंड III में वर्णित है, बैंक विभिन्न तरीकों से धन विप्रेषण प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें से आरडीए चैनल की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, इसके बाद विदेशी बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष वोस्ट्रो स्थानांतरण और फिनटेक द्वारा संचालित आरडीए चैनल है (चार्ट 6)। प्रेषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैनल का



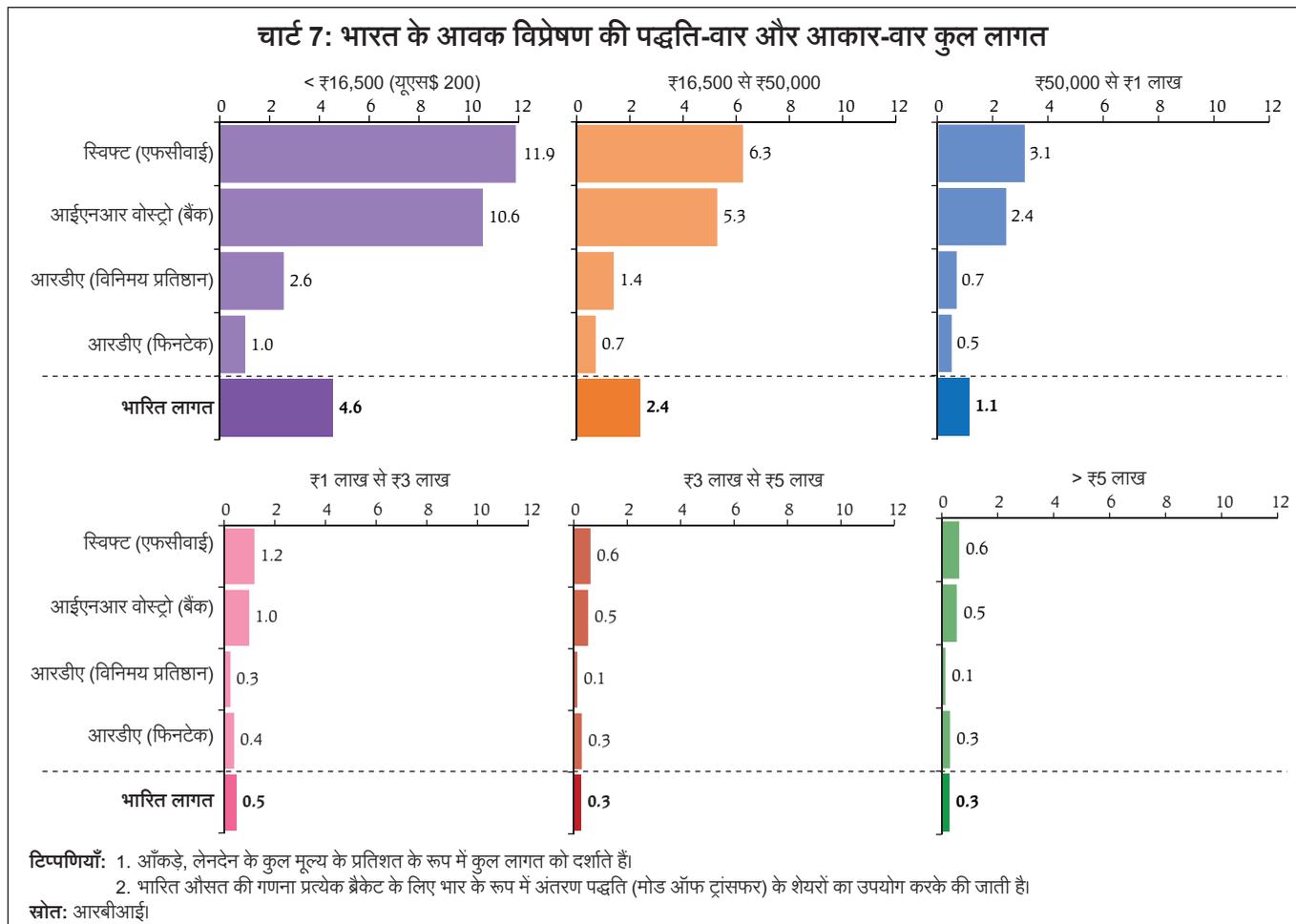
<sup>23</sup> सर्वेक्षणों में स्रोत देशों के सामान्य समूह को ध्यान में रखते हुए, 2023-24 में ईई में भारत के आवक विप्रेषण का 51.0 प्रतिशत शामिल था, जबकि जीसीसी देशों का हिस्सा 33.7 प्रतिशत था।

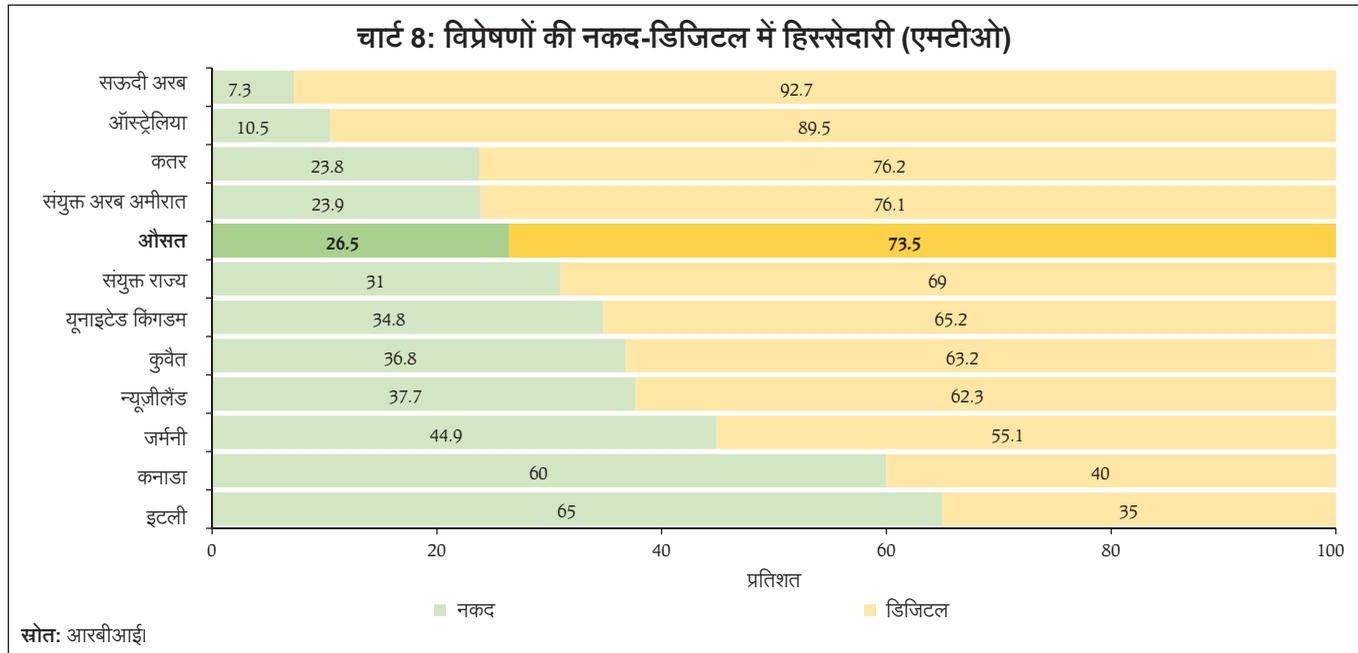
<sup>24</sup> महामारी के कारण हुए भारत में रिवर्स माइग्रेशन के कारण, पारंपरिक विप्रेषण प्राप्तकर्ता राज्यों, जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जो बड़े पैमाने पर जीसीसी देशों पर निर्भर हैं, का हिस्सा 2020-21 में लगभग आधा हो गया, जिससे विप्रेषण में राज्यवार हिस्सेदारी में वितरणात्मक बदलाव आया (आरबीआई, 2022ए)।

चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें औपचारिक बैंकिंग चैनलों की पहुंच, प्रभार और वितरण की गति शामिल है (आईएमएफ, 2009)। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, विनिमय दरों में अंतर के रूप में निहित लागत है। लेनदेन के मूल्य (आकार) के संदर्भ में, ₹5 लाख से अधिक राशि के प्रेषणों की हिस्सेदारी 2023-24 में लगभग 29 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर थी (चार्ट 6बी)। इसके विपरीत, सबसे अधिक लेनदेन 200 अमेरिकी डॉलर से कम के विप्रेषण आकार की श्रेणी में थे और अधिक मूल्य वाले विप्रेषण की हिस्सेदारी में भी गिरावट का रुझान जारी रहा। चूंकि अधिकांश धन-विप्रेषण अल्प राशि में भेजे जाते हैं, इसलिए 2030 तक 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत को 3 प्रतिशत या उससे कम पर लाने का सतत विकास लक्ष्य महत्वपूर्ण है।

### आवक विप्रेषण की लागत

सर्वेक्षण के नवीनतम दौर के अनुसार, यह पाया गया है कि हस्तांतरण के तरीके और धन विप्रेषण के आकार के आधार पर लागत में व्यापक रूप से भिन्नता होती है (चार्ट 7)। भारत में आवक धन विप्रेषण की भारत औसत लागत 200 अमेरिकी डॉलर से कम के लेनदेन आकार के लिए 4.6 प्रतिशत और 200-500 अमेरिकी डॉलर के लेनदेन वर्ग (ट्रांजैक्शन ब्रैकेट) के लिए 2.4 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण में दर्ज सभी लेनदेन वर्गों में 200 अमेरिकी डॉलर से कम की राशि के लिए विप्रेषण की भारत औसत लागत सर्वाधिक थी। इसके अलावा, ब्रैकेट के अंतर्गत प्रतिनिधि बैंकों के नोस्ट्रो खातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लागत सबसे अधिक थी, उसके बाद वोस्ट्रो खातों के माध्यम से आईएनआर लेनदेन का स्थान रहा। विप्रेषण के आकार के बावजूद, आरडीए (एमटीओ और फिनटेक) के





माध्यम से विप्रेषण की लागत सबसे कम थी। फिनटेक कंपनियों की फायदेमंद सीमा-पार धन-विप्रेषण सेवाएं की पेशकश करती पायी गई हैं, जिससे विभिन्न धन-विप्रेषण सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

वर्तमान सर्वेक्षण दौर में एमटीओ के डिजिटल विप्रेषण लेनदेन का हिस्सा भी शामिल था और यह पाया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन कुल विप्रेषण का 73.5 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल मोड के माध्यम से प्राप्त हुआ (चार्ट 8)। विप्रेषण लेनदेन के लिए सर्वाधिक डिजिटल हिस्सा सऊदी अरब (92.7 प्रतिशत) से प्राप्त हुआ, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया (89.5 प्रतिशत), कतर (76.2 प्रतिशत) और यूएई (76.1 प्रतिशत) का स्थान रहा।

## V. निष्कर्ष

भारत के संदर्भ में विप्रेषण ने महामारी के बाद की अवधि में पुनरुत्थान प्रदर्शित किया, जो बाह्य वित्तपोषण के एक स्थिर स्रोत के रूप में उभरा। 2023-24 के लिए भारत के विप्रेषण पर सर्वेक्षण के छठे दौर के परिणाम, प्रमुख स्रोत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जीसीसी देशों से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत के प्रवासी

वर्ग की बदलती गतिकी को उजागर करते हैं। राज्यवार आँकड़ें दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक का स्थान रहा। इसके अलावा, बैंकों के लिए हस्तांतरण के तरीके पर आरडीए चैनल का प्रभुत्व रहा। विप्रेषण भेजने की लागत हस्तांतरण के तरीके और लेनदेन की राशि के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती है। यह पाया गया कि सर्वेक्षण में दर्ज सभी लेनदेन वर्गों में 200 अमेरिकी डॉलर से कम राशि के लिए विप्रेषण भेजने की भारित औसत लागत सर्वाधिक थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023-24 के दौरान एमटीओ द्वारा प्राप्त कुल विप्रेषण का औसतन 73.5 प्रतिशत हिस्सा डिजिटल मोड के माध्यम से था। यह, नकद विप्रेषण की तुलना में डिजिटल विप्रेषण की कम लागत के साथ, विप्रेषण परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती पहुँच के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, सीमा-पार तीव्र भुगतान प्रणालियों के आपस में जुड़ने से ऐसे लेनदेन की आसानी और दक्षता बढ़ सकती है। हालाँकि विप्रेषण भेजने की लागत में कमी के संबंध में भारत का निष्पादन उत्साहजनक है, फिर भी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ

उठाने पर एकीकृत नीतिगत ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, प्रवासी भारतीयों की बदलती गतिकी की संभाव्यता का लाभ उठाने के लिए, बढ़ते भारतीय कार्यबल के निरंतर कौशल विकास और पुनर्कौशलीकरण की आवश्यकता है।

### संदर्भ

Chakravorty, S., Kapur, D. and Singh, N. (2016). *The Other One Percent: Indian's in America*. Oxford University Press.

Greene, M. and Batalova, J. (2024). *Indian Immigrants in the United States*. Migration Policy Institute.

GSMA. (2024). *The State of the Industry Report on Mobile Money 2024*.

IMF. (2009). *International Transactions in Remittances: Guide for Compilers and Users*. *International Monetary Fund*.

Khanna, G., and Morales, N. (2023). Did US Immigration Policy Influence India's IT Boom? *Economic Brief*, No. 23-42. Federal Reserve Bank of Richmond.

Rajan, S.I. (2024). Kerala Migration Survey 2023. *Kerala Economy*. Vol. 5, No. 3, pp 1-13.

Ratha, D., Plaza, S., and Kim, E. J. (2024). In 2024, remittance flows to low- and middle-income countries are expected to reach \$685 billion, larger than FDI and ODA combined. *World Bank Blogs*, December 18.

RBI. (2018). *Globalising People: India's Inward Remittances*. *RBI Bulletin* (November).

RBI. (2022a). *Headwinds of COVID-19 and India's Inward Remittances*. *RBI Bulletin* (July).

RBI. (2022b). *Master Direction - Opening and Maintenance of Rupee / Foreign Currency Vostro Accounts of Non-resident Exchange Houses* (updated as on December 22, 2022).

RBI (2024). *Report on Currency and Finance (RCF) 2023-24: India's Digital Revolution*.

RBI. (2025). *Payment Systems Report*.

World Bank. (2024). *Remittance Prices Worldwide: Issue 50* (June).

World Bank and BIS (Committee on Payment and Settlement Systems). (2007). *General principles for international remittance services*. Bank for International Settlements.

## अनुबंध

### अनुबंध सारणी ए1: आवक विप्रेषणों के संकलन की पद्धति - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष छह देश

क्र. सं.	देश	आवक विप्रेषणों के संकलन की पद्धति	नवीनतम विप्रेषण सर्वेक्षण/विवरण
1	भारत	भुगतान संतुलन के संकलन के लिए धन विप्रेषण के आँकड़े बैंक द्वारा अपनी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे विदेशी मुद्रा लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (एफईटीईआरएस) कहा जाता है।	<a href="https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=21141">https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=21141</a>
2	मेक्सिको	बैंको डी मेक्सिको ने 2012 में वैयक्तिक धन हस्तांतरण के व्यवसाय में शामिल फर्मों (वित्तीय संस्थाओं और धन हस्तांतरण संस्थाओं) के लिए धन विप्रेषण पर डेटा के संकलन के लिए मासिक रिपोर्ट का एक सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।	<a href="https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&amp;idCuadro=CE81&amp;locale=en">https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&amp;idCuadro=CE81&amp;locale=en</a>
3	चीन	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के भुगतान संतुलन मैन्युअल (बीपीएम) में उल्लिखित कार्यप्रणाली और मानकों के आधार पर भुगतान संतुलन डेटा के एक भाग के रूप में राज्य विदेशी मुद्रा प्रशासन (एसएएफई) चीन के विप्रेषण को संकलित करता है।	<a href="https://dsbb.imf.org/sdds/dqaf-base/country/CHN/category/BOP00">https://dsbb.imf.org/sdds/dqaf-base/country/CHN/category/BOP00</a>
4	फिलिपींस	भुगतान संतुलन में द्वितीयक आय के अंश वाले धन विप्रेषण को आईटीआरएस के माध्यम से दर्ज किया जाता है तथा सीमापार लेनदेन सर्वेक्षण (सीबीटीएस) द्वारा इसकी पूर्ति की जाती है।	<a href="https://psa.gov.ph/statistics/survey/labor-and-employment/survey-overseas-filipinos">https://psa.gov.ph/statistics/survey/labor-and-employment/survey-overseas-filipinos</a>
5	पाकिस्तान	स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) का सांख्यिकी और डेटा वेयरहाउस विभाग मासिक आधार पर श्रमिकों द्वारा भेजे गए धन के आंकड़ों को संकलित और प्रसारित करता है। ये आँकड़े बैंकों, विनिमय कंपनियों और पाकिस्तान डाकघर से एकत्र किए जाते हैं।	<a href="https://www.sbp.org.pk/departments/stats/AdvanceNotice.pdf">https://www.sbp.org.pk/departments/stats/AdvanceNotice.pdf</a> <a href="https://easydata.sbp.org.pk/apex/f?p=10:211:18595026959410::NO:RP:P211_DATASET_TYPE_CODE.P211_PAGE_ID:TS_GP_BOP_WR_M.210&amp;cs=1F743692A58FE97CD791417EFAE146503">https://easydata.sbp.org.pk/apex/f?p=10:211:18595026959410::NO:RP:P211_DATASET_TYPE_CODE.P211_PAGE_ID:TS_GP_BOP_WR_M.210&amp;cs=1F743692A58FE97CD791417EFAE146503</a>
6	बांग्लादेश	भुगतान संतुलन के संकलन के लिए विप्रेषण के आँकड़े बैंक द्वारा अपनी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली (आईटीआरएस) के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं।	<a href="https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremittance">https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/wageremittance</a>

स्रोत: आरबीआई; आईएमएफ एसडीएसएस; एवं केंद्रीय बैंक वेबसाइटों



## आर्थिक संवृद्धि को उत्सर्जन से अलग करना: एक एलएमडीआई अपघटन विश्लेषण

मधुरेश कुमार, शोभित गोयल,  
मनु शर्मा और मुस्कान गर्ग द्वारा ^

यह लेख एलएमडीआई अपघटन का उपयोग करके 2012 से 2022 तक भारत के CO<sub>2</sub> उत्सर्जन वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण करता है। इस दौरान, ऊर्जा-संबंधी CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में 706 मिलियन टन की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण आर्थिक संवृद्धि (+1073 मीट्रिक टन) थी, जबकि अर्थव्यवस्था के ईंधन मिश्रण में बदलाव (+78 मीट्रिक टन) का प्रभाव कम था। हालाँकि, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि (-399 मीट्रिक टन), संरचनात्मक परिवर्तन (-15 मीट्रिक टन), और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की उत्सर्जन तीव्रता में सुधार (-30 मीट्रिक टन) ने उत्सर्जन को कम करने में मदद की। भारत की ऊर्जा दक्षता में सालाना 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक औसत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, भारत की वृद्धि उत्सर्जन से वियुग्मित हुई, जिसकी वियुग्मन लोच 0.59 है, जो अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों के बराबर है।

### परिचय

जलवायु परिवर्तन पर बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों ने नीतियों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार देने वाले वैश्विक विमर्श को गति दी है। हाल के वर्षों में, दुनिया के जीवाश्म ईंधन से दूर हटने के साथ, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमनकारी कार्रवाइयों में तेजी आई है। वैश्विक उत्सर्जन के 90 प्रतिशत को कवर करने वाले 140 से अधिक देशों ने हजारों कंपनियों, शहरों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर नेट-जीरो उत्सर्जन का

^ मधुरेश कुमार आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग में सहायक महाप्रबंधक हैं। शोभित गोयल और मनु शर्मा पर्यवेक्षण विभाग से हैं। मुस्कान गर्ग आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग में प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

संकल्प लिया है (संयुक्त राष्ट्र, 2023)। नेट-जीरो उत्सर्जन तक पहुँचने के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बावजूद, देश हर पाँच साल में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन करते हैं, जिसमें अल्प से मध्यम अवधि के लिए अपनी जलवायु कार्य योजनाओं का विवरण दिया जाता है। अधिकांश एनडीसी का केंद्रबिंदु उत्सर्जन की तीव्रता को कम करना है, जिसका उद्देश्य विकास से समझौता किए बिना आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से अलग करना है।

नवीकरणीय ऊर्जा की गिरती कीमतों ने यह उम्मीद जगाई है कि नेट जीरो की ओर यह बदलाव पहले की कल्पना से कहीं कम कष्टदायक हो सकता है। फिर भी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर उत्कट ध्यान देने के बावजूद; सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (बड़ी पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) वर्तमान में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत का मात्र 2.1 प्रतिशत है (ऊर्जा सांख्यिकी, 2024)। बिजली क्षेत्र के बाहर, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपयोग लगभग न के बराबर है, और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से अप्रत्यक्ष उपयोग, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे परिपक्व होने में समय लगेगा। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग आगे चलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा दक्षता में सुधार करके और कोयले जैसे गंदे ईंधन से प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ विकल्पों की ओर स्थानांतरित होकर अलगाव हासिल किया है।

अपने अद्यतन एनडीसी में, भारत ने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करके उत्सर्जन को विकास से महत्वपूर्ण रूप से अलग करने की प्रतिबद्धता जताई है (यूएनएफसीसीसी, 2022)। इस पृष्ठभूमि में, इस पत्र का उद्देश्य पिछले दशक के दौरान भारत में उत्सर्जन वृद्धि के चालकों की जांच करना और उस डिकप्लिंग लोच का पता लगाना है जो भारत ने इस अवधि के दौरान हासिल की। संरचनात्मक अपघटन विश्लेषण (एसडीए) और सूचकांक अपघटन विश्लेषण (आईडीए) CO<sub>2</sub> उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच के लिए दो व्यापक रूप

से इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ हैं। एसडीए, जो इनपुट-आउटपुट विश्लेषण पर आधारित है, उत्सर्जन में बदलाव को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के योगदान में विभाजित करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों की विस्तृत जांच संभव हो पाती है (मिलर और ब्लेयर, 2009)। नीति विश्लेषण में इसकी सरलता और अनुप्रयोग में आसानी के लिए इसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता है (आंग और झांग, 2000)। इस पत्र में, 2012-22 के दौरान CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में वृद्धि को लघुगणकीय माध्य विभाज्य सूचकांक (एलएमडीआई) का उपयोग करके विघटित किया गया है जो अपघटन की आईडीए विधि का एक हिस्सा है। उत्सर्जन वृद्धि को पांच कारकों में विघटित किया गया है, अर्थात् आउटपुट प्रभाव, संरचनात्मक प्रभाव, ऊर्जा तीव्रता प्रभाव, ईंधन मिश्रण प्रभाव और उत्सर्जन कारक प्रभाव। हालांकि एलएमडीआई अपघटन पर वैश्विक शोध में काफी विस्तार हुआ है, और भारत को कई क्रॉस-कंट्री अध्ययनों में शामिल किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एलएमडीआई अपघटन पर विशेष रूप से केंद्रित साहित्य की उल्लेखनीय कमी है। क्रॉस-कंट्री अध्ययनों के परिणामों को सावधानी से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपयोग किए गए डेटा अक्सर पूरी तरह से सजातीय या सीधे तुलनीय नहीं होते हैं।

लेख का शेष भाग पाँच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II में साहित्य समीक्षा शामिल है, जबकि खंड III में आँकड़े और कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। खंड IV और V में क्रमशः अनुभवजन्य परिणामों और वियुग्मन विश्लेषण पर चर्चा की गई है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

## II. साहित्य समीक्षा

सूचकांक अपघटन विश्लेषण (आईडीए) ऊर्जा और पर्यावरण अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग ऊर्जा खपत, कार्बन उत्सर्जन, या अन्य समग्र संकेतकों में परिवर्तनों को उनके योगदान कारकों में विघटित करने के लिए किया जाता है। वर्षों से, इन अपघटनों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए विभिन्न विधियों का विकास और परिशोधन किया गया है। अपघटन विश्लेषण की प्रारंभिक विधियाँ, जिनमें लासपेयर्स सूचकांक जैसी विधियाँ शामिल हैं, अवशिष्ट पदों से बचने में असमर्थता के कारण सीमित थीं, जो व्याख्या को जटिल बना सकती थीं और अशुद्धियों को जन्म दे सकती थीं (आंग और झांग, 2000)। परिष्कृत लासपेयर्स सूचकांक दृष्टिकोण, जैसे कि फिशर आदर्श सूचकांक और शैप्ली और सन दृष्टिकोण, पूर्ण अपघटन प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक सटीक अंतिम परिणाम प्राप्त होते हैं। लघुगणकीय माध्य दिविशिया सूचकांक (एलएमडीआई) और अंकगणितीय माध्य दिविशिया सूचकांक (एएमडीआई) दिविशिया सूचकांक परिवार की प्रमुख विधियाँ हैं। एंग (2004) ने अपघटन विधि की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए सूचकांक संख्या सिद्धांत से चार परीक्षणों—कारक-उत्क्रमण, समय-उत्क्रमण, आनुपातिकता और एकत्रीकरण—की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इनमें से, उपयुक्त विधि का चयन करते समय कारक-उत्क्रमण परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। सारणी 1 विभिन्न अपघटन विधियों के गुणों को प्रस्तुत करती है।

कारक-उत्क्रमण परीक्षण बिना किसी अस्पष्टीकृत अवशेष के पूर्ण अपघटन सुनिश्चित करता है। समय-उत्क्रमण परीक्षण

**सारणी 1: आईडीए विधियों के गुण**

आईडीए विधि	कारक उत्क्रमण परीक्षण	समय उलट परीक्षण	आनुपातिकता परीक्षण	एकत्रीकरण परीक्षण	शून्य मूल्य मजबूत	नकारात्मक मूल्य मजबूत
लासपेयर्स	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
संशोधित फिशर अपघटन	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
शेप्ली और सन	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
एएमडीआई	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
एलएमडीआई	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

**टिप्पणी:** यहाँ संदर्भित एलएमडीआई, लघुगणकीय माध्य विभाजन विधि (एलएमडीआई I) से संबंधित है। इसका एक संबंधित प्रकार, एलएमडीआई II, एलएमडीआई I की तुलना में थोड़ी अधिक जटिल भार योजना प्रस्तुत करता है (आंग एवं अन्य, 2003)।

**स्रोत:** आंग (2004)।

इंगित करता है कि समयावधि को उलटने पर व्युत्क्रम परिणाम प्राप्त होने चाहिए। आनुपातिकता परीक्षण का तात्पर्य है कि यदि निर्धारक  $\lambda$  के कारक से बदलते हैं, तो सूचकांक मान भी  $\lambda$  से बदलेगा। एकत्रीकरण में संगति का अर्थ है कि उप-समूहों के लिए प्राप्त परिणामों को लगातार उच्च स्तर पर एकत्रित किया जा सकता है (वर्तिया 1976, बाल्क 1996, आंग 2000)। इसके अतिरिक्त, शून्य-मान प्रबल परीक्षण (आंग और चोई, 1997) और ऋणात्मक-मान प्रबल परीक्षण (चुंग और री, 2001) का उपयोग सबसे उपयुक्त अपघटन विधि निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

एलएमडीआई अपघटन, ऋणात्मक मान वाले प्रबल परीक्षण को छोड़कर, अधिकांश परीक्षणों में सफल होता है। हालाँकि, हमारे डेटासेट में कोई ऋणात्मक मान नहीं है और इसलिए इस अध्ययन में अपघटन के लिए एलएमडीआई का उपयोग किया गया है। शैप्ले/सन विधि सूत्रीकरण में पदों की संख्या कारकों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है, जिससे इसे लागू करना कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप, यदि तीन से अधिक कारक हों, तो अपघटन के लिए एलएमडीआई का अधिक उपयोग किया जाता है (आंग, 2004)।

एलएमडीआई अपघटन पर साहित्य का प्रसार एंग एवं अन्य (1998) के मौलिक शोधपत्र के बाद हुआ है, जिसने ऊर्जा-संबंधी कार्बन उत्सर्जन विश्लेषण में एलएमडीआई पद्धति के अनुप्रयोग की नींव रखी। लेखकों ने सिंगापुर में कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तनों का अपघटन करने के लिए एलएमडीआई पद्धति का प्रयोग किया और पाया कि ऊर्जा तीव्रता कार्बन उत्सर्जन में कमी का मुख्य कारण थी, जबकि आर्थिक गतिविधियों ने उत्सर्जन में वृद्धि में योगदान दिया। कई अन्य अध्ययनों में भी इस सामान्य प्रवृत्ति को देखा गया है जिसमें ऊर्जा तीव्रता में सुधार उत्सर्जन में कमी का प्राथमिक चालक है (झांग एवं अन्य, (2009); वांग एवं अन्य, (2005); ली एट अल., (2018); मैटिसॉफ और एडवर्ड्स (2014); राउपच एट अल., (2007); नाग और पारिख (2000); वाज़हायिल और बालासुब्रमण्यन (2019); अज़ेवेदो एट अल., (2011); अचौर और बेलौमी (2016); रोमैन-कोलाडो और कोलिनेट (2018))।

भारत को कई क्रॉस-कंट्री अध्ययनों में शामिल किया गया है (आंद्रेओनी और गैल्मारिनी (2016); शुआंग एवं अन्य (2016); कांग्यिन एवं अन्य (2019); हेनरिक्स और कैंडर (2010); इंग्लेसी-लोट्ज़ (2018); कानिटकर एवं अन्य (2015); लीमा एवं अन्य (2017); मार्कुची और फ्रैगोस (2015); सोलायमानी (2019) और वोइग्ट एवं अन्य (2014))। हालांकि, इन अध्ययनों के निष्कर्षों की व्याख्या करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि उपयोग किए गए डेटा पूरी तरह से सजातीय या सीधे तुलनीय नहीं हैं। इसके अलावा, इनमें से कई अध्ययनों में अधिक विस्तृत, बारीक डेटा तक पहुंच का अभाव है।

हैरानी की बात है कि एलएमडीआई अपघटन विश्लेषण का उपयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन बहुत कम हैं। जी। ओर्टेगा-रुइज़ एवं अन्य (2018) ने एलएमडीआई का उपयोग करके पाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि CO2 उत्सर्जन में वृद्धि में योगदान देने वाली प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है, जबकि ऊर्जा तीव्रता में सुधार उत्सर्जन को कम करने का प्रमुख कारक रहा है। अध्ययन की समय अवधि 1990-2015 तक फैली हुई है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और परमाणु ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के डेटा का उपयोग करती है। दास और रॉय (2020) ने MoSPI द्वारा प्रकाशित ऊर्जा सांख्यिकी से ऊर्जा डेटा का उपयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए CO2 उत्सर्जन के चालकों को विघटित करने के लिए एलएमडीआई तकनीक का भी उपयोग किया। उनका अध्ययन 1990-2013 तक फैला था।

### III. डेटा और कार्यप्रणाली

#### III.1 डेटा

वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य के लिए, अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना), द्वितीयक क्षेत्र (खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और निर्माण) में वर्गीकृत किया गया है और शेष आर्थिक गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र के रूप में रखा गया है। MoSPI भारत के ऊर्जा आंकड़े सालाना

सारणी 2: ईंधन का उत्सर्जन कारक	
ईंधन	उत्सर्जन कारक (किलोग्राम CO2 प्रति किलोवाट घंटा)
कोयला	0.323
तेल उत्पाद	0.25
प्राकृतिक गैस	0.2106
बिजली	0.741 (2012); 0.739 (2017); 0.713 (2022)

स्रोत: यूएस ईपीए; और अवर वर्ल्ड इन डेटा

प्रकाशित करता है जो ईंधन के अनुसार क्षेत्रीय अंतिम ऊर्जा खपत प्रदान करता है। ईंधन<sup>1</sup> की उत्सर्जन तीव्रता का उपयोग करके ऊर्जा खपत से क्षेत्रीय उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है। प्रति ईंधन प्रकार उत्सर्जन कारक यूएस ईपीए (2019) से लिया गया है, जिसे दीर्घकालिक औसत मूल्यों (सारणी 2) का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। ग्रिड बिजली के लिए उत्सर्जन कारक हमारे विश्व के डेटा से प्राप्त किया गया है। CO2 उत्सर्जन की गणना सरल सूत्र का उपयोग करके की जाती है:

$$C_{ij}^t = EC_{ij}^t XEF_j^t \quad (3.1)$$

जहाँ,  $C_{ij}^t$  = ईंधन प्रकार  $j$  और क्षेत्र के लिए CO2 उत्सर्जन समय अवधि  $t$  में  $i$ ।

$EC_{ij}^t$  = ईंधन प्रकार  $j$  और क्षेत्र के लिए ऊर्जा खपत समय अवधि  $t$  में  $i$ ,

$XEF_j^t$  = समय अवधि  $t$  में ईंधन प्रकार  $j$  के लिए उत्सर्जन कारक। इस अध्ययन की समयावधि 2012-13 से 2022-23 तक है। इसका ध्यान पूरी तरह से ऊर्जा-संबंधी उत्सर्जन पर है, प्रक्रिया उत्सर्जन को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

### III.2 कार्यप्रणाली

ऊर्जा पहचान विश्लेषण के अनुसार, CO2 उत्सर्जन को पांच कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: आउटपुट प्रभाव, संरचनात्मक प्रभाव, ऊर्जा तीव्रता प्रभाव, ईंधन-मिश्रण प्रभाव और उत्सर्जन-कारक प्रभाव (एंग, 2003) (सारणी 3)।

<sup>1</sup> यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रों के स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जनों को दोहरी गणना के जोखिम से बचाते हुए, ध्यान में रखा जाए। उत्सर्जन की एक से अधिक गणना की संभावना को रोकने के लिए स्कोप 3 उत्सर्जनों को बाहर रखा गया है।

सारणी 3: CO2 उत्सर्जन का अपघटन	
विघटित घटक	विवरण
आउटपुट प्रभाव	आर्थिक गतिविधि के पैमाने में परिवर्तन के कारण ऊर्जा-संबंधी CO2 उत्सर्जन में भिन्नता।
संरचनात्मक प्रभाव	उत्सर्जन में परिवर्तन को अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव द्वारा समझाया गया है, विशेष रूप से समग्र सकल घरेलू उत्पाद में व्यक्तिगत क्षेत्र के योगदान में परिवर्तन द्वारा।
ऊर्जा तीव्रता प्रभाव	अलग-अलग क्षेत्रों में ऊर्जा तीव्रता में बदलाव के कारण उत्सर्जन में होने वाले बदलाव को जीवीए उत्पादन की प्रति इकाई खपत की गई ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह बदलाव उत्पादन और उपभोग दक्षता में वृद्धि या अधिक उन्नत पूंजीगत उपकरणों को अपनाने को दर्शाता है।
ईंधन मिश्रण प्रभाव	उत्सर्जन में परिवर्तन, जिसका कारण ईंधन संरचना में परिवर्तन हो सकता है।
उत्सर्जन कारक प्रभाव	उत्सर्जन में परिवर्तन जिसे ईंधन के उत्सर्जन कारक या कार्बन तीव्रता में परिवर्तन के कारण माना जा सकता है।

समग्र उत्सर्जन को आर्थिक क्षेत्रों और ईंधन के प्रकारों के अनुसार विभाजित किया गया है। अपघटन पहचान को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है:

$$C = \sum_{ij} C_{ij} = \sum_{ij} Q \frac{Q_i E_i E_{ij} C_{ij}}{Q_i E_i E_{ij}} = \sum_{ij} Q S_i I_i M_{ij} U_{ij} \quad (3.2)$$

जहाँ  $C$  कुल CO<sub>2</sub> उत्सर्जन है और  $C_{ij}$  सेक्टर  $i$  द्वारा ईंधन  $j$  की खपत से निकलने वाला CO<sub>2</sub>, उत्सर्जन है;  $Q (= \sum_i Q_i)$  आउटपुट प्रभाव को दर्शाता है;  $S_i (= \frac{Q_i}{Q})$  संरचनात्मक प्रभाव है;  $I_i (= \frac{E_i}{Q_i})$  ऊर्जा तीव्रता प्रभाव है;  $E_{ij}$  सेक्टर  $i$  में  $E$   $Q_i$  ईंधन  $j$  से ऊर्जा खपत है, जहाँ  $E_i = \sum_j E_{ij}$  सेक्टर  $i$  द्वारा सभी ईंधनों से खपत की गई कुल ऊर्जा है; ईंधन-मिश्रण चर  $M_{ij} (= \frac{E_{ij}}{E_j})$  द्वारा दिया गया है और  $CO_2$  उत्सर्जन कारक  $U_{ij} (= \frac{C_{ij}}{E_{ij}})$  द्वारा दिया गया है।

$$\Delta C_{tot} = C_T - C_0 = \Delta C_{out} + \Delta C_{str} + \Delta C_{int} + \Delta C_{mix} + \Delta C_{enf} \quad (3.3)$$

ये उप-अंक आउटपुट प्रभाव, संरचनात्मक प्रभाव, ऊर्जा तीव्रता प्रभाव, ईंधन मिश्रण प्रभाव और उत्सर्जन कारक प्रभाव दर्शाते हैं। इन प्रभावों के लिए एलएमडीआई सूत्र इस प्रकार हैं:

$$\Delta C_{out} = \sum_{ij} \frac{c_{ij}^T - c_{ij}^0}{\ln c_{ij}^T - \ln c_{ij}^0} \ln \left( \frac{Q^T}{Q^0} \right) \quad (3.4)$$

$$\Delta C_{str} = \sum_{ij} \frac{c_{ij}^T - c_{ij}^0}{\ln c_{ij}^T - \ln c_{ij}^0} \ln \left( \frac{S_i^T}{S_i^0} \right) \quad (3.5)$$

$$\Delta C_{int} = \sum_{ij} \frac{c_{ij}^T - c_{ij}^o}{\ln c_{ij}^T - \ln c_{ij}^o} \ln \left( \frac{I_{ij}^T}{I_{ij}^o} \right) \quad (3.6)$$

$$\Delta C_{mix} = \sum_{ij} \frac{c_{ij}^T - c_{ij}^o}{\ln c_{ij}^T - \ln c_{ij}^o} \ln \left( \frac{M_{ij}^T}{M_{ij}^o} \right) \quad (3.7)$$

$$\Delta C_{emf} = \sum_{ij} \frac{c_{ij}^T - c_{ij}^o}{\ln c_{ij}^T - \ln c_{ij}^o} \ln \left( \frac{U_{ij}^T}{U_{ij}^o} \right) \quad (3.8)$$

गणनाओं में, यह माना गया है कि बिजली को छोड़कर, ईंधनों के उत्सर्जन कारक नहीं बदलते। चूँकि बिजली एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसके ईंधन मिश्रण और तकनीकी मापदंडों में बदलाव के कारण इसका उत्सर्जन कारक समय के साथ बदलता रहता है।

चूँकि एलएमडीआई विधि लघुगणकीय फलनों पर निर्भर करती है, इसलिए यह शून्य मानों को संभाल नहीं सकती। हालाँकि, शून्यों के स्थान पर बहुत छोटी धनात्मक संख्याएँ (जैसे,  $10^{-20}$ ) प्रतिस्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। आंग और चोई (1997) ने प्रदर्शित किया है कि जब डेटासेट में शून्य मानों के स्थान पर छोटी धनात्मक संख्याएँ आती हैं, तो एलएमडीआई अभिसारी हो जाता है। एलएमडीआई की एक और सीमा ऋणात्मक मानों को संसाधित करने में इसकी अक्षमता है। हालाँकि, हमारे डेटासेट में कोई भी ऋणात्मक मान मौजूद नहीं है।

### III.3 वियुग्मन विश्लेषण

टैपियो डिक्ॉप्लिंग विश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि आर्थिक प्रदर्शन में परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव किस प्रकार

संबंधित हैं, विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन से आर्थिक संवृद्धि के डिक्ॉप्लिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह यह समझने में मदद करता है कि क्या कोई अर्धव्यवस्था बढ़ रही है और साथ ही साथ अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रही है। वर्तमान अध्ययन के संदर्भ में, हम CO<sub>2</sub> उत्सर्जन की आय लोच में रुचि रखते हैं, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\text{लोच} = (\text{CO}_2 \text{ उत्सर्जन में प्रतिशत परिवर्तन}) / (\text{जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन}) \quad (3.9)$$

लोच गुणांक के आधार पर, टैपियो मॉडल संबंध को नौ अवस्थाओं में वर्गीकृत करता है (सारणी 4)।

### IV. अनुभवजन्य परिणाम

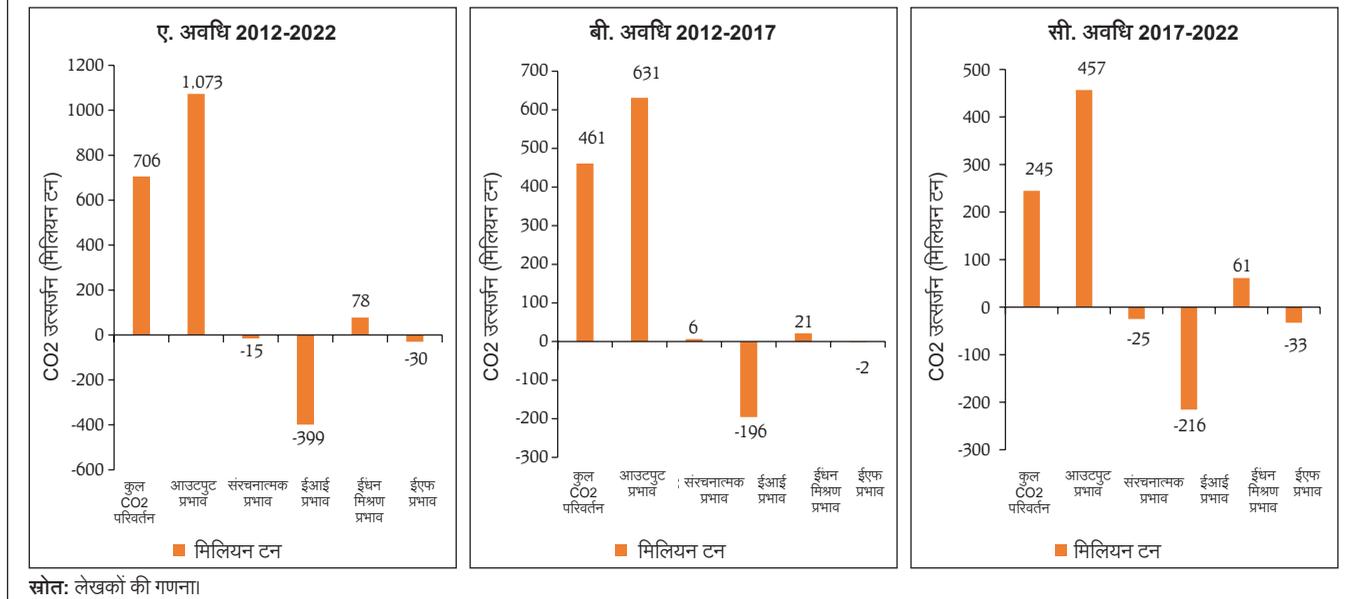
2012-13 से 2022-23 की अवधि के दौरान कुल ऊर्जा संबंधी उत्सर्जन में 706 मिलियन टन की वृद्धि हुई। एलएमडीआई अपघटन से पता चलता है कि CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कुल परिवर्तन को एक सकारात्मक आउटपुट प्रभाव (+1073 मीट्रिक टन) और ईंधन मिश्रण प्रभाव (+78 मीट्रिक टन) में विघटित किया जा सकता है, जिसे आंशिक रूप से एक नकारात्मक ऊर्जा तीव्रता प्रभाव (-399 मीट्रिक टन)<sup>2</sup> द्वारा ऑफसेट किया जाता है। संरचनात्मक (-15 मीट्रिक टन) और उत्सर्जन कारक प्रभाव (-30 मीट्रिक टन) थोड़ा नकारात्मक थे (चार्ट 1 ए)। हम व्यक्तिगत प्रभावों की जांच करने के लिए 10 साल की लंबी अवधि को दो समान उप-अवधियों 2012-17 और 2017-22 में तोड़ते हैं। हम समान रुझान देखते हैं कि आउटपुट प्रभाव उत्सर्जन को चला रहा है जबकि ऊर्जा तीव्रता में सुधार उत्सर्जन में वृद्धि को कम कर रहा है (चार्ट 1 बी और सी)।

सारणी 4: टैपियो डिक्ॉप्लिंग विश्लेषण

CO <sub>2</sub> उत्सर्जन में प्रतिशत परिवर्तन	सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन	वियुग्मन लोच (e)	वियुग्मन स्थिति
< 0	> 0	ई < 0	एसडी (मजबूत वियुग्मन)
> 0	> 0	ई = 0	WD (कमजोर वियुग्मन)
< 0	< 0	0.8 ≤ ई < 1.2	आरसी (रिसेसिव कप्लिंग)
> 0	> 0	ई > 1.2	END (विस्तारक नकारात्मक वियुग्मन)
> 0	< 0	ई < 0	एसएनडी (मजबूत नकारात्मक वियुग्मन)
< 0	< 0	0 < ई ≤ 0.8	WND (कमजोर नकारात्मक वियुग्मन)
> 0	> 0	0.8 ≤ ई < 1	ईडी (विस्तारक वियुग्मन)
> 0	> 0	ई = 1	ईसी (विस्तारक युग्मन)
< 0	< 0	ई > 1.2	आरडी (रिसेसिव डिक्ॉप्लिंग)

<sup>2</sup> एलएमडीआई अपघटन के परिणामों की व्याख्या अन्य सभी बातों के समान रहने पर होने वाले प्रभावों के रूप में की जा सकती है।

**चार्ट 1: CO2 उत्सर्जन का योगात्मक अपघटन**



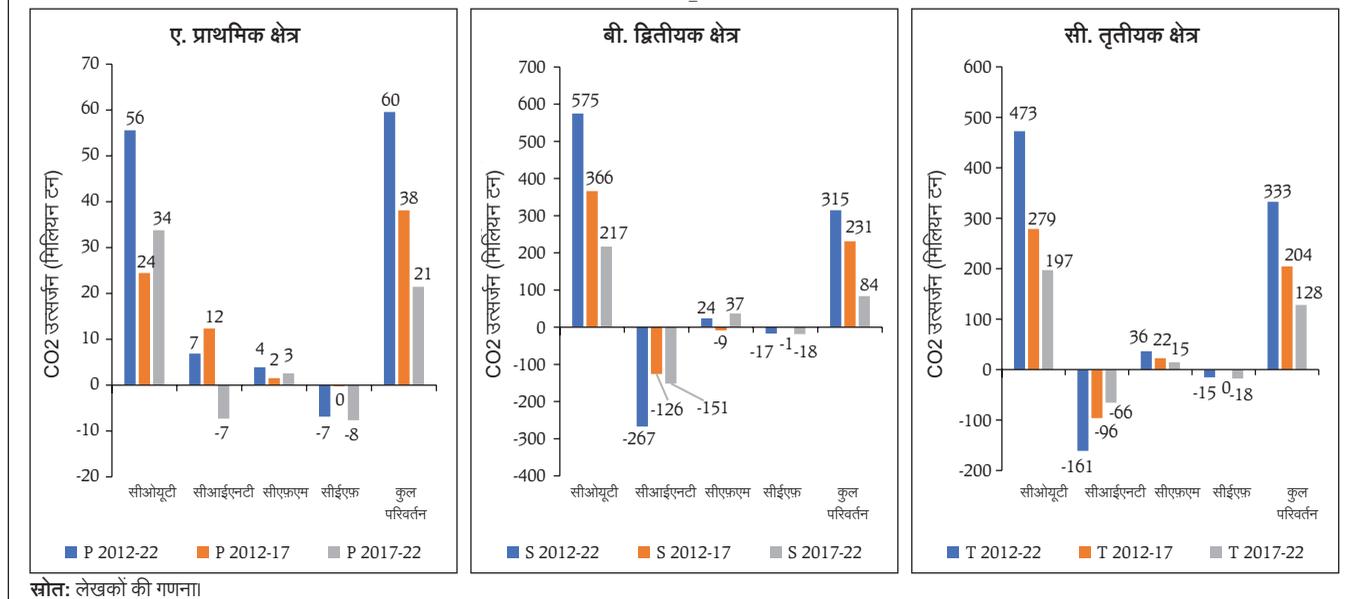
हमने क्षेत्रों के भीतर गतिशीलता की जांच करने के लिए CO2 उत्सर्जन में क्षेत्रवार परिवर्तनों को चार कारकों में विभाजित किया है, अर्थात् आउटपुट प्रभाव, ऊर्जा तीव्रता प्रभाव, ईंधन मिश्रण और उत्सर्जन कारक प्रभाव (चार्ट 2)।

**IV.1 आउटपुट प्रभाव**

आउटपुट प्रभाव, आर्थिक गतिविधि के पैमाने में बदलाव के कारण ऊर्जा-संबंधी CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को दर्शाता है। इस

अध्ययन के निष्कर्ष, व्यापक शोध से मेल खाते हैं, जो दर्शाता है कि ऊर्जा खपत और CO2 उत्सर्जन में वृद्धि में आउटपुट वृद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2012-2017 की अवधि में, आउटपुट प्रभाव का पूर्ण परिमाण बाद की अवधि की तुलना में अधिक था क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत की वृद्धि दर दूसरी छमाही की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी, जो कोविड-19 से ग्रस्त थी। क्षेत्रीय स्तर पर, केवल कृषि क्षेत्र में ही 2017-22

**चार्ट 2: CO2 उत्सर्जन का क्षेत्रवार अपघटन**



की अवधि में अपने आउटपुट प्रभाव में वृद्धि देखी गई क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में कोविड-19 से कम प्रभावित हुआ था।

#### IV.2 संरचनात्मक प्रभाव

इस अवधि के दौरान तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी कम हुई है। हालांकि उत्सर्जन-प्रधान द्वितीयक क्षेत्र में गिरावट से आमतौर पर एक नकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र, जो सबसे कम उत्सर्जन-प्रधान है, की घटती हिस्सेदारी ने इसकी भरपाई कर दी। परिणामस्वरूप, कुल मिलाकर केवल एक मामूली नकारात्मक संरचनात्मक प्रभाव देखा गया।

#### IV.3 ऊर्जा तीव्रता प्रभाव

अकेले ऊर्जा तीव्रता (ईआई) प्रभाव ने 399 मीट्रिक टन CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया, जो 2012 और 2022 के बीच कुल 706 मीट्रिक टन उत्सर्जन का 56 प्रतिशत है। यह प्रभाव 2017-22 की अवधि के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जहां इसके परिणामस्वरूप 216 मीट्रिक

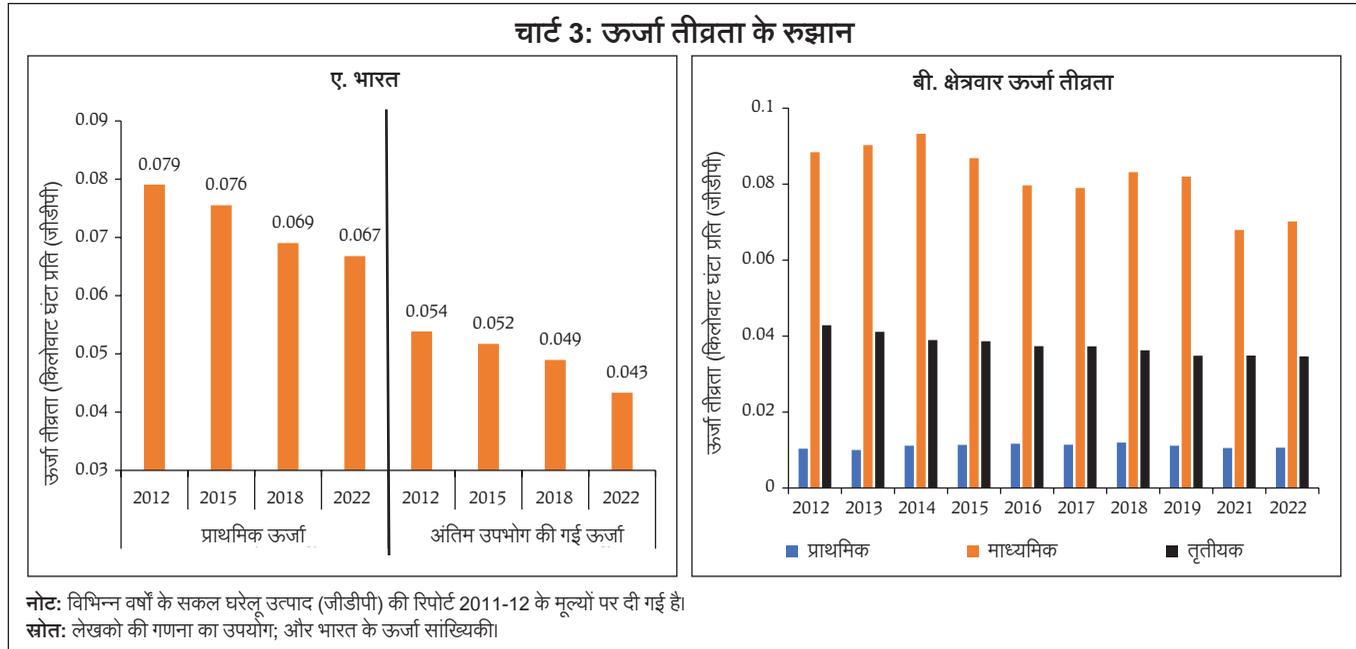
#### सारणी 5: ऊर्जा दक्षता का रुझान

क्षेत्र	ऊर्जा दक्षता में सुधार [2000 - 2023 (%/वर्ष)]	क्षेत्र	ऊर्जा दक्षता में सुधार [2000 - 2023 (%/वर्ष)]
दुनिया	1.35	जर्मनी	2.38
ओईसीडी	1.91	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.10
जी7	1.91	चीन	1.81
बीआरआईसी	1.62	भारत	1.86
यूरोपीय संघ	2.13	ऑस्ट्रेलिया	1.92
उत्तरी अमेरिका	2.00	वियतनाम	0.37
लैटिन अमेरिका	0.67	यूनाइटेड किंगडम	3.22

स्रोत: विश्व बैंक; अवर वर्ल्ड इन डेटा; और लेखकों की गणना।

टन की कमी आई, जो उस समय के दौरान कुल उत्सर्जन का 88 प्रतिशत था, जबकि पिछली अवधि में यह 42 प्रतिशत था। 2012-22 के दौरान, भारत की ऊर्जा दक्षता प्राथमिक ऊर्जा<sup>3</sup> के लिए 1.67 प्रतिशत और अंतिम ऊर्जा खपत के लिए 2.15 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ बेहतर हुई, जो मोटे तौर पर इसके दीर्घकालिक औसत 1.9 प्रतिशत के अनुरूप है (चार्ट 3)। भारत की ऊर्जा दक्षता 2000-23 के दौरान विश्व औसत की तुलना में अधिक दर से सुधर रही है (सारणी 5)।

#### चार्ट 3: ऊर्जा तीव्रता के रुझान



<sup>3</sup> प्राथमिक ऊर्जा उन ऊर्जा स्रोतों को संदर्भित करती है जो किसी भी रूपांतरण या परिवर्तन से गुजरने से पहले प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण भाग रूपांतरण और वितरण में नष्ट हो जाता है। अंतिम उपभोगित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपभोग के लिए प्रदान की जाती है। यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जिसका वास्तव में घरों, व्यवसायों और उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

## IV.4 ईंधन मिश्रण प्रभाव

भारत की अंतिम ऊर्जा खपत बिजली की ओर बढ़ रही है, जिससे कोयले का हिस्सा कम हो रहा है (सारणी 6)<sup>4</sup>। हालाँकि तेल और प्राकृतिक गैस में मामूली वृद्धि देखी गई है, लेकिन बिजली, जो अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक उत्सर्जन-गहन है, ने ईंधन मिश्रण प्रभाव में शुद्ध सकारात्मक बदलाव लाया है।

बिजली की स्थिति पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है। परिवहन और उद्योग में विद्युतीकरण को अक्सर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ा कदम माना जाता है। अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बिजली वास्तव में ऊर्जा का एक अत्यधिक कुशल रूप है। हालाँकि, उन देशों में जो अपने ताप विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए कोयले या लिग्नाइट पर अत्यधिक निर्भर हैं, प्रति किलोवाट-घंटा (किलोवाट) CO<sub>2</sub> उत्सर्जन काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, भारत में, 1 किलोवाट ग्रिड बिजली की खपत से 0.741 किलोग्राम CO<sub>2</sub> उत्सर्जित होती है, जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में तीन गुना अधिक प्रदूषणकारी है। एक पारंपरिक कोयला-आधारित बिजली संयंत्र में, कोयले से प्राप्त ऊर्जा का लगभग 70-73 प्रतिशत रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा और फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त, शेष 21 प्रतिशत बिजली पारेषण और वितरण के दौरान नष्ट हो जाती है। हालाँकि, बिजली की उच्च दक्षता इसके उच्च उत्सर्जन कारक को कुछ हद तक संतुलित कर देती है।

## IV.5 उत्सर्जन कारक प्रभाव

नकारात्मक उत्सर्जन कारक प्रभाव मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से प्रेरित है, जिसमें मौजूदा ताप

सारणी 6: भारत का ईंधन मिश्रण\*

ईंधन	2012	2017	2022
कोयला	36.0	33.4	30.6
तेल	40.1	41.5	41.2
एनजी	6.0	5.7	6.4
बिजली	17.9	19.4	21.9

\*: अंतिम ऊर्जा खपत पर आधारित।

स्रोत: भारत के ऊर्जा सांख्यिकी; और लेखकों की गणनाएँ।

<sup>4</sup> अंतिम उपभोग की जाने वाली ऊर्जा में कोयले की घटती हिस्सेदारी का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी कम हो गई है। भारत में, अधिकांश बिजली का उत्पादन कोयला ऊर्जा से किया जा रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी हाल ही में बढ़ रही है।

विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार से अतिरिक्त योगदान मिलता है। नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग एक अपेक्षाकृत हालिया विकास है, जो बताता है कि 2012-2017 के दौरान उत्सर्जन कारक प्रभाव न्यूनतम क्यों था और अध्ययन अवधि के उत्तरार्ध में ही महत्वपूर्ण हो गया। वर्तमान में, सौर और पवन ऊर्जा कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का केवल 2.1 प्रतिशत ही प्रदान करते हैं। हालाँकि, आगे चलकर, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा बहुत बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है क्योंकि उनकी गिरती लागत न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि हरित हाइड्रोजन के माध्यम से उद्योगों के अप्रत्यक्ष विद्युतीकरण के माध्यम से भी जीवाश्म ईंधनों का स्थान ले रही है। भारत ने पहले ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पर्याप्त मात्रा में हरित हाइड्रोजन क्षमता की नीलामी कर दी है, जिसके जल्द ही ऑनलाइन होने की उम्मीद है।

## V. वियुग्मन विश्लेषण

टैपिओ डिक्लिनिंग विश्लेषण दर्शाता है कि भारत ने इस अवधि के दौरान कमज़ोर डिक्लिनिंग हासिल की है, जिसकी डिक्लिनिंग लोच 0.59 है, जो अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) के समान है। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और सड़कों, इमारतों और ऊर्जा सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचे के विकास की माँग के कारण ऊर्जा की खपत और उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे लोच बढ़ती है। हालाँकि, उच्च मध्यम आय और उच्च आय वाले देशों ने इस अवधि के दौरान बहुत कम लोच हासिल की है (सारणी 7)।

प्राथमिक क्षेत्र ने शुरुआत में आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन के बीच बिगड़ते संबंध को प्रदर्शित किया। हालाँकि इस

सारणी 7: देश-समूहवार वियुग्मन लोच

इकाई	$\frac{\delta C_i^t}{C_i^0}$	$\frac{\delta Q_i^t}{Q_i^0}$	डी कपलिंग इलास्टिसिटी
भारत	0.43	0.73	0.59
उच्च आय वाले देश	-0.08	0.20	-0.41
निम्न-मध्यम आय वाले देश	0.34	0.58	0.59
उच्च-मध्यम आय वाले देश	0.12	0.54	0.23
कम आय वाले देश	0.17	0.29	0.61
विश्व	0.06	0.31	0.20

स्रोत: विश्व बैंक; अवर वर्ल्ड इनडाटा ; और लेखकों की गणना।

सारणी 8: विकास से CO2 उत्सर्जन का पृथक्करण

सेक्टर	अवधि	$\frac{\delta C_i^t}{C_i^0}$	$\frac{\delta Q_i^t}{Q_i^0}$	वियुग्मन लोच	स्कोर
कुल सकल घरेलू उत्पाद	2012-22	0.43	0.73	0.59	डब्ल्यूडी
	2012-17	0.34	0.21	1.65	ईएनडी
प्राथमिक क्षेत्र	2017-22	0.14	0.23	0.61	डब्ल्यूडी
	2012-22	0.53	0.49	1.09	ईसी
	2012-17	0.23	0.39	0.59	डब्ल्यूडी
द्वितीयक क्षेत्र	2017-22	0.07	0.18	0.37	डब्ल्यूडी
	2012-22	0.31	0.64	0.49	डब्ल्यूडी
	2012-17	0.34	0.49	0.69	डब्ल्यूडी
तृतीयक क्षेत्र	2017-22	0.16	0.26	0.62	डब्ल्यूडी
	2012-22	0.55	0.87	0.64	डब्ल्यूडी

स्रोत: एमओएसपीआई; और लेखकों की गणना।

अवधि के उत्तरार्ध में इस प्रवृत्ति में सुधार हुआ, लेकिन उत्सर्जन जीडीपी वृद्धि से आगे बढ़ता रहा। द्वितीयक क्षेत्र में सबसे तेज़ वियोजन हुआ, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का स्थान रहा। इसके अलावा, अध्ययन के उत्तरार्ध में भारत की समग्र कार्बन तीव्रता में तीव्र गति से कमी आई, जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि और व्यवसायों एवं जनता के बीच बढ़ती पर्यावरणीय जागरूकता के अनुरूप थी (सारणी 8)।

## VI. निष्कर्ष

इस पत्र में एलएमडीआई अपघटन का उपयोग करके पिछले दशक (2012-2022) में भारत में उत्सर्जन वृद्धि को संचालित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया गया है। इस अवधि के दौरान, ऊर्जा-संबंधी CO2 उत्सर्जन में 706 मिलियन टन की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का प्राथमिक चालक आउटपुट प्रभाव (+1073 मीट्रिक टन) था, जिसमें ईंधन मिश्रण प्रभाव (+78 मीट्रिक टन) का मामूली योगदान था, जो भारत में अत्यधिक उत्सर्जन-गहन स्रोत—बिजली की बढ़ती हिस्सेदारी से प्रभावित था। हालांकि, ऊर्जा तीव्रता प्रभाव (-399 मीट्रिक टन) ने उत्सर्जन में वृद्धि को कम करने में मदद की, जो ऊर्जा दक्षता में 1.9 प्रतिशत वार्षिक सुधार को दर्शाता है। सुधार की यह दर 2000-2023 तक भारत के दीर्घकालिक रुझान के अनुरूप है और इसी अवधि के वैश्विक औसत से अधिक है।

संरचनात्मक प्रभाव (-15 मीट्रिक टन) थोड़ा नकारात्मक रहा, क्योंकि कम उत्सर्जन-गहन तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सा अधिक उत्सर्जन-गहन द्वितीयक क्षेत्र की कीमत पर बढ़ा। हालाँकि, कम उत्सर्जन वाले प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट ने संरचनात्मक परिवर्तनों से संभावित उत्सर्जन में कमी को सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, उत्सर्जन कारक प्रभाव (-30 मीट्रिक टन) भी नकारात्मक रहा, जो ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण ग्रिड बिजली की उत्सर्जन तीव्रता में कमी के कारण हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि यह प्रभाव 2012-2017 तक न्यूनतम था, लेकिन दशक के उत्तरार्ध में अधिक महत्वपूर्ण हो गया।

नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद, 2022-23 में सौर और पवन ऊर्जा की कुल प्राथमिक ऊर्जा में हिस्सेदारी केवल 2.1 प्रतिशत थी। हालाँकि, आगे चलकर, उत्सर्जन कारक प्रभाव की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा तेज़ी से जीवाश्म ईंधन की जगह ले रही है और उद्योगों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ रहा है।

इस अवधि के दौरान भारत ने 0.59 की वियुग्मन लोचता हासिल की, जो अन्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों में देखी गई वियुग्मन लोचता के अनुरूप है। हालाँकि उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों ने बहुत कम वियुग्मन लोचता हासिल की है, फिर भी भारत का यह आँकड़ा उसकी विकास आवश्यकताओं को

देखते हुए सराहनीय है, जिसमें तेज़ शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे व निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश शामिल हैं।

भारत ने आर्थिक संवृद्धि से उत्सर्जन को अलग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को तेज़ करने के लिए और प्रयास आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए, भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सौर और पवन ऊर्जा शुल्क अब नए कोयला बिजली संयंत्रों की तुलना में कम हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च लागत को लेकर पहले की चिंताएँ दूर हो गई हैं (सीईए, 2024 और सीईआरसी, 2024)। भारत में बैटरी भंडारण<sup>5</sup> के साथ संयुक्त सौर पीवी के लिए बिजली की स्तरीकृत लागत (एलसीओई) पहले से ही नए कोयला-आधारित संयंत्रों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी है और इसके घटते रहने की उम्मीद है (आईईए, 2024)। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के अलावा, ऊर्जा दक्षता में सुधार पर ज़ोर देना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शक्तिशाली साधन बना हुआ है।

## संदर्भ

Achour, H., & Belloumi, M. (2016). Decomposing the influencing factors of energy consumption in Tunisian transport sector using the LMDI method. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 159-169.

Andreoni, V., & Galmarini, S. (2016). Drivers in CO2 emissions variation: A decomposition analysis for 33 world countries. *Energy*, 103, 27-37.

Ang, B. W. (2005). The LMDI approach to decomposition analysis: A practical guide. *Energy Policy*, 33(7), 867-871. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.10.010>

Ang, B. W., Liu, F. L., & Chung, H. S. (2004). A generalized Fisher index approach to energy decomposition analysis. *Energy Economics*, 26(4), 757-763. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2004.04.019>

<sup>5</sup> भंडारण के साथ सौर पी.वी. = चार घंटे की अवधि वाली बैटरी भंडारण के साथ सौर पी.वी. स्थापना, सौर पी.वी. की उत्पादन क्षमता के 20 प्रतिशत तक बढ़ाई गई।

<sup>6</sup> अक्षय ऊर्जा चौबीसों घंटे (आरई-आरटीसी) निविदाओं में खोजे गए टैरिफ पारंपरिक स्रोतों के मुकाबले अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं, हाल ही में बोली टैरिफ 4.0-4.5 रुपये प्रति यूनिट (मिंट, 2023) की सीमा में हैं।

Ang, B. W., & Zhang, F. Q. (2000). A survey of index decomposition analysis in energy and environmental studies. *Energy*, 25(12), 1149-1176.

Ang, B. W., Zhang, F. Q., & Choi, K. H. (1998). Factorizing changes in energy and environmental indicators through decomposition. *Energy*, 23(6), 489-495.

Azevedo, I. M. L., Morgan, M. G., & Morgan, F. (2011). The transition to solid-state lighting. *Proceedings of the IEEE*, 99(10), 1780-1804.

Bansal, R. S., & Gupta, A. S. (2020). Impact of structural changes on energy-related CO2 emissions in India: A decomposition approach. *Energy Economics*.

Das, N., & Roy, J. (2020). India can increase its mitigation ambition: An analysis based on historical evidence of decoupling between emission and economic growth. *Energy for Sustainable Development*, 57, 189-199.

Henriques, S. T., & Kander, A. (2010). The modest environmental relief resulting from the transition to a service economy. *Ecological Economics*, 30, 271-282.

Inglesi-Lotz, R. (2018). Decomposing the South African CO2 emissions within SA BRICS countries context: Signaling potential energy rebound effects. *Energy*, 147, 648-654.

Jain, M., & Mukherjee, S. (2019). Estimating sectoral energy use in the Indian economy using input-output approach. *Indira Gandhi Institute of Development Research Working Paper*, WP-2019-019.

Kangyin, D., Hongdian, J., Renjin, S., & Xiucheng, D. (2019). Driving forces and mitigation potential of global CO2 emissions from 1980 through 2030: Evidence from countries with different income levels. *Science of The Total Environment*, 649, 335.

Kanitkar, T., Banerjee, R., & Jayaraman, T. (2015). Impact of economic structure on mitigation targets for developing countries. *Energy for Sustainable Development*, 26, 56-61.

- Kant, S., Kumar, M., Khan, S., & Sharma, S. (2022). Carbon dioxide emissions from India's manufacturing sector: A decomposition analysis. *RBI Occasional Papers*, 43(1). Reserve Bank of India.
- Lima, F., Lopes Nunes, M., Cunha, J., & Lucena, A. F. P. (2017). Driving forces for aggregate energy consumption: A cross-country approach. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 68, 1033–1050.
- Li, W., Li, Z., & Ni, W. (2018). LMDI decomposition of energy-related CO<sub>2</sub> emissions based on energy and CO<sub>2</sub> allocation Sankey diagrams: The method and an application to China. *Sustainability*, 10(2), 344.
- Li, Y., Liu, X., & Feng, C. (2018). Exploring the driving forces of energy-related CO<sub>2</sub> emissions in China's agricultural sector. *Journal of Cleaner Production*, 195, 20-28.
- Mangla, S. K., & Ahuja, J. (2014). Carbon emission in BRICS countries: Trends, issues, and drivers using Kaya decomposition. *FIIB Business Review*, 3(3), 3-12.
- Matisoff, D. C., & Edwards, J. (2014). Kindred spirits or intergovernmental competition? Decomposing the effect of policy instruments on renewable energy growth. *Energy Policy*, 65, 743-753.
- Marcucci, A., & Fragkos, P. (2015). Drivers of regional decarbonization through 2100: A multimodel decomposition analysis. *Energy Economics*, 51, 111–124.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-output analysis: Foundations and extensions*. Cambridge University Press.
- Nag, B., & Parikh, J. (2000). Indicators of carbon emission intensity from commercial energy use in India. *Energy Economics*, 22(4), 441-461.
- Ortega-Ruiz, G., Mena-Nieto, A., & Garcia-Ramos, J. E. (2020). Is India on the right pathway to reduce CO<sub>2</sub> emissions? Decomposing an enlarged Kaya identity using the LMDI method for the period 1990–2016. *Science of The Total Environment*, 737, 139638.
- Rao, P. S., & Bhattacharya, L. N. (2019). Sectoral decomposition of CO<sub>2</sub> emissions and its policy implications for India. *Journal of Cleaner Production*.
- Raupach, M. R., Marland, G., Ciais, P., Le Quéré, C., Canadell, J. G., Klepper, G., & Field, C. B. (2007). Global and regional drivers of accelerating CO<sub>2</sub> emissions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(24), 10288-10293.
- Román-Collado, R., & Colinet, M. J. (2018). The impact of economic growth on energy consumption in European emerging economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(16), 15624-15632.
- Sahu, N. C., & Narayanan, K. (2011). Decomposition of industrial energy consumption in Indian states: An application of the LMDI method. *Energy Policy*, 39(6), 3108-3119.
- Shahbaz, M., Farhani, S., & Ozturk, I. (2015). Do coal consumption and industrial development increase environmental degradation in China and India? *Environmental Science and Pollution Research*, 22(5), 3895-3907.
- Sharma, A. K., & Jain, R. K. (2017). Decoupling of economic growth and CO<sub>2</sub> emissions in India: A sectoral analysis. *Environmental Science and Policy*.
- Shuang, D., Ming, Z., & Wei, H. (2016). Decomposing the decoupling of CO<sub>2</sub> emission from economic growth in BRICS countries. *Natural Hazards*, 84(2), 1055–1073.
- Singh, S. K., & Ghosh, V. K. (2016). Decomposition analysis of CO<sub>2</sub> emissions in India: A study of sectoral and regional variations. *Energy Policy*.
- Solaymani, S. (2019). CO<sub>2</sub> emissions patterns in 7 top carbon emitter economies: The case of transport sector. *Energy*, 168, 989–1001.
- Timilsina, G. R., & Shrestha, A. (2009). Transport sector CO<sub>2</sub> emission growth in Asia: Underlying factors and policy options. *Energy Policy*, 37(11), 4523-4539.

- United Nations. (2023). For a liveable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action. Retrieved from <https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition>
- UNFCCC. (2022). India's updated first nationally determined contribution under Paris Agreement. Retrieved from <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-08/India%20Updated%20First%20Nationally%20Determined%20Contrib.pdf>
- Vazhayil, J. P., & Balasubramanian, R. (2019). Decomposition analysis of carbon dioxide emissions in the Indian industrial sector. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(24), 24415-24429.
- Voigt, S., De Cian, E., Schymura, M., & Verdolini, E. (2014). Energy intensity developments in 40 major economies: Structural change or technology improvement? *Energy Economics*, 41, 47-62.
- Wang, C., Chen, J., & Zou, J. (2005). Decomposition of energy-related CO<sub>2</sub> emission in China: 1957-2000. *Energy*, 30(1), 73-83.
- Wang, L., Wang, J. Y., Zhao, Y. F., Li, Z., & Guo, R. (2020). Spatiotemporal characteristics of the relationship between carbon emissions and economic growth in China's transportation industry. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(30), 32962-32979.
- Yeo, Y., Shim, D., Lee, J. D., & Altmann, J. (2015). Driving forces of CO<sub>2</sub> emissions in emerging countries: LMDI decomposition analysis on China and India's residential sector. *Sustainability*, 7(12), 16108-16129.
- Zhang, M., Mu, H., Ning, Y., & Song, Y. (2009). Decomposition of energy-related CO<sub>2</sub> emissions over 1991-2006 in China. *Ecological Economics*, 68(7), 2122-2128.

# बाजार पहुँच और आईएमएफ व्यवस्थाएँ: दुनिया भर से साक्ष्य

श्रुति जोशी और पीएसएस विद्यासागर द्वारा ^

यह लेख विभिन्न देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लिए गए ऋणों का विश्लेषण करता है और 2000-2023 की अवधि में बाजार पहुँच और आईएमएफ के धन पर निर्भरता के बीच संबंध स्थापित करता है। यह पाया गया है कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमडीई) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों और वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों तक अपनी सीमित पहुँच के चलते चलनिधि दबावों के प्रबंधन के लिए आईएमएफ के संसाधनों पर निर्भर बनी हुई हैं।

## परिचय

1980 के दशक के मध्य से, विश्व में सीमा-पार व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह में वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार और वित्तीय एकीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है (आईएमएफ, 2016)। यह बढ़ा हुआ एकीकरण विकास, नवाचार और पैमाने की अर्थव्यवस्था जैसे लाभ प्रदान करता है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भी प्रस्तुत करता है (विलावेर्दे और माज़ा, 2011; अहमद, 2019)। उच्च अंतर्संबंधता वित्तीय प्रवाह में अचानक उतार-चढ़ाव के माध्यम से कमजोर देशों में वित्तीय तनाव के सीमा-पार संक्रमण और बढ़े हुए संकट के दौर को जन्म दे सकती है, जिससे दुनिया भर में देशों की सकल और निवल विदेशी संपत्ति की स्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है (गिलियो और अन्य, 2016; लेन और मिलेसी-फेरेटी, 2006) और/या व्यापार व्यवधानों के माध्यम से देशों में वित्तीय प्रवाह कम हो सकता है (अत्तिनासी और अन्य, 2022)। महामारी के बाद के वर्षों में, भू-आर्थिक विखंडन, ऊंचा वैश्विक ऋण और बढ़ी हुई समष्टि आर्थिक नीति अनिश्चितता जैसे कारकों के संयोजन से कमजोर बफर और उच्च विदेशी मुद्रा ऋण वाले देशों के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) जोखिम पैदा किया है (जीएफएसआर, 2024)।

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय विभाग से हैं। इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

आईएमएफ, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) के केंद्र के रूप में, अपनी लगभग सार्वभौमिक सदस्यता और संसाधन आकार के कारण तीव्र भुगतान संतुलन के दबाव वाले देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। मौजूदा अध्ययनों से पता चला है कि आईएमएफ सहायता प्राप्त करने वाले देशों में आमतौर पर कमजोर समष्टि आर्थिक बुनियाद होती है, जैसे उच्च चालू खाता घाटा, कम अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधि, उच्च राजकोषीय घाटा, कम प्रति व्यक्ति आय और विनिमय दर असंतुलन, और उनकी कमजोरी वैश्विक कारकों जैसे वैश्विक व्यापार चक्र, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और विश्व ब्याज दरों में भारी वृद्धि से और बढ़ सकती है (बर्ड एंड ऑर्न, 1986; कॉर्नेलियस, 1987; जॉयस, 1992; बर्ड एंड रोलेँड्स, 2002; जॉयस, 2004; एलेकडैंग, 2008)। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों जैसे स्वैप लाइनों और क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था (आरएफए) तक बढ़ती पहुँच के साथ अब बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा, गैर-रियायती आईएमएफ ऋण बाजार-निर्धारित दरों पर प्रदान किए जाते हैं, जो यद्यपि बाजार दरों से कम हो सकते हैं, फिर भी निष्पादन की शर्तों और संबंधित कलंक के कारण अनाकर्षक हो सकते हैं (कावर्ड, 2010)।

हालाँकि, यह देखा गया है कि कई उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमडीई) आईएमएफ ऋण व्यवस्थाओं, जिन्हें आईएमएफ कार्यक्रम भी कहा जाता है, पर निर्भर बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दशक (2014-2024 के दौरान) में, ईएमडीई ने कुल 329 आईएमएफ व्यवस्थाओं में प्रवेश किया, जिनमें से लगभग आधे कार्यक्रम/व्यवस्थाएँ गैर-रियायती ऋणयुक्त थीं। दूसरी ओर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) ने 2014 के बाद से आईएमएफ व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है। नई सहस्राब्दी में, जहां ईएमडीई की आईएमएफ ऋणों पर निर्भरता अधिक रही है, भारत और चीन सहित कई तेज़ी से बढ़ रही बड़ी ईएमडीई को आईएमएफ ऋणों का सहारा नहीं लेना पड़ा। वास्तव में, ये अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक विकास की प्रमुख चालक रही हैं, कोविड काल को छोड़कर, जहाँ लगभग पूरे विश्व में नकारात्मक

<sup>1</sup> <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Lending>

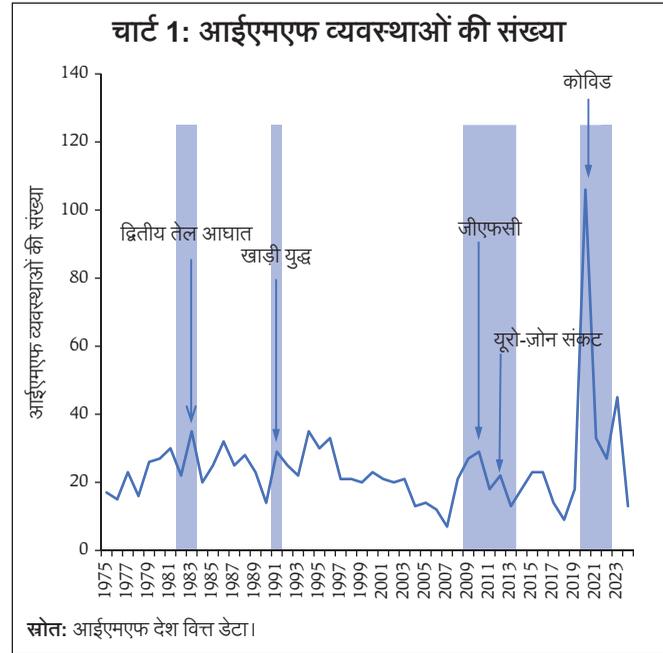
वृद्धि दर्ज की गई थी। तेज़ी से बढ़ते ईएम वैश्विक विकास के चालक बने हुए हैं और अपेक्षाकृत मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियाद उनकी विशेषता है। वास्तव में, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद कई बड़ी और तेज़ी से बढ़ती ईएमडीई आईएमएफ के लेनदार के रूप में सामने आई हैं। इस पृष्ठभूमि में, इस लेख का उद्देश्य उन प्रमुख कारकों की पहचान करना है जिनके चलते देशों को आईएमएफ कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। लेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है: खंड II विभिन्न क्षेत्रों में आईएमएफ ऋणों की पहुँच के विषय में बताता है; खंड III आईएमएफ के ऋणों की माँग और देशों की बाज़ार पहुँच के बीच संबंध का विश्लेषण करता है; और खंड IV में अंतिम टिप्पणियाँ शामिल हैं।

## II. आईएमएफ ऋणों की माँग

ऐतिहासिक रूप से, यह देखा गया है कि वैश्विक मंदी के दौरान आईएमएफ ऋण की माँग बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, 1983 की वैश्विक मंदी के दौरान, जो कि तेल-आघात और उसके बाद लैटिन अमेरिका में ऋण संकट से उत्पन्न हुई थी, कई ईएमडीई, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका (एसएसए) में, लंबे समय तक प्रगति में मंदी का सामना करना पड़ा (कोसे एवं अन्य., 2020)। परिणामस्वरूप, आईएमएफ ने 1982-83 के दौरान इन क्षेत्रों में अपने ऋण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उदाहरण के लिए, 1983 में फंड का लगभग 85 प्रतिशत ऋण लैटिन अमेरिका और एसएसए को दिया गया था। इसके बाद, खाड़ी युद्ध के दौरान आईएमएफ ऋण में वृद्धि हुई, जहां 1991 में 50 प्रतिशत ऋण एशिया-प्रशांत क्षेत्र (एपीआर) को दिया गया, जो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों से प्रभावित हुआ था। इसी प्रकार, जीएफसी और यूरो-ज़ोन संकट के दौरान, कुछ यूरोपीय देशों के लिए आईएमएफ व्यवस्था में वृद्धि हुई, और कोविड संकट के परिणामस्वरूप दुनिया भर में धन संसाधनों की माँग बढ़ गई (चार्ट 1)।

आईएमएफ के पास सदस्य देशों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई साधन/विंडो हैं। "आरक्षित अंश", जो आईएमएफ से सदस्य का बिना शर्त आहरण अधिकार है,<sup>2</sup> सदस्य देश को भुगतान संतुलन के वित्तपोषण की आवश्यकता होने पर अल्प सूचना पर आईएमएफ से धन

<sup>2</sup> आरक्षित निधि का निर्माण कोटा सदस्यता के विदेशी मुद्रा भाग के साथ-साथ आईएमएफ द्वारा सदस्य की मुद्रा की बिक्री (पुनर्खरीद) के माध्यम से वृद्धि (कमी) द्वारा किया जाता है, ताकि भुगतान संतुलन के वित्तपोषण की आवश्यकता वाले अन्य सदस्यों द्वारा आईएमएफ संसाधनों के उपयोग की माँग को पूरा किया जा सके।

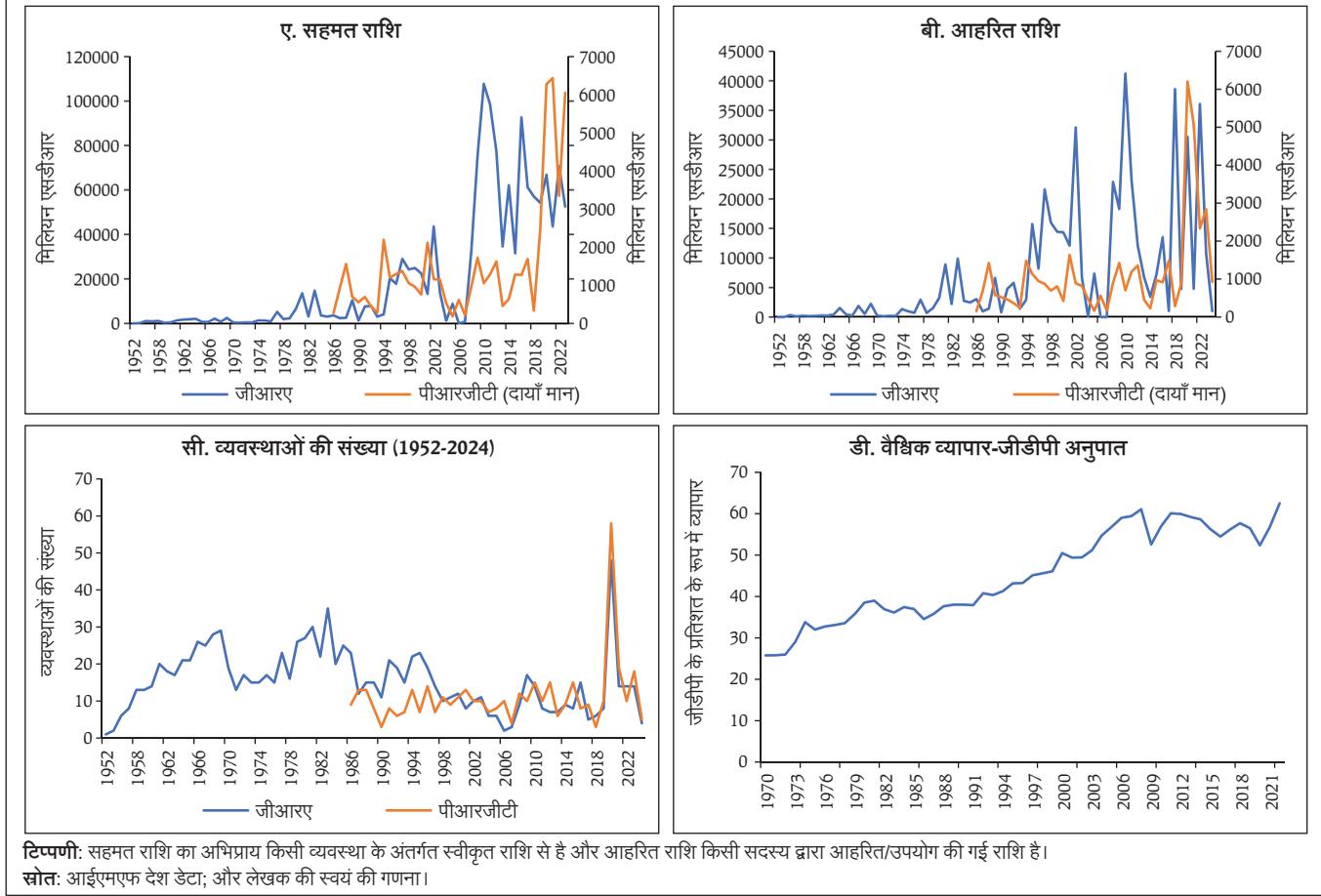


निकालने की अनुमति देता है। इसके अलावा, आईएमएफ के ऋण दो मदों के अंतर्गत दिए जाते हैं, अर्थात् जनरल रिसोर्स अकाउंट (जीआरए), जो बाजार-आधारित दरों पर ऋण प्रदान करता है, और पात्र देशों (मुख्यतः निम्न-आय वाले देशों) को ट्रस्ट-आधारित रियायती सहायता, जिसका प्रमुख स्रोत पोवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (पीआरजीटी) है। इन दोनों में समान शर्तों वाली अलग-अलग ऋण सुविधाएँ हैं और ये अल्पकालिक से दीर्घकालिक वित्तपोषण सहायता प्रदान करते हैं।

आईएमएफ ऋणों तक पहुँच सदस्यों के कोटा द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें ऋण की मात्रा आमतौर पर कोटा का गुणक होती है।<sup>3</sup> चूंकि पीआरजीटी देश कम आय वाले विकासशील देश हैं, इसलिए उनके द्वारा लिए गए ऋणों की मात्रा जीआरए के माध्यम से अन्य सदस्यों द्वारा लिए गए ऋणों की तुलना में काफी कम है (2023 में ली गई जीआरए राशि के 12 प्रतिशत से थोड़ा कम), हालांकि पीआरजीटी व्यवस्थाओं की संख्या जीआरए व्यवस्थाओं के लगभग बराबर है (चार्ट 2सी)। नई सहस्राब्दी के दौरान, विशेष रूप से आघातों के दौर में, सदस्यों द्वारा प्राप्त आईएमएफ सहायता की मात्रा और आईएमएफ व्यवस्थाओं की संख्या में उल्लेखनीय

<sup>3</sup> वर्तमान में, सामान्य पहुँच सीमा 145 प्रतिशत है; और संचयी पहुँच कोटे का 435 प्रतिशत है। 2023 में, कोविड महामारी से उत्पन्न माँगों को पूरा करने के लिए पहुँच सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया था, जिसमें सामान्य पहुँच सीमा 200 प्रतिशत थी और संचयी पहुँच सीमा कोटे का 600 प्रतिशत थी। पहुँच सीमा में यह अस्थायी वृद्धि 2024 के अंत में समाप्त होने वाली है।

चार्ट 2: सभी सदस्यों को आईएमएफ ऋण



वृद्धि हुई है (चार्ट 2ए और 2बी)। यह बढ़ती वैश्विक अंतर्संबंधता के अनुरूप है, जिससे संकेत मिलता है कि वैश्विक प्रभाव-विस्तार का संचरण तेज हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य देशों में बाह्य वित्तपोषण की समस्या उत्पन्न हुई है (चार्ट 2डी)।<sup>4</sup>

### II.1 आईएमएफ से क्षेत्रवार उधारी

जीआरए के तहत व्यवस्थाओं की संख्या और ऋणों की मात्रा के संदर्भ में, पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्र (डब्ल्यूएचआर<sup>5</sup>) - मुख्यतः लैटिन अमेरिका - सबसे बड़ा उधारकर्ता है, जबकि

एसएसए<sup>6</sup> पीआरजीटी से सबसे बड़ा उधारकर्ता है (चार्ट 3)। इसके अलावा, डब्ल्यूएचआर, एसएसए और एपीआर<sup>7</sup> के अंतर्गत आने वाले कुछ देशों ने आईएमएफ से बार-बार उधार लिया है।

विभिन्न क्षेत्रों में आईएमएफ ऋणों के सामयिक पर वितरण से पता चलता है कि आईएमएफ के परिचालन के शुरुआती दौर में, ये ऋण ज्यादातर अब विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) द्वारा

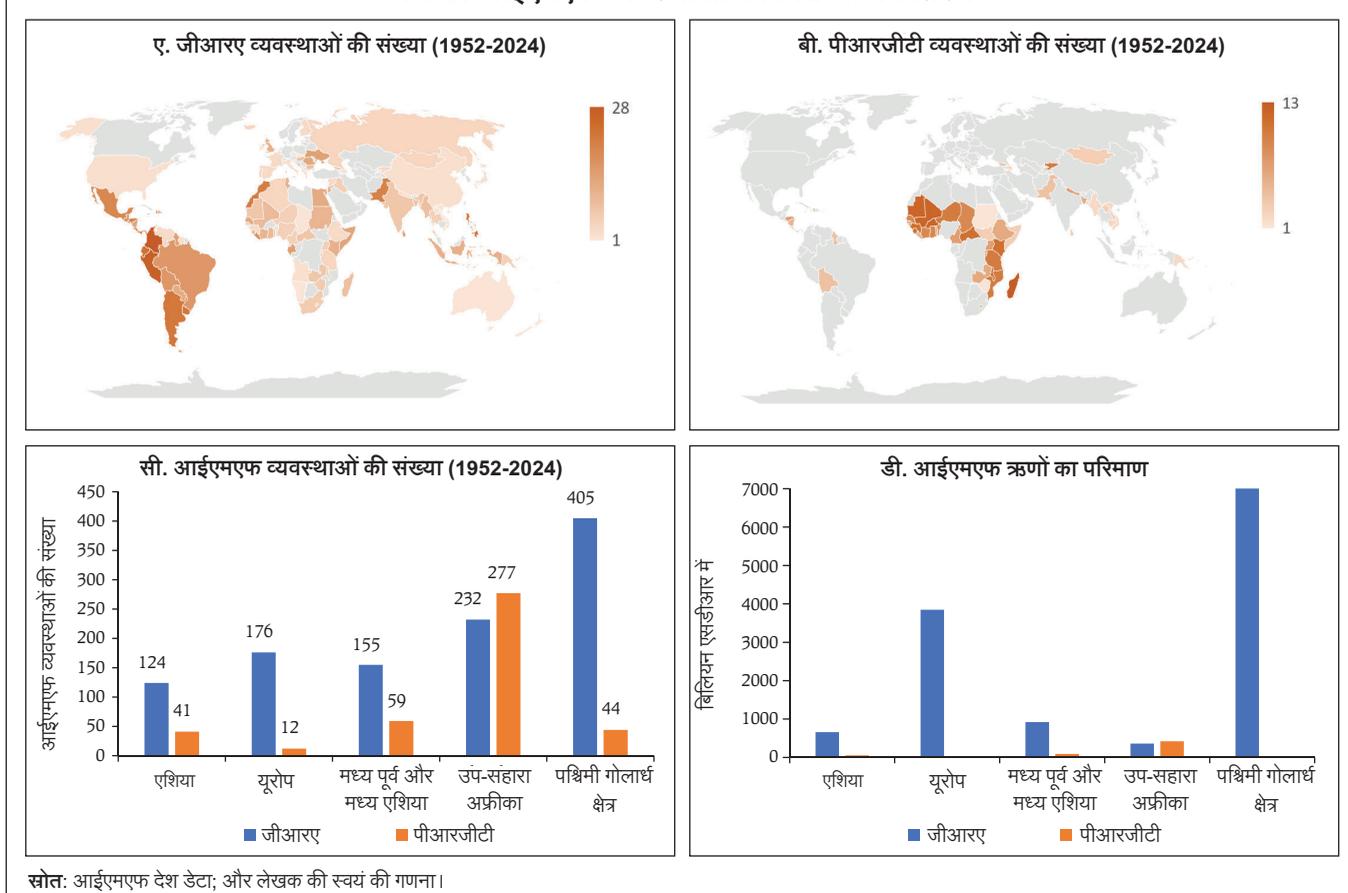
<sup>4</sup> 1970 से 2024 के दौरान व्यापार से जीडीपी अनुपात और आईएमएफ से आहरित कुल राशि के बीच सहसंबंध 0.54 है, जो दर्शाता है कि आईएमएफ से आहरित अधिक राशि के साथ अधिक अंतर्संबंध जुड़ा हुआ है।

<sup>5</sup> डब्ल्यूएचआर में अमेरिका और केरिबियन शामिल हैं और इसमें एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, बोलीविया, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिका, डोमिनिकन गणराज्य, ईक्वाडोर, अल साल्वाडोर, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गयाना, हैती, होंडुरास, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं।

<sup>6</sup> एसएसए में शामिल हैं: अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, केप वर्दे, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस, कांगो, कांगो डीआर, कोत दिव्वार, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, एस्वातीनी, इथियोपिया, गैबॉन, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, साओ टोमे और प्रिंसिपे, सेनेगल, सेशेल्स, सिएरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, तंजानिया, टोगो, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।

<sup>7</sup> एपीआर में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रूनई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, फिजी, कोरिया, हाँगकाँग, भारत, इंडोनेशिया, किरिबाती, लाओस, मालदीव, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नाउरू, नेपाल, न्यूजीलैंड, पालाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, समोआ, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते, ताईवान, टोंगा, तुवालु, वानुअतु और वियतनाम शामिल हैं।

**चार्ट 3: आईएमएफ व्यवस्थाओं का विश्वव्यापी वितरण**



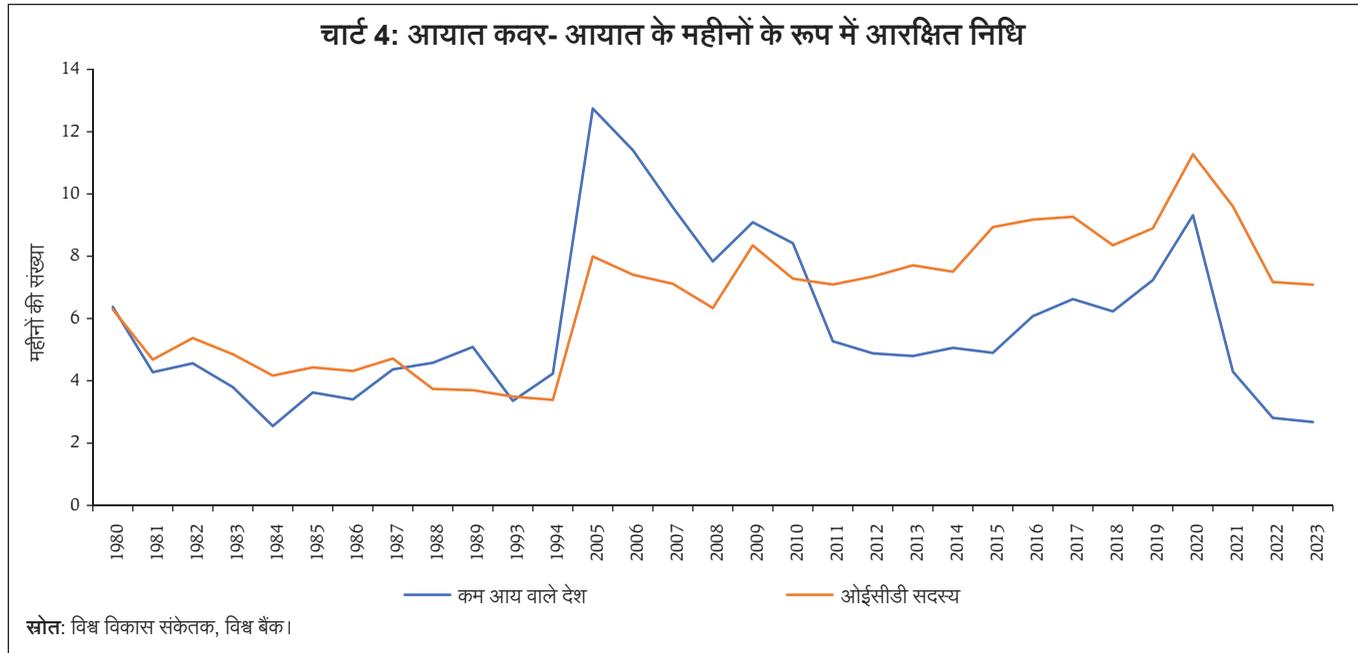
लिए गए थे। हालाँकि, समय के साथ विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) से आईएमएफ ऋणों की माँग कम हो गई, जीएफसी-यूरोज़ोन संकट इसमें अपवाद है, जहाँ कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस) ने आईएमएफ से असाधारण रूप से बड़ी मात्रा में ऋण लिए। आईएमएफ वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए चालक कारकों में से एक कम आय वाले देशों (विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (आईडीए) से सहायता के लिए उनकी पात्रता के अनुसार चुने गए) के लिए बिगड़ती बाहरी वित्त पोषण / चलनिधि स्थिति है (संकेतकों जैसे विदेशी मुद्रा भंडार का आयात कवर, अल्पकालिक ऋण का हिस्सा, ऋण सेवा अनुपात, आदि द्वारा प्रॉक्सी किया गया है)। ईई के लिए आयात कवर (ओईसीडी देशों द्वारा प्रॉक्सी) में 1995 से लगातार सुधार हुआ है, संकट अवधि के दौरान गिरावट को छोड़कर, जबकि यह 2003 (जीएफसी की शुरुआत से पहले भी) से कम आय वाले

देशों के लिए कमजोर हो गया है और उसके बाद कमजोर ही रहा (चार्ट 4)।

### II.2 रीजनल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स (आरएफए) की भूमिका

भुगतान संतुलन (बीओपी) के मुद्दों के सामने, रक्षा की पहली पंक्ति देश के अपने संसाधन (जैसे विदेशी मुद्रा भंडार) होते हैं, उसके बाद अन्य विकल्प जैसे स्वैप - द्विपक्षीय और आरएफए दोनों - और बाज़ार उधारी है, जिन्हें भुगतान संतुलन (बीओपी) वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दिए जाने की संभावना होती है, क्योंकि इन वित्तपोषण विकल्पों में आईएमएफ से उधार लेने जैसा कलंक नहीं होता है। अंततः, जब अन्य विकल्प व्यवहार्य नहीं लगते हैं, तो देश आईएमएफ ऋण और/या आधिकारिक द्विपक्षीय ऋण का सहारा लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का आयात कवर सुखद है और उनकी क्रेडिट रेटिंग आम तौर पर निवेश ग्रेड में

चार्ट 4: आयात कवर- आयात के महीनों के रूप में आरक्षित निधि



रहती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों से चलनिधि की सुगम पहुँच प्राप्त हुई है। दूसरी ओर, अधिकांश निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) और ईएमडीई की संप्रभु रेटिंग गैर-निवेश योग्य श्रेणी की रही है, और कई एलआईसी के पास देश रेटिंग नहीं है, जिससे उनकी बाजार पहुँच गंभीर रूप से सीमित हो गई है। हालाँकि, अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले ईएमडीई, जैसे एएसईएन क्षेत्र, ब्रिक्स और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की आरएफए या करेंसी-स्वैप व्यवस्था तक पहुँच थी (अनुलग्नक सारणियाँ ए2, ए3 और ए4)।

इन तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए आरएफए या करेंसी-स्वैप व्यवस्थाओं के माध्यम से वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच के चलते आईएमएफ ऋणों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। उदाहरण के लिए, एएसईएन+3 देशों<sup>8</sup> ने अपने क्षेत्र में अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चियांग माई मल्टीलेटेरलाइज़ेशन इनिशिएटिव (सीएमआईएम) शुरू की, जो 2010 में लागू हुई। अपनी स्थापना के बाद से, सीएमआईएम के सदस्य देशों ने आईएमएफ से उधार नहीं लिया, जबकि 2010 से पहले कोरिया और फिलीपींस जैसे कुछ एएसईएन

देश आईएमएफ से बार-बार उधार लेते थे। इसी प्रकार, ब्रिक्स देशों ने 2015 में ब्रिक्स कॉटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स (सीआरए) में प्रवेश किया और उसके बाद से केवल दक्षिण अफ्रीका ने कोविड संकट के दौरान आईएमएफ की व्यवस्था से सहायता ली। 2002 में, यूरोपीय संघ ने गैर-यूरोज़ोन देशों<sup>9</sup> के लिए ईयू-बीओपी सुविधा स्थापित की और 2012 में यूरोज़ोन संकट के बाद, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज़्म<sup>10</sup> (ईएसएम) लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सदस्य देशों द्वारा आईएमएफ उधारी में कमी आई। इसी प्रकार, 1978 में, एफएलएआर - लैटिन अमेरिकी रिजर्व फंड<sup>11</sup> - की स्थापना की गई, जिसके परिणामस्वरूप इसके सदस्य देशों के लिए आईएमएफ व्यवस्थाओं की संख्या में कमी आई (चार्ट 5)। हालाँकि, अन्य आरएफए के सदस्यों की तुलना में एफएलएआर के लिए आईएमएफ उधारी में गिरावट उतनी तीव्र नहीं थी। फिर भी, कोलंबिया, पेरू और पैराग्वे जैसे देशों के लिए आईएमएफ व्यवस्थाओं से कोई निकासी नहीं हुई।

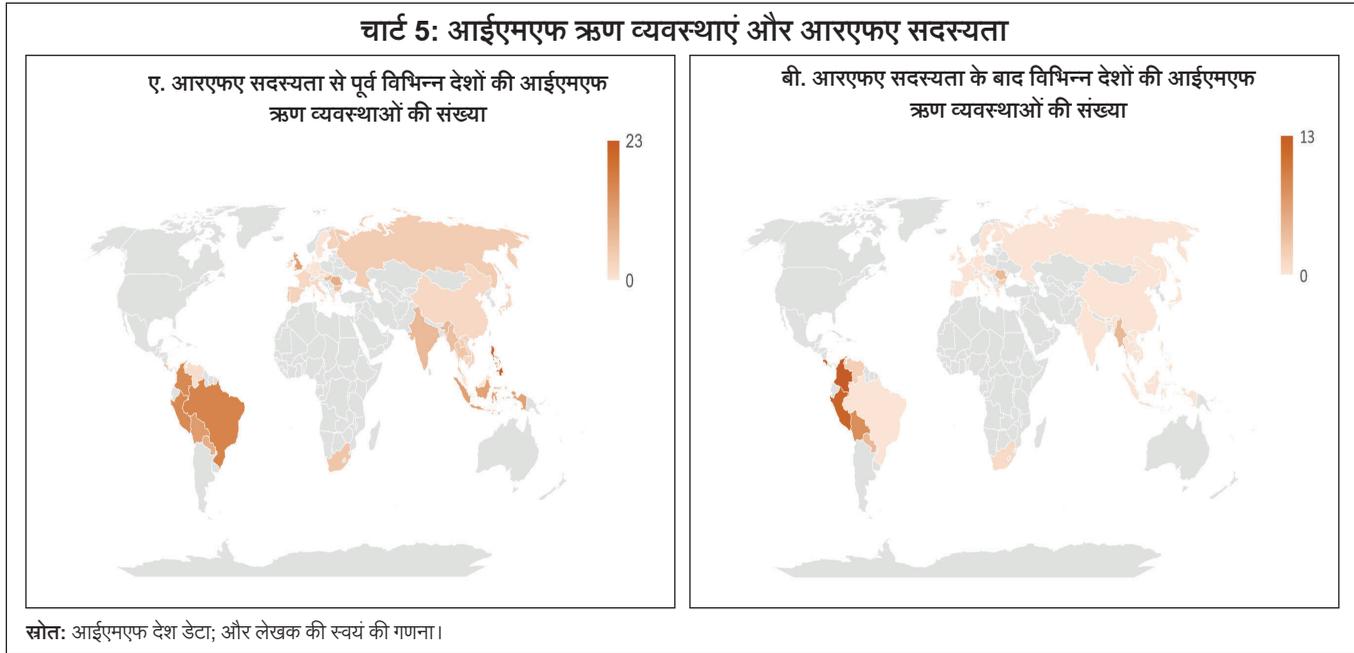
<sup>8</sup> ब्रूनई दारुस्सलाम, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस लोकतांत्रिक लोक गणराज्य, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और हांगकांग।

<sup>9</sup> बल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, स्वीडन और युनाइटेड किंगडम।

<sup>10</sup> ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन।

<sup>11</sup> सदस्यों में बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, पेरू, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं।

चार्ट 5: आईएमएफ ऋण व्यवस्थाएँ और आरएफए सदस्यता



### III. बाजार पहुँच और आईएमएफ व्यवस्था

उच्चतर देश जोखिम प्रोफाइल के कारण उधार लेने की लागत बढ़ जाती है क्योंकि बाजार अतिरिक्त जोखिम की भरपाई के लिए उच्च प्रतिफल की मांग करता है। इसलिए, किसी देश के लिए खराब संप्रभु रेटिंग, या यहाँ तक कि संप्रभु रेटिंग का अभाव, और उच्च क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड जैसे कारक, अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक उसकी पहुँच को सीमित कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताओं से उधार लेने के अलावा, ऐसे देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेना ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताओं से उधार लेना भी देशों के लिए पसंदीदा विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि जाम्बिया जैसे भारी कर्ज में डूबे कुछ देशों को ऋण संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ऋण उपचार के लिए जी-20 कॉमन फ्रेमवर्क में ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया कठिन हो गई।

इस संदर्भ में, देशों की बाजार पहुँच और आईएमएफ से ऋण लेने वाले देशों को आईएमएफ ऋणों के सहारे का विश्लेषण किया गया है, जिसमें जीएफसी (2008-2010), यूरोज़ोन संकट (2012-14) और कोविड संकट (2020-2021) जैसे वैश्विक अशांति के चुनिंदा प्रकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

दामोदरन (2024) द्वारा उपलब्ध कराए गए, 2000 के बाद की अवधि के लिए देश के डिफॉल्ट स्प्रेड और जोखिम

प्रीमियम पर आंकड़ों के अलग-अलग विश्लेषण से पता चलता है कि आईएमएफ से ऋण लेने वाले अधिकांश देश गैर-निवेश योग्य ग्रेड संप्रभु रेटिंग वाले देश हैं, और इसलिए, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता माना जाता है, जिससे उनकी बाजार पहुँच सीमित हो जाती है। ये उधारकर्ता ज्यादातर डब्ल्यूएचआर, एसएसए और एपीआर में केंद्रित हैं, और ज्यादातर कम आय वाले देश और ईएमडीई हैं। उदाहरण के लिए, डब्ल्यूएचआर में, इक्वाडोर, होंडुरास और जमैका जैसे देशों ने आईएमएफ से कई बार उधार लिया, और उनकी गैर-निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग थी, जिसके परिणामस्वरूप देश जोखिम प्रीमियम (सीआरपी) और डिफॉल्ट स्प्रेड अधिक थे। इसी प्रकार, एसएसए के कई देश, जैसे मेडागास्कर, मलावी और साओ टोमे और प्रिंसिपे अन्य सहित पीआरजीटी के तहत ऋण ले रहे हैं, उनके पास कोई देश रेटिंग उपलब्ध नहीं है (सारणी 1)।

नई सहस्राब्दी में जीएफसी के दौरान तनाव के विशिष्ट प्रसंगों की बात करें तो, हालाँकि एई संकट के केंद्र में थे, फिर भी इसका प्रभाव दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पड़ा, जिसके बाद विकास में मंदी का दौर आया (कोसे एवं अन्य, 2020)। इसके बाद, यूरोज़ोन संकट के दौरान, यूरोप में साइप्रस, ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन संकटग्रस्त प्रमुख देश थे (गौरिन्चस एवं अन्य, 2023)। जीएफसी और यूरोज़ोन संकट के दौरान आईएमएफ से

**सारणी 1: 2000-2023 के दौरान अनेक उधारकर्ता (> 5 गुना)**

	देश	जीआरए		पीआरजीटी	
		सीआरपी (प्रतिशत में)	डिफॉल्ट स्प्रेड (प्रतिशत में)	सीआरपी (प्रतिशत में)	डिफॉल्ट स्प्रेड (प्रतिशत में)
डब्ल्यूएचआर	ईक्वाडोर	14	42		
	होंडुरास	7.1	29		
	जमैका	7.3	23		
एसएसए	मेडागास्कर			एनए	एनए
	मलावी			एनए	एनए
	साओ टोमे और प्रिंसिपे			एनए	एनए

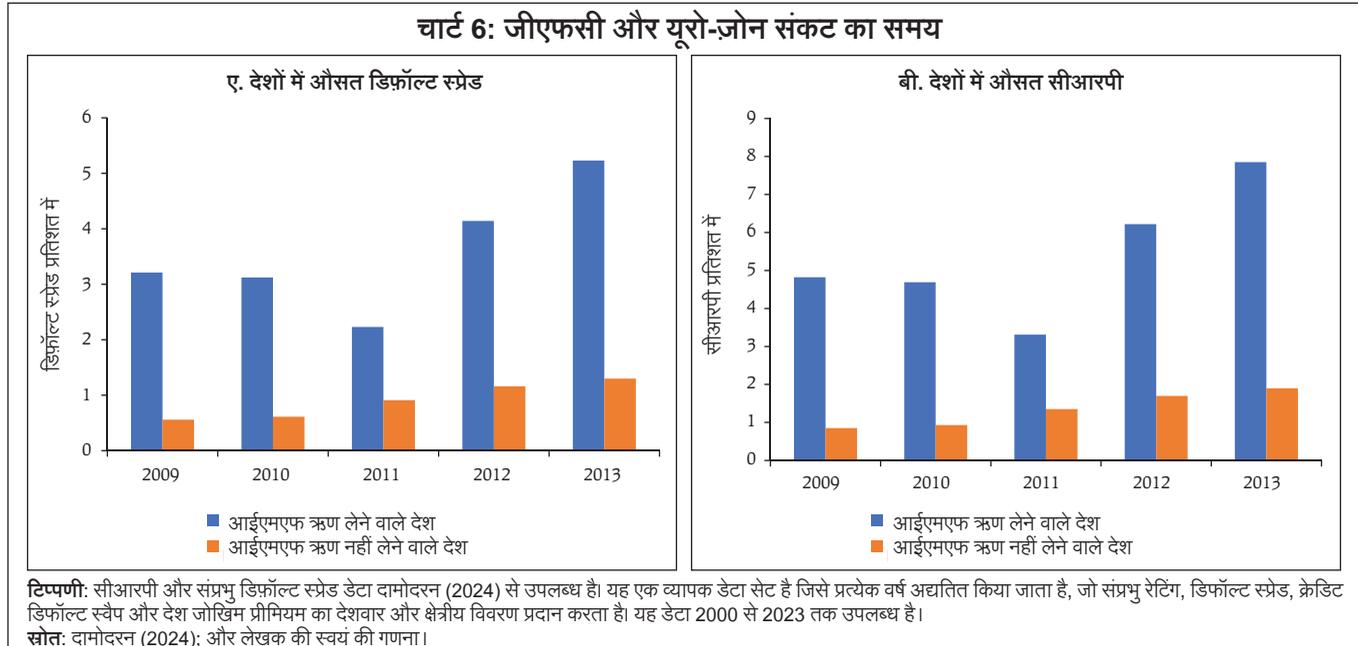
**टिप्पणियाँ:** 1. डिफॉल्ट स्प्रेड का अनुमान मूडीज से स्थानीय मुद्रा संप्रभु रेटिंग का उपयोग करके लगाया जाता है और इसकी गणना डिफॉल्ट निशुल्क सरकारी बॉण्ड दर पर अंतर के रूप में की जाती है। सीआरपी की गणना सापेक्ष इक्विटी बाजार अस्थिरता का प्रयोग कर डिफॉल्ट स्प्रेड को स्केलिंग-अप कर की जाती है, जिसकी इसी क्रम में एस एंड पी इमर्जिंग मार्केट इक्विटी इंडेक्स मानक विचलन से बीएएमएल इमर्जिंग पब्लिक बॉण्ड इंडेक्स मानक विचलन के अनुपात के रूप में गणना की जाती है।  
 2. उपर्युक्त पद्धति का उपयोग करके अनुमानित सीआरपी दामोदरन (2024) द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से सीधे उपलब्ध है।  
 3. एनए का अर्थ है कि किसी देश रेटिंग उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: दामोदरन (2024)।

ऋण लेने वाले अधिकांश देशों को मूडीज रेटिंग स्केल पर बीएए या उससे कम रेटिंग दी गई थी या उनकी कोई रेटिंग उपलब्ध नहीं थी। उदाहरण के लिए, आर्मेनिया, कोलंबिया, अल साल्वाडोर, बांग्लादेश, जमैका और मोरक्को सहित अन्य देशों की अनुमानित ग्रेड या निम्न निवेश ग्रेड रेटिंग थी, जबकि अंगोला, कांगो, कोमोरोस, इथियोपिया और घाना सहित अन्य देशों की कोई रेटिंग उपलब्ध नहीं थी (अनुलग्नक सारणी ए2 और ए3)। दूसरी ओर, जीएफसी और यूरोज़ोन संकट से प्रभावित होने के बावजूद, आईएमएफ से

ऋण न लेने वाले देशों की ऋण-योग्यता स्थिर रही क्योंकि उन्हें निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग प्राप्त थी। इनमें, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, स्वीडन और अमेरिका भी शामिल थे। 2009-2014 के दौरान आईएमएफ से ऋण लेने वाले देशों के लिए औसत डिफॉल्ट स्प्रेड 3 से 5 प्रतिशत के बीच था, जबकि आईएमएफ से ऋण न लेने वाले देशों के लिए यह 0.6 से 1 प्रतिशत था। इसी प्रकार, इन दोनों समूहों के देशों के लिए सीआरपी 4 से 8 प्रतिशत और 0.9 से 1.9 प्रतिशत के बीच था (चार्ट 6)।

**चार्ट 6: जीएफसी और यूरो-ज़ोन संकट का समय**



दूसरे, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड, अपने बढ़ते सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणों के कारण 2008-11 के दौरान आईएमएफ ऋण व्यवस्था में शामिल हो गईं। इस अवधि के दौरान, इन देशों की रेटिंग में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप इनकी बाज़ार पहुँच सीमित हो गई। उदाहरण के लिए, ग्रीस की रेटिंग 2009 से 2010 तक ए2 से घटाकर बीए1 कर दी गई और आयरलैंड की रेटिंग इसी अवधि में एए1 से बीएए1 कर दी गई। पुर्तगाल की रेटिंग 2010 में ए1 से घटाकर 2011 में बीए2 कर दी गई। आइसलैंड और लातविया ने भी 2007 में अपनी रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद 2008 में आईएमएफ से धन प्राप्त किया था। आइसलैंड को 2007 में एए से घटाकर 2008 में बीएए1 कर दिया गया था और लातविया को ए2 से घटाकर ए3 कर दिया गया था (अनुलग्नक सारणी ए2)। इसी प्रकार, अंगोला, जिबूती, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो, घाना, माली, नाइजर, टोगो जैसे अफ्रीकी देशों ने आईएमएफ पीआरजीटी वित्तपोषण का लाभ उठाया और संबंधित अवधि के लिए उनके पास संप्रभु रेटिंग नहीं थी। दूसरी ओर, आयरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन ने 2012-14 के बीच मध्यम निवेश ग्रेड से गैर-निवेश योग्य ग्रेड में डाउनग्रेड होने के बावजूद, 2012 में गठित यूरोपियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ़ैसिलिटी (ईएफएसएफ)<sup>12</sup> से वित्तीय सहायता की उपलब्धता के चलते आईएमएफ की ऋण व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, कुछ देशों ने अपनी बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिए आईएमएफ कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए, और उन्हें आईएमएफ से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आईएमएफ की फ़्लैक्सिबल क्रेडिट लाइन (एफसीएल) इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन की गई है, खासकर उन देशों के लिए जिनके पास टिकाऊ बाह्य स्थिति, कम मुद्रास्फीति और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त जैसे मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियाद है।<sup>13</sup> आईएमएफ का यह प्रमाणन कि इन देशों के पास बहुत मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियाद है, का बाज़ार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय पूँजी बाजारों से धन प्राप्त करना आसान हो जाता

<sup>12</sup> ईएफएसएफ संवितरण डैशबोर्ड।

<sup>13</sup> <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/Flexible-Credit-Line-FCL>.

है। इसी प्रकार, प्रिकोशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन (पीएलएल) उन देशों के लिए उपलब्ध है जिनकी कुछ कमजोरियाँ उन्हें एफसीएल से वंचित कर सकती हैं, हालाँकि अन्यथा उनके पास उचित समष्टि बुनियाद हो सकती है। फिर भी, पीएलएल तक पहुँच सुनिश्चित आईएमएफ निधियों के बारे में बाज़ार संकेत के रूप में भी कार्य करती है। हालाँकि, पीएलएल प्रदान किए जाने के बाद भी मोरक्को के लिए सीआरपी में गिरावट नहीं आई, संभवतः इस तथ्य के कारण कि पीएलएल यह बाज़ार संकेत नहीं देता कि इस देश के पास मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियाद है। दूसरी ओर, पीएलएल की समाप्ति के बाद, मोरक्को के लिए सीआरपी में वृद्धि हुई। (सारणी 2)।

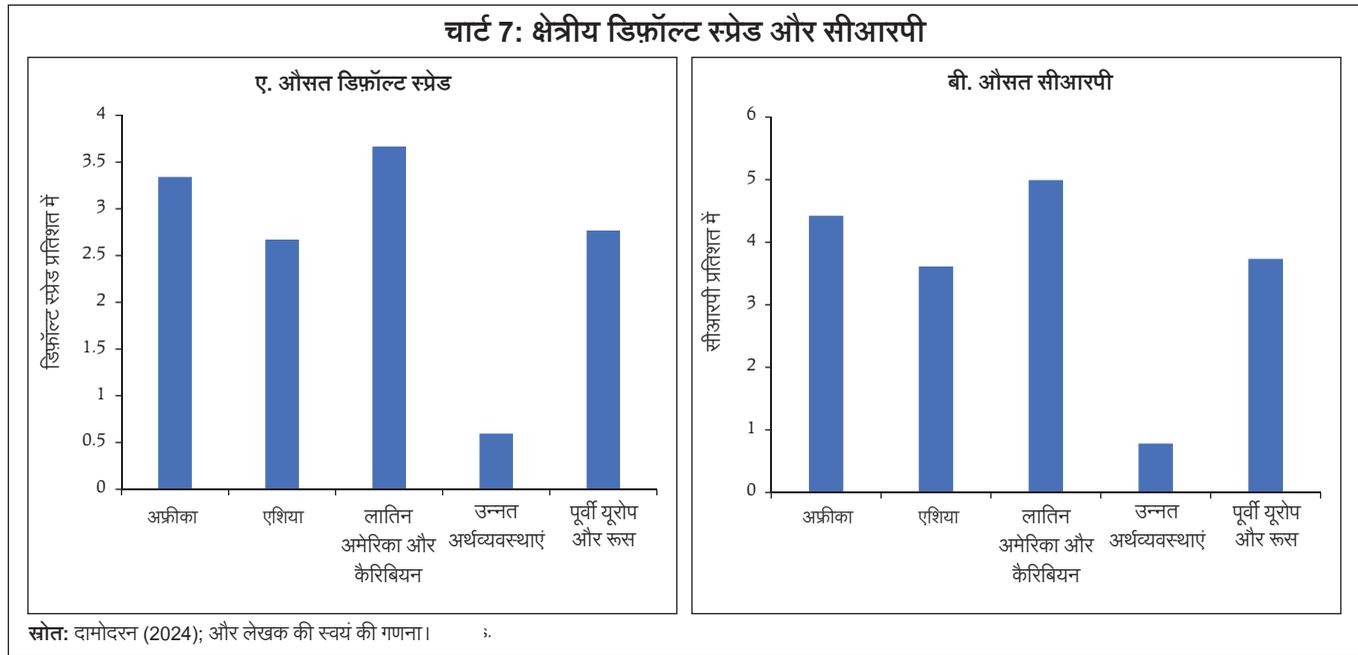
कोविड महामारी (2020-2021) के दौरान, डब्ल्यूएचआर और एसएसए क्षेत्रों से उधार लेने वाले देशों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक थी (अनुलग्नक सारणी ए4)। इस क्षेत्र के देशों का गैर-उधारकर्ताओं की तुलना में जोखिम प्रीमियम अधिक और रेटिंग कम थी। उदाहरण के लिए, आईएमएफ से उधार लेने वाले देशों के लिए औसत सीआरपी 2020 और 2021 में क्रमशः 5.1 और 5.4 प्रतिशत थी, जबकि गैर-उधारकर्ताओं के लिए यह 2.7 और 2.8 प्रतिशत थी। वास्तव में, इन क्षेत्रों को अपनी कमज़ोर बाज़ार पहुँच के कारण आईएमएफ से बार-बार उधार लेना पड़ा है। उदाहरण के लिए, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा सीआरपी (5.0 प्रतिशत) और ज़्यादा डिफ़ॉल्ट स्प्रेड (3.7 प्रतिशत) था, जबकि एशिया के ईएमडीई में सीआरपी (3.6 प्रतिशत) और डिफ़ॉल्ट स्प्रेड (2.6 प्रतिशत) कम था। एई में औसत डिफ़ॉल्ट स्प्रेड (0.7 प्रतिशत) और सीआरपी (0.8

## सारणी 2: देश जोखिम प्रीमियम

(प्रतिशत में)

देश	एफसीएल		
	एफसीएल-पूर्व (2008)	एफसीएल सीआरपी के दौरान (2009-11)	एफसीएल सीआरपी के बाद (2012)
कोलंबिया	3.9	3.0	3.0
मेक्सिको	3.0	2.3	2.3
पोलैंड	2.4	1.5	1.0
पीएलएल			
	पीएलएल पूर्व (2011)	पीएलएल के दौरान (2012)	पीएलएल के बाद (2013)
मोरक्को	3.6	3.6	3.7

स्रोत: दामोदरन (2024); और लेखक की स्वयं की गणना।



प्रतिशत) सबसे कम था, और इस प्रकार, उन्हें आईएमएफ ऋणों की आवश्यकता नहीं पड़ी (चार्ट 7)। इसके अलावा, कुछ तेज़ी से बढ़ते ईएमडीई की, विशेष रूप से एपीआर क्षेत्र में, बाज़ार पहुँच बेहतर थी और उन्हें आईएमएफ से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

बाज़ार पहुँच और आईएमएफ ऋणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए देश निश्चित प्रभाव मॉडल के साथ एक पैन्ल प्रतिगमन का अनुमान लगाया गया है। यह प्रतिगमन उन देशों द्वारा लिए गए ऋणों की राशि पर अनुमानित है जिसमें संबंधित देश जोखिम प्रीमियम व्याख्यात्मक चर<sup>14</sup> के रूप में है, और इसके विनिर्देश निम्नलिखित हैं:

$$Amount\ Drawn_{it} = \alpha + \beta CRP_{it} + Global\ Shock + Country\ Fixed\ Effects$$

उपर्युक्त समीकरण में,

आहरित राशि, वर्ष  $t$  में देश  $i$  द्वारा प्राप्त आईएमएफ ऋण सहायता की राशि को एसडीआर मिलियन में दर्शाती है; बाज़ार पहुँच को देश जोखिम प्रीमियम (सीआरपी) के माध्यम से मापा जाता है, और वैश्विक आघात जीएफसी, यूरो-ज़ोन और कोविड संकट के लिए टाइम-डमी को इंगित करता है।

यह नमूना 124 विभिन्न देशों के एक असंतुलित पैन्ल<sup>15</sup> पर आधारित है, जिन्होंने 2000 से 2024 के दौरान आईएमएफ से उधार लिया है। यह प्रतिगमन पूरे नमूना अवधि के लिए देश-विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, देश प्रभावों के साथ लगाया जाता है। मॉडल 1 में, वैश्विक आघातों को नियंत्रित किए बिना सीआरपी के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। मॉडल 2, 3, 4 और 5 में, तीन आघातों, अर्थात् जीएफसी, यूरो-ज़ोन और कोविड, को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग डमी जोड़े गए हैं। और मॉडल 5 में, तीनों आघातों को एक साथ जोड़ा गया है।

प्रतिगमन परिणामों से पता चलता है कि उच्च देश जोखिम प्रीमियम द्वारा इंगित कम बाज़ार पहुँच वाले देशों ने आईएमएफ से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की। ये परिणाम सभी पाँच मॉडलों में प्रमुख थे, जो दर्शाता है कि बाज़ार पहुँच की कमी ही विभिन्न देशों को आईएमएफ से अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती है। बिना टाइम डमी वाले सीआरपी के लिए प्रतिगमन पैरामीटर 90% विश्वास अंतराल पर सार्थक है। दूसरी ओर, टाइम डमी वाले सीआरपी के लिए अनुमानित पैरामीटर 99% विश्वास अंतराल पर सार्थक हो जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जहाँ उच्च सीआरपी (अर्थात्, बाज़ार पहुँच का अभाव) विभिन्न देशों द्वारा

<sup>14</sup> चूंकि सीआरपी की गणना डिफॉल्ट स्प्रेड का उपयोग करके की जाती है, इसलिए हम बहुसंख्यता से बचने के लिए केवल प्रतिगमन विश्लेषण में सीआरपी को शामिल करते हैं।

<sup>15</sup> सभी 124 देशों ने उल्लिखित वर्ष में उधार नहीं लिया है, और इसलिए, नमूना एक असंतुलित पैन्ल है।

**सारणी 3: पैनल प्रतिगमन परिणाम**

	आहरित राशि (2000-2024)
<b>मॉडल 1: वैश्विक आघात डमी के बिना</b>	
देश जोखिम प्रीमियम	149.2*(2.5)
देश निश्चित प्रभाव	हाँ
अवलोकनों की संख्या	312
<b>मॉडल 2: वैश्विक वित्तीय संकट डमी (2008-2010)</b>	
देश जोखिम प्रीमियम	143.5*(2.4)
जीएफसी डमी	8.2 (1.0)
देश निश्चित प्रभाव	हाँ
अवलोकनों की संख्या	312
<b>मॉडल 3: यूरो-जोन संकट डमी (2012-2014)</b>	
देश जोखिम प्रीमियम	160.2*** (2.6)
यूरो-जोन डमी	-4.9 (-0.9)
देश निश्चित प्रभाव	हाँ
अवलोकनों की संख्या	312
<b>मॉडल 4: कोविड (2020-2021)</b>	
देश जोखिम प्रीमियम	185.8*** (2.8)
कोविड डमी	5.3 (0.1)
देश निश्चित प्रभाव	हाँ
अवलोकनों की संख्या	312
<b>मॉडल 5: सभी वैश्विक आघात</b>	
देश जोखिम प्रीमियम	189.9*** (2.9)
जीएफसी डमी	8.7* (1.7)
यूरो-जोन संकट डमी	-2.5 (-0.4)
कोविड डमी	6.0 (0.1)
देश निश्चित प्रभाव	हाँ
अवलोकनों की संख्या	312

कोष्ठक में आँकड़े. \*:  $p < 0.1$ , \*\*:  $p < 0.05$ , and \*\*\*:  $p < 0.01$

आईएमएफ ऋणों का सहारा लेने में एक महत्वपूर्ण कारक है, वहीं आघात घटनाएँ इन देशों द्वारा आईएमएफ ऋणों का सहारा लेने की स्थिति को और बढ़ा देती हैं (सारणी 3)।

जैसा कि पहले कहा गया है, संकट के दौरान विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ ऋणों का सहारा लेने में वृद्धि हुई है। ऐसा संभवतः इस तथ्य के कारण है कि संकट की घटनाओं के कारण समष्टि आर्थिक बुनियाद बिगड़ जाती है और प्रभावित देशों के देश जोखिम प्रीमियम में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बाजार पहुँच कम हो जाती है और उन्हें आईएमएफ ऋणों का सहारा लेना पड़ता है।

**IV. निष्कर्ष**

यह लेख दर्शाता है कि पिछले तीन दशकों में, दुनिया भर में बढ़ते आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से एलआईसी और कुछ ईएमडीई के लिए, आईएमएफ ऋणों पर निर्भरता बढ़ी है। जिन देशों के पास स्वैप लाइन और आरएफए सहित वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध थे, और जिनकी बेहतर रेटिंग के माध्यम से बाजार पहुँच थी, वे आमतौर पर आईएमएफ ऋण नहीं लेते थे। दूसरी ओर, आईएमएफ से ऋण लेने वालों की रेटिंग आमतौर पर कमजोर होती थी और बाजार पहुँच सीमित होती थी। इसके अलावा, आघातपूर्ण घटनाएँ आईएमएफ ऋणों पर विभिन्न देशों की निर्भरता बढ़ाती प्रतीत होती हैं क्योंकि ये घटनाएँ संकटग्रस्त देशों के बाजार को बढ़ी हुई सीआरपी के माध्यम से सीमित करती प्रतीत होती हैं। एफसीएल और पीसीएल जैसे कुछ आईएमएफ कार्यक्रम, जो मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियाद वाले देशों के लिए बाजार पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे, अपने उद्देश्य में सफल होते प्रतीत होते हैं। मुख्यतः, बाजार पहुँच और वैकल्पिक संसाधनों की कमी या सीमितता वाले देश आईएमएफ ऋण का लाभ उठाते हैं, जो अंतिम उपाय के वैश्विक ऋणदाता के रूप में आईएमएफ की भूमिका की ओर इशारा करता है और जीएफएसएन में इसकी केंद्रीय भूमिका को उजागर करता है।

**संदर्भ**

- Ahmad, M. (2019). Globalisation, economic growth, and spillovers: A spatial analysis. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*, 13(3), 255-276.
- Attinasi, M. G., Balatti, M., Mancini, M., & Metelli, L. (2022). Supply chain disruptions and the effects on the global economy. *Economic Bulletin Boxes*, 8.
- Bird, G., & Bird, G. (1988). An analysis of drawings on the International Monetary Fund by developing countries. *Managing Global Money: Essays in International Financial Economics*, 104-112.
- Bird, G., & Rowlands, D. (2002). The pattern of IMF lending: an analysis of prediction failures. *The Journal of Policy Reform*, 5(3), 173-186.
- Cornelius, P. (1987). The demand for IMF credits by sub-Saharan African countries. *Economics Letters*, 23(1), 99-102.

- Damodaran, A. (2024). Country risk: determinants, measures and implications Measures and Implications-The 2024 Edition. *SSRN Electron. J.*
- Elekdağ, S. (2008). How does the global economic environment influence the demand for IMF resources. *IMF Staff Papers*, 55(4), 624-653.
- International Monetary Fund. Monetary, & Capital Markets Department. (2004). *Global Financial Stability Report, April 2004: Market Developments and Issues*. International Monetary Fund.
- IMF. (2016). Adequacy of the global financial safety net. *IMF Policy Papers, International Monetary Fund, Washington DC*.
- IMF. (2017). Collaboration between the Regional Financing Arrangements and IMF. *IMF Policy Papers, International Monetary Fund, Washington DC*.
- Joyce, J. P. (1992). The economic characteristics of IMF program countries, *Economics Letters*, 38(2), 237-242.
- Joyce, J. P. (2004). Adoption, implementation and impact of IMF programmes: A review of the issues and evidence. *Comparative Economic Studies*, 46, 451-467.
- Kawai, M. (2010). Reform of the international financial architecture: An Asian perspective. *The Singapore Economic Review*, 55(01), 207-242.
- Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. M. (2007). The external wealth of nations mark II: Revised and extended estimates of foreign assets and liabilities, 1970–2004. *Journal of international Economics*, 73(2), 223-250.
- Villaverde, J., & Maza, A. (2011). Globalisation, growth and convergence. *The World Economy*, 34(6), 952-971.

## अनुलग्नक सारणियाँ

## सारणी ए1: मूडीज रेटिंग स्केल

निवेश योग्य ग्रेड	एएए एए1, एए2 एवं एए3 ए1, ए2 एवं ए3 बीएए1, बीएए2 एवं बीएए3	प्राइम उच्च श्रेणी उच्च मध्यम श्रेणी निम्न मध्यम श्रेणी
अनुमानित ग्रेड	बीए1, बीए2 एवं बीए3 बी1, बी2 एवं बी3 सीएए1, सीएए2 एवं सीएए3 सीए सी डी	गैर-निवेश ग्रेड अनुमानित अधिक अनुमानित पर्याप्त जोखिम अत्यधिक अनुमानित डिफॉल्ट

सारणी ए2: वैश्विक वित्तीय संकट

2008-11 के दौरान आईएमएफ से उधार लेने वाले देश

देश	2008		2009		2010		2011	
	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी
अंगोला			एनए	एनए				
आर्मीनिया	बीए2	6	बीए2	4.5	बीए2	4.125		
कोलंबिया			बीएए3	3	बीएए3	3	बीएए3	3
कोमोरोस			एनए	एनए				
कांगो	एनए	एनए						
जिबूती	एनए	एनए						
डॉमिनिकन गणराज्य			बी2	8.25				
अल साल्वाडोर			बीए1	3.75	डब्ल्यूआर*	15		
इथियोपिया			एनए	एनए				
घाना			एनए	एनए				
यूनान			ए2	1.57	बीए1	3.6		
आइसलैंड	बीएए1	3						
आयरलैंड			ए	0.45	बीएए1	2.25		
जमैका					बी3	9		
लाटविया	ए3	2.625						
मलावी	एनए	एनए						
माली	एनए	एनए						
नाइजर	एनए	एनए						
पुर्तगाल					ए1	1.275	बीए2	4.125
टोगो	एनए	एनए						

टिप्पणी: \*डब्ल्यूआर: रेटिंग वापस ले ली गई; एनए: कोई रेटिंग उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: दामोदरन (2024)।

चुनिंदा देश जिन्होंने 2008-11 के दौरान आईएमएफ से उधार नहीं लिया

देश	2008		2009		2010		2011	
	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी
ऑस्ट्रिया	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
बेल्जियम	एए1	1.05	एए1	0.45	एए1	0.375	एए3	1.05
डेनमार्क	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
फिनलैंड	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
फ्रांस	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
जर्मनी	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
इटली	एए2	1.5	एए2	0.9	एए2	0.75	ए2	1.5
स्वीडन	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
युनाइटेड किंगडम	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0
संयुक्त राज्य अमेरिका	एएए	0	एएए	0	एएए	0	एएए	0

स्रोत: दामोदरन (2024)।

**सारणी ए3: यूरो-ज़ोन संकट**  
**2012-14 के दौरान आईएमएफ से उधार लेने वाले देश**

देश	2012		2013		2014	
	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी
अल्बानिया					बी1	6.75
आर्मीनिया					बीए2	4.50
बांग्लादेश	बीए3	4.88				
बुर्किना फासो			बी2	8.25		
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	बी3	9.00				
कोलंबिया			बीएए3	3.30		
साइप्रस	बी3	9.00	सीएए3	15	बी3	9.75
जॉर्जिया	बीए3	4.88			बीए3	5.40
यूनान	सीएए3	15.00	सीएए3	15	सीएए1	11.25
होंडुरास					बी3	9.75
जमैका			सीएए3	15		
जॉर्डन	बीए2	4.13				
मेक्सिको	बीएए1	2.25			ए3	1.80
मोरक्को	बीए1	3.60			बीए1	3.75
पाकिस्तान			सीएए1	11.25		
पोलैंड			ए2	1.28		
रोमानिया			बीएए3	3.30		
सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस					बी3	9.75
ट्यूनीशिया			बीए3	5.40		
यूक्रेन					सीएए3	15

स्रोत: दामोदरन (2024)।

**जिन देशों ने 2012-14 के दौरान आईएमएफ से उधार नहीं लिया**

देश	2012		2013		2014	
	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी
आयरलैंड	बीए1	3.60	बीए1	3.75	बीएए1	2.40
पुर्तगाल	बीए3	4.88	बीए3	5.40	बीए1	3.75
स्पेन	बीएए3	3	बीएए3	3.30	बीएए2	2.85

स्रोत: दामोदरन (2024)।

**सारणी ए4: कोविड संकट**  
**आईएमएफ से उधार लेने वाले चुनिंदा देश**

देश	2020		2021	
	रेटिंग	सीआरपी	रेटिंग	सीआरपी
बहामास	बीए2	2.91	बीए3	3.56
बेनिन	बी2	5.33	बी1	4.45
बोलीविया	बी2	5.33	बी2	5.44
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना	बी3	6.30	बी3	6.43
बुर्किना फासो	बी2	5.33	बी2	5.44
कैमरून	बी2	5.33	बी2	5.44
केप वर्दे	बी2	5.33	बी3	6.43
कांगो (का लोकतांत्रिक गणराज्य)	सीएए1	7.26	सीएए1	7.41
कोस्टारिका	बी2	5.33	बी2	5.44
कोत दिव्वार	बीए3	3.49	बीए3	3.56
डॉमिनिकन गणराज्य	बीए3	3.49	बीए3	3.56
ईक्वाडोर	सीएए3	9.68	सीएए3	9.89
अल साल्वाडोर	बी3	6.30	सीएए1	7.41
इथियोपिया	बी2	5.33	सीएए2	8.90
गैबॉन	सीएए1	7.26	सीएए1	7.41
घाना	बी3	6.30	बी3	6.43
ग्वाटेमाला	बीए1	2.42	बीए1	2.47
जमैका	बी2	5.33	बी2	5.44
जॉर्डन	बी1	4.36	बी1	4.45
केन्या	बी2	5.33	बी2	5.44
माली	सीएए1	7.26	सीएए1	7.41
मोल्दोवा	बी3	6.30	बी3	6.43
मंगोलिया	बी3	6.30	बी3	6.43
मोंटेनेग्रो	बी1	4.36	बी1	4.45
मोज़ाम्बिक	सीएए2	8.72	सीएए2	8.90
नामीबिया	बीए3	3.49	बीए3	3.56
निकारागुआ	बी3	6.30	बी3	6.43
नाइजर	बी3	6.30	बी3	6.43
नाइजीरिया	बी2	5.33	बी2	5.44
पाकिस्तान	बी3	6.30	बी3	6.43
पनामा	बीएए1	1.55	बीएए2	1.88
पापुआ न्यू गिनी	बी2	5.33	बी2	5.44
पैराग्वे	बीए1	2.42	बीए1	2.47
पेरू	ए3	1.16	बीएए1	1.58
रवांडा	बी2	5.33	बी2	5.44
सेनेगल	बीए3	3.49	बीए3	3.56
सोलोमन द्वीप	बी3	6.30	सीएए1	7.41
दक्षिण अफ्रीका	बीए2	2.91	बीए2	2.97
ट्यूनीशिया	बी2	5.33	सीएए1	7.41
युगांडा	बी2	5.33	बी2	5.44

स्रोत: दामोदरन (2024)।



# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुद्रा और बैंकिंग  
मूल्य और उत्पादन  
सरकारी खाते और खजाना बिल  
वित्तीय बाजार  
बाह्य क्षेत्र  
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ  
आवसरिक शृंखलाएं



## विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	129
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	130
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	131
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	132
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	133
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	133
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	134
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	135
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	136
9	कुल चलनिधि राशियाँ	137
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	138
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	138
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	139
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	139
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	140
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	141
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	142
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	143
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	144
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	144
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	144
21	थोक मूल्य सूचकांक	145
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	149
	<b>सरकारी खाते और खज़ाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	149
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	150
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	150
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	151
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	152
28	वाणिज्यिक पत्र	152
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	152
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	153

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	<b>बाह्य क्षेत्र</b>	
31	विदेशी व्यापार	154
32	विदेशी मुद्रा भंडार	154
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	154
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	155
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	155
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	156
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	157
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	158
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	159
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	160
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	161
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	162
	<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	163
	<b>आवसरिक शृंखलाएं</b>	
44	लघु बचत	165
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	166
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	167
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	168
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	169
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	170
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	171
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	174

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

## सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2023-24		2024-25	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
<b>1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)</b>					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.6	9.2	8.0	5.8	6.2
1.1.1 कृषि	2.7	3.7	1.5	4.1	5.6
1.1.2 उद्योग	11.0	15.3	12.6	2.0	3.5
1.1.3 सेवाएं	9.2	8.3	8.5	7.4	7.3
1.1ए अंतिम खपत व्यय	5.9	5.1	5.3	5.6	7.1
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	8.8	11.7	9.3	5.8	5.7
	2023-24	2023	2024	2025	
	1	दिसं	जन	दिसं	जन
		2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	4.4	4.2	3.5	5.0
<b>2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)</b>					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9 (13.5)	12.6 (13.3)	12.5 (13.2)	10.2 (9.8)	11.6 (11.3)
2.1.2 ऋण#	16.3 (20.2)	15.6 (20.0)	16.1 (20.3)	12.4 (11.2)	12.9 (11.8)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3 (20.2)	15.8 (20.1)	16.2 (20.4)	12.4 (11.1)	12.9 (11.8)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1 (12.8)	15.6 (17.6)	13.2 (15.0)	11.1 (10.1)	10.4 (9.6)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.0	6.3	4.9	4.4
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1 (11.6)	11.0 (11.5)	11.0 (11.5)	9.3 (9.0)	9.6 (9.3)
<b>3 अनुपात (%)</b>					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.25	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0 (5.0)	5.2 (5.2)	5.1 (5.1)	4.7 (4.7)	4.6 (4.5)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1 (80.3)	77.1 (79.5)	77.7 (80.0)	78.7 (80.4)	78.6 (80.3)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8 (113.4)	95.8 (111.9)	95.6 (117.5)	86.1 (82.6)	83.8 (81.0)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5 (29.8)	29.5 (29.8)	29.5 (29.8)	29.8 (29.9)	29.4 (29.5)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8 (28.4)	24.7 (28.2)	24.5 (27.7)	32.6 (30.8)	27.7 (26.3)
<b>4 ब्याज दरें (%)</b>					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.95/10.25	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.95/8.50	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.50/7.25	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.81	6.77	6.71	6.57
4.11 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.93	7.04	6.55	6.56
4.12 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.16	7.18	6.70	6.67
4.13 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.13	7.15	6.69	6.63
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.20	7.15	6.76	6.71
<b>5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम</b>					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	83.12	83.12	85.59	86.64
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	92.00	90.42	89.11	90.01
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम					
1-माह (%)	1.00	1.23	1.30	3.70	2.80
3-माह (%)	1.11	1.65	1.59	2.91	2.69
6-माह (%)	1.31	1.51	1.60	2.61	2.30
<b>6 मुद्रास्फीति (%)</b>					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.7	5.1	5.2	4.3
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	4.9	4.6	3.5	3.1
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	0.9	0.3	2.6	2.3
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	5.7	4.1	6.0	4.7
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-1.4	-0.4	-2.6	-2.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-0.8	-1.2	2.1	2.5
<b>7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)</b>					
7.1 आयात	-5.3	-6.6	2.0	1.9	10.3
7.2 निर्यात	-3.1	0.8	4.3	-1.2	-2.4

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेचमार्क

का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी परखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

\*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2024-25	2024	2025				
			फर	जन 31	फर 07	फर 14	फर 21
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3423265	3564965	3596638	3606046	3615412	3615574
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	12	15	14	12	14
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>3482344</b>	<b>3423278</b>	<b>3564977</b>	<b>3596653</b>	<b>3606060</b>	<b>3615424</b>	<b>3615588</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 स्वर्ण	162996	148980	217109	223243	227652	228657	226730
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3274006	3347525	3373139	3378001	3386454	3388603
1.2.3 रुपया सिक्का	463	293	343	271	407	313	255
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1656495	1446595	1382908	1433291	1530307	1445017
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	100	100	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	43	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	909400	924083	878388	953498	888462	927189
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	8520	7772	7929	7798	7826	7452
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	5127	4567	5154	4873	5018	4814
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	47991	46275	46118	45756	46181	46630
2.1.1.8 अन्य	545400	540867	362067	346482	327887	482446	363484
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	144448	101688	98695	93336	100231	95305
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1712392	2034572	2124837	2110913	2125676	2173208
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>3587080</b>	<b>3368888</b>	<b>3481167</b>	<b>3507746</b>	<b>3544204</b>	<b>3655983</b>	<b>3618225</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	12	15	14	12	14
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1315955	1344426	1420016	1341554	1364059	1402695
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	14809	19332	35454	25646	22112	22937
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	256374	256989	185420	261331	301901	229480
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	35	-	-	-	35	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	9066	20988	18951	23894	26632	28827
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	142640	101053	98469	93021	99679	94847
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1364312	1319974	1319818	1360558	1401314	1401615
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	265683	418394	429601	438187	440241	437810
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	247933	396899	408114	416172	418010	414488

\* डेटा अनंतिम हैं।

## सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन- शील रेपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
								1	2	
जन. 1, 2025	-	-	-	-	666	115712	-	-	-	-115046
जन. 2, 2025	-	-	-	-	15	152048	-543	-	-	-152576
जन. 3, 2025	-	-	-	-	2179	99805	-	-	-	-97626
जन. 4, 2025	-	-	-	-	1398	94806	-	-	-	-93408
जन. 5, 2025	-	-	-	-	342	94235	-	-	-	-93893
जन. 6, 2025	-	-	-	-	15860	54274	-	-	-	-38414
जन. 7, 2025	-	-	50007	-	24676	66630	57	-	-	8110
जन. 8, 2025	-	-	-	-	44652	48937	-408	-	-	-4693
जन. 9, 2025	-	-	50004	-	20639	56581	980	-	-	15042
जन. 10, 2025	-	-	275011	-	17638	76178	-	-	-	216471
जन. 11, 2025	-	-	-	-	5712	50540	-	-	-	-44828
जन. 12, 2025	-	-	-	-	5882	53734	-	-	-	-47852
जन. 13, 2025	-	-	50008	-	539	84042	-	-	-	-33495
जन. 14, 2025	-	-	-	-	2069	77450	1020	-	-	-74361
जन. 15, 2025	-	-	3980	-	794	66409	-635	-	2570	-59700
जन. 16, 2025	-	-	30760	-	1138	84506	611	-	4480	-47517
जन. 17, 2025	-	-	33467	-	4096	80248	24	-	3125	-39536
जन. 18, 2025	-	-	-	-	14661	83219	-	-	-	-68558
जन. 19, 2025	-	-	-	-	13064	71692	-	-	-	-58628
जन. 20, 2025	-	-	75772	-	4461	78650	-10	-	4980	6553
जन. 21, 2025	-	-	71900	-	8207	43894	-	-	1355	37568
जन. 22, 2025	-	-	125009	-	3349	75393	-	-	4045	57010
जन. 23, 2025	-	-	145683	-	2831	67458	-	-	3900	84956
जन. 24, 2025	-	-	362107	-	3232	92874	-	-	6570	279035
जन. 25, 2025	-	-	-	-	3351	53731	-	-	-	-50380
जन. 26, 2025	-	-	-	-	3459	54345	-	-	-	-50886
जन. 27, 2025	-	-	193661	-	682	55881	0	-	4710	143172
जन. 28, 2025	-	-	139281	-	1779	61541	-	-	3080	82599
जन. 29, 2025	-	-	166833	-	522	83366	-	-	-	83989
जन. 30, 2025	-	-	117354	-	3099	69667	-	-	-	50786
जन. 31, 2025	-	-	100013	-	6311	102895	-	-	20020	23449

## सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

## i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2024		2025
		जन	दिसं	जन
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	1950	-15150	-11139
1.1 क्रय (+)	194296	10400	53898	49145
1.2 विक्रय (-)	153025	8450	69048	60284
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	16205	-128753	-95388
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	19465	-36106	-47245
(₹ करोड़)	339528	158524	-306406	-401795
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	9974	-67938	-77528

## ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2024		2025
		जन	दिसं	जन
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	1050	3552	3703
1.2 विक्रय (-)	7930	1050	3552	3703
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	0	-3450	-2683

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)  
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 जनवरी 2025 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	5100	26045	-20945
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	25978	-25978
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	30605	-30605
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>5100</b>	<b>82628</b>	<b>-77528</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2023-24	2024					2025	
		फर 23	सितं 20	अक्तू 18	नवं 29	दिसं 27	जन 24	फर 21
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	144270	21731	4216	18513	31127	3232	500
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	9900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	9066	8547	7223	8428	8459	9556	9096
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	153336	30278	11439	26941	39586	12788	9596

## मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3323406	3459977	3497219	3503602
1.1 संचलन में नोट	3477795	3386177	3524608	3553367	3563413
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	32144	34940	34940	34940
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	95801	101225	92748	96376
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2578240	2812342	2722910	2756006
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2497829	2710713	2619285	2651712
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	80411	101629	103625	104294
<b>3 एम1 (1+2)</b>	<b>6091700</b>	<b>5901646</b>	<b>6272318</b>	<b>6220129</b>	<b>6259608</b>
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	195777	218498	200889	200889	200889
<b>5 एम2 (3+4)</b>	<b>6287477</b>	<b>6120144</b>	<b>6473207</b>	<b>6421018</b>	<b>6460497</b>
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	18399864	20240455	20425953	20369151
	<b>(18848160)</b>	<b>(18516165)</b>	<b>(20307146)</b>	<b>(20491381)</b>	<b>(20433390)</b>
7 एम3 (3+6)	24831618	24301509	26512774	26646082	26628759
	<b>(24939860)</b>	<b>(24417811)</b>	<b>(26579464)</b>	<b>(26711510)</b>	<b>(26692999)</b>
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1313366	1268920	1379283	1379283	1379283
9 एम4 (7+8)	26144984	25570429	27892057	28025365	28008042
	<b>(26253226)</b>	<b>(25686731)</b>	<b>(27958747)</b>	<b>(28090793)</b>	<b>(28072282)</b>

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम<sub>3</sub>) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>7512016</b>	<b>7116700</b>	<b>7850250</b>	<b>7987492</b>	<b>7937526</b>
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7210188)	(7901119)	(8038367)	(7988402)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	934359	1000891	1104710	1047893
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1372005	1276034	1270175	1309316
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1359195	1254193	1255555	1288822
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	12810	21841	14620	20495
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	437646	275143	165465	261423
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	437603	275101	165423	261381
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6182341	6849360	6882782	6889633
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6275829)	(6900228)	(6933657)	(6940509)
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>16672145</b>	<b>16239988</b>	<b>18090813</b>	<b>18156833</b>	<b>18230417</b>
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(16793224)	(18529356)	(18589884)	(18672006)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5237	10519	10512	22760
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	16234750	18080294	18146321	18207657
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(16787986)	(18518837)	(18579372)	(18649246)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	15490356	17304495	17367609	17426890
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(16043592)	(17743037)	(17800660)	(17868479)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	726809	757258	759628	761677
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	17586	18541	19085	19091
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(17586)	(18541)	(19085)	(19091)
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>5567504</b>	<b>5275455</b>	<b>5691089</b>	<b>5592318</b>	<b>5638730</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5241083	4975898	5324382	5225611	5272023
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4975899	5324384	5225611	5272019
3.1.2 विदेशी देयताएं	0	1	2	0	-4
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	326421	299557	366707	366707	366707
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>33432</b>	<b>32887</b>	<b>35683</b>	<b>35683</b>	<b>35683</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>4953478</b>	<b>4363521</b>	<b>5155062</b>	<b>5126245</b>	<b>5213597</b>
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5467477)	(4893943)	(5577783)	(5544742)	(5641822)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1790134	1721382	1891177	1910748	1986997
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3163344	2642139	3263885	3215497	3226600
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3677343)	(3172560)	(3686606)	(3633995)	(3654825)
<b>एम<sub>3</sub> (1+2+3+4-5)</b>	<b>24831618</b>	<b>24301509</b>	<b>26512774</b>	<b>26646082</b>	<b>26628759</b>
एम <sub>3</sub> (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(24417811)	(26579464)	(26711510)	(26692999)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
<b>समग्र मौद्रिक राशियाँ</b>					
एनएम <sub>1</sub> (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5901646	6272318	6220129	6259608
एनएम <sub>2</sub> (एनएम <sub>1</sub> + 1.2.2.1)	14424855	14090468	15252461	15282992	15296176
एनएम <sub>2</sub> (एनएम <sub>1</sub> + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(14142803)	(15282471)	(15312435)	(15325083)
एनएम <sub>3</sub> (एनएम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	24909855	27183290	27283273	27294849
एनएम <sub>3</sub> (एनएम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(25026157)	(27249981)	(27348701)	(27359088)
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3323406	3459977	3497219	3503602
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	20695211	22666584	22758981	22732973
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(20811512)	(22733275)	(22824409)	(22797212)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2497829	2710713	2619285	2651712
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	18197382	19955872	20139696	20081261
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(18313684)	(20022562)	(20205125)	(20145500)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	8188822	8980142	9062863	9036567
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(8241158)	(9010153)	(9092306)	(9065475)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	353658	499061	494242	503843
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	10008560	10975729	11076833	11044693
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(10072526)	(11012409)	(11112819)	(11080025)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	80411	101629	103625	104294
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	810828	955100	923448	953980
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	25295986	24461941	27103156	27346110	27384392
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(25108664)	(27592567)	(27830036)	(27876856)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7116700	7850250	7987492	7937526
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7210188)	(7901119)	(8038367)	(7988402)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	934359	1000891	1104710	1047893
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6182341	6849360	6882782	6889633
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6275829)	(6900228)	(6933657)	(6940509)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	17345240	19252905	19358618	19446866
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(17898476)	(19691448)	(19791669)	(19888454)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5237	10519	10512	22760
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	17340003	19242386	19348106	19424106
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(17893239)	(19680929)	(19781157)	(19865694)
<b>2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ)</b>	1089184	1087256	1146977	1189681	1201967
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32887	35683	35683	35683
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5111079	4952946	5300371	5247997	5321759
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5241083	4975898	5324382	5225611	5272023
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	-130004	-22951	-24011	22386	49737
2.4 पूंजी खाता	3912897	3977586	4396751	4403935	4467201
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653834	1090755	1281889	1361080	1408009

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2024			2025
		जन	नवं	दिसं	जन
	1	2	3	4	5
<b>1 एनएम<sub>3</sub></b>	<b>25387764</b>	<b>24909855</b>	<b>27122450</b>	<b>27183290</b>	<b>27294849</b>
	(25496006)	(25026157)	(27191610)	(27249981)	(27359088)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	713503	732774	732774	732774
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>26117010</b>	<b>25623358</b>	<b>27855224</b>	<b>27916064</b>	<b>28027623</b>
	(26225252)	(25739660)	(27924384)	(27982755)	(28091862)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	76805	66263	73559	75298
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	1990	26	16	16
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	61750	52765	59920	61430
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	13065	13473	13622	13852
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>26202160</b>	<b>25700164</b>	<b>27921487</b>	<b>27989623</b>	<b>28102921</b>
	(26310403)	(25816465)	(27990647)	(28056313)	(28167160)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	..	..	116921	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>26305155</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>28106544</b>	<b>..</b>

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।  
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3419207	3561202	3589967	3599978
1.2 आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	1025449	994201	1000260	988744	948414
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	933808	939428	930602	889895
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	80411	101629	103625	104294
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4493820	4663090	4682337	4652687
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1206417	1194202	1331790	1331978
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	934359	1000891	1104710	1047893
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	921591	979092	1090132	1027441
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1358899	1253916	1255213	1288414
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1363369	1358899	1253916	1255213	1288414
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	296	278	342	408
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	437603	275101	165423	261381
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	12768	21798	14578	20452
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	266820	182792	216568	261325
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	266820	182792	216568	261325
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5237	10519	10512	22760
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3174	8459	8546	9556
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32887	35683	35683	35683
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5241083	4975898	5324382	5225611	5272023
2.3.1 स्वर्ण	439319	394644	566843	583572	600379
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	4801764	4581255	4757541	4642039	4671640
2.4 पूंजी खाता	1589134	1670689	1803583	1812997	1870465
2.5 अन्य मदें (निवल)	201000	50693	87594	97750	116532

## सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2023-24	2024		2025			
		जन 26	जन 3	जन 10	जन 17	जन 24	जन 31
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4493820	4632320	4682337	4653249	4652687	4689418
<b>1 घटक</b>							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3419207	3561655	3589967	3594621	3599978	3600982
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियाँ	1025449	994201	967198	988744	954987	948414	982697
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	80411	103468	103625	103641	104294	105739
<b>2 स्रोत</b>							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	934359	1177644	1104710	1144445	1047893	1189067
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	266820	30725	216568	181949	261325	154192
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	5237	9952	10512	15982	22760	22953
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5241083	4975898	5290108	5225611	5249634	5272023	5305327
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	32887	35683	35683	35683	35683	36017
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1790134	1721382	1911792	1910748	1974445	1986997	2018138

## सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमा राशियाँ	20145188 (20253430)	19740368 (19856670)	21711317 (21778008)	21799489 (21864918)	21774443 (21838682)
1.1.1 मांग जमा राशियाँ	2443853	2355015	2569573	2478180	2510913
1.1.2 निवासियों की सावधि जमा राशियाँ	17701334 (17809577)	17385354 (17501655)	19141745 (19208435)	19321310 (19386738)	19263530 (19327769)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमा राशियाँ	7965600	7823409	8613785	8694589	8668588
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	353658	499061	494242	503843
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमा राशियाँ	9735734	9561944	10527960	10626720	10594941
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	777942	810828	955100	923448	953980
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	23019606 (23641847)	22467590 (23114313)	25002766 (25492177)	25138245 (25622171)	25219289 (25711754)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054 (6105610)	5879874 (5973361)	6544381 (6595249)	6577038 (6627913)	6584147 (6635022)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551 (17536238)	16587716 (17140952)	18458385 (18896928)	18561207 (18994258)	18635143 (19076731)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477 (16432164)	15490356 (16043592)	17304495 (17743037)	17367609 (17800660)	17426890 (17868479)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397 (16409083)	15444737 (15997973)	17248356 (17686899)	17309886 (17742937)	17370711 (17812300)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	18260	15378	12367	14744
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	807	498	513	504
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1078293	1138015	1180718	1193005
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	-22951	-24011	22386	49737
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	241661	300706	443646	489771	520849
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमा राशियाँ	221796	202482	284584	286257	287890
2.2.3 ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार	149868	121175	183074	181129	183222
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	751085	845902	795218	713399
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	933808	939428	930602	889895
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	84097	89267	81185	84829
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	266820	182792	216568	261325
2.4 पूंजी खाता	2299592	2282726	2568998	2566767	2572565
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	361801	589242	666145	681437
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	769739	813552	801722	807699
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	194211	132284	144231	153034

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2024		2025	
		जन 26	दिसं 27	जन 10	जन 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियाँ	6106558 (6015003)	5974168 (5880681)	6595747 (6544879)	6628426 (6577551)	6635526 (6584651)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	177924	157389	161152	164435
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	49323	60941	60955	58059
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	8879	13264	13168	13078
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	80230	97546	96894	96841
4.3 अन्य	5624	5616	7491	7481	7505
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	96460	127702	125328	125694
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	284842	232630	235197	234938
5.3 अन्य	124690	109879	157698	156511	156608
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	81790	92068	130665	141035
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	183109	191321	193367	194810

टिप्पणी: कॉलम सं. (1), (2) व (3) में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं. (4) व (5) में दिया गया डेटा अर्न्ततम है।

14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुरुवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक			सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक				
	2023-24	2024		2025	2023-24	2024		2025
		जन	दिसं	जन		जन	दिसं	जन
1	2	3	4	5	6	7	8	
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	210	208	208	137	137	135	135
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>554117</b>	<b>539209</b>	<b>461496</b>	<b>453754</b>	<b>549351</b>	<b>534661</b>	<b>456515</b>	<b>448167</b>
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	269499	296174	282726	294471	265719	291575	277698
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	197881	138393	140165	182429	197782	138334	139948
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	71829	26929	30863	72452	71160	26606	30521
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>22664868</b>	<b>22220145</b>	<b>24491884</b>	<b>24920355</b>	<b>22190597</b>	<b>21760894</b>	<b>24014317</b>	<b>24436108</b>
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	20501415	22522349	22944468	20475226	20059152	22062591	22478747
	(20823825)	(20385113)	(22455658)	(22880802)	(20366984)	(19942850)	(21995901)	(22415081)
2.1.1 माँग	2492916	2403089	2617452	2713641	2443853	2355015	2569573	2665610
2.1.2 मीयादी	18439151	18098326	19904896	20230827	18031373	17704137	19493019	19813137
2.2 उधार	782260	815756	959775	905090	777942	810828	955100	900495
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	902974	1009761	1070797	937428	890914	996626	1056866
<b>3 रिजर्व बैंक से उधार</b>	<b>222716</b>	<b>337637</b>	<b>244697</b>	<b>256989</b>	<b>222716</b>	<b>337637</b>	<b>244697</b>	<b>256989</b>
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	337637	244697	256989	222716	337637	244697	256989
<b>4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेषराशि</b>	<b>1043272</b>	<b>1039630</b>	<b>1051004</b>	<b>1040610</b>	<b>1020916</b>	<b>1017905</b>	<b>1028694</b>	<b>1019921</b>
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	86504	91928	98119	89433	84097	89267	95838
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेषराशि	951386	953126	959076	942491	931483	933808	939428	924083
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>	<b>455057</b>	<b>431114</b>	<b>410612</b>	<b>394465</b>	<b>374474</b>	<b>358710</b>	<b>339609</b>	<b>321252</b>
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	244412	271169	252244	198327	199024	216738	199731
5.1.1 चालू खाते में	12010	12583	16333	12608	8971	10038	13938	10034
5.1.2 अन्य खातों में	234373	231829	254836	239636	189357	188986	202800	189697
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	39669	30173	33505	12355	17404	18342	19311
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	44910	42099	42812	48368	42300	40682	39374
5.4 अन्य आस्तियां	117734	102122	67172	65903	115424	99982	63847	62835
<b>6 निवेश</b>	<b>6256962</b>	<b>6122017</b>	<b>6747371</b>	<b>6785751</b>	<b>6106558</b>	<b>5974168</b>	<b>6595747</b>	<b>6633676</b>
	(6165407)	(6028529)	(6696503)	(6734869)	(6015003)	(5880681)	(6544879)	(6582794)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	6115133	6739533	6777484	6105610	5973361	6595249	6633133
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6884	7839	8267	949	807	498	544
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>16866336</b>	<b>16472360</b>	<b>18194821</b>	<b>18514465</b>	<b>16432164</b>	<b>16043592</b>	<b>17743037</b>	<b>18055619</b>
	(16335650)	(15919124)	(17756278)	(18076210)	(15901477)	(15490356)	(17304495)	(17617364)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	94822	106755	105577	23081	45619	56139	54961
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	16190447	17870643	18178056	16134303	15764523	17422048	17722634
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	51383	73546	76575	60467	51372	72063	74881
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	191500	212904	216741	197358	189237	211819	215621
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	16786	15770	18142	16412	16575	15551	17917
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	22244	21957	24951	23624	21885	21557	24565

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2024		2025	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन 26	दिसं 27	जन 24	2024-25	2025
		1	2	3	4	%
<b>I. बैंक ऋण (II+III)</b>	<b>16432164</b>	<b>16043592</b>	<b>17742873</b>	<b>17874756</b>	<b>8.8</b>	<b>11.4</b>
<b>II. खाद्यान्न ऋण</b>	(15901477)	(15490356)	(17304330)	(17433167)	(9.6)	(12.5)
<b>III. गैर-खाद्यान्न ऋण</b>	<b>23081</b>	<b>45619</b>	<b>56139</b>	<b>56179</b>	<b>143.4</b>	<b>23.1</b>
<b>1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ</b>	<b>16409083</b>	<b>15997973</b>	<b>17686734</b>	<b>17818577</b>	<b>8.6</b>	<b>11.4</b>
(15878397)	(15444737)	(17248192)	(17376988)	(9.4)	(12.5)	
<b>2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)</b>	<b>2071251</b>	<b>2009090</b>	<b>2239028</b>	<b>2253510</b>	<b>8.8</b>	<b>12.2</b>
(15878397)	(15444737)	(17248192)	(17376988)	(9.4)	(12.5)	
2.1 सूक्ष्म और लघु	3652804	3586425	3854429	3874601	6.1	8.0
2.2 मध्यम	(3635810)	(3569346)	(3842044)	(3862535)	(6.2)	(8.2)
2.3 बड़े	726315	710740	771039	778391	7.2	9.5
3. सेवाएं	303998	292053	348108	345986	13.8	18.5
2622490	2583632	2735282	2750224	4.9	6.4	
<b>4.592227</b>	<b>4457085</b>	<b>4962520</b>	<b>5013597</b>	<b>9.2</b>	<b>12.5</b>	
(4490467)	(4341029)	(4888308)	(4941743)	(10.0)	(13.8)	
3.1 परिवहन परिचालक	230175	227091	252966	253917	10.3	11.8
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	26312	31582	33729	30.1	28.2
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	77513	76956	80218	81478	5.1	5.9
3.4 शिपिंग	7067	7104	7102	7180	1.6	1.1
3.5 विमानन	43248	44372	45979	44788	3.6	0.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	161390	189578	190859	14.1	18.3
3.7 व्यापार	1025752	987612	1111227	1131031	10.3	14.5
3.7.1 थोक व्यापार <sup>1</sup>	538744	518664	584857	612701	13.7	18.1
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	468948	526370	518330	6.4	10.5
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	459751	520913	523535	11.6	13.9
(400470)	(377941)	(470949)	(476106)	(18.9)	(26.0)	
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से	1548027	1503363	1621767	1618650	4.6	7.7
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	325626	337673	319910	325646	0.0	-3.6
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	226963	210586	218657	219865	-3.1	4.4
3.10 अन्य सेवाएं <sup>3</sup>	998281	963135	1101188	1128430	13.0	17.2
(978198)	(942207)	(1084711)	(1112253)	(13.7)	(18.0)	
<b>4. व्यक्तिगत ऋण</b>	<b>5331290</b>	<b>5214317</b>	<b>5794866</b>	<b>5831547</b>	<b>9.4</b>	<b>11.8</b>
(4919468)	(4794254)	(5442956)	(5473924)	(11.3)	(14.2)	
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	24147	24012	23508	-0.9	-2.6
4.2 आवास	2718715	2658077	2931739	2950974	8.5	11.0
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	(2331935)	(2263913)	(2601206)	(2614403)	(12.1)	(15.5)
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	125239	116831	140998	135900	8.5	16.3
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	8492	7340	9791	9765	15.0	33.0
4.6 शिक्षा	257016	258503	291087	292084	13.6	13.0
4.7 वाहन ऋण	119380	117186	133140	135864	13.8	15.9
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	573398	560968	613302	615236	7.3	9.7
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	102562	101115	172581	178861	74.4	76.9
1402775	1370150	1478217	1489354	6.2	8.7	
(1377966)	(1344544)	(1456900)	(1468357)	(6.6)	(9.2)	
<b>5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)</b>						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ <sup>4</sup>	2081856	2028944	2236648	2248829	8.0	10.8
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम <sup>5</sup>	1974191	1939655	2145252	2191766	11.0	13.0
(iii) मध्यम उद्यम <sup>6</sup>	490703	470617	575433	574228	17.0	22.0
(iv) आवास	755222	756997	751317	747261	-1.1	-1.3
(v) शिक्षा ऋण	(660572)	(659871)	(667336)	(664181)	(0.5)	(0.7)
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	62235	61682	62993	63056	1.3	2.2
(vii) सामाजिक अवसरचना	5991	5564	8034	7559	26.2	35.8
(viii) निर्यात ऋण	2613	2580	999	983	-62.4	-61.9
(ix) अन्य	11774	11882	12352	12739	8.2	7.2
61336	64169	55134	53143	-13.4	-17.2	
1647778	1619097	1748608	1793997	8.9	10.8	

## टिप्पणियाँ:

- डेटा अनंतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
- 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।
  - थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
  - एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
  - "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
  - मई 2024 से, एक बैंक ने कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को खुदरा खंड के अंतर्गत "स्वर्ण आभूषण पर ऋण" में बदल दिया है।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों" में प्राथमिकता-प्राप्त ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

## सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2024		2025	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन 26	दिसं 27	जन 24	2025-26	2025
	1	2	3	4	%	%
<b>2 उद्योग (2.1 से 2.19)</b>	3652804 (3635810)	3586425 (3569346)	3854429 (3842044)	3874601 (3862535)	6.1 (6.2)	8.0 (8.2)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	52757	53892	53191	-1.8	0.8
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	195763	211986	217363	4.1	11.0
2.2.1 चीनी	26383	19920	19889	23147	-12.3	16.2
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	19802	21798	21313	8.2	7.6
2.2.3 चाय	5692	5967	6470	6116	7.5	2.5
2.2.4 अन्य	157089	150074	163829	166786	6.2	11.1
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	28624	30669	30468	-2.1	6.4
2.4 वस्त्र	256048	252975	264055	267676	4.5	5.8
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	96847	98163	101271	2.1	4.6
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	4233	4340	4328	1.1	2.2
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	45854	48251	49071	8.8	7.0
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	106041	113303	113005	5.2	6.6
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	12134	12804	12711	1.0	4.8
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	23748	26601	26895	12.8	13.2
2.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	46426	45875	51508	51885	11.8	13.1
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक ईंधन	132356	129735	139840	154402	16.7	19.0
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	242309	263647	265385	6.4	9.5
2.9.1 उर्वरक	37569	33977	31829	31244	-16.8	-8.0
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	79658	88026	88010	8.6	10.5
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	22679	26038	27832	20.2	22.7
2.9.4 अन्य	107584	105995	117754	118299	10.0	11.6
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	89863	98914	100175	10.8	11.5
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	11732	12507	12611	4.3	7.5
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59757	59193	61541	60576	1.4	2.3
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	380536	432757	434354	13.0	14.1
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	269707	306185	308145	12.5	14.3
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	110830	126572	126210	14.1	13.9
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	194009	227079	229142	16.5	18.1
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	43175	44413	50108	51243	18.7	15.4
2.14.2 अन्य	153468	149596	176972	177899	15.9	18.9
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	113185	109035	115180	117775	4.1	8.0
2.16 रत्न और आभूषण	84860	82137	87797	86364	1.8	5.1
2.17 निर्माण	133520	133824	143789	145199	8.7	8.5
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1288823	1314369	1309202	0.4	1.6
2.18.1 बिजली	644042	636084	656191	664682	3.2	4.5
2.18.2 दूरसंचार	138192	136797	124624	124061	-10.2	-9.3
2.18.3 सड़क	318072	317275	325833	314494	-1.1	-0.9
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	6888	8733	8682	19.3	26.0
2.18.5 बंदरगाह	6681	7171	6282	5465	-18.2	-23.8
2.18.6 रेलवे	13062	12074	13325	13306	1.9	10.2
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	172534	179380	178513	1.0	3.5
2.19 अन्य उद्योग	259016	253352	305493	299228	15.5	18.1

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति									
	2023-24	2023		2024					दिसं 13	दिसं 27
		दिसं 29	अक्टू 18	अक्टू 25	नवं 01	नवं 15	नवं 29			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	34	34	34	34	34	34	34	
<b>1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)</b>	<b>138788.9</b>	<b>134207.5</b>	<b>131965.1</b>	<b>132037.8</b>	<b>132552.8</b>	<b>138073.1</b>	<b>138154.1</b>	<b>131867.2</b>	<b>140702.2</b>	
2 मांग और मीयादी देयताएं										
<b>2.1 मांग देयताएं</b>	<b>30226.7</b>	<b>28479.2</b>	<b>25419.0</b>	<b>25724.0</b>	<b>25854.5</b>	<b>26021.8</b>	<b>26562.1</b>	<b>26329.5</b>	<b>25817.1</b>	
2.1.1 जमाराशियाँ										
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	6777.1	7243.0	7210.1	7147.7	7239.1	6670.1	6850.3	6676.5	
2.1.1.2 अन्य	15000.4	14679.1	13121.6	13179.2	13327.5	13293.6	13187.7	12967.4	13201.0	
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0		190.0	639.7	574.6	449.8	1454.3	1576.4	997.9	
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	7023.0	4864.4	4695.0	4804.7	5039.2	5249.9	4935.4	4941.7	
<b>2.2 मीयादी देयताएं</b>	<b>198141.8</b>	<b>178662.9</b>	<b>177986.9</b>	<b>177577.6</b>	<b>177539.8</b>	<b>178177.3</b>	<b>176625.0</b>	<b>168281.8</b>	<b>179599.5</b>	
2.2.1 जमाराशियाँ										
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	55648.9	56392.3	56169.6	55653.7	51788.5	50047.3	47748.7	50440.5	
2.2.1.2 अन्य	123788.5	119528.4	118843.5	118858.6	119225.3	124779.5	124966.4	118899.8	127501.2	
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	2244.3	1712.2	1460.2	1591.7	651.9	651.9	651.9	651.9	
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1241.3	1038.9	1089.2	1069.1	957.3	959.5	981.4	1005.9	
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0							0.0	0.0	
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	88584.8	89225.0	88927.0	89398.0	173712.9	112111.7	114646.7	112137.9	
4.1 मांग	27317.7	22764.0	25217.3	24980.3	25033.3	102827.6	45109.3	44426.4	44100.3	
4.2 मीयादी	68596.8	65820.8	64007.2	64224.1	64364.7	70885.3	67002.4	70220.3	68037.6	
<b>5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि</b>	<b>16263.7</b>	<b>11065.3</b>	<b>12371.3</b>	<b>11411.6</b>	<b>13169.8</b>	<b>12004.2</b>	<b>11145.5</b>	<b>12024.9</b>	<b>11868.9</b>	
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	766.3	838.2	818.0	828.9	772.6	821.1	773.9	845.0	
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	10299.0	11533.2	10593.6	12340.9	11231.6	10324.4	11251.0	11023.9	
<b>6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि</b>	<b>2088.1</b>	<b>1645.3</b>	<b>1229.3</b>	<b>1135.9</b>	<b>1084.0</b>	<b>1035.0</b>	<b>1118.1</b>	<b>1287.5</b>	<b>1010.4</b>	
<b>7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश</b>	<b>77700.5</b>	<b>74036.6</b>	<b>73111.6</b>	<b>73805.6</b>	<b>74545.3</b>	<b>75275.2</b>	<b>75074.9</b>	<b>74143.9</b>	<b>74779.2</b>	
<b>8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा</b>	<b>34355.3</b>	<b>23160.0</b>	<b>17854.6</b>	<b>16692.6</b>	<b>16150.3</b>	<b>15588.7</b>	<b>12457.8</b>	<b>13852.0</b>	<b>12854.5</b>	
<b>9 बैंक ऋण (10.1+11)</b>	<b>135141.9</b>	<b>132527.0</b>	<b>135003.0</b>	<b>136490.2</b>	<b>136802.8</b>	<b>167629.4</b>	<b>166666.0</b>	<b>141596.3</b>	<b>168136.4</b>	
10 अग्रिम										
<b>10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट</b>	<b>134936.8</b>	<b>132420.5</b>	<b>134807.4</b>	<b>136282.1</b>	<b>136593.9</b>	<b>167432.0</b>	<b>166480.4</b>	<b>141403.7</b>	<b>167935.8</b>	
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	142185.2	133287.7	141859.4	142706.5	143073.6	113950.8	111546.4	110681.2	110877.6	
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	106.5	195.6	208.1	208.9	197.4	185.6	192.6	200.6	

## कीमत और उत्पादन

## सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	फर 24	जन. 25	फर 25 (अ)	फर 24	जन. 25	फर 25 (अ)	फर 24	जन. 25	फर 25 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 खाद्य और पेय पदार्थ</b>	<b>185.9</b>	<b>192.7</b>	<b>188.4</b>	<b>187.8</b>	<b>198.8</b>	<b>195.4</b>	<b>194.6</b>	<b>204.6</b>	<b>201.3</b>	<b>190.3</b>	<b>200.9</b>	<b>197.6</b>
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	188.6	199.8	200.6	188.3	197.5	198.6	188.5	199.1	200.0
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	214.8	220.9	219.2	223.9	230.8	228.9	218.0	224.4	222.6
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	201.7	206.0	194.8	204.7	210.8	200.0	202.9	207.9	196.8
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	182.9	187.7	187.6	183.2	188.2	188.4	183.0	187.9	187.9
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	160.2	189.0	188.9	155.1	175.6	176.0	158.3	184.1	184.2
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	169.2	192.0	195.0	174.0	193.8	198.8	171.4	192.8	196.8
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	179.8	203.5	181.3	226.1	245.6	217.0	195.5	217.8	193.4
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	200.8	207.7	200.2	206.0	213.0	205.2	202.6	209.5	201.9
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	128.7	129.6	131.4	130.7	132.4	133.8	129.4	130.5	132.2
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	240.7	227.2	224.9	232.0	222.9	222.0	237.8	225.8	223.9
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	182.2	187.7	188.3	169.9	176.6	177.2	177.1	183.1	183.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	195.4	201.7	202.4	204.0	212.9	213.9	199.4	206.9	207.7
<b>2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ</b>	<b>202.0</b>	<b>207.1</b>	<b>203.3</b>	<b>203.7</b>	<b>208.3</b>	<b>209.0</b>	<b>209.5</b>	<b>212.6</b>	<b>213.2</b>	<b>205.2</b>	<b>209.4</b>	<b>210.1</b>
<b>3 कपड़ा और जूते</b>	<b>192.9</b>	<b>181.5</b>	<b>188.4</b>	<b>194.8</b>	<b>199.7</b>	<b>199.8</b>	<b>183.4</b>	<b>188.1</b>	<b>188.6</b>	<b>190.3</b>	<b>195.1</b>	<b>195.4</b>
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	195.4	200.6	200.7	185.5	190.3	190.8	191.5	196.5	196.8
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	190.9	193.9	194.1	172.0	176.0	176.2	183.0	186.5	186.7
<b>4 आवास</b>	<b>--</b>	<b>176.7</b>	<b>176.7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>178.5</b>	<b>182.6</b>	<b>183.7</b>	<b>178.5</b>	<b>182.6</b>	<b>183.7</b>
<b>5 ईंधन और बिजली</b>	<b>183.0</b>	<b>178.9</b>	<b>181.4</b>	<b>183.8</b>	<b>182.8</b>	<b>182.8</b>	<b>175.6</b>	<b>170.6</b>	<b>171.0</b>	<b>180.7</b>	<b>178.2</b>	<b>178.3</b>
<b>6 विविध</b>	<b>181.7</b>	<b>173.7</b>	<b>177.8</b>	<b>183.8</b>	<b>191.5</b>	<b>192.8</b>	<b>175.5</b>	<b>182.7</b>	<b>183.7</b>	<b>179.8</b>	<b>187.2</b>	<b>188.4</b>
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	183.3	187.3	187.7	173.3	178.8	179.2	178.6	183.3	183.7
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	193.8	200.8	201.6	188.3	195.4	196.2	191.7	198.8	199.6
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	172.2	177.3	177.7	162.3	166.1	166.5	167.0	171.4	171.8
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	177.4	181.6	182.0	172.5	177.1	177.3	174.6	179.1	179.4
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	186.0	192.5	192.6	180.9	188.0	188.2	183.0	189.9	190.0
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	188.8	208.4	214.1	190.1	210.3	216.3	189.3	209.2	215.0
<b>सामान्य सूचकांक (सभी समूह)</b>	<b>185.6</b>	<b>182.4</b>	<b>184.1</b>	<b>187.4</b>	<b>195.9</b>	<b>194.5</b>	<b>184.0</b>	<b>190.6</b>	<b>190.1</b>	<b>185.8</b>	<b>193.4</b>	<b>192.5</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।  
अ: अंतिम

## सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2024		2025
				जन	दिस	जन
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	138.9	143.7	143.2
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1258	1320	1316
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1268	1331	1328

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2024		2025
		जन	दिस	जन
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	62322	76195	79079
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	71723	89265	90020

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैल्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन (अ)	फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1 सभी पण्य</b>	<b>100.000</b>	<b>151.4</b>	<b>151.2</b>	<b>155.7</b>	<b>154.7</b>	<b>154.8</b>
<b>1.1 प्राथमिक वस्तुएँ</b>	<b>22.618</b>	<b>183.0</b>	<b>181.5</b>	<b>193.8</b>	<b>189.9</b>	<b>186.6</b>
<b>1.1.1 खाद्य वस्तुएँ</b>	<b>15.256</b>	<b>191.3</b>	<b>189.4</b>	<b>207.5</b>	<b>199.9</b>	<b>195.8</b>
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	201.5	213.7	213.2	212.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	187.7	244.7	210.8	198.1
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	183.5	185.6	187.2	186.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	169.0	174.7	174.7	171.5
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	248.9	240.2	232.6	213.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएँ	0.948	189.5	197.6	216.3	217.1	223.0
<b>1.1.2 खाद्येतर वस्तुएँ</b>	<b>4.119</b>	<b>162.4</b>	<b>159.1</b>	<b>166.2</b>	<b>167.4</b>	<b>166.8</b>
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	159.6	159.3	161.7	161.8
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	178.7	182.8	183.0	178.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएँ	1.960	134.9	133.3	140.7	142.7	143.1
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	297.9	349.3	343.7	349.2
<b>1.1.3 खनिज</b>	<b>0.833</b>	<b>217.7</b>	<b>225.0</b>	<b>230.1</b>	<b>230.1</b>	<b>227.2</b>
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	209.7	219.1	219.1	216.3
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	278.9	268.7	268.8	265.5
<b>1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस</b>	<b>2.410</b>	<b>153.6</b>	<b>155.0</b>	<b>141.9</b>	<b>150.9</b>	<b>148.7</b>
<b>1.2 ईंधन और बिजली</b>	<b>13.152</b>	<b>152.0</b>	<b>154.9</b>	<b>151.8</b>	<b>150.6</b>	<b>153.8</b>
<b>1.2.1 कोयला</b>	<b>2.138</b>	<b>136.4</b>	<b>136.0</b>	<b>135.6</b>	<b>135.6</b>	<b>135.6</b>
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	241.8	231.2	231.2	231.0
<b>1.2.2 खनिज तेल</b>	<b>7.950</b>	<b>159.0</b>	<b>159.2</b>	<b>153.9</b>	<b>155.0</b>	<b>157.9</b>
<b>1.2.3 बिजली</b>	<b>3.064</b>	<b>145.0</b>	<b>157.0</b>	<b>157.5</b>	<b>149.7</b>	<b>156.1</b>
<b>1.3 विनिर्मित उत्पाद</b>	<b>64.231</b>	<b>140.2</b>	<b>139.8</b>	<b>143.0</b>	<b>143.2</b>	<b>143.8</b>
<b>1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>9.122</b>	<b>160.5</b>	<b>160.1</b>	<b>176.8</b>	<b>177.0</b>	<b>177.8</b>
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	147.4	155.7	156.8	158.1
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	143.2	143.5	145.1	146.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	130.0	133.3	132.8	132.3
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	141.1	185.6	186.6	188.5
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	179.1	182.1	182.0	182.8
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	181.8	189.5	189.6	189.8
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	165.7	165.1	164.5	162.8
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	166.0	173.7	174.7	174.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	136.9	136.0	138.3	141.4
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	143.6	167.2	168.3	172.2
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	149.3	166.4	161.0	159.2
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	150.1	173.0	161.8	156.1
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	196.9	192.5	193.8	192.1
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	148.1	154.7	155.5	154.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	179.7	189.0	189.6	188.1
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	203.7	201.7	200.4	197.4
<b>1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण</b>	<b>0.909</b>	<b>131.5</b>	<b>132.3</b>	<b>134.5</b>	<b>134.4</b>	<b>134.5</b>
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	133.3	133.9	137.0	136.9	137.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	136.1	139.0	138.9	138.9
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	126.8	127.2	127.1	126.5
<b>1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>0.514</b>	<b>173.5</b>	<b>175.2</b>	<b>180.3</b>	<b>177.4</b>	<b>180.0</b>
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	175.2	180.3	177.4	180.0

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन (अ)	फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>134.6</b>	<b>134.4</b>	<b>136.8</b>	<b>136.9</b>	<b>137.0</b>
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	119.8	120.7	120.6	120.8
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	156.5	161.2	160.9	161.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	120.3	123.7	124.1	124.8
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	157.5	161.5	161.7	160.4
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	139.9	144.4	146.1	147.8
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	132.5	133.7	136.7	136.5
<b>1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण</b>	<b>0.814</b>	<b>150.8</b>	<b>151.7</b>	<b>154.4</b>	<b>154.1</b>	<b>154.3</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	148.8	151.6	151.4	151.8
१.३.५.२ बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	159.3	161.9	161.3	161.2
<b>1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>124.1</b>	<b>123.7</b>	<b>126.0</b>	<b>126.3</b>	<b>125.8</b>
१.३.६.१ चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	103.6	108.6	108.9	107.7
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	140.9	142.4	142.4	143.0
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	128.5	129.9	130.3	129.9
<b>१.३.७ लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>0.772</b>	<b>146.6</b>	<b>149.5</b>	<b>148.3</b>	<b>149.3</b>	<b>148.8</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	140.0	140.7	141.6	141.6
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	149.9	147.5	148.7	147.5
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	206.4	210.3	214.6	214.5	215.1
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	139.7	139.5	140.4	141.7
<b>1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>140.3</b>	<b>137.9</b>	<b>138.3</b>	<b>139.4</b>	<b>140.8</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	145.4	143.2	143.9	145.2
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	142.1	148.9	149.6	150.8
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	121.3	119.7	121.5	123.7
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>182.3</b>	<b>184.2</b>	<b>188.7</b>	<b>189.8</b>	<b>190.7</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	184.2	188.7	189.8	190.7
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>136.9</b>	<b>135.4</b>	<b>136.5</b>	<b>136.7</b>	<b>137.1</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	136.7	139.7	139.3	140.7
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	142.0	143.0	143.4	143.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	131.8	132.9	133.5	134.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	132.8	130.0	128.7	129.2	129.2
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	142.9	138.6	139.2	138.5
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	138.6	140.4	140.4	140.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	133.2	135.1	135.0	135.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	103.4	103.9	104.3	104.1
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>142.9</b>	<b>143.9</b>	<b>144.0</b>	<b>145.0</b>	<b>145.0</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	143.9	144.0	145.0	145.0
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>127.5</b>	<b>127.7</b>	<b>129.0</b>	<b>129.3</b>	<b>129.7</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.9	117.1	116.9	117.2
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	108.3	112.3	112.4	113.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	137.4	137.3	137.9	138.3
<b>1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>134.7</b>	<b>133.8</b>	<b>131.7</b>	<b>131.8</b>	<b>132.6</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	164.2	163.2	163.5	163.8
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	119.4	125.2	125.3	126.2
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	115.1	123.3	131.9	132.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	124.0	124.6	124.9	125.1
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	136.2	130.2	130.0	131.2

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन (अ)	फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएँ	0.292	137.7	137.0	140.2	139.6	140.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	131.2	135.9	135.5	136.0
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	101.5	94.6	94.1	92.2
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>141.0</b>	<b>138.5</b>	<b>137.5</b>	<b>137.1</b>	<b>137.6</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	134.9	129.1	129.3	129.2
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	150.4	133.4	131.8	131.6
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	116.7	116.8	116.7	117.3
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	138.3	139.5	138.7	138.4
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	140.3	130.1	129.9	129.6
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	133.4	132.3	132.8	132.1
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	129.4	129.1	127.7	127.4
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	169.5	162.3	164.1	164.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	145.0	157.5	157.3	160.8
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	144.1	145.3	144.8	144.6
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएँ	0.271	173.3	172.4	172.1	172.4	169.7
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>138.6</b>	<b>137.6</b>	<b>135.9</b>	<b>135.4</b>	<b>136.2</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	130.7	130.8	130.2	132.0
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	156.0	147.8	147.4	147.0
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	106.3	105.6	107.6	111.1	108.0
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	139.5	140.8	137.9	139.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	109.4	102.1	102.5	102.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	144.0	144.8	144.8	145.6
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>119.3</b>	<b>119.5</b>	<b>121.3</b>	<b>121.5</b>	<b>121.5</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	114.6	118.3	118.3	119.0
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.1	132.7	132.7	131.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	139.3	146.2	146.3	146.2
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	102.7	99.8	100.0	100.6
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	114.0	121.1	121.9	121.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	159.8	172.7	172.7	172.2
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	108.3	115.5	116.1	117.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	105.3	108.9	108.9	108.3
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>131.4</b>	<b>131.8</b>	<b>133.9</b>	<b>134.1</b>	<b>134.1</b>
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	131.3	133.0	133.1	133.0
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	137.8	139.2	141.3	140.9	141.5
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	122.4	118.0	116.8	115.9
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	146.1	145.2	154.0	154.8	155.2
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	117.8	117.7	117.9	117.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	133.1	131.5	132.0	132.0
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	120.6	125.0	124.7	124.8
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>129.0</b>	<b>130.0</b>	<b>130.5</b>	<b>131.0</b>	<b>131.2</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	131.2	132.5	133.3	134.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	132.2	134.9	135.6	135.7
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	118.0	118.9	118.8	119.0
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	130.5	129.6	129.7	128.6
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	85.2	87.0	87.4	87.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	129.8	129.9	129.6	130.0

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन (अ)	फर. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	144.1	141.5	142.0	140.3
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	144.1	145.8	146.7	147.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.6	123.1	123.1	123.3
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	88.8	90.0	91.0	91.3
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.3	126.0	126.9	127.1
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	137.8	141.3	141.6	145.1
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	146.0	144.0	143.9	144.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	70.0	69.0	69.0	69.3
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>128.4</b>	<b>128.9</b>	<b>130.0</b>	<b>130.1</b>	<b>130.2</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	129.5	130.8	131.0	131.0
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	128.3	129.1	129.0	129.3
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>143.1</b>	<b>143.5</b>	<b>145.7</b>	<b>145.7</b>	<b>145.9</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	177.9	188.4	188.4
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	108.4	108.8	108.4	109.3
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	145.2	146.8	146.0	146.2
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	137.9	135.1	134.4	134.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	160.5	163.7	165.7	164.9
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>159.6</b>	<b>158.8</b>	<b>161.3</b>	<b>161.8</b>	<b>162.0</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	158.8	161.3	161.8	162.0
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>158.2</b>	<b>161.5</b>	<b>183.1</b>	<b>186.9</b>	<b>197.0</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	161.6	184.6	188.8	199.5
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	191.9	200.6	197.2	199.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	155.2	167.9	167.7	168.2
1.3.22.4 खेल और खिलाड़ियों	0.005	159.6	159.9	163.7	164.4	164.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	161.2	158.6	156.5	156.5
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>179.8</b>	<b>178.4</b>	<b>196.0</b>	<b>191.4</b>	<b>189.0</b>

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

## सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रैल-जनवरी		जनवरी	
				2023-24	2024-25	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	145.3	151.4	153.6	161.3
<b>1 क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	125.1	129.3	144.3	150.7
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	143.5	149.5	150.8	159.1
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	198.8	209.0	197.1	201.9
<b>2 उपयोग आधारित वर्गीकरण</b>							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	146.1	152.0	154.3	162.8
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	104.1	109.7	108.3	116.8
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	156.1	163.3	163.8	172.3
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	174.1	185.0	186.6	199.6
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	117.1	127.2	121.4	130.2
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	154.0	152.0	164.9	164.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सरकारी लेखा और खजाना बिल

## सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष		अप्रैल-जनवरी		
	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
	1	2	3	4	5
<b>1 राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>3087960</b>	<b>2371188</b>	<b>2217909</b>	<b>76.8</b>	<b>82.2</b>
1.1 कर राजस्व (निवल)	2556960	1903558	1879840	74.4	80.9
1.2 करेतर राजस्व	531000	467630	338069	88.1	90.0
<b>2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>59000</b>	<b>29224</b>	<b>34219</b>	<b>49.5</b>	<b>61.1</b>
2.1 ऋण की वसूली	26000	20205	21664	77.7	83.3
2.2 अन्य प्राप्तियां	33000	9019	12555	27.3	41.9
<b>3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)</b>	<b>3146960</b>	<b>2400412</b>	<b>2252128</b>	<b>76.3</b>	<b>81.7</b>
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3698058	2812595	2633543	76.1	74.4
4.1 ब्याज भुगतान	1137940	875461	821731	76.9	77.9
5 पूंजी व्यय	1018429	757359	721187	74.4	75.9
<b>6 कुल व्यय (4+5)</b>	<b>4716487</b>	<b>3569954</b>	<b>3354730</b>	<b>75.7</b>	<b>74.7</b>
<b>7 राजस्व घाटा (4-1)</b>	<b>610098</b>	<b>441407</b>	<b>415634</b>	<b>72.4</b>	<b>49.4</b>
<b>8 राजकोषीय घाटा (6-3)</b>	<b>1569527</b>	<b>1169542</b>	<b>1102602</b>	<b>74.5</b>	<b>63.6</b>
<b>9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]</b>	<b>431587</b>	<b>294081</b>	<b>280871</b>	<b>68.1</b>	<b>41.3</b>

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2025-26।

**सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप**

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024		2025				
		फर. 2	दिसं. 27	जन 3	जन 10	जन 17	जन 24	जन 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 91-दिवसीय</b>								
1.1 बैंक	18054	9131	8030	4580	7076	7197	6520	7728
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	22804	6404	9295	14235	13720	14311	13506
1.3 राज्य सरकारें	5701	24142	109146	108346	108361	96762	78012	78400
1.4 अन्य	88670	77464	88165	92226	89489	95883	100968	107166
<b>2 182-दिवसीय</b>								
2.1 बैंक	84913	73296	49106	47781	44071	42769	39047	36704
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	72085	34108	37733	38116	42521	46104	51382
2.3 राज्य सरकारें	4070	5037	8515	7515	7515	8265	8268	8243
2.4 अन्य	102311	83623	80386	80087	86713	84110	86549	85014
<b>3 364-दिवसीय</b>								
3.1 बैंक	91819	98282	76181	75174	73432	70970	72359	73685
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	166658	104156	109132	107108	108408	108412	109263
3.3 राज्य सरकारें	41487	44282	35184	35185	35341	35656	34014	36794
3.4 अन्य	165095	179060	160663	155695	158461	158622	156229	153053
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी	318736	150113	173736	120024	247038	243703	298216	271755
4.3 राज्य सरकारें	442	181	449	1764	673	1839	838	694
4.4 अन्य	871662	855865	760045	762745	769916	764882	750794	760937

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।  
**टिप्पणी:** प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

**सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी**

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>91-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
जन 1	12000	95	32115	26	16	11974	26	12000	98.38	6.5961
जन 8	12000	109	27051	6243	54	11957	6243	18200	98.38	6.5940
जन 15	12000	108	31166	13435	53	11966	13435	25401	98.38	6.6036
जन 22	12000	130	32847	7452	77	11948	7452	19400	98.38	6.6089
जन 29	12000	138	39833	2879	44	11959	2879	14838	98.39	6.5625
<b>182-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
जन 1	8000	96	21130	42	38	7958	42	8000	96.76	6.7199
जन 8	8000	124	25863	1332	38	7968	1332	9300	96.77	6.6995
जन 15	8000	89	19631	780	48	7970	780	8750	96.76	6.7186
जन 22	8000	102	20279	980	42	7978	980	8958	96.76	6.7068
जन 29	8000	84	25022	1019	41	7981	1019	9000	96.78	6.6691
<b>364-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
जन 1	8000	111	22719	176	34	7986	176	8162	93.74	6.6998
जन 8	8000	119	27817	203	52	7968	203	8172	93.75	6.6895
जन 15	8000	119	24784	1309	50	7967	1309	9276	93.73	6.7038
जन 22	8000	131	38752	1036	19	7989	1036	9025	93.76	6.6789
जन 29	8000	138	41006	2931	27	7990	2931	10921	93.79	6.6345

# वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
जनवरी 1, 2025	5.10-6.70	6.52
जनवरी 2, 2025	5.10-6.60	6.47
जनवरी 3, 2025	5.10-6.75	6.50
जनवरी 4, 2025	5.75-6.60	6.12
जनवरी 6, 2025	5.10-6.80	6.64
जनवरी 7, 2025	5.10-6.95	6.73
जनवरी 8, 2025	5.10-7.05	6.74
जनवरी 9, 2025	5.10-7.05	6.82
जनवरी 10, 2025	5.10-7.10	6.87
जनवरी 13, 2025	5.70-7.10	6.81
जनवरी 14, 2025	5.50-6.75	6.52
जनवरी 15, 2025	5.10-6.70	6.45
जनवरी 16, 2025	5.10-6.80	6.55
जनवरी 17, 2025	5.50-6.80	6.54
जनवरी 18, 2025	5.75-6.70	6.12
जनवरी 20, 2025	5.10-6.85	6.62
जनवरी 21, 2025	5.10-6.90	6.57
जनवरी 22, 2025	5.10-6.70	6.56
जनवरी 23, 2025	5.10-6.75	6.57
जनवरी 24, 2025	5.10-6.70	6.56
जनवरी 27, 2025	5.10-6.65	6.57
जनवरी 28, 2025	5.10-6.65	6.55
जनवरी 29, 2025	5.10-6.65	6.58
जनवरी 30, 2025	5.10-6.65	6.58
जनवरी 31, 2025	5.10-6.70	6.59
फरवरी 01, 2025	5.50-6.65	6.23
फरवरी 03, 2025	5.10-6.65	6.55
फरवरी 04, 2025	5.10-6.65	6.49
फरवरी 05, 2025	5.15-6.60	6.46
फरवरी 06, 2025	5.15-6.60	6.45
फरवरी 07, 2025	5.15-6.55	6.25
फरवरी 10, 2025	5.15-6.45	6.29
फरवरी 11, 2025	5.15-6.42	6.32
फरवरी 12, 2025	5.15-6.40	6.29
फरवरी 13, 2025	5.15-6.50	6.34
फरवरी 14, 2025	5.15-6.50	6.35
फरवरी 15, 2025	5.25-6.50	5.89

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

**सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र**

मद	2024			2025		2025	
	जन. 26	दिसं. 13	दिसं. 27	जन. 10	जन. 24	फर. 7	फर. 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	355281.29	488257.46	494416.56	493930.59	499396.94	519276.82	513816.40
1.1 परखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	20013.21	74226.34	59838.75	33890.42	30080.60	71093.96	30077.77
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.07-8.02	6.96-7.75	7.02-7.85	7.05-7.48	7.07-7.88	7.03-7.83	7.02-7.93

**सं. 28: वाणिज्यिक पत्र**

मद	2024			2025		2025	
	जन. 31	दिसं. 15	दिसं. 31	जन. 15	जन. 31	फर. 15	फर. 28
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	377707.20	463801.30	435779.45	450242.05	456483.15	479257.25	465926.95
1.1 परखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	53532.05	98956.25	51524.05	39647.30	69001.15	80693.35	64880.85
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.00-14.74	7.00-11.89	6.98-12.00	7.06-12.12	7.12-13.77	6.97-12.40	6.78-12.24

**सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार**

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024		2025				
		फर. 2	दिसं. 27	जन. 3	जन. 10	जन. 17	जन. 24	जन. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	19483	18396	15234	17914	16683	20631	23225
2 नोटिस मुद्रा	2550	4491	177	4005	376	6107	598	4419
3 मीयादी मुद्रा	871	1478	539	1113	1324	217	798	976
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	687384	698889	770717	653486	779174	649147	744181
5 बाजार रेपो	574534	635275	452238	614692	536952	661241	525850	606457
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	1980	8475	8232	7738	7717	6711	7411
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	112243	130014	109915	129738	147970	133491	137918
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	131234	63621	71586	134354	133314	127533	126216
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	6282	10874	8577	4615	7851	7675	10831
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	5796	6006	4367	3821	7629	6107	5708
10.2 182-दिवसीय	6079	2837	3089	3330	2701	2031	2691	2525
10.3 364-दिवसीय	4307	5371	2669	5103	3959	2288	1893	3326
10.4 नकदी प्रबंधन बिल			0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	151521	86258	92962	149450	153113	145899	148605
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	1705	306	7	329	2452	4307	5572

## सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रै.-जन.)		2024-25 (अप्रै.-जन.) *		जन. 2024		जन. 2025 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 इक्विटी शेयर</b>	<b>339</b>	<b>80942</b>	<b>268</b>	<b>61023</b>	<b>411</b>	<b>192589</b>	<b>25</b>	<b>3612</b>	<b>43</b>	<b>3572</b>
1.1 पब्लिक	272	65832	217	54292	289	175203	22	3419	28	3066
1.2 राइट्स	67	15110	51	6731	122	17388	3	194	15	507
<b>2 बॉण्ड और डिबेंचर</b>	<b>44</b>	<b>16342</b>	<b>37</b>	<b>15122</b>	<b>38</b>	<b>7397</b>	<b>5</b>	<b>2190</b>	<b>5</b>	<b>685</b>
<b>3 कुल (1+2+3)</b>	<b>383</b>	<b>97284</b>	<b>305</b>	<b>76145</b>	<b>449</b>	<b>199986</b>	<b>30</b>	<b>5802</b>	<b>48</b>	<b>4257</b>
3.1 पब्लिक	316	82174	254	69414	327	182599	27	5609	33	3750
3.2 राइट्स	67	15110	51	6731	122	17388	3	194	15	507

**टिप्पणी:** 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

3. सारणी में केवल इक्विटी और कर्ज के सार्वजनिक और अधिकार निर्गमों को शामिल किया गया है। इसमें ऋण के निजी स्थानन, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन और अधिमानी आबंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

**स्रोत:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

## बाह्य क्षेत्र

## सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24		2024				2025	
		1	2	जन	सित.	अक्टू.	नव.	दिसं.	जन
				3	4	5	6	7	
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	310239	287698	327476	270300	322469	314229	
	मिलियन यूएस \$	437072	37324	34328	38972	32040	37944	36426	
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	71607	37790	37000	30517	41187	30726	
	मिलियन यूएस \$	84157	8615	4509	4403	3617	4846	3562	
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	238632	249908	290476	239783	281283	283503	
	मिलियन यूएस \$	352915	28709	29819	34568	28422	33097	32864	
2 आयात	₹ करोड़	5616042	447827	490071	542709	538789	495169	512618	
	मिलियन यूएस \$	678215	53877	58475	64585	63865	58265	59423	
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	129050	124924	158683	134207	115546	115868	
	मिलियन यूएस \$	178733	15526	14906	18884	15908	13596	13432	
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	318777	365147	384026	404583	379623	396750	
	मिलियन यूएस \$	499482	38351	43569	45701	47957	44669	45992	
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-137588	-202373	-215233	-268490	-172700	-198389	
	मिलियन यूएस \$	-241143	-16553	-24147	-25614	-31825	-20321	-22997	
3.1 तेल	₹ करोड़	-783382	-57443	-87135	-121683	-103689	-74359	-85142	
	मिलियन यूएस \$	-94576	-6911	-10397	-14481	-12291	-8750	-9870	
3.2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-80145	-115239	-93550	-164800	-98340	-113247	
	मिलियन यूएस \$	-146567	-9642	-13750	-11133	-19534	-11571	-13128	

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

## सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2024				2025			
		मार्च 01	जन. 24	जन. 31	फर. 07	फर. 14	फर. 21	फर. 28	
		1	2	3	4	5	6	7	
1 कुल आरक्षित निधियां	₹ करोड़	5161947	5476869	5443633	5380402	5404532	5426706	5461741	
	यूएस \$ मिलियन	622469	640279	634585	625871	623983	629557	630607	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4572053	4721047	4679273	4607932	4617658	4636524	4656917	
	यूएस \$ मिलियन	551331	551921	545480	536011	533133	537891	537684	
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	398786	566843	575530	583572	597172	600379	614007	
	यूएस \$ मिलियन	48088	66268	67092	67883	68947	69651	70893	
1.3 एसडीआर	मात्रा (मीट्रिक टन)	812.33	876.18	876.18	877.14	877.14	877.14	879.01	
	एसडीआर मिलियन	13688	13705	13705	13705	13705	13705	13705	
	₹ करोड़	150849	152881	152818	152861	154015	153955	154942	
	यूएस \$ मिलियन	18190	17873	17815	17781	17782	17861	17889	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	40260	36097	36012	36037	35687	35848	35875	
	यूएस \$ मिलियन	4860	4217	4199	4195	4122	4154	4141	

\* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।

टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

## सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2024		2025	2023-24	2024-25
		जन.	दिसं	जन. (अ)	अप्रै.-जन	अप्रै.-जन (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	151879	147732	161804	161206	10160	14308
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	23517	32198	32752	4154	7018
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	97466	99565	98494	2689	3708
1.3 एनआरओ	27522	26749	30041	29961	3317	3582

अ: अनंतिम।

## सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (अ)	2024 (अ)		2025
	1	अप्रै.-जन	अप्रै.-जन	जन	दिसं.	जन
		2	3	4	5	6
<b>1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)</b>	<b>10129</b>	<b>11523</b>	<b>1393</b>	<b>3677</b>	<b>467</b>	<b>916</b>
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	26807	23308	21592	4548	2257	3719
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	71279	60173	67653	8352	6633	5784
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	39175	44835	6120	4458	3451
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	474	1864	147	1248	16
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	31826	26582	29954	5516	1543	2588
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	10975	12216	332	1583	759
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	1143	800	125	85	88
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	16213	18113	1777	1792	1854
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5694	4785	4704	454	383	479
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	44472	36865	46061	3804	4377	2065
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	34045	44320	3645	4299	2009
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	2819	1741	159	77	56
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	16678	11785	20198	871	1790	2803
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	6317	11796	414	1166	1928
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	4821	5046	482	505	505
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	3801	6155	210	651	561
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	3154	2799	235	532	191
<b>1.2 निवल सविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)</b>	<b>44081</b>	<b>32550</b>	<b>2661</b>	<b>-139</b>	<b>1712</b>	<b>-6591</b>
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	32970	2424	-77	1766	-6683
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा सविभागीय निवेश	544	419	-236	62	54	-91
<b>1 विदेशी निवेश अंतर्वाह</b>	<b>54210</b>	<b>44073</b>	<b>4054</b>	<b>3538</b>	<b>2179</b>	<b>-5676</b>

अ: अनंतिमा

## सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2024			2025
		जन	नव.	दिसं.	जन
	1	2	3	4	5
<b>1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण</b>	<b>31735.74</b>	<b>2619.71</b>	<b>1946.43</b>	<b>2315.96</b>	<b>2768.89</b>
1.1 जमाराशियाँ	916.45	33.88	40.21	48.10	58.20
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	17.31	23.53	30.14	34.19
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	59.87	85.79	179.34	104.98
1.4 उपहार	3580.27	209.58	216.51	229.47	232.76
1.5 दान	11.31	0.82	0.62	0.63	0.63
1.6 यात्रा	17006.27	1549.97	1113.78	1323.64	1646.74
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्च	4611.53	267.02	276.78	279.02	308.76
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	9.32	7.49	5.13	4.47
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	449.46	172.40	210.20	368.21
1.10 अन्य	298.23	22.47	9.32	10.31	9.96

**सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और  
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक**

मद	2022-23	2023-24	2024	2025	
			फर	जन	फर
	1	2	3	4	5
<b>40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100 )</b>					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	91.20	90.75	91.94	90.88	89.36
1.2 रीर	102.78	103.71	104.71	104.84	102.37
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.01	93.13	94.37	93.26	91.98
2.2 रीर	101.10	101.22	102.00	101.77	99.60
<b>6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)</b>					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	85.93	83.62	83.77	82.02	80.93
1.2 रीर	101.80	101.66	101.95	102.29	100.33
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	100.00	97.31	97.48	95.45	94.18
2.2 रीर	100.00	99.86	100.14	100.48	98.55

टिप्पणी: वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए अब तक के डेटा अनंतिम हैं।

## सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2024-25	2024		2025
		जन	दिसं.	जन
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	77	112	108
1.2 राशि	29461	1820	6234	1978
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	5	12	5
2.2 राशि	19748	1270	3309	2020
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	82	124	113
3.2 राशि	49209	3090	9543	3998
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.60	3.70	4.50	5.80
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारत औसत मार्जिन	1.66	1.33	1.45	0.98
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-11.00	0.00-10.60	0.00-11.00

## उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	166	3685	242
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	706	533	831
ए) परिवहन	1505	100	0	0
बी) ऊर्जा	3513	55	0	398
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	0
डी) संचार	6309	0	0	13
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	1	0	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	550	530	207
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	0	3	213
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	13	685	115
IV. अन्य संस्थाएं	1728	0	3	1000
ए) एसईजेड में इकाई	1	0	3	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1727	0	0	1000
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	20	-	0
VII. एनबीएफसी	13361	2145	4614	1792
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	1437	3042	1370
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	0	0	56
सी) एनबीएफसी - अन्य	5096	708	1572	366
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	40	23	18

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जुला-सित 2023			जुला-सित 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	438441	435922	2519	553557	534943	18614
1 चालू खाता (1.1+1.2)	231670	242956	-11286	245671	256854	-11182
1.1 पण्य	108254	172799	-64544	103967	179285	-75319
1.2 अप्रत्यक्ष मदे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	123416	70158	53258	141705	77568	64137
1.2.1 सेवाएं	83352	43411	39940	93493	48943	44550
1.2.1.1 यात्रा	7482	8662	-1180	7635	9367	-1732
1.2.1.2 परिवहन	7054	7277	-223	8792	9188	-396
1.2.1.3 बीमा	828	821	7	902	786	116
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	140	244	-104	147	316	-169
1.2.1.5 विविध	67848	26408	41440	76017	29287	46730
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	39570	4333	35237	44164	4539	39624
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	21472	13673	7799	25176	15548	9628
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2069	1183	887	2190	1265	926
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	887	365	522	519	497	21
1.2.2 अंतरण	28147	3221	24926	31938	2829	29109
1.2.2.1 आधिकारिक	23	267	-244	28	265	-237
1.2.2.2 निजी	28124	2954	25170	31910	2564	29346
1.2.3 आय	11917	23526	-11608	16274	25796	-9522
1.2.3.1 निवेश आय	10158	22609	-12451	14279	24774	-10494
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1760	917	843	1995	1023	972
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	205807	192966	12841	307885	277368	30518
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	128572	124460	4112	203323	185710	17612
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16586	17420	-834	21214	23452	-2238
2.1.1.1 भारत में	15722	12686	3036	20666	15622	5044
2.1.1.1.1 इक्विटी	9877	12278	-2401	13847	15016	-1169
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4740		4740	5559		5559
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1105	409	697	1261	606	655
2.1.1.2 विदेश में	864	4734	-3870	548	7830	-7282
2.1.1.2.1 इक्विटी	864	1683	-820	548	4313	-3765
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1514	-1514
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1604	-1604	0	2003	-2003
2.1.2 संविभाग निवेश	111986	107040	4947	182108	162258	19850
2.1.2.1 भारत में	111127	105841	5286	181433	161618	19815
2.1.2.1.1 एफआईआई	111127	105841	5286	181433	161618	19815
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	101529	97937	3593	160273	149590	10683
2.1.2.1.1.2 ऋण	9598	7905	1693	21160	12028	9132
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	859	1198	-339	675	640	35
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	29728	26453	3274	38662	31126	7536
2.2.1 बाह्य सहायता	2601	1800	802	3727	1581	2146
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	49	-40	8	30	-22
2.2.1.2 भारत को	2592	1751	842	3720	1551	2168
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	7464	10422	-2958	17443	15416	2027
2.2.2.1 भारत द्वारा	2853	3926	-1073	5059	8028	-2969
2.2.2.2 भारत को	4612	6496	-1884	12384	7388	4996
2.2.3 भारत को अल्पावधि	19662	14232	5430	17492	14129	3363
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	17632	14232	3400	14817	14129	688
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	2030	0	2030	2675	0	2675
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	34020	29686	4333	52432	46345	6087
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	34020	29614	4405	52112	46345	5767
2.3.1.1 आस्तियां	8673	11210	-2538	17627	18853	-1226
2.3.1.2 देयताएं	25347	18404	6943	34485	27492	6993
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	21257	18048	3209	28921	22753	6167
2.3.2 अन्य	0	72	-72	319	0	319
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	0	1	-1	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	13488	12365	1123	13469	14184	-716
3 भूल-चक	963	0	963	0	722	-722
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	2519	-2519	0	18614	-18614
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	2519	-2519	0	18614	-18614

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

## सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जुला-सित 2023			जुला-सित 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	3624220	3603401	20819	4636946	4481027	155919
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1915021	2008316	-93295	2057901	2151571	-93670
1.1 पण्य	894849	1428380	-533531	870890	1501809	-630919
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	1020172	579936	440236	1187011	649762	537249
1.2.1 सेवाएं	688997	358846	330151	783157	409979	373178
1.2.1.1 यात्रा	61845	71601	-9756	63958	78464	-14506
1.2.1.2 परिवहन	58311	60151	-1840	73649	76965	-3316
1.2.1.3 बीमा	6842	6785	57	7553	6581	972
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1154	2018	-863	1228	2643	-1415
1.2.1.5 विविध	560846	218292	342554	636769	245326	391443
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	327091	35818	291272	369945	38026	331920
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	177488	113019	64469	210894	130244	80650
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	17106	9777	7329	18349	10595	7754
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	7334	3015	4319	4345	4167	177
1.2.2 अंतरण	232665	26623	206042	267531	23696	243835
1.2.2.1 आधिकारिक	189	2206	-2018	232	2218	-1985
1.2.2.2 निजी	232476	24416	208060	267298	21478	245821
1.2.3 आय	98510	194468	-95957	136323	216087	-79763
1.2.3.1 निवेश आय	83966	186888	-102922	119611	207519	-87908
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	14544	7579	6965	16712	8568	8145
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1701234	1595084	106150	2579045	2323409	255635
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	1062795	1028803	33993	1703161	1555629	147532
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	137100	143996	-6896	177706	196451	-18745
2.1.1.1 भारत में	129962	104866	25096	173115	130862	42253
2.1.1.1.1 इक्विटी	81644	101488	-19844	115988	125784	-9796
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	39181	0	39181	46563	0	46563
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9137	3378	5759	10564	5078	5486
2.1.1.2 विदेश में	7138	39130	-31992	4591	65589	-60998
2.1.1.2.1 इक्विटी	7138	13916	-6778	4591	36128	-31537
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	11956	-11956	0	12680	-12680
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	13258	-13258	0	16780	-16780
2.1.2 संविभाग निवेश	925695	884807	40889	1525455	1359178	166277
2.1.2.1 भारत में	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
2.1.2.1.1 एफआईआई	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	839257	809559	29698	1342550	1253064	89486
2.1.2.1.1.2 ऋण	79340	65343	13997	177250	100752	76498
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	7099	9905	-2806	5656	5363	293
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	245733	218667	27066	323859	260732	63127
2.2.1 बाह्य सहायता	21502	14877	6626	31222	13242	17979
2.2.1.1 भारत द्वारा	72	404	-331	64	247	-184
2.2.1.2 भारत को	21430	14473	6957	31158	12995	18163
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	61702	86150	-24448	146114	129136	16979
2.2.2.1 भारत द्वारा	23582	32453	-8871	42379	67249	-24870
2.2.2.2 भारत को	38120	53697	-15577	103735	61887	41849
2.2.3 भारत को अल्पावधि	162529	117640	44888	146523	118354	28169
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	145745	117640	28105	124117	118354	5763
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	16783	0	16783	22406	0	22406
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	281213	245392	35820	439202	388217	50985
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	281213	244798	36415	436527	388217	48311
2.3.1.1 आस्तियां	71689	92667	-20978	147657	157925	-10268
2.3.1.2 देयताएं	209524	152131	57393	288870	230292	58759
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	175715	149187	26528	242259	190597	51662
2.3.2 अन्य	0	594	-594	2675	0	2675
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	12	-12	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	111493	102211	9282	112822	118816	-5994
3 भूल-चूक	7964	0	7964	0	6046	-6046
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	20819	-20819	0	155919	-155919
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	20819	-20819	0	155919	-155919

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस \$)

मद	जुला-सित्त 2023			जुला-सित्त 2024 (मा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)</b>	<b>231670</b>	<b>242934</b>	<b>-11264</b>	<b>245671</b>	<b>256828</b>	<b>-11157</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)</b>	<b>191606</b>	<b>216210</b>	<b>-24604</b>	<b>197459</b>	<b>228229</b>	<b>-30769</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)</b>	<b>108254</b>	<b>172799</b>	<b>-64544</b>	<b>103967</b>	<b>179285</b>	<b>-75319</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	107367	160246	-52879	103981	161701	-57720
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	888	0	888	-14	0	-14
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		12553	-12553		17585	-17585
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>83352</b>	<b>43411</b>	<b>39940</b>	<b>93493</b>	<b>48943</b>	<b>44550</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	283	39	244	276	20	256
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	56	308	-251	90	263	-172
1.अ.ख.3 परिवहन	7054	7277	-223	8792	9188	-396
1.अ.ख.4 यात्रा	7482	8662	-1180	7635	9367	-1732
1.अ.ख.5 निर्माण	954	677	277	1263	951	312
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	828	821	7	902	786	116
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2069	1183	887	2190	1265	926
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	422	3341	-2919	448	3877	-3428
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	40546	4968	35578	44772	5333	39439
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	21472	13673	7799	25176	15548	9628
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1211	2080	-869	1107	1794	-688
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	140	244	-104	147	316	-169
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	835	140	695	694	237	458
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>11917</b>	<b>23526</b>	<b>-11608</b>	<b>16274</b>	<b>25796</b>	<b>-9522</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1760	917	843	1995	1023	972
1.आ.2 निवेश आय	8939	22196	-13257	12849	24336	-11486
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2322	12281	-9959	2725	13008	-10283
1.आ.2.2 सविभाग निवेश	84	3657	-3573	78	4152	-4074
1.आ.2.3 अन्य निवेश	520	6040	-5520	1168	6953	-5785
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	6013	217	5796	8878	223	8655
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1219	413	806	1430	438	992
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>28146</b>	<b>3198</b>	<b>24948</b>	<b>31937</b>	<b>2803</b>	<b>29134</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	28124	2954	25170	31910	2564	29346
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	27335	2040	25296	31084	1803	29282
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	788	914	-126	826	761	64
1.इ.2 सामान्य सरकार	22	245	-222	27	239	-212
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>151</b>	<b>202</b>	<b>-51</b>	<b>186</b>	<b>192</b>	<b>-6</b>
2.1 अनुष्ठापित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तरण (जमा)	9	91	-82	7	68	-61
2.2 पूंजी अंतरण	142	110	31	179	124	55
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>205657</b>	<b>195305</b>	<b>10352</b>	<b>307700</b>	<b>295815</b>	<b>11885</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>16586</b>	<b>17420</b>	<b>-834</b>	<b>21214</b>	<b>23452</b>	<b>-2238</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15722	12686	3036	20666	15622	5044
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14617	12278	2339	19405	15016	4389
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9877	12278	-2401	13847	15016	-1169
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4740		4740	5559		5559
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1105	409	697	1261	606	655
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1105	409	697	1261	606	655
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	864	4734	-3870	548	7830	-7282
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	864	3130	-2266	548	5827	-5279
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	864	1683	-820	548	4313	-3765
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		1446	-1446		1514	-1514
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1604	-1604	0	2003	-2003
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1604	-1604		2003	-2003
<b>3.2 सविभाग निवेश</b>	<b>111986</b>	<b>107040</b>	<b>4947</b>	<b>182108</b>	<b>162258</b>	<b>19850</b>
3.2अ भारत में सविभाग निवेश	111127	105841	5286	181433	161618	19815
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	101529	97937	3593	160273	149590	10683
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	9598	7905	1693	21160	12028	9132
3.2आ. भारत द्वारा सविभाग निवेश	859	1198	-339	675	640	35
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारियों स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>5476</b>	<b>7362</b>	<b>-1887</b>	<b>6359</b>	<b>11892</b>	<b>-5533</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>71609</b>	<b>60964</b>	<b>10645</b>	<b>98018</b>	<b>79598</b>	<b>18419</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	21257	18120	3137	29240	22753	6487
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	0	72	-72	319	0	319
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	21257	18048	3209	28921	22753	6167
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	22828	23788	-960	44362	40589	3773
3.4.3अ भारत को ऋण	19967	19813	153	39295	32531	6764
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2862	3975	-1113	5067	8058	-2991
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	144	10	134	47	3	44
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	19662	14232	5430	17492	14129	3363
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	7718	4814	2903	6877	2124	4753
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>2519</b>	<b>-2519</b>	<b>0</b>	<b>18614</b>	<b>-18614</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए		0	0		0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए		0	0		0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	2519	-2519	0	18614	-18614
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>205657</b>	<b>195305</b>	<b>10352</b>	<b>307700</b>	<b>295815</b>	<b>11885</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	123488	121915	1574	187308	182969	4339
4.2 ऋण लिखत	74451	66057	8394	113515	92108	21407
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	7718	7333	385	6877	20738	-13861
<b>5. निवल भूल-यूक</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>-722</b>

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

## सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जुला-सित 2023			जुला-सित 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)</b>	<b>1915018</b>	<b>2008132</b>	<b>-93114</b>	<b>2057899</b>	<b>2151355</b>	<b>-93457</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)</b>	<b>1583846</b>	<b>1787226</b>	<b>-203380</b>	<b>1654047</b>	<b>1911789</b>	<b>-257742</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)</b>	<b>894849</b>	<b>1428380</b>	<b>-533531</b>	<b>870890</b>	<b>1501809</b>	<b>-630919</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	887510	1324618	-437107	871011	1354507	-483496
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	7339	0	7339	-121	0	-121
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	103763	-103763	0	147303	-147303
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>688997</b>	<b>358846</b>	<b>330151</b>	<b>783157</b>	<b>409979</b>	<b>373178</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2339	320	2019	2316	169	2147
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	465	2544	-2078	755	2199	-1444
1.अ.ख.3 परिवहन	58311	60151	-1840	73649	76965	-3316
1.अ.ख.4 यात्रा	61845	71601	-9756	63958	78464	-14506
1.अ.ख.5 निर्माण	7887	5598	2289	10580	7963	2616
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6842	6785	57	7553	6581	972
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	17106	9777	7329	18349	10595	7754
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3485	27618	-24133	3754	32473	-28719
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	335161	41064	294097	375037	44672	330366
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	177488	113019	64469	210894	130244	80650
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	10012	17193	-7180	9269	15029	-5760
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सारकारी माल और सेवाएं	1154	2018	-863	1228	2643	-1415
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	6902	1160	5742	5815	1982	3834
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>98510</b>	<b>194468</b>	<b>-95957</b>	<b>136323</b>	<b>216087</b>	<b>-79763</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	14544	7579	6965	16712	8568	8145
1.आ.2 निवेश आय	73890	183473	-109583	107633	203850	-96217
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	19194	101520	-82327	22828	108966	-86138
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	692	30227	-29535	653	34776	-34123
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4298	49928	-45630	9783	58239	-48455
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	49705	1797	47908	74369	1870	72499
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	10076	3415	6661	11978	3669	8309
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>232662</b>	<b>26438</b>	<b>206224</b>	<b>267528</b>	<b>23480</b>	<b>244048</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	232476	24416	208060	267298	21478	245821
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	225958	16860	209099	260383	15102	245281
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6518	7557	-1039	6915	6376	539
1.इ.2 सामान्य सरकार	186	2022	-1836	230	2002	-1772
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>1245</b>	<b>1668</b>	<b>-423</b>	<b>1558</b>	<b>1611</b>	<b>-53</b>
2.1 अनुत्पादित वित्ततर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	74	755	-680	57	570	-513
2.2 पूंजी अंतरण	1170	913	257	1501	1041	460
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>1699992</b>	<b>1614420</b>	<b>85572</b>	<b>2577489</b>	<b>2477933</b>	<b>99556</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>137100</b>	<b>143996</b>	<b>-6896</b>	<b>177706</b>	<b>196451</b>	<b>-18745</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	129962	104866	25096	173115	130862	42253
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	120825	101488	19336	162551	125784	36767
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	81644	101488	-19844	115988	125784	-9796
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	39181	0	39181	46563	0	46563
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9137	3378	5759	10564	5078	5486
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9137	3378	5759	10564	5078	5486
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	39130	39130	-31992	4591	65589	-60998
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	7138	25872	-18734	4591	48809	-44218
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	7138	13916	-6778	4591	36128	-31537
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	11956	0	0	12680	-12680
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	13258	-13258	0	16780	-16780
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	13258	-13258	0	16780	-16780
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>925695</b>	<b>884807</b>	<b>40889</b>	<b>1525455</b>	<b>1359178</b>	<b>166277</b>
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	918597	874902	43695	1519799	1353816	165984
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	839257	809559	29698	1342550	1253064	89486
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	79340	65343	13997	177250	100752	76498
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	7099	9905	-2806	5656	5363	293
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>45263</b>	<b>60858</b>	<b>-15595</b>	<b>53269</b>	<b>99618</b>	<b>-46349</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>591934</b>	<b>503940</b>	<b>87993</b>	<b>821059</b>	<b>666767</b>	<b>154291</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	175715	149782	25933	244933	190597	54337
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज म्यूचुअल; एनआरजी)	0	594	-594	2675	0	2675
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	175715	149187	26528	242259	190597	51662
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	188702	196637	-7935	371605	339998	31607
3.4.3अ भारत को ऋण	165048	163780	1267	329162	272501	56660
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	23654	32857	-9202	42443	67497	-25054
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1194	85	1109	393	25	368
3.4.5 व्यापार ऋण और अधिम	162529	117640	44888	146523	118354	28169
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	63794	39797	23998	57605	17794	39811
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>20819</b>	<b>-20819</b>	<b>0</b>	<b>155919</b>	<b>-155919</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	20819	-20819	0	155919	-155919
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>1699992</b>	<b>1614420</b>	<b>85572</b>	<b>2577489</b>	<b>2477933</b>	<b>99556</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1020775	1007766	13008	1569010	1532662	36348
4.2 ऋण लिखत	615423	546038	69385	950874	771559	179316
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	63794	60616	3179	57605	173712	-116108
<b>5. निवल भूल-चूक</b>	<b>7964</b>	<b>0</b>	<b>7964</b>	<b>0</b>	<b>6046</b>	<b>-6046</b>

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

## सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023		2024			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542931	232097	528679	246248	552865	253530	555484
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	146159	497612	156225	520706	161504	523010
1.2 अन्य पूंजी	88927	31789	85938	31067	90023	32160	92026	32474
2. संविभाग निवेश	12162	277038	12096	259358	12103	277140	12306	293649
2.1 इक्विटी	10644	162061	8974	154634	10367	160898	10983	170934
2.2 ऋण	1517	114977	3122	104723	1736	116242	1323	122715
3. अन्य निवेश	132654	575068	120311	546182	140952	589624	146190	617176
3.1 व्यापार ऋण	33450	123662	30854	124733	32865	126576	32428	129931
3.2 ऋण	17547	221738	11962	208669	20803	224823	22147	240166
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	53519	154787	45711	146166	57747	160628	56105	164076
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	28138	74880	31784	66615	29537	77597	35510	83002
4. आरक्षित निधियाँ	646419		587714		651997		705782	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1033505	1395036	952218	1334219	1051300	1419629	1117808	1466309
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361531		-382001		-368329		-348501	

टिप्पणी: \* इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

## भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

## भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2024		2025	वि.व. 2023-24	2024		2025
		जन	दिसं	जन		जन	दिसं	जन
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. निपटान प्रणाली</b>								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)								
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	43.04	3.74	3.78	4.88	259206893	21705635	27448820	30296790
1.1.1 आउटराइट	16.80	1.42	1.49	1.77	170464587	14658627	16506680	17807347
1.1.2 रेपो	9.51	0.79	0.84	1.10	13463848	1100547	1348782	1627265
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	4.94	0.43	0.41	0.41	76718788	6039056	6377679	7288494
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.21	0.24	0.25	80281951	7519024	8780219	8891588
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.21	2.16	2.94	80984671	6439543	9919285	11164125
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.11	0.13	0.17	7757636	607465	1022855	1325318
<b>बी. भुगतान प्रणाली</b>								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	230.99	262.29	268.15	170886670	14691625	19163587	17499363
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	229.79	261.11	266.89	152406168	13127720	17161423	15571748
1.2 अलबैंक लेनदेन	14.12	1.20	1.17	1.26	18480503	1563905	2002163	1927615
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	137068.03	183786.41	186538.41	67542859	5945126	6935632	7000487
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.36	0.31	0.31	261	24	17	18
2.2 एपीबीएस \$	25888.17	2118.74	2451.41	2263.21	390743	42872	58705	52280
2.3 आईएमपीएस	60053.35	5087.92	4411.64	4442.23	6495652	566310	601549	606420
2.4 एनएसीएच जमा \$	16227.27	948.05	1315.94	1304.72	1525104	127514	135695	145699
2.5 एनईएफटी	72639.50	6882.78	8307.02	8567.93	39136014	3367322	3814966	3848033
2.6 यूपीआई @	1311294.68	122030.18	167300.09	169960.01	19995086	1841084	2324700	2348037
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	1.90	1.56	1.38	352	21	16	16
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1571.50	1905.47	1878.45	1687658	154405	198303	199535
3.1 भीम आधार पे @	193.59	18.82	17.18	15.79	6112	619	547	486
3.2 एनएसीएच नामे \$	16426.49	1440.08	1738.32	1715.83	1678769	153564	197549	198857
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	112.60	149.97	146.83	2777	222	207	193
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	4934.19	5608.59	5522.42	2423563	211931	228548	223090
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	3289.52	4328.50	4305.72	1831134	166444	187949	184126
4.1.1 पीओएस आधारित \$	18614.08	1725.59	2240.03	2177.43	651911	58532	73048	69429
4.1.2 अन्य \$	16996.08	1563.93	2088.46	2128.29	1179223	107912	114901	114697
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1644.68	1280.10	1216.69	592429	45487	40599	38963
4.2.1 पीओएस आधारित \$	16477.95	1193.18	964.50	910.91	393589	30383	27609	25999
4.2.2 अन्य \$	6381.69	451.50	315.60	305.78	198840	15103	12990	12965
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	7087.25	6377.99	6547.10	283048	25784	18992	19496
5.1 वालेट	63256.69	5766.67	4830.75	4875.14	234353	21259	14437	14700
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1320.58	1547.24	1671.97	48695	4525	4556	4796
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8429.87	690.67	684.93	701.18	11247	927	991	1000
5.2.2 अन्य \$	7088.84	629.91	862.31	970.79	37447	3598	3565	3796
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	547.17	506.56	516.61	7212333	583653	587879	606756
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	547.17	506.56	516.61	7212333	583653	587879	606756
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	151208.15	198185.02	201003.00	79149461	6920899	7969354	8049363
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	151439.14	198447.31	201271.14	250036131	21612523	27132941	25548726
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	150891.97	197940.75	200754.53	242823799	21028871	26545062	24941970

### भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2024		2025	वि.व. 2023-24	2024		2025
		जन	दिस	जन		जन	दिस	जन
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. अन्य भुगतान चैनल</b>								
<b>1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)</b>	1252599.21	117854.93	156762.66	158779.34	30687088	2815296	3455800	3451690
1.1 अंतर्बैंक \$	83000.56	7654.37	9183.14	9234.68	5676805	524854	618347	607529
1.2 अंतर-बैंक \$	1169598.65	110200.56	147579.52	149544.66	25010283	2290441	2837453	2844161
<b>2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउजर आधारित) @ (2.1 से 2.2)</b>	45034.98	3837.71	4072.71	4167.05	102117736	9123990	12203095	11639721
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	1028.04	1155.00	1212.87	53247042	4767036	6414756	6130804
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2809.67	2917.71	2954.18	48870694	4356954	5788339	5508917
<b>बी. एटीएम</b>								
<b>3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)</b>	66440.72	5306.01	4950.77	4910.07	3259388	260746	252471	251938
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	95.80	8.26	8.12	7.79	4648	404	429	412
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	66001.01	5272.19	4923.54	4883.53	3241538	259326	251161	250646
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	343.90	25.56	19.11	18.75	13202	1016	881	879
<b>4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)</b>	15.18	0.65	0.29	0.27	148	6	3	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	15.06	0.64	0.26	0.24	147	6	3	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.12	0.02	0.03	0.03	1	0	0	0
<b>5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @</b>	11754.95	839.66	910.87	915.09	314003	22351	23195	23246
5.1 ईपीएस @	11754.95	839.66	910.87	915.09	314003	22351	23195	23246

### भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2024		2025
		जन	दिस	जन
	1	2	3	4
<b>भुगतान प्रणाली अवसंरचना</b>				
<b>1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)</b>	10667.22	10570.66	10990.04	10909.12
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	995.00	1080.56	1088.73
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9575.66	9909.48	9820.39
<b>2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)</b>	16743.63	17676.26	13269.07	13463.21
2.1 वालेट @	13381.80	14396.94	8904.25	8954.73
2.2 कार्ड @	3361.82	3279.33	4364.82	4508.48
<b>3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)</b>	2.58	2.58	2.55	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.24	2.19	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.35	0.34	0.36	0.36
<b>4 माइक्रो एटीएम की संख्या @</b>	17.55	17.60	14.67	14.64
<b>5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या</b>	89.03	85.93	100.01	103.53
<b>6 भारत क्यूआर @</b>	62.50	60.04	63.83	64.43
<b>7 यूपीआई क्यूआर *</b>	3434.93	3213.79	6334.39	6400.67

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

#: सहकारी बैंको, एलाएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मरदों का हिस्सा रहा होगा।

\* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल रिश्तर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएस के साथ मिला दिया गया है।

3. कार्ड फ्रेमवर्क (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहलू के महीनों / अवधि के साथ तल्लु नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल धरलु वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वालेट को शामिल नहीं किया गया है।

भाग I-ए. निपटान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-महीने के 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।

भाग I-बी. भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वालेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।

5.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन डिजिट से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एनएसीएस लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।

भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।

जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

# आवसरिक शृंखला

## सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

योजना		2023-24	2023		2024	
			दिसं.	अक्तू.	नव.	दिसं.
		1	2	3	4	5
<b>1. लघु बचत</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>232460</b>	<b>16670</b>	<b>10981</b>	<b>9805</b>	<b>11133</b>
	<b>बकाया</b>	<b>1865029</b>	<b>1789946</b>	<b>1962367</b>	<b>1971752</b>	<b>1982465</b>
<b>1.1 कुल जमाराशियां</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>161344</b>	<b>12386</b>	<b>8792</b>	<b>7469</b>	<b>8734</b>
	<b>बकाया</b>	<b>1298795</b>	<b>1247555</b>	<b>1379283</b>	<b>1386750</b>	<b>1395484</b>
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	2279	1062	20	1090
	बकाया	191692	213964	200889	200909	201999
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	2171	1787	1944	2244
	बकाया	157611	104859	172819	174763	177007
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	1713	1033	900	827
	बकाया	269007	263383	280416	281316	282142
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2197	1699	1609	1531
	बकाया	175472	169033	191465	193074	194605
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	2429	2121	2109	2125
	बकाया	305776	297989	326679	328786	330912
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	135196	155580	157349	159174
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	11265	13910	14093	14299
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8472	10033	10166	10308
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	143056	147156	147178	147131
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	1616	1238	1023	1025
	बकाया	197134	196491	205221	206244	207269
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-19	-149	-137	-108
	बकाया	1754	1488	1440	1303	1195
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	1	1	0
	बकाया	349	348	354	355	355
<b>1.2 बचत प्रमाणपत्र</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>56069</b>	<b>3957</b>	<b>2080</b>	<b>2184</b>	<b>2226</b>
	<b>बकाया</b>	<b>418021</b>	<b>407244</b>	<b>434502</b>	<b>436268</b>	<b>438074</b>
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1213	637	524	430
	बकाया	183905	177154	191667	192191	192621
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1568	783	932	1113
	बकाया	220560	216509	226662	227594	228707
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1176	660	728	683
	बकाया	18277	15064	23891	24620	25303
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-1483	-7718	-8137	-8557
<b>1.3 लोक भविष्य निधि</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>15047</b>	<b>327</b>	<b>109</b>	<b>152</b>	<b>173</b>
	<b>बकाया</b>	<b>148213</b>	<b>135147</b>	<b>148582</b>	<b>148734</b>	<b>148907</b>

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल प्राप्तियों हैं, अर्थात् सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ

## सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
<b>(क) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>10538792</b>	<b>10740389</b>	<b>10946860</b>	<b>11271589</b>	<b>11422728</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	37.55	37.66	37.52	37.55	37.98
2. सहकारी बैंक	1.49	1.47	1.42	1.35	1.36
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.67	0.66	0.70	0.77	0.65
4. बीमाकृत कंपनियां	26.16	25.98	26.11	25.95	26.14
5. म्यूच्युअल फंड	3.03	2.90	2.87	3.14	3.11
6. भविष्य निधियां	4.57	4.47	4.41	4.25	4.25
7. पेंशन निधि	4.44	4.52	4.74	4.86	5.05
8. वित्तीय संस्थाएं	0.55	0.55	0.57	0.63	0.64
9. कॉरपोरेट	1.33	1.35	1.44	1.60	1.45
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.92	2.34	2.34	2.80	2.81
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	12.54	12.31	11.92	11.16	10.55
12. अन्य	5.74	5.79	5.97	5.92	6.01
12.1 राज्य सरकार	2.07	2.04	2.13	2.19	2.21

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023		2024		
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
<b>(ख) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>5338587</b>	<b>5646219</b>	<b>5727482</b>	<b>5909490</b>	<b>6055711</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	33.90	34.14	33.85	34.39	35.11
2. सहकारी बैंक	3.53	3.39	3.38	3.29	3.22
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.63	0.60	0.59	0.60	0.53
4. बीमाकृत कंपनियां	26.64	26.14	25.85	25.56	25.16
5. म्यूच्युअल फंड	2.00	2.09	2.08	1.93	1.89
6. भविष्य निधियां	22.00	22.35	22.94	23.02	22.90
7. पेंशन निधि	4.56	4.76	4.87	4.87	4.82
8. वित्तीय संस्थाएं	1.63	1.59	1.58	1.57	1.58
9. कॉरपोरेट	2.03	2.02	2.03	1.95	1.97
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.03	0.07	0.05	0.04	0.03
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.66	0.63	0.62	0.60	0.58
12. अन्य	2.37	2.20	2.17	2.18	2.19
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26

खजाना बिल					
श्रेणी	2023		2024		
	दिसं.	मार्च	जून	सितं.	दिसं.
	1	2	3	4	5
<b>(ग) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>849151</b>	<b>871662</b>	<b>858193</b>	<b>747242</b>	<b>760045</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	57.18	58.53	47.79	44.74	40.45
2. सहकारी बैंक	1.28	1.67	1.49	1.58	1.22
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.70	1.66	2.69	2.28	1.41
4. बीमाकृत कंपनियां	5.50	5.06	5.78	5.26	4.73
5. म्यूच्युअल फंड	11.21	11.89	14.50	15.06	15.41
6. भविष्य निधियां	0.08	0.15	0.60	0.26	0.04
7. पेंशन निधि	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	5.34	7.16	6.56	6.36	6.77
9. कॉरपोरेट	4.58	4.50	4.79	4.66	4.56
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.07	0.01	0.20	0.15	0.12
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	13.06	9.36	15.59	19.65	25.29
12.1 राज्य सरकार	9.26	5.88	11.55	14.95	20.11

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में विशिष्ट प्रतिभूतियां और सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड शामिल हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

अन्य श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
<b>1. कुल वितरण</b>	<b>5410887</b>	<b>6353359</b>	<b>7098451</b>	<b>7880522</b>	<b>9110725</b>	<b>9800798</b>
1.1 विकास संबंधी	3074492	3823423	4189146	4701611	5514584	5862996
1.1.1 राजस्व	2446605	3150221	3255207	3574503	3965270	4195108
1.1.2 पूंजी	588233	550358	861777	1042159	1453849	1526993
1.1.3 ऋण	39654	122844	72163	84949	95464	140895
1.2 गैर-विकास संबंधी	2253027	2442941	2810388	3069896	3467270	3800321
1.2.1 राजस्व	2109629	2271637	2602750	2895864	3266628	3537378
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	955801	1060602	1226672	1377807	1562660	1711972
1.2.2 पूंजी	141457	169155	175519	171131	196073	259346
1.2.3 ऋण	1941	2148	32119	2902	4569	3597
1.3 अन्य	83368	86995	98916	109015	128871	137481
<b>2. कुल प्राप्तियां</b>	<b>5734166</b>	<b>6397162</b>	<b>7156342</b>	<b>7855370</b>	<b>9054999</b>	<b>9650488</b>
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3851563	3688030	4823821	5447913	6379349	7209647
2.1.1 कर प्राप्तियां	3231582	3193390	4160414	4809044	5456913	6142276
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2012578	2076013	2626553	2865550	3248450	3631569
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1216203	1114805	1530636	1939550	2204462	2506181
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2800	2572	3225	3943	4001	4526
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	619981	494640	663407	638870	922436	1067371
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	31137	33448	35250	42975	49552	57273
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	110094	64994	44077	62716	86733	118239
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	59515	16951	27665	15970	55895	45125
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	50578	48044	16412	46746	30839	73114
<b>3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]</b>	<b>1449230</b>	<b>2600335</b>	<b>2230553</b>	<b>2369892</b>	<b>2644642</b>	<b>2472912</b>
<b>3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार</b>						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	571872	890012	627255	687904	346483	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	190241	107493	350911	529	-257913	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	868676	1640143	1567151	1644864	2273328	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
<b>3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार</b>						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	971378	1696012	1213169	1651076	1962969	1983757
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	209232	458801	526693	358764	434151	447511
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	38280	41273	28100	13880	21386	19857
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	10411	4545	42153	68803	52385	-33653
3ख.1.5 जमा राशियां और अग्रिम	-14227	25682	42203	51989	35819	-10138
3ख.1.6 नकद शेष	-323279	-43802	-57891	25152	55726	150310
3ख.1.7 अन्य	548753	347643	399980	163104	57374	-100684
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	26.9	32.0	30.1	29.2	30.8	30.0
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	28.5	32.2	30.3	29.1	30.7	29.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	19.2	18.6	20.4	20.2	21.6	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	16.1	16.1	17.6	17.8	18.5	18.8
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	7.2	13.1	9.5	8.8	9.0	7.6

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2024-25 के लिए जीडीपी केन्द्रीय बजट 2024-25 से है।

डेटा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: डेटा केन्द्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।

1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।

2: डेटा केन्द्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।

उप.1.1: आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार डेटा।

उप.1.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।

उप.1.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।

नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

उप.1.6: केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

उप.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

## सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2025 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	6184.49	31	1653.54	26	1025.05	5
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	473.94	8	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	386.28	25	164.97	6
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	-	-	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1590.49	31	1554.61	29	1645.12	10
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	84.61	21	168.80	11	280.07	3
17	मेघालय	453.99	9	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	56.39	7	-	-	-	-
19	नगालैंड	308.00	9	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	4317.04	31	1165.95	10	199.92	2
23	राजस्थान	2317.76	11	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4703.70	31	1697.94	25	723.84	8
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	1285.81	27	832.80	7	354.10	6
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

- टिप्पणीयां:** 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।  
2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।  
3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।  
4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।  
5) -: नगण्य

**स्रोत :** भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11543	1139	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2743	7	0	4600
3	असम	9183	90	0	0
4	बिहार	12492	-	0	19000
5	छत्तीसगढ़	7791	489	0	9495
6	गोवा	1050	456	0	0
7	गुजरात	15328	664	0	2000
8	हरियाणा	2331	1695	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2406	-	0	830
12	कर्नाटक	20254	750	0	29709
13	केरल	3110	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1274	0	0
15	महाराष्ट्र	71768	1740	0	0
16	मणिपुर	69	140	0	0
17	मेघालय	1274	108	0	0
18	मिज़ोरम	458	63	0	0
19	नगालैंड	1888	46	0	0
20	उड़ीसा	18171	2046	117	13488
21	पुदुचेरी	578	-	0	1500
22	पंजाब	9143	0	0	0
23	राजस्थान	1780	-	0	7700
24	तमिलनाडु	3439	-	0	3616
25	तेलंगाना	7880	1726	0	0
26	त्रिपुरा	1220	27	0	0
27	उत्तर प्रदेश	5006	210	0	0
28	उत्तराखंड	10696	415	0	30000
29	पश्चिम बंगाल	13810	1029	0	1500
	<b>कुल</b>	<b>235431</b>	<b>14134</b>	<b>117</b>	<b>123437</b>

- टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।  
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।  
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

**सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ**

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में ली गई कुल राशि	
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	नवंबर		दिसंबर		जन		सकल	निवल
						ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	4000	2000	4237	3237	5000	4000	63237	44155
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	400	400	395	315	-	-	795	569
3	असम	17100	16105	18500	16000	-	-500	1800	1100	1000	1000	12050	9400
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	6000	3000	6000	3500	8000	5000	40000	24422
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	-	-	-	-	-	-700	6500	2300
6	गोवा	1350	500	2550	1560	200	100	-	-	-	-	1050	250
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	3000	1000	4500	2000	7000	2700	20500	5700
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	4000	3500	2000	1150	6000	3400	33000	23270
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	500	300	1000	900	-	-300	6700	4450
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	400	400	1600	1600	920	720	12670	11130
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-	-	-750	-	-2700	-	-3450
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	4000	1500	16000	13500	16025	13025	59025	42525
13	केरल	30839	15620	42438	26638	2249	1249	2755	2455	4000	2500	36002	22302
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	5000	4250	5000	4250	5000	4000	35000	26900
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	-	-2700	-	-3100	18000	15600	85000	57300
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	-	-	200	200	-	-100	1000	640
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	-	-	635	535	-	-100	1882	1194
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	80	60	140	40	119	119	930	700
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	-	-150	250	250	-	-	550	200
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	1000	1000	-	-	1000	500	2000	-
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	-	-100	350	350	-	-300	900	200
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	387	387	2500	2200	3900	2500	36830	30676
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	4265	3015	4800	3800	5000	3000	57565	39483
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	-	-	-	-	-	-	1000	870
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	9025	5400	11000	10000	10000	7000	88025	60175
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	1000	200	3500	2500	6209	4609	46709	36591
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तर प्रदेश	55612	41797	97650	85335	6000	3500	12000	8422	5000	3000	26000	10713
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	500	500	1000	-	1000	350	4400	2750
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	3000	1000	7000	5000	8500	5500	46500	28400
	कुल	758392	518829	1007058	717140	55006	29311	88662	63454	111673	74323	725820	483815

- : शून्य

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	3,42,813	3,30,490	4,85,203	5,54,816	17,13,322
जीडीपी का प्रतिशत	6.6	5.9	7.7	8.5	7.3
I. वित्तीय आस्तियां	3,63,395	5,25,419	8,16,484	9,07,366	26,12,664
जीडीपी का प्रतिशत	7.0	9.3	13.0	13.9	11.1
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	(81,064)	2,04,486	4,28,035	2,83,634	8,35,091
(ए) बैंक जमाराशि	(1,06,429)	1,97,105	4,22,393	2,70,025	7,83,094
i. वाणिज्यिक बैंक	(1,07,941)	1,95,442	4,18,267	2,62,326	7,68,094
ii. सहकारी बैंक	1,512	1,663	4,126	7,699	15,000
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	25,365	7,380	5,642	13,610	51,997
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	17,555	(435)	(2,178)	5,770	20,712
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5,578	(1,371)	73	4,021	8,302
ii. आवास वित्त कंपनियां	11,977	936	(2,252)	1,748	12,410
2. जीवन बीमा निधियाँ	1,15,539	1,28,277	1,04,076	1,38,998	4,86,889
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	1,24,971	1,12,810	95,493	2,18,719	5,51,993
4. मुद्रा	1,28,660	(68,631)	62,793	1,46,845	2,69,667
5. निवेश	24,884	82,260	69,715	50,926	2,27,785
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14,573	63,151	37,912	44,964	1,60,600
(बी) इक्विटी	4,502	13,218	27,808	3,084	48,613
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	50,405	66,218	56,372	68,243	2,41,238
II. वित्तीय देयताएँ	20,583	1,94,929	3,31,281	3,52,550	8,99,343
जीडीपी का प्रतिशत	0.4	3.5	5.3	5.4	3.8
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	20,479	1,94,825	3,31,178	3,52,446	8,98,928
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	21,428	1,38,720	2,67,955	2,74,181	7,02,284
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26,979	1,40,269	2,65,271	3,37,010	7,69,529
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	(949)	56,105	63,223	78,266	1,96,644
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	(8,708)	30,151	32,177	40,003	93,623
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,132	24,404	29,495	37,436	98,467
iii. बीमा कंपनियाँ	627	1,550	1,551	827	4,554
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	34	34	34	34	135
3. सामान्य सरकार	70	70	70	70	279

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	2,89,980	2,99,395	2,96,132	4,54,240	13,39,748
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	4.6	4.3	6.4	5.0
I. वित्तीय आस्तियां	5,79,958	6,34,471	7,50,245	9,71,526	29,36,200
जीडीपी का प्रतिशत	8.9	9.8	10.9	13.6	10.9
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	1,85,429	3,17,361	2,80,233	3,25,853	11,08,876
(ए) बैंक जमाराशि	1,63,172	2,99,533	2,56,400	3,07,867	10,26,971
i. वाणिज्यिक बैंक	1,58,613	3,00,565	2,48,460	2,84,968	9,92,606
ii. सहकारी बैंक	4,559	(1,032)	7,940	22,899	34,365
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22,257	17,829	23,833	17,986	81,905
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	6,505	2,077	8,082	2,234	18,897
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,231	3,267	3,247	3,946	14,690
ii. आवास वित्त कंपनियां	2,274	(1,191)	4,835	(1,712)	4,207
2. जीवन बीमा निधियाँ	73,298	1,51,677	1,67,522	1,56,613	5,49,109
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	1,48,915	1,20,367	1,38,584	2,18,709	6,26,575
4. मुद्रा	66,439	(54,579)	76,760	1,48,990	2,37,610
5. निवेश	51,503	48,530	49,779	64,151	2,13,962
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35,443	44,484	40,206	58,955	1,79,088
(बी) इक्विटी	13,561	1,378	6,434	1,665	23,038
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	54,375	51,115	37,368	57,211	2,00,068
II. वित्तीय देयताएँ	2,89,978	3,35,076	4,54,113	5,17,285	15,96,452
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	5.2	6.6	7.3	5.9
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	2,89,781	3,34,880	4,53,917	5,17,089	15,95,667
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	2,34,235	2,63,450	3,70,783	3,83,845	12,52,313
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,30,284	2,61,265	3,68,305	3,31,293	11,91,146
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	55,546	71,429	83,134	1,33,244	3,43,354
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30,532	36,650	55,792	94,565	2,17,539
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22,337	33,031	24,903	36,746	1,17,017
iii. बीमा कंपनियाँ	2,678	1,748	2,439	1,933	8,798
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	34	34	34	34	135
3. सामान्य सरकार	163	163	163	163	650

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	3,53,093	2,89,675	2,98,111	6,11,366	15,52,245
जीडीपी का प्रतिशत	5.0	4.1	3.9	7.8	5.3
I. वित्तीय आस्तियां	6,74,763	8,15,842	8,08,779	11,32,130	34,31,514
जीडीपी का प्रतिशत	9.6	11.5	10.7	14.5	11.6
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	2,68,925	4,12,388	2,99,372	4,10,559	13,91,244
(ए) बैंक जमाराशि	2,55,249	5,06,208	2,79,872	3,94,573	14,35,902
i. वाणिज्यिक बैंक	2,46,079	5,06,700	2,82,537	3,87,313	14,22,629
ii. सहकारी बैंक	9,170	(492)	(2,665)	7,260	13,273
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	13,676	(93,820)	19,499	15,986	(44,658)
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	(485)	(1,07,982)	5,338	1,825	(1,01,305)
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6,119	4,782	4,896	1,943	17,740
ii. आवास वित्त कंपनियां	(6,605)	(1,12,764)	442	(118)	(1,19,045)
2. जीवन बीमा निधियाँ	1,58,358	1,41,413	1,61,192	1,30,036	5,90,999
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	1,63,508	1,48,178	1,53,255	2,53,719	7,18,661
4. मुद्रा	(48,636)	(36,701)	56,719	1,46,644	1,18,026
5. निवेश	41,409	73,060	79,633	1,08,732	3,02,834
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32,086	55,769	60,135	90,973	2,38,962
(बी) इक्विटी	3,757	7,146	9,941	8,236	29,080
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	91,198	77,504	58,607	82,441	3,09,751
II. वित्तीय देयताएँ	3,21,670	5,26,167	5,10,667	5,20,764	18,79,269
जीडीपी का प्रतिशत	4.6	7.4	6.7	6.7	6.4
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	3,21,520	5,26,016	5,10,516	5,20,613	18,78,666
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	2,13,606	8,68,874	4,02,647	3,92,330	18,77,458
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,08,027	8,75,654	3,89,898	3,82,558	18,56,136
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	1,07,914	(3,42,858)	1,07,869	1,28,283	1,208
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81,449	59,684	85,032	1,00,836	3,27,001
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23,784	(4,04,294)	21,233	25,853	(3,33,424)
iii. बीमा कंपनियाँ	2,681	1,753	1,604	1,594	7,631
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉर्पोरेट व्यापार)	34	35	35	35	138
3. सामान्य सरकार	116	116	116	116	465

- टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसंपत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
2. 2023-24 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2023-24 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2023-24 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,33,27,377	2,39,99,280	2,47,08,474	2,54,40,650
जीडीपी का प्रतिशत	110.4	108.9	108.2	107.8
(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)	1,07,90,832	1,09,87,937	1,14,10,330	1,16,80,355
i. वाणिज्यिक बैंक	99,53,044	1,01,48,486	1,05,66,753	1,08,29,079
ii. सहकारी बैंक	8,37,788	8,39,451	8,43,577	8,51,276
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,06,509	2,06,074	2,03,896	2,09,665
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67,840	66,469	66,542	70,564
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,38,669	1,39,605	1,37,353	1,39,102
(सी) जीवन बीमा निधि	49,29,725	51,42,279	52,13,527	53,57,350
(डी) मुद्रा	27,42,897	26,74,266	27,37,059	28,83,904
(ई) म्यूचुअल फंड	18,55,000	20,64,364	21,26,112	21,52,141
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	7,57,398	7,62,264	7,67,287	8,34,148
(जी) पेंशन निधि	6,16,517	6,67,379	6,99,173	7,36,592
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	14,28,499	14,94,717	15,51,089	15,86,496
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	77,43,630	79,38,456	82,69,633	86,22,079
जीडीपी का प्रतिशत	36.6	36.0	36.2	36.5
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	61,80,377	63,19,097	65,87,052	68,61,233
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	56,47,239	57,87,508	60,52,779	63,89,789
ii. सहकारी बैंक	5,31,728	5,30,164	5,32,833	4,69,989
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	15,63,253	16,19,358	16,82,581	17,60,847
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	7,36,312	7,66,463	7,98,641	8,38,643
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,21,510	7,45,914	7,75,408	8,12,845
iii. बीमा निगम	1,05,431	1,06,981	1,08,532	1,09,359

## 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियाँ (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,56,21,348	2,64,23,992	2,71,87,716	2,78,44,981
जीडीपी का प्रतिशत	102.8	102.6	103.2	103.3
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	1,18,43,527	1,21,43,060	1,23,99,459	1,27,07,326
i. वाणिज्यिक बैंक	1,09,87,692	1,12,88,257	1,15,36,717	1,18,21,685
ii. सहकारी बैंक	8,55,835	8,54,803	8,62,742	8,85,641
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,16,170	2,18,247	2,26,328	2,28,562
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74,794	78,061	81,308	85,254
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,41,376	1,40,185	1,45,020	1,43,308
(सी) जीवन बीमा निधि	53,25,967	55,59,682	57,86,593	57,95,431
(डी) मुद्रा	29,50,343	28,95,764	29,72,524	31,21,514
(ई) म्यूचुअल फंड	20,48,097	22,60,210	23,55,316	23,67,793
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	8,51,913	8,58,591	8,64,731	9,39,449
(जी) पेंशन निधि	7,44,459	7,96,454	8,53,412	8,98,343
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	16,40,871	16,91,985	17,29,353	17,86,563
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	89,11,861	92,46,741	97,00,657	1,02,17,746
जीडीपी का प्रतिशत	35.8	35.9	36.8	37.9
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	70,95,468	73,58,918	77,29,701	81,13,546
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	66,20,073	68,81,338	72,49,643	75,80,936
ii. सहकारी बैंक	4,73,897	4,76,025	4,78,487	5,30,915
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	18,16,393	18,87,823	19,70,956	21,04,201
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	8,69,175	9,05,825	9,61,617	10,56,182
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	8,35,181	8,68,213	8,93,116	9,29,862
iii. बीमा निगम	1,12,037	1,13,785	1,16,223	1,18,157

## 50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,87,56,851	2,96,44,299	3,07,47,010	3,19,86,847
जीडीपी का प्रतिशत	104.6	105.4	106.6	108.3
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	1,29,62,575	1,34,68,783	1,37,48,656	1,41,43,228
i. वाणिज्यिक बैंक	1,20,67,764	1,25,74,464	1,28,57,001	1,32,44,314
ii. सहकारी बैंक	8,94,811	8,94,319	8,91,655	8,98,914
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,28,077	1,20,095	1,25,432	1,27,257
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91,373	96,156	1,01,051	1,02,994
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,36,703	23,939	24,381	24,263
(सी) जीवन बीमा निधि	60,64,437	62,55,801	65,53,726	67,69,272
(डी) मुद्रा	30,72,878	30,36,177	30,92,896	32,39,540
(ई) म्यूचुअल फंड	26,26,046	28,29,859	31,56,299	33,87,208
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	9,55,061	9,60,344	9,64,852	10,51,376
(जी) पेंशन निधि	9,70,016	10,17,975	10,91,276	11,72,651
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	18,77,761	19,55,265	20,13,873	20,96,314
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	1,05,39,266	1,10,65,282	1,15,75,799	1,20,96,412
जीडीपी का प्रतिशत	38.3	39.3	40.2	41.0
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	83,27,152	91,96,026	95,98,673	99,91,003
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	77,88,962	86,64,616	90,54,514	94,37,072
ii. सहकारी बैंक	5,36,409	5,29,528	5,42,241	5,51,852
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	22,12,114	18,69,256	19,77,126	21,05,409
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	11,37,631	11,97,315	12,82,347	13,83,183
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	9,53,646	5,49,352	5,70,585	5,96,438
iii. बीमा निगम	1,20,837	1,22,590	1,24,194	1,25,788

- टिप्पणियाँ:**
- जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आय 2023-24 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
  - पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
  - लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
  - अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
  - संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।  
3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।  
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।  
4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।  
4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।  
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।  
7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।  
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य अर्थात् एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।  
2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

- एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।  
2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।  
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एकजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

#### सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

#### सारणी सं. 17

- 2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।  
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।  
4 : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

#### सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

#### सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

- 1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।  
2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

#### सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

#### सारणी सं. 34

- 1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान  
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान  
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

#### सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

#### सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर/रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

#### सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

### सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

### सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

○ इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।

○ जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

### सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एथोरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

#### सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनः चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

#### सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य।

#### सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

:- लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>)

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का समय शृंखला डेटा <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध है। विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2025	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (काउंटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-दिसंबर 2024	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्तूबर 2024	आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2024 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (काउंटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<https://data.rbi.org.in>)।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

## हाल के प्रकाशन

### सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:  
निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,  
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),  
भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,  
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001  
टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in)
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in) पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।
- ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

- बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।
8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।